



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 1975/ भाद्रपद 4, 1897

No. 30]

NEW DELHI, SATURDAY 26, 1975/SRAVANA 4, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India

(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities

(other than the Administrations of Union Territories)

NOTICE

The undermentioned Gazette of India Extraordinary was/were published upto the 31st January, 1975:--

Issue No.	No. and date	Issued by	Subject
16. का० प्रा० 25 (अ) दिनांक 10 जनवरी, 1975 S.O. 25 (E) Dated the 10 January, 1975.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	Central Board of Direct Taxes	आय-कर नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए नियमों का बनाना। Making rules to amend the Income-tax Rules, 1962.
17. का० प्रा० 26 (अ) दिनांक 13 जनवरी, 1975 S.O. 26 (E) dated the 13th January, 1975.	पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Chemicals.	13 जनवरी, 1975 से तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना करना। Establishment of the Oil Industry Development Board w.e.f. 13th January, 1975.
18. का० प्रा० 27 (अ) दिनांक 13 जनवरी, 1975 S.O. 27 (E) dated the 13th January, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	Ministry of Industry and Civil Supplies.	मैसर्स आर्थर बटलर एंड कंपनी (मुजफ्फरपुर लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (बिहार) के सम्बंध में 7 मई, 1973 से पूर्व किये गये या दिये गये सविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पचाटों, स्थायी आदेशों इत्यादि के प्रवर्तन का निलम्बन। Suspension of the operation of contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders, etc. entered into, given or made before the 17th May 1973 in regard to M/s. Arthur Butler and Company. (Muzaffarpore) Limited Muzaffarpore (Bihar).
19. का० प्रा० 28 (अ) दिनांक 13 जनवरी, 1975 S.O. 28 (E) dated the 13th January, 1975.	श्रम मंत्रालय	Ministry of Labour.	सोन बैलिपोर्ट लैण्ड सीमेन्ट कंपनी लिमिटेड, बूला-पत्थर खदान, बोलिया, जिला रोहतास में विद्यमान हड़ताल के जारी रखे जाने को प्रतिषिद्ध करना। Prohibiting the continuance of the strike in existence in Sone Valley Port Land Cement Company Limited, Limestone Quarry, Baulia, District Rohtas.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
20. का० प्रा० 29(प्र) दिनांक 15 जनवरी, 1975 S.O. 29(E) dated the 15th January, 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	प्रथम फरवरी, 1975 को कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों में लागू होने की तारीख निर्दिष्ट करना। Appointing the first days of February, 1975 as the date on which the provisions of the Companies (Amendment) Act, 1974 shall come into force.	
21. का० प्रा० 30(प्र) दिनांक 15 जनवरी, 1975 S.O. 30 (E) dated the 15th January, 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में संशोधन करने के लिए आदेश का निर्माण करना। Making order to amend the Exports (Control) Order, 1968.	
22. का० प्रा० 31 (प्र) दिनांक 16 जनवरी, 1975 S.O. 31 (E) dated the 16th January, 1975.	श्रम मंत्रालय Ministry of Labour.	भारत रक्षा नियम, 1971 के अर्बई, कोचीन, कांडला, मद्रास, मोरमुगाओ पारादीप और विशाखापत्तनम में पत्तनों तथा गोदियों में हड़ताल को प्रति-बिद्ध करना। Prohibiting any strike in the ports and docks at Bombay, Cochin, Kandla, Madras, Mormugao, Paradip and Visakhapatnam under Defence of India Rules, 1971.	
का० प्रा० 32(प्र) दिनांक 16 जनवरी, 1975 S.O. 32(E) dated the 16th January, 1975.	श्रम मंत्रालय Ministry of Labour.	अर्बई, कोचीन, कांडला, मद्रास, मोरमुगाओ, पारादीप और विशाखापत्तनम में पत्तनों और गोदियों में नियोजन को ऐसे नियोजन के रूप घोषित करना जिसे भारत रक्षा नियम, 1971 का नियम 119 लागू होता है। Declaring that employment in ports and docks at Bombay, Cochin, Kandla, Madras, Mormugao, Paradip and Visakhapatnam to be an employment to which rule 119 of the Defence of India Rules, 1971 applies.	
23. का० प्रा० 33(प्र) दिनांक 17 जनवरी, 1975 S.O. 33(E) dated the 17th January, 1975.	भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India.	असम राज्य के 6-बारपेटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुए रिक्त स्थान के लिए एक व्यक्ति का निर्वाचन। To elect a person as to fill the vacancy from 6-Barpeta Parliamentary Constituency in the State of Assam.	
का० प्रा० 34(प्र), दिनांक 17 जनवरी, 1975 S.O. 34(E), dated the 17th January, 1975	तद्वै -do-	असम राज्य के 6-बारपेटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामनिर्देशन, नाम-निर्देशन की संवीक्षा, अस्पष्टता वापस लेने की मतदान देने की और निर्वाचन समाप्त करने की अन्तिम तारीखें। Last Dates for making nominations, scrutiny, withdrawal of Candidatures and polling date and the Completion of election date for the 6-Barpeta Parliamentary Constituency in the State of Assam.	
का० प्रा० 35(प्र) दिनांक 17 जनवरी 1975 S.O. 35(E), dated the 17th January, 1975	तद्वै -do-	6-बारपेटा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए मतदान करने के समय का निर्धारण Fixation of hours for the bye-election of 6-Barpeta Parliamentary Constituency.	
24. का० प्रा० 36(प्र) 18वख/आई० डी० आर० ए०/75, दिनांक 17 जनवरी 1975 S.O. 36(E)/18FB/IDRA/75, dated the 17th January, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	18 जनवरी, 1976 तक आदेश सं० का० प्रा० 41(ई) आई० डी० आर० ए०/74 तारीख 17 जनवरी, 1974 को बढ़ाए जाना। Extension of duration of Order No. 41(E)/IDRA/74, dated the 17th January 1974 upto the 18th January 1976.	
25. का० प्रा० 37(प्र) / 18 वख आई० डी० आर० ए०/75, दिनांक 17 जनवरी, 1975 S.O. 37(E)/18FB/IDRA/75, dated the 17th January 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय -do-	मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क के अधीन 8 अक्टूबर, 1979 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया। Taking over of the Motor and Machinery Manufacturers Ltd; Calcutta under Section 18 AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for a period of 5 years upto and inclusive of the 8th October 1979.	
26. का० प्रा० 38(प्र)/ 18 वख। आई० डी० आर० ए०/75 दिनांक 17 जनवरी, 1975 S.O. 38(E)/ 18FB/IDRA/75, dated the 17th January 1975.	तद्वै Ministry of Industry and Civil Supplies.	18 जनवरी, 1976 तक आदेश सं० का० प्रा० 35(ई) 18 वख/आई० डी० आर० ए०/73, तारीख 19 जनवरी, 1973 की अवधि की बढ़ती। Extension of the order No. 35(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January 1973 for a further period upto the 18th of January, 1976.	

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
27.	का० प्रा० 39(घ) / 18 वच/ आई०टी०आर०ए०/75, दिनांक 17 जनवरी, 1975 S.O. 39(E)/18FB/IDRA/75, dated the 17th January, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	18 जनवरी, 1976 तक प्रादेश सं० का० प्रा० 36(ई)/18 वच/आई०टी०आर०ए०/ 73, तारीख 19 जनवरी, 1973 की अवधि को बढ़ाती। Extension of Order No. S.O. 36(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973 upto the 18th January, 1976.
28.	का० प्रा० 40(घ)/18/वच/ 18 कक/आई०टी०आर०ए०/ 74, दिनांक 20 जनवरी, 1975 S.O. 40(E) / 18FA/18AA / IDRA/74, dated the 20th Jan- uary, 1975.	तदैव -do-	का० प्रा० 128(ई) 18 वच/18 कक/आई०टी०आर०ए०/73, तारीख 5 मार्च, 1973 में संशोधन। Amendment in S.O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March, 1973.
29.	का० प्रा० 41(घ), दिनांक 20 जनवरी, 1975 S.O. 41(E), dated the 20th January, 1975.	ऊर्जा मंत्रालय Ministry of Energy.	आसाम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रहण किए जाने वाले उपक्रम प्राप्ति/अधि- कार और दायित्व तथा कर्मचारी/मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रहण किए जाने वाले उपक्रम, प्राप्ति, अधिकार और दायित्व तथा कर्मचारी। Undertakings, assets, rights and liabilities and employees to be taken over by the Assam State Electricity Board and Under- takings, assets, rights and liabilities and employees to be taken over by the Meghalaya State Electricity Board.
30.	का० प्रा० 42(घ), दिनांक 20 जनवरी, 1975 S.O. 42(E), dated the 20th Jan- uary, 1975.	कृषि और सिंचाई मंत्रालय Ministry of Agriculture and Irrigation.	आसाम राज्य भाण्डागारण निगम और मेघालय राज्य भाण्डागारण निगम द्वारा ग्रहण की जाने वाली प्राप्ति/अधिकार और दायित्व। Assets, rights and liabilities to be taken over by the Assam State Warehousing Corporation and by the Meghalaya State Ware- housing Corporation.
31.	का० प्रा० 43(घ), दिनांक 20 जनवरी, 1975 S.O. 43(E), dated the 20th January, 1975.	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय Ministry of Petroleum & Chemicals.	घोषणा (कीमत नियंत्रण) प्रादेश, 1970 के प्रादेश सं० का० प्रा० 1873 संशोधन। Amendment to the Drugs (Prices Control) Order, 1970, S.O. 1873 dated the 18th May, 1970.
32.	का० प्रा० 44(घ), दिनांक 21 जनवरी, 1975 S.O. 44(E), dated the 21st, January, 1975.	कृषि और सिंचाई मंत्रालय Ministry of Agriculture & Irrigation.	आसाम राज्य भाण्डागारण निगम 21 जनवरी, 1975 से कार्य करना बन्द कर देगा और वह तारीख 21 जनवरी, 1975 से विघटित कर दिया जायगा। Assam State Warehousing Corporation ceases to function as from and shall be dissolved on the 21st Day of January, 1975.
33.	का० प्रा० 45(घ), दिनांक 22 जनवरी, 1975। S.O. 45(E), dated. the 22nd January, 1975.	श्रम मंत्रालय Ministry of Labour	प्रादेश संख्या का० प्रा० 31(ई), दिनांक 17 जनवरी, 1975 को निरुपेक्षित। Rescission of the Order No. S.O. 31 (E), dated the 16th January, 1975.
	का० प्रा० 46(घ), दिनांक 22 जनवरी, 1975 S.O. 46 (E), dated the 22nd January, 1975.	तदैव -do-	प्रादेश संख्या का० प्रा० 589(ई) दिनांक 6 अक्टूबर, 1974 का निरुपेक्षित। Rescission of the Order No. S.O. 589(E), dated the 6th October, 1974.
	का० प्रा० 47(घ), दिनांक 22 जनवरी, 1975 S.O. 47(E), dated the 22nd January, 1975.	तदैव -do-	प्रादेश संख्या का० प्रा० 600(ई), दिनांक 8 अक्टूबर, 1974 का निरुपेक्षित। Rescission of the Order No. S.O. 600(E), dated the 8th October, 1974.
	का० प्रा० 48(घ), दिनांक 22 जनवरी, 1975 S.O. 48(E), dated the 22nd January, 1975.	तदैव -do-	प्रादेश संख्या का० प्रा० 32(ई), दिनांक 16 जनवरी, 1975 का निरुपेक्षित। Rescission of the Order No. S.O. 32 (E), dated the 16th January, 1975.
14.	का० प्रा० 49(घ)/15/आई० टी०आर०ए०/74, दिनांक 24 जनवरी, 1975 S.O. 49(E)/15/IDRA/ 74, dated the 24th January, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry & Civil Supplies.	लक्ष्मीरत्न काटन मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर के मामले की परिस्थितियों की जांच करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों की नियुक्ति। Appointing a body of persons to investigate into the Circumstances of the case of Lakshmirattan Cotton Mills Co. Ltd. Kanpur.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
35.	का०घा० 50(घ), दिनांक 24 जनवरी, 1975 S.O. 50(E) dated the 24th January 1975.	ऊर्जा मंत्रालय Ministry of Energy	2800.00 एकड़ (लगभग) या 1133.10 हेक्टेयर (लगभग) वाली भूमियाँ जो उपाखण्ड अनुसूची में वर्णित हैं अर्जित की जाएगी। Lands measuring 2800.00 acres (approximately) or 1133.10 hectares (approximately) described in the Schedule are acquired.
	का०घा० 51(घ), दिनांक 24 जनवरी, 1975 S.O. 51(E) dated the 24th January 1975.	तदैव -do-	अनुसूची में वर्णित 2557.00 एकड़ (लगभग) या 1034.77 हेक्टेयर (लगभग) वाली भूमियाँ अर्जित की जाएगी। Lands measuring 2557.00 acres (approx.) or 1034.77 hectares (approx.) described in the Schedule be acquired.
36.	का०घा० 52(घ), दिनांक 24 जनवरी, 1975 S.O. 52(E) dated the 24th January 1975.	कृषि और सिंचाई मंत्रालय Ministry of Agriculture and Irrigation.	पशुचारे की किस्में। Varieties of cattle fodder.
37.	का०घा० 53(घ), दिनांक 27 जनवरी 1975 S.O. 53(E), dated the 27th January 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	स्कूटर (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण (संशोधन), आदेश, 1975 Scooters (Distribution and Sale) Control (Amendment) Order, 1975.
38.	का०घा० 54(घ) / 18 बख / आई०डी०आर०ए०/75, दिनांक 28 जनवरी, 1975 S.O. 54(E)/18 FB/IDRA/75, dated the 28th January, 1975.	तदैव -do-	आदेश सं० का०घा० 72(ई)/18 बख/आई०डी०आर०ए०/74, तारीख 29 जनवरी, 1974 की अवधि को बढ़ाती। Extension of the duration of the Order No. S.O. 72(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th January, 1974.
39.	का०घा० 55(घ) / 18 बख / आई०डी०आर०ए० / 75, दिनांक 28 जनवरी, 1975 S.O. 55(E)/ 18FB/IDRA/75, dated the 28th January 1975.	तदैव -do-	आदेश सं० का०घा० 71(ई)/18 बख/आई०डी०आर०ए०/74 तारीख 29 जनवरी 1974 की अवधि को बढ़ाती। Extension of the duration of the Order No. S.O. 71(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th January, 1974.
40.	का०घा० 56(घ), दिनांक 28 जनवरी, 1975 S.O. 56(E), dated the 28th January 1975.	भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India	अधिसूचना सं० 100/असम-लो०स०/1/74 (उप) (2) तारीख 17 जनवरी, 1975 में संशोधन। Amendments in the Notification No. 100/AS-HP/1/74 (Bye)(2), dated 17th January, 1975.
41.	का०घा० 57(घ), दिनांक 29 जनवरी, 1975 S.O. 57(E), dated the 29th January 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce.	निर्यात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1975 Exports (Control) Second Amendment Order, 1975.
42.	का०घा० 58(घ), दिनांक 29 जनवरी, 1975 S.O. 58(E), dated the 29th January, 1975.	तदैव -do-	निर्यात (नियंत्रण) तृतीय संशोधन, आदेश, 1975 Exports (Control) Third Amendment Order, 1975.
43.	का०घा० 59(घ), दिनांक 30 जनवरी, 1975 S.O. 59(E), dated the 30th January, 1975.	तदैव -do-	निर्यात (नियंत्रण) चतुर्थी संशोधन आदेश, 1975 Exports (Control) Fourth Amendment Order, 1975.
44.	का०घा० 60(घ), दिनांक 31 जनवरी, 1975 S.O. 60(E), dated the 31st January, 1975.	भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों जो असम राज्य के 6-बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए हैं। List of Contesting Candidates to the House of the People from 6-Barpeta Constituency in the State of Assam.
45.	का०घा० 61(घ), दिनांक 31 जनवरी, 1975 S.O. 61(E) dated the 31st January, 1975.	तदैव -do-	आरक्षित तथा मुक्त प्रतीक जो राष्ट्रीय दल, राज्य दल और राज्य के हैं। Reserved and Free Symbols of National Parties, State Parties and States

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1975

कां० प्र० 2319.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 25—पिछोर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गया प्रसाद, गांव धाला, परगना पिछोर, जिला शिवपुरी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री गया प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि० सं०/25/72(73)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 1st July, 1975

S.O. 2319.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gaya Prasad, Village Dhala, Pargana Pichhore, District Shivpuri who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 25-Pichhore constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10 A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gaya Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/25/72(73)]

कां० प्र० 2320.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 25 पिछोर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बंशीधर, गांव छिरबाहा, पो० पांडेरा, परगना पिछोर, जिला शिवपुरी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री बंशीधर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० म० प्र० वि० सं०/25/72(74)]

ORDER

S.O. 2320.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bansidhar, Village Chirbaha, post Padera, Pargana Pichhore, District Shivpuri who was contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 25-Pichhore constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section-10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Banshidhar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/25/72(74)]

कां० प्र० 2321.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये मध्य प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये गोपब बन्नास (प्र० ज० प्र०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रत्नबामन सिंह, गांव खेरा, पो० मझौली जिला सोदी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रभावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री रत्नबामन सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० म० प्र० वि० सं०/61/72(72)]

ए० एम० सेन, सचिव

S.O. 2321.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Randaman Singh, Village, Khaira, P.O. Majhau, District Sidhi who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 61-Gopadbanas (ST) constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Randaman Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/61/72(72)]

A. N. SEN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1975

सीमा-शुल्क

का० प्रा० 2322.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग सीमा-शुल्क कलक्टरों द्वारा भी किया जा सकेगा।

[संख्या 79/सीमा-शुल्क/का०/सं० 473/2/75 सीमा-शुल्क 7]

यू० के० सैन, धनर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
New Delhi, the 18th July, 1975

CUSTOMS

S. O. 2322.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby directs that the powers of the Central Board of Excise and Customs under section 9 of the said Act shall also be exercisable by all the Collectors of Customs.

[No. 79/Customs/F.No. 473/2/75-Cus.VII]

U. K. SEN, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1973

आयकर

का० प्रा० 2323.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 49 (261/13/72-आइ टी जे), तारीख 4-3-1972 से उपाबद्ध और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, जलपाईगुड़ी रेंज जलपाईगुड़ी को ए रेंज, जलपाईगुड़ी के रूप में पुनः अविहित किया जाएगा तथा इस रेंज के सामने वाली प्रविष्टियों निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

'ए'-रेंज, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी के सामने:—

1. आयकर सर्कल, जलपाईगुड़ी।
उसके पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—
- 'बी'-रेंज, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी।
1. आयकर सर्कल, सिलीगुड़ी।
2. आयकर सर्कल, दार्जिलिंग।
3. प्रयोजना सर्कल, उत्तरी बंगाल।

यह अधिसूचना 2-7-1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 408 क/का० सं० 261/9/73-आइ टी जे]

स्पष्टीकारक विषय:

यह संशोधन जलपाईगुड़ी के मुफ़सिल भारतसाधन में एक और रेंज बना दी जाने और उनके परिणामस्वरूप हुए पश्चिमी बंगाल के भारतसाधन में सहायक आयुक्त (अपील) की अधिकारिता के पुनरीक्षण के कारण आवश्यक हो गया है।

(यह अधिसूचना का माग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकरण के रूप में प्राणयित है)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 2nd July, 1973

INCOME-TAX

S.O. 2323.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its notification No. 49 (261/13/72-ITJ) dated 4-3-1972 as amended from time to time, viz.

In the said Schedule Jalpaiguri Range, Jalpaiguri shall be re-designated as A-Range, Jalpaiguri and the entries against this Range shall be substituted by the following :—

Against 'A' Range Jalpaiguri, Jalpaiguri :—

1. I. T. Circle, Jalpaiguri.

After that the following shall be added:—

'B'-Range, Jalpaiguri, Jalpaiguri.

1. I. T. Circle, Siliguri.

2. I. T. Circle, Darjeeling.

3. Project Circle, North Bengal.

This Notification shall take effect from the 2-7-1973.

[No. 460A/F. No. 261/9/73-ITJ]

EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary on account of creation of one more Range in the mofussil charge of Jalpaiguri and consequent revision of Appellate Assistant Commissioner's jurisdiction in West Bengal Charge.

(This does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1973

का० प्रा० 2324.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में अभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निवेदन देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 2 में के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, बाडों और जिलों में आयकर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने दूरियों का पालन करें :—

अनुसूची

नाम	आयकर सर्किल, बाडें, जिला
(1)	(2)

कालीकट

1. आयकर सर्किल, कालीकट

2. कम्पनी सर्किल, कालीकट।

3. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, एरनाकुलम (जो उत्साहित कर दिया गया है), उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान उपरोक्त आयकर सर्किलों की अधिकारिता में है या जो उनके भीतर रहते हैं।

(1)	(2)
	4. केन्द्रीय सफिल, लिचूर (जो उत्साहित कर दिया गया है) ।
	5. आयकर सफिल, कन्नानोर ।
	6. आयकर सफिल, पलघाट ।
	7. आयकर सफिल, लिचूर ।

एरनाकुलम

1. आयकर सफिल, मतमचेरी ।
2. आयकर सफिल, एरनाकुलम ।
3. वेतन सफिल, एरनाकुलम ।
4. सम्पदा शुल्क एवम् आयकर सफिल, एरनाकुलम ।
5. विशेष सर्वेक्षण सफिल, एरनाकुलम (जो उत्साहित कर दिया गया है) ।
उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान उपरोक्त आयकर सफिल की अधिकांशता में है या जो उसके भीतर रहते हैं ।
6. आयकर सफिल, भलवाय ।
7. आयकर सफिल, कोट्टायम ।
8. आयकर सफिल, अलेप्पी ।
9. सम्पदा शुल्क एवम् आयकर सफिल, कालीकट ।

त्रिवेन्द्रम

1. आयकर सफिल, त्रिवेन्द्रम ।
2. वेतन सफिल, त्रिवेन्द्रम ।
3. आयकर सफिल, त्रिवेलोन ।
4. कम्पनी सफिल, त्रिवेन्द्रम (जो उत्साहित कर दिया गया है) ।
5. विशेष सर्वेक्षण सफिल, एरनाकुलम (जो उत्साहित कर दिया गया है) ।
उन व्यक्तियों की बाबत जिनके कारबार का मुख्य स्थान उपरोक्त आयकर सफिलों की अधिकांशता में है या जो उनके भीतर रहते हैं ।
6. विशेष अन्वेषण सफिल, त्रिवेन्द्रम (जो उत्साहित कर दिया गया है) ।
7. आयकर सफिल, तिरुवला ।
8. विशेष सफिल, एरनाकुलम ।
9. कम्पनी सफिल, एरनाकुलम ।
10. केन्द्रीय सफिल, एरनाकुलम ।

2. जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सफिल, बाई या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तर्गत किया गया है, वहाँ उस आयकर सफिल, बाई या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक उस रेंज के, जिससे वह आयकर सफिल, बाई या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयकर प्रायुक्त (अपील) के समक्ष सम्पन्न थी, इस अधिसूचना की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, बाई या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक प्रायुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जायेगी जो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा ।

3. यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1973 से प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकरण टिप्पणः—

यह संशोधन प्रायुक्त भार साधन में के सहायक प्रायुक्त (अपील), लिचूर के उत्साधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया ।

(यह अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकरण रूप में प्राणयित है)

[सं 506/फा० सं० 261/18/73-आई० टी० जे०]

New Delhi, the 30th November, 1973.

S. O. 2324—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax, of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in the column 2 thereof:—

SCHEDULE

Name	Income-tax Circles, Wards and Districts.
(1)	(2)
Calicut	1. Income-tax Circle, Calicut. 2. Companies Circle, Calicut. 3. Special Survey Circle, Ernakulam (since abolished), in respect of persons who have their principal place of business in or reside within the jurisdiction of the Income-tax Circles mentioned above. 4. Central Circle, Trichur (since abolished). 5. Income-tax Circle, Cannanore. 6. Income-tax Circle, Palghat. 7. Income-tax Circle, Trichur.
Ernakulam	1. Income-tax Circle, Mattancherry. 2. Income-tax Circle, Ernakulam. 3. Salary Circle, Ernakulam. 4. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Ernakulam. 5. Special Survey Circle, Ernakulam (since abolished), in respect of persons who have their principal place of business in or reside within the jurisdiction of the Income-tax Circle, Mentioned above. 6. Income-tax Circle, Alwaye. 7. Income-tax Circle, Kottayam. 8. Income-tax Circle, Alleppey. 9. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Calicut.
Trivandrum	1. Income-tax Circle, Trivandrum. 2. Salary Circle, Trivandrum. 3. Income-tax Circle, Quilon. 4. Companies Circle, Trivandrum (since abolished).

(1)	(2)	1	2	3
5. Special Survey Circle, Ernakulam (since abolished), in respect of persons who have their principal place of business in or reside within the jurisdiction of the Income-tax Circles mentioned above.				(2) विशेष सर्कल I, I (प्रतिरिक्त), II, II (प्रतिरिक्त), VI, VI (प्रतिरिक्त) और V II, नई दिल्ली।
6. Special Investigation Circle, Trivandrum (since abolished).				(3) डी- II जिला, नई दिल्ली।
7. Income-tax Circle, Tiruvalla.		3. विशेष रेंज-III, नई दिल्ली (नया सजित)		कम्पनी सर्कल X एण्ड XII, नई दिल्ली।
8. Special Circle, Ernakulam.		4. विशेष रेंज-I, नई दिल्ली नया सजित		कम्पनी सर्कल XVII, XVIII, XXI, और XXII, नई दिल्ली।
9. Companies Circle, Ernakulam.		5. विशेष रेंज-V, नई दिल्ली। (नया सजित)।		विशेष सर्कल V, VIII, VIII, (प्रतिरिक्त) और IX, नई दिल्ली।
10. Central Circle, Ernakulam.		6. ए-रेंज, नई दिल्ली (नया सजित)।		(i) जिला VIII (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) और (19) प्रतिरिक्त, नई दिल्ली।
		7. बी-रेंज, नई दिल्ली।		(i) जिला I (1), I (2), I (2) (प्रतिरिक्त) और I (3), नई दिल्ली।
				(ii) जिला III (19), (20), (21), (22) और (23), नई दिल्ली।
				(iii) जिला VII (1), (2), (3) और (4) नई दिल्ली।
				(iv) जिला IX (1), नई दिल्ली।
				(v) प्रतिवाय सर्कल, नई दिल्ली।
				(vi) न्यास सर्कल, नई दिल्ली।
				(vii) जिला III, बाई ए, ए (प्रतिरिक्त) ए (प्रतिरिक्त I), ओ और ओ (प्रतिरिक्त), नई दिल्ली।
				(viii) जिला VII, बाई ए, ए (1) और बी, नई दिल्ली।
				(ix) जिला बी-1, बी-1 (1), सी-1, सी-1, सी-II और सी III, नई दिल्ली।
				(x) जिला 1, बाई-ए और ए (1), नई दिल्ली।
				(xi) जिला IX, बाई-ए, नई दिल्ली।
		8. डी-रेंज, नई दिल्ली।		(i) जिला II (7), (8), (8) (प्रतिरिक्त), (9), 9 (प्रतिरिक्त), (10), (11), (11) (प्रतिरिक्त), (12) और (12) (प्रतिरिक्त), नई दिल्ली।
				(ii) जिला VIII (1), (2), (2), (4) (5), और (6), नई दिल्ली।
				(iii) विशेष सर्कल-III, XI और XIII नई दिल्ली।
2. Where an Income-tax Circle, Ward, or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward, or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Asstt. Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward of District or part thereof is transferred shall, from the date of this Notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle Ward or District or part thereof is transferred.				
3. This Notification shall take effect from 1st December, 1973.				
Explanatory Note:—				
The amendment has become necessary consequent on abolition of A.A.C. Range Trichur in Commissioner's charge.				
(This does not form part of the Notification but is intended be merely clarificatory).				
[No. 506/F.No. 261/18/73-ITJ]				
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1973				
क्रा० धा० 2325.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्कलों, बाई और जिलों में आयकर या अधिकार से निर्धारित व्यक्तियों और घायों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—				
अनुसूची				
क्रम सं०]	रेंज	आयकर सर्कल, बाई और जिले		
1	2	3		
1. विशेष रेंज-I, नई दिल्ली	(1) कम्पनी II, III, VII, XIII, XIV XV, XVI, XIX, और XX, नई दिल्ली।			
	(2) विशेष सर्कल X, नई दिल्ली।			
	(3) डी आई जिला, नई दिल्ली।			
2. विशेष रेंज-II, नई दिल्ली	(1) कम्पनी सर्कल I, IV, V, VI, VIII IX और XI, नई दिल्ली।			

1	2	3	1	2	3
		(iv) जिला VIII, बाई ए, ए (अतिरिक्त), बी, बी (अतिरिक्त), बी (अतिरिक्त (I) बी (अतिरिक्त II), सी, डी, डी (I), ई और एफ नई दिल्ली। V-ए-I, ए-II, ए-III, ए-IV, ए IV (I) और 1(I) जिले नई दिल्ली। (vi) आयकर एवं धनकर सर्कल VIII, नई दिल्ली।			(ii) जिला III, बाई ए, ए, ए, जे, के, एल, ए(1), सी (1), डू डू (1), जी (1), बाई(1) और के (1), नई दिल्ली। (iii) विशेष निर्धारण सर्कल I, II, III, IV और VII, VIII और X, नई दिल्ली। (iv) विशेष सर्वेक्षण सर्कल II, III, IV और IX, नई दिल्ली। (v) विदेशी अनुभाग, नई दिल्ली। (vi) आयकर एवं धनकर सर्कल II, नई दिल्ली। (vii) बी-VI, बी VII, बी, VII (अतिरिक्त), बी IX, और बी-IX (अतिरिक्त) जिले, नई दिल्ली।
10. एफ-रेंज, नई दिल्ली (नया सजित)		जिला III (6), (6) (अतिरिक्त), (7), (7) (अतिरिक्त), (8), (9), (11), (12), (12) (अतिरिक्त) और (13), नई दिल्ली।			
11. जी-रेंज, नई दिल्ली		जिला iv (1), (2), और (3), नई दिल्ली।			
12. एच-रेंज, नई दिल्ली		(i) जिला vi (1), (2), (3), (4) (5) (6), (7), (8), (9), (10) (10) (अतिरिक्त) (11), (12), (13), (14), और (15), नई दिल्ली (ii) जिला III (10), और (13) (अतिरिक्त), नई दिल्ली। (iii) जिला VI, बाई ए, ए (अतिरिक्त) ए(1), ए(II), बी (अतिरिक्त), सी, सी (अतिरिक्त), सी (1), सी(I), (अतिरिक्त), डी और ई, नई दिल्ली। (iv) आयकर एवं धनकर सर्कल IV और XI नई दिल्ली।	16. एम-रेंज, नई दिल्ली		(i) जिला III (1), III (1) (अतिरिक्त), III (1), प्रथम अतिरिक्त (संग्रहण), III (1) द्वितीय अतिरिक्त (संग्रहण), III (1) तृतीय अतिरिक्त (संग्रहण), III (2), III (2) (अतिरिक्त), III (3), III (4) और III (5), नई दिल्ली। (ii) जिला III, बाई बी, सी, डी, ई, एफ, एफ (अतिरिक्त) जी, एम, एम(1) और एन, नई दिल्ली।
13. जे-रेंज, नई दिल्ली		(i) जिला II (1), (2), (2), (अतिरिक्त), (3), (4), (5), और (ii) जिला II, बाई ए, (6) नई दिल्ली बी, सी, डी, ई एफ, ए (I), सी ए(I), सी(I) (अतिरिक्त) और सी (II), नई दिल्ली।	17. एम-रेंज नई दिल्ली		(i) जिला IV (4), (5), (5) (अतिरिक्त), (6), (6) (अतिरिक्त), (7), (8), (9), (10), और (11), नई दिल्ली। (ii) जिला IV, बाई ए, बी, सी, डी और सी (1), नई दिल्ली। (iii) जिला III (14), III (14) (अतिरिक्त) और III (14) (प्रथम अतिरिक्त), नई दिल्ली। (iv) जिला V (1), (2), (3), (14), (15), (15) (अतिरिक्त), (16), (16) (अतिरिक्त), (17), (17) (अतिरिक्त), (18), (18) और (20) नई दिल्ली। (v) जिला V, बाई ए, ए (अतिरिक्त), ए(1), बी, बी (1) (अतिरिक्त), बी (1), सी, सी (1), डी, डू, एफ, एफ (1), एफ (1) (अतिरिक्त), एफ (III) और जी, नई दिल्ली। (vi) जिला बी-XII, नई दिल्ली।
14. के-रेंज, नई दिल्ली		(i) जिला V (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (11) (अतिरिक्त), (12), (12) (अतिरिक्त), (13), और (13) (अतिरिक्त), नई दिल्ली। (ii) जिला III (25), (25) (अतिरिक्त) और (26), नई दिल्ली। (iii) बी-XV जिला, नई दिल्ली।			
15. एल-रेंज, नई दिल्ली		(i) जिला III (15), (16), 16 (अतिरिक्त), (17), (17), (अतिरिक्त) (18), (18) (अतिरिक्त), 18 (प्रथम अतिरिक्त), (18), (द्वितीय अतिरिक्त), (24), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), एष्ट (35), नई दिल्ली।			

1

2

3

New Delhi, the 1st December, 1973

(vii) आयकर एवं धनकर सर्कल IX और X, नई दिल्ली।

18. जी-रेंज, नई दिल्ली

(i) सभी सरकारी वेतन सर्कल, नई दिल्ली।

(ii) सभी प्राइवेट वेतन सर्कल, नई दिल्ली।

(iii) विशेष सर्कल IV, IV (अतिरिक्त) और XII, नई दिल्ली।

(iv) आयकर अधिकारी (विशेष कार्य अधिकारी, कृषि धनकर शाखा), नई दिल्ली।

(v) जिला X (7), (8), (9), (10), (10) अतिरिक्त, (11), (12), और (13), नई दिल्ली।

(vi) जिला VII (5), नई दिल्ली।

(vii) आयकर एवं धनकर सर्कल-VII, नई दिल्ली।

(viii) आयकर एवं सम्पदा शुल्क सर्कल, नई दिल्ली।

(ix) अतिरिक्त सम्पदा शुल्क एवम् आयकर सर्कल, नई दिल्ली।

(X) भविष्य निधि सर्कल, नई दिल्ली

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्कल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तर्गत हो गया हो, वहाँ उस आयकर सर्कल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उन रेंजों के जिनसे वह आयकर सर्कल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयकर आयुक्तों (अपील) के समक्ष सम्बन्ध थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्कल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएगी और वह उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना जो 1 दिसम्बर 1973 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण

संशोधन, सहायक आयुक्तों (अपील) की 6 नई रेंजों के, अर्थात् सहायक आयुक्त (अपील), विशेष रेंज III, सहायक आयुक्त (अपील), विशेष रेंज IV, सहायक आयुक्त (अपील), विशेष रेंज V, सहायक आयुक्त (अपील), 'ए' रेंज, सहायक आयुक्त (अपील), 'एफ' रेंज तथा सहायक आयुक्त (अपील), जी रेंज के 1 दिसम्बर, 1973 से क्रमशः आयकर आयुक्तों नई दिल्ली, भारतसंघन में सृष्ट किए जाने के परिणामस्वरूप और सहायक आयुक्तों (अपील) के बीच कार्य के पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकारक के रूप में प्राप्यित है)

[सं० 508 (फा० सं० 261/8/73-आइ टी जे) :

S.O. 2325.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of the persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles, Wards and Districts
(1)	(2)	(3)
1. Special Range-I, New Delhi.		(i) Companies Circles II, III, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX & XX, New Delhi. (ii) Special Circle-X, New Delhi. (iii) D-I District, New Delhi.
2. Special Range-II, New Delhi.		(i) Companies Circles I, IV, V, VI, VIII, IX and XI, New Delhi. (ii) Special Circles I, I(Addl.), II, II(Addl.), VI, VI(Addl.) and VII, New Delhi. (iii) D-II District, New Delhi.
3. Special Range-III, New Delhi. (Newly created).		Companies Circles X & XII, New Delhi.
4. Special Range-VI, New Delhi (Newly created).		Companies Circles XVII, XVIII, XXI and XXII, New Delhi.
5. Special Range-V, New Delhi, Newly created).		Special Circles V, VIII, VIII(Addl.) and IX, New Delhi.
6. A-Range, New Delhi. (Newly created).		(i) District VIII (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and (19) (Addl.) New Delhi.
7. B-Range, New Delhi.		(i) District I(1), I(2), I(2) (Addl.) and I(3), New Delhi. (ii) District III(19), (20), (21) (22) and (23), New Delhi. (iii) District VII (1), (2) (3) & (4), New Delhi. (iv) District IX(1), New Delhi. (v) Refund Circle, New Delhi. (vi) Trust Circle, New Delhi. (vii) District III, Wards A, A(Addl.), A(Addl. I), O & O (Addl.), New Delhi. (viii) District VII, Wards A, A(I) and B, New Delhi. (ix) District B-I, B-I(I), C-I, C-I(I), C-II and C-III, New Delhi. (x) District I, Wards A & A(I), New Delhi. (xi) District IX, Ward-A, New Delhi.

(1)	(2)	(3)
8. D-Range, New Delhi.	(i) District II(7), (8), (8), (Addl.), (9), 9(Addl.), (10), (11), (11) (Addl.), (12) and (12) (Addl.), New Delhi.	(iii) Special Assessment Circles I, II, III, VI, VII, VIII and X, New Delhi.
9. E-Range, New Delhi.	(i) District VIII(1), (2), (2) (Addl.), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and (12), New Delhi. (ii) District X(1), (2), (3), (4), (5) and (6), New Delhi. (iii) Special Circles-III, XI and XIII, New Delhi. (iv) District VIII, Wards A, A(Addl.), B, B(Addl.), B(Addl. I), B(Addl. II), C, D, D(I), E and F, New Delhi. (v) A-I, A-II, A-III, A-IV, A-IV(I) and I(I) Districts, New Delhi. (vi) Income-Tax-cum-Wealth-tax Circle VIII, New Delhi.	(iv) Special Survey Circles II, III, IV and IX, New Delhi. (v) Foreign Section, New Delhi. (vi) Income-tax-cum-Wealth-tax Circle II, New Delhi. (vii) B-VI, B-VII, B-VII(Addl.), B-IX and B-IX (Addl.), Districts, New Delhi.
10. F-Range, New Delhi. (Newly created).	District III(6), (6)(Addl.), (7) (7)(Addl.), (8) (9), (11), (12), (12)(Addl.) and (13), New Delhi.	16. M-Range, New Delhi. (i) District III(1), III(1) (Addl.), III(1), 1st Addl. (Collection), III(1) 2nd. Addl. (Collection), III(1) 3rd. Addl. (Collection), III(2), III(2) (Addl.), III (3), III(4) and III(5), New Delhi. (ii) District III, Wards B, C, D, E, F, F(Addl.), G, M, M(I) and N, New Delhi.
11. G-Range, New Delhi. (Newly Created).	District IV (1), (2) and (3), New Delhi.	17. N-Range, New Delhi. (i) District IV (4), (5), (5) (Addl.), (6), (6)(Addl.), (7), (8), (9), (10) and (11), New Delhi. (ii) District IV, Wards A, B, C, D and C(I), New Delhi. (iii) District III(14), III(14) (Addl.) and III(14) (1st. Addl.), New Delhi. (iv) District V(1), (2), (3), (14), (15), (15)(Addl.), (16), (16)(Addl.), (17), (17) (Addl.), (18), (19) and (20), New Delhi. (v) District V, Wards A, A (Addl.), A(I), B, B(Addl.), B(I), C, C(I), D, E, F, F(I), F(I) (Addl.), F(II) and G, New Delhi. (vi) District B-XII, New Delhi. (vii) Income-tax-cum-Wealth-tax Circles IX and X, New Delhi.
12. H-Range, New Delhi.	(i) District VI(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (10)(Addl.), (11), (12), (13), (14) and (15), New Delhi. (ii) District III(10) and (13) (Addl.), New Delhi. (iii) District VI, Wards A, A(Addl.), A(I), A(II), B (Addl.), C, C(Addl.), C(I), C(I)(Addl.), D & E, New Delhi. (iv) Income-tax-cum-Wealth tax Circles IV and XI, New Delhi.	18. O-Range, New Delhi. (i) All Government Salary Circles, New Delhi. (ii) All Private Salary Circles, New Delhi. (iii) Special Circles IV, IV (Addl.) and XII, New Delhi. (iv) Income-tax Officer (Officer on Special Duty, Agricultural Wealth-tax Branch), New Delhi. (v) District X(7), (8), (9), (10), (10)(Addl.), (11), (12) and (13) New Delhi. (vi) District VIII(5), New Delhi. (vii) Income-tax-cum-Wealth-tax Circle-VII, New Delhi. (viii) Income-tax-cum-Estate Duty Circle, New Delhi. (ix) Addl. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, New Delhi. (x) Provident Fund Circle, New Delhi.
13. J-Range, New Delhi.	(i) District II(1), (2), (2) (Addl.), (3), (4), (5) and (6), New Delhi. (ii) District II, Wards A, B, C, D, E, F, A(I), C(I), C(I)(Addl.) and C(II), New Delhi.	
14. K-Range, New Delhi.	(i) District V(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (11) (Addl.), (12), (12) (Addl.), (13) and (13) (Addl.), New Delhi. (ii) District III(25), (25)(Addl.) and (26), New Delhi. (iii) B-XV District, New Delhi.	
15. L-Range, New Delhi.	(i) District III(15), (16), (16) (Addl.), (17), (17) (Addl.), (18), (18)(Addl.), (18) (1st Addl.), (18) (2nd Addl.), (24), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34) & (35), New Delhi. (ii) District III, Wards H, I, J, K, L, A(I), C(I), E(I), G(I), I(I) and K(I), New Delhi.	

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1st December, 1973.

Explanatory Note

Amendment has become necessary consequent on the creation of 6 new ranges of Appellate Assistant Commissioners, namely A.A.C., Special Range-III, A.A.C., Special Range-IV, A.A.C., Special Range-V, A.A.C., 'A' Range, A.A.C. 'F' Range, and A.A.C., 'G' Range respectively in the charges of the Commissioners of Income-tax, New Delhi with effect from 1st December, 1973, the consequent redistribution of work amongst the Appellate Assistant Commissioners.

(This note does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 508/F.N. 261/8/73-ITJ]

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1973

क्र० भा० 2326:— आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को प्रतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तंभ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आयकर सफिल, वार्ड और जिले
1	2	3
1. विशेष रेंज, लखनऊ		1. ख-वार्ड, सफिल-1, लखनऊ। 2. बी-वार्ड, सफिल-1, लखनऊ। 3. सी-वार्ड, सफिल-1, लखनऊ। 4. ए-वार्ड, सफिल II, लखनऊ जो 31 मई, 1968 तक और 1-8-68 से 1-6-1969 तक और तत्पश्चात विद्यमान रहा) 5. कम्पनी सफिल, लखनऊ। 6. विशेष सफिल, लखनऊ। 7. फैजाबाद। 8. सम्पदा शुल्क एवम् आयकर सफिल, लखनऊ।

1	2	3
2. ए-रेंज, लखनऊ	1. सफिल-1, लखनऊ, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:- (I) ए-वार्ड, सफिल-1, लखनऊ (II) बी-वार्ड, सफिल-1, लखनऊ। (III) सी-वार्ड, सफिल-1 लखनऊ। (IV) एफ-वार्ड, सफिल-1, लखनऊ। 2. वेतन सफिल, लखनऊ। 3. ए-वार्ड को छोड़कर, सफिल-2, लखनऊ (जो 31 मई, 1968 तक और 1-8-1968 से 1-6-1969 तक और तत्पश्चात विद्यमान रहा) 4. गोरखपुर। 5. लखीमपुर खेरी।	
3. बी-रेंज, लखनऊ	1. एफ-वार्ड, सफिल-1, लखनऊ। 2. हरदोई। 3. बहराईच। 4. सीतापुर। 5. बस्ती। 6. गोंडा। 7. आजमगढ़। 8. जौनपुर। 9. बलिया।	
4. वाराणसी रेंज, वाराणसी	1. ए-सफिल-I, वाराणसी। 2. वाराणसी। 3. विशेष सफिल, वाराणसी। 4. विशेष सर्वेक्षण सफिल, वाराणसी। 5. प्रायोजना सफिल, वाराणसी।	
5. इलाहाबाद रेंज, इलाहाबाद	1. इलाहाबाद। 2. मिरजापुर। 3. वेतन सफिल, इलाहाबाद। 4. सम्पदा शुल्क एवम् आयकर सफिल, इलाहाबाद। 5. सफिल-II, वाराणसी।	
6. ए-रेंज, बरेली	1. ए-वार्ड, बरेली। 2. बी-वार्ड, बरेली। 3. हलद्वानी। 4. नैनीताल।	
7. बी-रेंज, बरेली	1. बरेली सफिल (जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं) i) ए-वार्ड, बरेली। ii) बी-वार्ड, बरेली। 2. पीलीभीत।	

1	2	3
		3. बादायूं ।
		4. अल्मोड़ा ।
		5. चम्पौसी ।
		6. रामपुर ।
		7. काशीपुर ।
		8. ग्राहजहांपुर ।
8. मुरादाबाद रेंज, मुरादाबाद	1. मुरादाबाद ।	
	2. नजीबाबाद ।	
	3. बुलंदशहर ।	

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तर्गत हो गया हो, वहाँ उस आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसके किसी भाग में दिए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त, (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, इसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएगी जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 15 दिसम्बर, 1973 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण :

यह संशोधन सहायक आयुक्तों (अपील) की अधिकारिता के और उनके कार्यभार वितरण के सुव्यवस्थीकरण के कारण आवश्यक हो गया है।

(यह अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकारक के रूप में प्राणित है)

[सं० 520 फा० सं० 261/14/73-आइटीजे]]

New Delhi, the 13th December, 1973.

S. O. 2326.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof :

SCHEDULE

Sl. No.	Ranges	Income-tax Circles, Wards & Districts.
1	2	3
1.	Special Range, Lucknow.	1. A-Ward, Circle-I Lucknow. 2. B-Ward, Circle-I, Lucknow. 3. C-Ward, Circle-I, Lucknow. 4. A-Ward, Circle-II, Lucknow (which existed upto 31-5-68 and from 1-8-1968 to 1-6-69 and thereafter).

1	2	3
		5. Company Circle, Lucknow. 6. Special Circle, Lucknow. 7. Faizabad. 8. Estate-duty-cum-Income-tax Circle, Lucknow.
2. A-Range, Lucknow.		1. Circle-I, Lucknow excluding: (i) A-Ward, Circle-I, Lucknow. (ii) B-Ward, Circle-I, Lucknow. (iii) C-Ward, Circle-I, Lucknow. (iv) F-Ward, Circle-I, Lucknow. 2. Salary Circle, Lucknow. 3. Circle-II, Lucknow (which existed upto 31-5-1968 and from 1-8-1968 to 1-6-1969 and thereafter) excluding A-Ward. 4. Gorakhpur. 5. Lakhimpur Kheri.
3. B-Range, Lucknow.		1. F-Ward, Circle-I, Lucknow. 2. Hardoi. 3. Bahraich. 3. Sitapur. 5. Basti. 6. Gonda. 7. Azamgarh. 8. Jaunpur. 9. Ballia.
4. Varanasi Range, Varanasi.		1. A Circle-I, Varanasi. 2. Varanasi. 3. Special Circle, Varanasi. 4. Special Survey Circle, Varanasi. 5. Project Circle, Varanasi.
5. Allahabad Range, Allahabad.		1. Allahabad. 2. Mirzapur. 3. Salary Circle, Allahabad. 4. Estate-duty-cum-Income-tax Circle, Allahabad. 5. Circle-II, Varanasi.
6. A-Range, Bareilly.		1. A-Ward, Bareilly. 2. B-Ward, Bareilly. 3. Haldwani. 3. Nainital.
7. B-Range, Bareilly.		1. Bareilly Circle (excluding) (i) A-Ward, Bareilly. (ii) B-Ward, Bareilly. 2. Pilibhit. 3. Badaun. 4. Almora. 5. Chandausi. 6. Rampur. 7. Kashipur. 8. Shahjahanpur.
8. Moradabad Range, Moradabad.		1. Moradabad. 2. Najibabad. 3. Bulandshahr.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessment made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Asstt. Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 15-12-73.

Explanatory Note :

The amendment has become necessary due to rationalising the jurisdiction of A.A.Cs. and their work load distribution.

(This does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory.

[No. 520 (F.No. 261/14/73-ITJ)]

क्रा० प्रा० 2327.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सं० 477 (फा० सं० 261/20/73-आईटीजे), तारीख 27 सितम्बर, 1973 द्वारा यथा संशोधित, बोर्ड की अधिसूचना सं० 435 (फा० सं० 261/20/73-आईटीजे), तारीख 14 अगस्त, 1973 का भागतः उपान्तरण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची में स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रेंज को सहायक आयकर आयुक्त,— (अपील), उसके स्तम्भ (2) में, तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर सर्किलों में आयकर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों—और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेगा :—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आयकर सर्कल और आयकर अधिकारी
1	2	3
2.	सहायक आयकर आयुक्त (अपील), बंगलौर रेंज, बंगलौर।	1. सर्कल-1, बंगलौर। 2. कोलार सर्कल, 3. तुमकुर सर्कल। 4. न्यास सर्कल एवं विदेशी अनुभाग, बंगलौर। 5. सर्कल-II, बंगलौर। 6. मैसूर सर्कल। 7. उदुपी सर्कल। 8. मैंगलोर सर्कल। 9. कुर्ग सर्कल, मरकारा। 10. मण्ड्या सर्कल। 11. आयकर अधिनियम के अधीन, आयकर, अधिकारी, चन्नपटना द्वारा पारित आदेशों के बारे में। 12. आयकर अधिनियम के अधीन, बंगलौर सर्कल (पुराना) के आयकर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के बारे में। 13. विशेष सर्वेक्षण सर्कल, बंगलौर। 14. हानस सर्कल। 15. चिकमंगलूर सर्कल। 16. बेतन, सर्कल, बंगलौर। 17. शिमोगा सर्कल।

यह अधिसूचना 15 दिसम्बर, 1973 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण :

यह संशोधन सहायक आयकर आयुक्त (अपील), मैसूर रेंज, मैसूर के भारसाधन के उत्पादन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकारक के रूप में प्राशयित है)।

[सं० 519 (फा० सं० 261/20/74-आईटीजे)]

S.O. 2327.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of Bord's notification No. 435 (F.No. 261/20/73-ITJ) dated 14-8-1973 as amended by No. 477 (F.No. 261/20/73-ITJ) dated 27th September, 1973, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in Col. (1) of the Schedule below, shall perform his function in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles by the Income-tax Officers specified in the corresponding entry in Col. (2) thereof :—

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles & Income-tax Officers
1	2	3
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bangalore Range, Bangalore.	1. Circle-I, Bangalore. 2. Kolar Circle. 3. Tumkur Circle. 4. Trust Circle-cum-Foreign Section Bangalore. 5. Circle-II, Bangalore. 6. Mysore Circle. 7. Udipi Circle. 8. Mangalore Circle. 9. Coorg Circle, Mercara. 10. Mandya Circle. 11. In respect of orders passed under the Income-tax Act by the Income-tax Officer, Channapattana. 12. In respect of orders passed under the I.T. Act, by the Income-tax Officers of Bangalore Circle (old). 13. Special Survey Circle, Bangalore 14. Hassan Circle. 15. Chickamglur Circle. 16. Salary Circle, Bangalore. 17. Shimoga Circle.

This notification shall take effect from 15th December, 1973

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on the abolition of the charge of the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Mysore Range, Mysore.

(This note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 519/F.No.261/20/73-ITJ]

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1973

क्रा० प्रा० 2328.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्वतन अधिवृत्तनाम्नों को अधि-क्रान्त करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनु-सूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रैंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्कलों/वार्डों और जिलों के आयकर या अधिकार से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची	
रैंज	आयकर सर्कल, वार्ड और जिले
1	2
1. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), ए-रेंज, जयपुर	1. विशेष वार्ड i और ii, जयपुर 2. बी और सी वार्ड, जयपुर 3. आयकर अधिकारी संग्रहण i और ii और सी-वार्ड, जयपुर। 4. कम्पनी सर्कल, जयपुर। 5. बेतन सर्कल, जयपुर। 6. विशेष अन्वेषण सर्कल, जयपुर। 7. सम्पदा शुल्क एवम् आयकर सर्कल, जयपुर।
2. सहायक आयकर आयुक्त, (अपील), बी-रेंज, जयपुर	1. सभी आयकर वार्ड/सर्कल, जयपुर जो उनसे भिन्न हैं जो ऊपर सहायक आयुक्त (अपील), ए-रेंज, जयपुर के सामने विनिर्दिष्ट हैं। 2. सभी आयकर वार्ड/सर्कल जो निम्न-लिखित स्थानों में स्थित हैं : (क) सीकर। (ख) झुनझुन।
3. सहायक आयकर आयुक्त, (अपील), जोधपुर रेंज, जोधपुर।	1. ए, बी और सी वार्ड, जोधपुर के सिवाय सभी आयकर वार्ड/सर्कल, जोधपुर। 2. सभी आयकर वार्ड/सर्कल जो निम्न स्थानों में स्थित हैं :— (क) बाड़मेर। (ख) जालोर।
4. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), कोटा रेंज, कोटा	1. सभी आयकर वार्ड (सर्कल जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं : (क) कोटा। (ख) सबाई माधोपुर। (ग) भरतपुर।
5. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), भजमेर रेंज, भजमेर।	1. सभी आयकर वार्ड/सर्कल जो निम्न स्थानों पर स्थित हैं :— (क) भजमेर। (ख) व्यावर। (ग) पाली। (घ) चित्तौड़गढ़। 2. बी-वार्ड, भीलवाड़ा।
6. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उदयपुर रेंज, उदयपुर।	1. सभी आयकर वार्ड/सर्कल जो निम्न स्थानों पर स्थित हैं :— (क) उदयपुर।

1	2
	(ख) अलवर (ग) सिरोंही। 2. ए-वार्ड, भीलवाड़ा।
7. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), बीकानेर रेंज, बीकानेर।	1. सभी आयकर वार्ड/सर्कल जो निम्न स्थानों पर स्थित हैं :— (क) श्रीगंगानगर (ख) बीकानेर (ग) नागौर (घ) चुरू (ङ) हनुमानगढ़ 2. ए, बी और सी वार्ड, जोधपुर।

जहां तक स अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्कल/वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज से अन्तरित हो गया हो, वहां उस आयकर सर्कल/वार्ड या जिला या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आयकर सर्कल/वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित हो, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के जिसको उक्त सर्कल/वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील), अन्तरित कर दिया जाएगा और वह उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1974 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण :

यह संशोधन, आयुक्त के भारसाधन में सहायक आयुक्त (अपील) की एक रेंज के, जो अलवर रेंज के नाम से ज्ञात है, उत्पादन के कारण आवश्यक हो गया है।

(उपरोक्त टिप्पण इस अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकारक के रूप में प्रासयित है)

[सं० 528/फा० सं० 261/11/73-आई टी जे]

New Delhi, the 24th December, 1973.

S. O. 2328—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in colm. 1 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles/Wards and districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof :—

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles/Wards and Districts
1	2
1. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, A-Range, Jaipur.	1. Special Wards I & II, Jaipur. 2. B. & C. Ward, Jaipur. 3. I.T.O. Collection I & II and C-Ward, Jaipur. 4. Company Circles, Jaipur. 5. Salary Circles, Jaipur. 6. Special Investigation Circles at Jaipur. 7. Estate Duty-Cum-I.T. Circle, Jaipur.

1	2
2. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, B-Range, Jaipur.	1. All I.T. Ward/Circles at Jaipur other than specified against AAC, A-Range, Jaipur as above. 2. All I.T. Wards/Circles at :— (a) Sikar. (b) Jhunjhunu.
3. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Jodhpur Range, Jodhpur.	1. All I.T. Wards/Circles at Jodhpur except A, B & C Wards, Jodhpur. 2. All I.T. Wards/Circles at :— (a) Barmer. (b) Jalore.
4. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Kota Range, Kota.	1. All I.T. Wards/Circles at :— (a) Kota. (b) Sawaimadhopur. (c) Bharatpur.
5. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Ajmer Range, Ajmer.	1. All I.T. Wards/Circles at :— (a) Ajmer. (b) Beawer. (c) Pali. (d) Chittorgarh. 2. B-Ward, Bhilwara.
6. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Udaipur Range, Udaipur.	1. All I.T. Wards/Circles at :— (a) Udaipur. (b) Alwar. (c) Sirohi. 2. A-Ward, Bhilwara.
7. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bikaner Range, Bikaner.	1. All I.T. Wards/Circles at :— (a) Sriganganagar. (b) Bikaner. (c) Nagaur. (d) Churu. (e) Hanumangarh. 2. A.B. & C. Wards at Jodhpur.

Where an Income-tax Circle/Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeal arising out of assessments made in that Income-tax Circle/Ward or district or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Range from whom that Income-tax Circle/Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said Circle/Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-1-1974.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary on account of the abolition of one Range of A. A. C. known as Alwar Range in the Commissioner's Charge,

(The above note does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory),

[No. 528/F. No. 261/11/73-ITJ]

क्र० प्रा० 2329. — आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को प्रतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है नीचे की अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, सफिलों और जिलों में आयकर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :-

अनुसूची	
मुख्यालय सहित रेंज	आयकर सफिल वार्ड और जिले
(1)	(2)
1. विशेष रेंज, डिब्रूगढ़	(i) ए-वार्ड और सी-वार्ड, डिब्रूगढ़ (ii) केन्द्रीय सफिल, डिब्रूगढ़।

1	2
	(iii) कम्पनी सफिल, डिब्रूगढ़। (iv) बी-वार्ड, डिब्रूगढ़। (v) वेतन सफिल, डिब्रूगढ़। (vi) सम्पदा शुल्क एवं आयकर सफिल, डिब्रूगढ़।
2. रेंज I, डिब्रूगढ़	(i) डिब्रूगढ़ सफिल। (ii) तिनसुकिया सफिल। (iii) डिब्रूगढ़ सफिल की अन्य सब अपीलें, जिनमें वे सम्मिलित नहीं हैं जो सहायक आयुक्त (अपील), विशेष रेंज, डिब्रूगढ़ को प्राबंठित है।
3. ओरहाट रेंज	(i) ओरहाट सफिल। (ii) गोसावाट सफिल। (iii) रोमापुर सफिल। (iv) गिबसागर सफिल। (v) मणिपुर सफिल।
4. तेजपुर सफिल	(i) तेजपुर सफिल। (ii) मौगांध
5. विशेष रेंज, गौहाटी	(i) गौहाटी सफिल का ए-वार्ड, प्रतिरिक्त ए-वार्ड, सी-वार्ड और विशेष वार्ड और सर्वेक्षण वार्ड। (ii) विशेष सफिल, शिलांग (iii) शिलांग सफिल, शिलोंग। (iv) वेतन सफिल शिलांग।
6. रेंज I, गौहाटी।	(i) गौहाटी सफिल की सभी अन्य अपीलें, जिन में वे सम्मिलित नहीं हैं जो सहायक आयुक्त (अपील), विशेष रेंज, गौहाटी को प्राबंठित हैं। (ii) धुबरी सफिल। (iii) नलबाड़ी सफिल (iv) त्रिपुरा सफिल। (v) सिलचर सफिल। (vi) करीम गंज सफिल।

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो गया हो, वहां उस आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के जिससे वह आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष सम्मिलित थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएगी जो उसके संबंध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 24 दिसम्बर, 1973 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पणः—

यह अधिसूचना शिल्लोंग रेंज और रेंज II, डिब्रुगढ़ के उत्पन्न तथा उसके परिणामस्वरूप, आयुक्त के भारसाधन में सहायक आयुक्तों (अपील), की अधिकारिता में हुए पुनर्गठन के फलस्वरूप आवश्यक हो गया है।

यह टिप्पणी अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकारक रूप में प्राणित है।

[सं० 527 (का० सं० 261/21/73-आई० टी० जे०)]

S.O. 2329.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Range, specified in Column I of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Wards, Circles and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof :—

SCHEDULE

Range with Head Quarters	Income-tax Circles, Wards & Districts
1. Special Range, Dibrugarh.	(i) A-Ward & C-Ward, Dibrugarh. (ii) Central Circle, Dibrugarh. (iii) Company Circle, Dibrugarh. (iv) B-Ward, Dibrugarh. (v) Salary Circle, Dibrugarh. (vi) E.D.-cum-I.T. Circle, Dibrugarh.
2. Range I Dibrugarh.	(i) Dibgoi Circle. (ii) Tinsukia Circle. (iii) All other appeals of Dibrugarh Circle excluding those allotted to AAC, Special Range, Dibrugarh.
3. Jorhat Range.	(i) Jorhat Circle. (ii) Golaghat Circle. (iii) Dimapur Circle. (iv) Sibsagar Circle. (v) Manipur Circle.
4. Tezpur Circle.	(i) Tezpur Circle. (ii) Nowgong Circle.
5. Special Range, Gauhati.	(i) A-Ward, Addl.-A-Ward, C-Ward, D-Ward, Special Ward and Survey Ward of Gauhati Circle. (ii) Special Circle, Shillong. (iii) Shillong Circle, Shillong. (iv) Salary Circle, Shillong.
6. Range-I, Gauhati.	(i) All other appeals of Gauhati Circle excluding those allotted to AAC, Special Range, Gauhati. (ii) Dhubri Circle. (iii) Nalbari Circle. (iv) Tripura Circle. (v) Silchar Circle. (iv) Karimganj Circle.

Where an Income-tax Circle, Ward, District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-

tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of that range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 24th December, 1973.

EXPLANATORY NOTE

This notification has become necessary consequent on the abolition of Shillong Range and Range II, Dibrugarh and consequential re-organisation of jurisdiction of A. A. Cs. in the Commissioner's charge.

(This note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 527/F.No. 261/21/73-ITJ]

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1975

का० भा० 2330.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसकी समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अपनी अधिसूचना सं० 95 (फ० सं० 261/6/72-आई० टी० जे०), तारीख 29 मई, 1972 से उपाबद्ध और समय-समय यथा संशोधित अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, स्तम्भ 1 और 2 के अधीन केन्द्रीय रेंज-1, मद्रास, विशेष रेंज, मद्रास, ए-रेंज, मद्रास, बी-रेंज, मद्रास, सी-रेंज, मद्रास, विशेष रेंज कोयम्बटूर, कोयम्बटूर रेंज, कोयम्बटूर और सालेम रेंज, सालेम के सामने क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

केन्द्रीय रेंज-I, मद्रास	1. केन्द्रीय सर्कल, आई से एक्स मद्रास।
मद्रास।	2. विशेष अन्वेषण सर्कल, 'ए' और 'बी', मद्रास।
विशेष रेंज, मद्रास,	1. कम्पनी सर्कल, I, मद्रास (सभी अनुभाग),
ए-रेंज, मद्रास।	2. सिटी सर्कल II (सभी अनुभाग), मद्रास।
	1. कम्पनी सर्कल II (सभी अनुभाग), मद्रास।
	2. सिटी सर्कल VII (सभी अनुभाग), मद्रास।
	3. बेलन सर्कल, मद्रास।
	4. बेलन सर्कल I, मद्रास।
	5. बेलन सर्कल II, मद्रास।
	6. विशेष सर्वेक्षण सर्कल (सभी अनुभाग), मद्रास।
	7. प्रतिदाय सर्कल, मद्रास।
	8. विदेशी सर्कल, मद्रास।
	9. कर वसूली सर्कल, मद्रास।
	10. सम्पदा शुल्क कर एवं आयकर सर्कल, मद्रास।
बी-रेंज, मद्रास।	1. सिटी सर्कल V, मद्रास।
	2. कुड्डालोर सर्कल (सभी अनुभाग)।
	3. पांडिचेरी सर्कल (सभी अनुभाग)।
	4. तारिगम सर्कल (सभी अनुभाग)।
	5. ताजवूर सर्कल (सभी अनुभाग)।
	6. सम्पदा शुल्क एवं आयकर सर्कल, ताजवूर।

- सी-रेंज, मद्रास।
1. सिटी सर्कल, I, मद्रास।
 2. सिटी सर्कल VI, मद्रास।
 3. कांचीपुरम सर्कल (सभी अनुभाग)।

- विशेष रेंज, कोयम्बटूर।
1. विशेष अन्वेषण सर्कल, कोयम्बटूर।
 2. केन्द्रीय सर्कल I, और II, कोयम्बटूर।
 3. कम्पनी सर्कल I (सभी अनुभाग) II और V, कोयम्बटूर।
 4. सर्कल I, कोयम्बटूर।
 5. सिटी सर्कल I (सभी अनुभाग), कोयम्बटूर।

- कोयम्बटूर रेंज, कोयम्बटूर।
1. कोयम्बटूर सर्कल।
 2. विशेष सर्वेक्षण सर्कल, कोयम्बटूर।
 3. ऊटकमंड सर्कल (सभी अनुभाग)।
 4. सम्पदा शुल्क एवम् आयकर सर्कल, कोयम्बटूर।
 5. प्रतिलाभ कर सर्कल, कोयम्बटूर और इरोड।
 6. कम्पनी सर्कल III और IV, कोयम्बटूर।
 7. सर्कल II, कोयम्बटूर।
 8. सिटी सर्कल II, (सभी अनुभाग), कोयम्बटूर।
 9. बेलूर सर्कल, कोयम्बटूर।
 10. पोलाची सर्कल (सभी अनुभाग)।
 11. तिरुपुर सर्कल।

- सालेम रेंज, सालेम।
1. सालेम सर्कल।
 2. कम्पनी सर्कल, सालेम।
 3. सर्कल I, सालेम।
 4. सर्कल II, सालेम।
 5. कृष्णागिरी सर्कल।
 6. बेलूर सर्कल।
 7. इरोड सर्कल (सभी अनुभाग)।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1974 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण टिप्पण :—

ये संशोधन सहायक आयुक्त (अपील) के रेंजों के पुनर्गठन के कारण आवश्यक हो गए हैं।

(उपरोक्त टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकरण के रूप में प्राशयित है)

[सं० 532 (फा० सं० 261/3/73-आई टी जे)]

New Delhi, the 1st January, 1974

S. O. 2330.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its Notification No. 95(F. No. 261/6/72-ITJ) dated the 29th May, 1972 as amended from time to time, namely :—

In the said Schedule against Central Range-I, Madras, Special Range, Madras, A-Range, Madras, B-Range, Madras, C-Range, Madras, Special Range, Coimbatore, Coimbatore Range Coimbatore and Salem Range, Salem under Column 1 and the following shall be respectively substituted namely :—

Central Range, I Madras, Madras.

Special Range, Madras

A-Range, Madras

B-Range, Madras

C-Range, Madras

Special Range, Coimbatore

Coimbatore Range, Coimbatore.

1. Central Circles I to X, Madras.

2. Special Investigation Circles, 'A' and 'B', Madras.

1. Companies Circles I, Madras (all Sections).

2. City Circle II (all Sections, Madras.

1. Company Circle II (all Sections), Madras.

2. City Circle VII, (all Sections), Madras.

3. Salaries Circle, Madras.

4. Salaries Circle I, Madras.

5. Salaries Circle II, Madras.

6. Special Survey Circle (all Sections), Madras.

7. Refund Circle, Madras.

8. Foreign Circle, Madras.

9. Tax Recovery Circle, Madras.

10. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Madras.

1. City Circle V, Madras.

2. Cuddalore Circle (all Sections).

3. Pondicherry Circle (all Sections).

4. Tambaram Circle (all Sections).

5. Thanjavur Circle (all Sections).

6. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Thanjavur.

1. City Circle I, Madras.

2. City Circle VI, Madras.

3. Kancheepuram Circle (all Sections).

1. Special Investigation Circle, Coimbatore.

2. Central Circles I and II, Coimbatore.

3. Company Circles I (all Sections), II and V, Coimbatore.

4. Circle I, Coimbatore.

5. City Circle I (all Sections), Coimbatore.

1. Coimbatore Circle.

2. Special Survey Circle, Coimbatore.

3. Ootacamund Circle (all Sections).

4. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Coimbatore.

5. Excess Profits Tax Circles, Coimbatore and Erode.

6. Company Circles III and IV, Coimbatore.

7. Circle II, Coimbatore.

8. City Circle II, (all Sections), Coimbatore.

1	2	3
		9. Salary Circle, Colmbatore. 10. Pollachi Circle (all Sections). 11. Tirupur Circle.
Salem Range, Salem		1. Salem Circle. 2. Company Circle, Salem. 3. Circle I, Salem 4. Circle II, Salem 5. Krishnagiri Circle 6. Vellore Circle 7. Erode Circle (all Sections).

This Notification shall take effect from 1-1-1974.

EXPLANATORY NOTE :

These amendments have become necessary on account of re-organisation of the A.A.C.'s Ranges.

(The above note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 532/F. No. 261/3/73-ITJ]

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1974

का० प्रा० 2331.-- प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रयत्न शक्तियों और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों, के सहायक प्रायकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायकर सर्कलों, बाडों और जिलों में प्रायकर या अधिकार से निर्धारित व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने हस्तों का पालन करेंगे :-

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	प्रायकर सर्कल, बाड और जिले
1	2	3
1.	विशेष रेंज-I, नई दिल्ली।	(i) कम्पनी सर्कल-II, III, VII, XIII, XIV, XVI, XIX, और XX, नई दिल्ली। (ii) विशेष सर्कल-III और X, नई दिल्ली। (iii) जिला X(4), नई दिल्ली। (IV) डी-I, जिला, नई दिल्ली।
2.	विशेष रेंज-II, नई दिल्ली।	(II) कम्पनी सर्कल-I, IV, VI, IX, XI, XXI और XXII, नई दिल्ली। (ii) विशेष सर्कल-II, नई दिल्ली। (iii) डी-II जिला, नई दिल्ली।
3.	विशेष रेंज-III, नई दिल्ली।	(i) कम्पनी सर्कल-X, XII और XV, नई दिल्ली। (ii) विशेष सर्कल-IV और IV (अतिरिक्त), नई दिल्ली।

1	2	3
4.	विशेष रेंज-I,	(i) कम्पनी सर्कल-V, VIII, XVII और XVIII, नई दिल्ली। (ii) विशेष सर्कल-I, I (अतिरिक्त), II (अतिरिक्त), VI, VI (अतिरिक्त) और VII, नई दिल्ली।
5.	विशेष रेंज-V,	(i) जिला-III(i), (2), (10), (19) और नई दिल्ली। (ii) विशेष सर्कल-V, VIII, VIII (अतिरिक्त) और IX, नई दिल्ली। (iii) न्यास सर्कल, नई दिल्ली।
6.	ए-रेंज, नई दिल्ली।	(i) जिला VIII (1), (2), 2 (अतिरिक्त), (3), (5) और (16), नई दिल्ली। (ii) जिला X(1), (2), (3), (5), (6), (8), (9) और (11), नई दिल्ली। (iii) विशेष सर्कल-XI, XII और XIII, नई दिल्ली।
7.	बी-रेंज, नई दिल्ली।	(i) जिला I(1), (2), (2) (अतिरिक्त) और (3), नई दिल्ली। (ii) जिला III(11), (12), (12) (अतिरिक्त) (20), (21) और (23), नई दिल्ली। (iii) जिला-IX-(1), नई दिल्ली। (iv) प्रतिदाय सर्कल, नई दिल्ली। (v) विदेशी अनुभाग, नई दिल्ली। (vi) VII, जिला बाड ए, ए(1) और बी, नई दिल्ली। (vii) जिला III, बाड ए, ए(अतिरिक्त) ए(अतिरिक्त-1), ओ और ओ(अतिरिक्त), नई दिल्ली। (viii) जिला बी-I, बी-I(I), सी-I, सी-I(I), सी-II और सी-III, नई दिल्ली। (ix) जिला -I, बाड ए और ए(1), नई दिल्ली। (x) जिला IX, बाड-ए, नई दिल्ली। (xi) जिला-VII(1), (2), (3) और (4), नई दिल्ली।
8.	डी-रेंज, नई दिल्ली	(i) जिला II(7), (8) (8) (अतिरिक्त), (9), (9) (अतिरिक्त), (10), (11), (11) (अतिरिक्त), (12) और 12 (अतिरिक्त), नई दिल्ली। (ii) जिला III(6), (6) (अतिरिक्त), (7) और (7) (अतिरिक्त), नई दिल्ली।
9.	ई-रेंज, नई दिल्ली।	(i) जिला VIII (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (17), (19) और (19) (अतिरिक्त), नई दिल्ली।

1	2	3	1	2	3
		(ii) जिला VIII, वाई ए, ए (अतिरिक्त), बी, बी (अतिरिक्त) बी (अतिरिक्त-I), बी (अतिरिक्त II), सी, डी, डी (i), इ, एफ और एफ (अतिरिक्त, नहीं दिल्ली।			(iii) विशेष निर्धारण सर्कल-I, II, III, VI, VII, VIII एण्ड X, नहीं दिल्ली।
		(iii) ए-I, ए-II, ए-III, ए-IV, ए-IV(1) और I(1) जिले, नहीं दिल्ली।			(iv) विशेष सर्वेक्षण सर्कल-II, III, IV और IX, नहीं दिल्ली।
		(iv) आयकर एवं धनकर सर्कल-VIII, नहीं दिल्ली।			(v) आयकर एवं धनकर सर्कल-II, नहीं दिल्ली।
10. एफ-रेंज, नहीं दिल्ली।		(i) जिला III(13), (13) (अतिरिक्त), (14), (14) (अतिरिक्त), (14) (प्रथम अतिरिक्त), (15), (16), (16) (अतिरिक्त), (17), (17) (अतिरिक्त), (18), (18) (अतिरिक्त) (18) (प्रथम अतिरिक्त) (18) (द्वितीय अतिरिक्त) नहीं दिल्ली।	16. एम-रेंज, नहीं दिल्ली।		(i) जिला III(1) (अतिरिक्त), III(1) (प्रथम अतिरिक्त) (संग्रहण), III(1), (द्वितीय अतिरिक्त), (संग्रहण), III(1) (तृतीय अतिरिक्त) (संग्रहण), III(2) (अतिरिक्त), III(3), III(4), III(5), III(8), III(9), नहीं दिल्ली।
11. जी-रेंज, नहीं दिल्ली।		(i) जिला VI (12), (13), (14) और (15), नहीं दिल्ली।			(ii) निष्क्रान्त सर्कल, नहीं दिल्ली।
12. एच-रेंज, नहीं दिल्ली।		(i) जिला VI(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (10) (अतिरिक्त) और (11), नहीं दिल्ली।	17. एन-रेंज, नहीं दिल्ली।		(i) जिला IV(1), (2), (3), (4), (5), (5) (अतिरिक्त), (6) और (6) (अतिरिक्त), नहीं दिल्ली।
		(ii) जिला IV(7), (8), (9), (10) और (11), नहीं दिल्ली।			(ii) जिला V(1), (2), (14), (15), (15) (अतिरिक्त), (16), (16) (अतिरिक्त), (17), (17) (अतिरिक्त), (18), (19) और (20), नहीं दिल्ली।
		(iii) जिला VI, वाई ए, (ए) (अतिरिक्त), (ए)(I), (ए)(II), बी (अतिरिक्त), सी, सी (अतिरिक्त), सी(I), सी(i) (अतिरिक्त), डी और ई, नहीं दिल्ली।			(iii) जिला IV, वाई ए, बी, सी डी, और सी(1), नहीं दिल्ली।
		(iv) आयकर एवं धनकर सर्कल-IV और XI, नहीं दिल्ली।			(iv) जिला V, वाई ए, ए(अतिरिक्त), ए(I), बी, बी (अतिरिक्त), (I), सी, (सी)(I), डी, ई, एफ, एफ(I), एफ(1), (अतिरिक्त), एफ(III) और जी, नहीं दिल्ली।
13. जे-रेंज, नहीं दिल्ली।		(i) जिला II(1), (2), (2) (अतिरिक्त), (3), (4), (5) और (6), नहीं दिल्ली।			(v) जिला बी-XII, नहीं दिल्ली।
		(ii) जिला II, वाई ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ए(i), सी(i), सी (i) (अतिरिक्त) और सी (II), नहीं दिल्ली।			(vi) आयकर एवं धनकर सर्कल-IX और X, नहीं दिल्ली।
		(iii) जिला (III) (26), नहीं दिल्ली।	18. ओ-रेंज, नहीं दिल्ली।		(i) सभी सरकारी भेदन सर्कल, नहीं दिल्ली।
14. के-रेंज, नहीं दिल्ली।		(i) जिला V(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (11) (अतिरिक्त) (12), (12) (अतिरिक्त), (13) और (13) (अतिरिक्त), नहीं दिल्ली।			(ii) सभी प्राइवेट भेदन सर्कल, नहीं दिल्ली।
		(ii) बी-I, जिला, नहीं दिल्ली।			(iii) आयकर अधिकारी (विशेष कार्य अधिकारी, कृषि धनकर शाखा), नहीं दिल्ली।
15. एल-रेंज, नहीं दिल्ली।		(i) जिला III(24), (25), (25) (अतिरिक्त), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), और (35), नहीं दिल्ली।			(IV) जिला X(7), (10), (10) (अतिरिक्त), (12) और (13), नहीं दिल्ली।
		(ii) जिला III, वाई एच, आई, जे, के, एल, ए(1), सी(1), ई(1), जी(1), आई(1) और के (1), नहीं दिल्ली।			(V) जिला VIII (15) और (18), नहीं दिल्ली।
					(VI) आयकर एवं धनकर सर्कल VII, नहीं दिल्ली।
					(VII) आयकर एवं सम्पदा शुल्क सर्कल, नहीं दिल्ली।

1	2	3
		(VIII) अतिरिक्त सम्पदा शुल्क एवं आयकर शुल्क सर्कल, नई दिल्ली।
		(IX) भविष्य निधि सर्कल, नई दिल्ली।
	<p>जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्कल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तर्गत हो गया हो, वहां उस आयकर सर्कल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उन रेंजों के, जिनमें वह आयकर सर्कल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयकर प्रावृक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्कल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक प्रावृक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएगी, जो उनके संबंध में कार्यवाही करेंगी।</p> <p>(यह अधिसूचना 3 जनवरी, 1974 को प्रभावी होगी)।</p> <p>स्पष्टीकारक टिप्पणः</p> <p>यह संशोधन दिल्ली में सहायक प्रावृक्तों (अपील) के बीच कार्य-भार में पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया है।</p> <p>(यह इस अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकारक के रूप में आशयित है)।</p> <p>[सं० 537/फा०सं० 261/8/73-आई०टी०जे०]</p> <p>New Delhi, the 3rd January, 1974</p> <p>S.O.2331.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of the persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—</p>	
Sl. No.	Ranges	Income-tax Circles, Wards and Districts
1	2	3
1. Special Range-I, New Delhi.		(i) Companies Circles-II, III, VII, XIII, XIV, XVI, XIX and XX, New Delhi. (ii) Special Circles-III & X New Delhi. (iii) District X(4), New Delhi. (iv) D-I, District, New Delhi.
2. Special Range-II, New Delhi.		(i) Companies Circles-I, IV, VI, IX, XI, XXI and XXII New Delhi. (ii) Special Circle-II, New Delhi. (iii) D-II, District, New Delhi.
3. Special Range-III, New Delhi.		(i) Companies Circles-X, XII and XV, New Delhi. (ii) Special Circles-IV and IV (Addl.), New Delhi.
4. Special Range-IV, New Delhi.		(i) Companies Circles-V, VIII, XVII and XVIII, New Delhi.

1	2	3
		(ii) Special Circles-I, I(Addl.), II (Addl.), VI, VI (Addl.) and VII, New Delhi.
5. Special Range-V, New Delhi.		(i) District-III (i), (2), (10) (19) and (22), New Delhi (ii) Special Circles-V, VIII, VIII(Addl.) and IX, New Delhi. (iii) Trust Circle, New Delhi.
6. A-Range, New Delhi		(i) District VIII (1), (2) 2 (Addl.), (3), (5) and (16), New Delhi. (ii) District X(1), (2), (3), (5), (6), (8), (9) and (11), New Delhi. (iii) Special Circles-XI, XII and XIII, New Delhi.
7. B-Range, New Delhi		(i) District I(1), (2), (2)(Addl.) and (3), New Delhi. (ii) District III(11), (12), 12 (Addl.), (20), (21) and (23), New Delhi. (iii) District-IX-(1), New Delhi. (iv) Refund Circle, New Delhi. (v) Foreign Section, New Delhi. (vi) District VII, Wards A, A(I) and B, New Delhi. (vii) District III, Wards A, A (Addl.), A(Addl.-I), O & O(Addl.), New Delhi. (viii) District B-I, B-I(I), C-I, C-I(I), C-II and C-III, New Delhi. (ix) District-I, Wards A & A(I), New Delhi. (x) District IX, Ward-A, New Delhi. (xi) District-VII(1), (2), (3) and (4), New Delhi.
8. D-Range, New Delhi		(i) District II(7), (8), (8) (Addl.) (9), (9)(Addl.), (10), (11), (11)(Addl.), (12) and 12 (Addl.), New Delhi. (ii) District III(6), (6)(Addl.), (7) and (7)(Addl.), New Delhi.
9. E-Range, New Delhi		(i) District VIII(4), (6), (7) (8), (9), (10), (11), (12), (13) (14), (17), (19) and (19) (Addl.), New Delhi. (ii) District VIII, Wards A, A(Addl.), B, B(Addl.), B, (Addl. I), B(Addl. II), C, D, D(I), E, F and F(Addl.) New Delhi. (iii) A-I, A-II, A-III, A-IV, A-IV(I) and I(I) Districts, New Delhi. (iv) Income-tax-cum-Wealthtax Circle-VIII, New Delhi.
10. F-Range, New Delhi		(i) District III(13), (13)(Addl.) (14), (14) (Addl.), (14)(1st Addl.) (15), (16), (16) (Addl.) (17), (17)(Addl.), (18), (18), (Addl.), (18) (1st Addl.) and (18) (2nd Addl.), New Delhi.
11. G-Range, New Delhi		(i) District VI(12), (13), (14) and (15), New Delhi.

1	2	3	1	2	3
12. H-Range, New Delhi	(i) Distt. VI(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (10)(Addl.) and (11), New Delhi.	(ii) Distt. IV(7), (8), (9), (10) and (11), New Delhi.	(iii) District IV, Wards A, B, C, D and C(I), New Delhi.	(iv) District V, Wards A, A(Addl.), A(I), B, B(Addl.), B(I), C, C(I), D, E, F, F(I), F(I)(Addl.), F(II) and G, New Delhi.	(v) District B-XII, New Delhi.
	(iii) Distt. VI, Wards A, (a) (Addl.), (A)(I), (A)(II) B (Addl.), C, C(Addl.), C(I), C(I)(Addl.), D & E, New Delhi.	(iv) Income-tax-cum-Wealth-tax Circles-IV and XI, New Delhi.	18. O-Range, New Delhi	(i) All Government Salary Circles, New Delhi.	(ii) All Private Salary Circles, New Delhi.
13. J-Range, New Delhi	(i) District II(1), (2), (2)(Addl.), (3), (4), (5) and (6), New Delhi.	(ii) District II, Wards A, B, C, D, E, F, A(I), C(I), C(I) (Addl.) and C(II), New Delhi.		(iii) Income-tax Officer (Officer on Special Duty, Agricultural Wealth-tax Branch), New Delhi.	(iv) District X.(7), (10), (10) (Addl.), (12) and (13), New Delhi.
	(iii) District III (26) New Delhi.			(v) District VIII(15) and (18), New Delhi.	(vi) Income-tax-cum-Wealth-tax Circle-VII, New Delhi.
14. K-Range, New Delhi	(i) District V(3), (4), (5)(6), (7), (8), (9), (10) (11), (11) (Addl.), (12), (12)(Addl.), (13) and (13) (Addl.), New Delhi.	(ii) B-XV, District, New Delhi.		(vii) Income-tax-cum - Estate Duty Circle, New Delhi.	(viii) Addl. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, New Delhi.
15. L-Range, New Delhi	(i) District III(24), (25), (25) (Addl.), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34) and (35), New Delhi.	(ii) District III, Wards H, I, J, K, L, A(I), C(I) E(I), G(I), I(I) and K(I), New Delhi.		(ix) Provident Fund Circle, New Delhi.	
	(iii) Special Assessment Circles-I, II, III, VI, VII, VIII & X, New Delhi.	(iv) Special Survey Circles-II, III, IV, & IX, New Delhi.			
	(v) Income-tax-cum-wealth-tax Circle-II, New Delhi.	(vi) B-VI, B-VII, B-VII(Addl.), B-IX and B-IX(Addl.), New Delhi.			
16. M-Range, New Delhi	(i) District III(1)(Addl.), III (1)(1st Addl.)(Coll.) III(1), 2nd Addl. (Collection), III(1) 3rd Addl. (Collection), III(2)(Addl.), III(3), III(4), III(5), III(8), III(9), New Delhi.	(ii) Evacuee Circle, New Delhi.			
	(iii) District III, Wards B, C, D, E, F, F(Addl.), G, M, M(I) and N, New Delhi.				
17. N-Range, New Delhi	(i) District IV(1), (2), (3), (4), (5), 5(Addl.), (6) and (6) (Addl.), New Delhi.	(ii) District V(1), (2) (14), (15), (15)(Addl.), (16) (16) (Addl.), (17) (17)(Addl.), (18), (19) and (20), New Delhi.			

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 3-1-1974.

EXPLANATORY NOTE :—

This amendment has become necessary as a result of re-distribution of work-load amongst the A.A.Cs. in Delhi

(This does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No 537/F.No.261/8/73- ITJ]

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1974

क्रा० प्र० 2332.—सायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस विधित उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 748 (क्रा० सं० 261/19/74- क्राई टी जे सारीख 25-11-74 से उपायय अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूची में निम्नलिखित परिवर्तन और परिवर्तन किए जायेंगे :-

क्रम सं०	रेंज	जोड़े गये आयकर सर्किल/वार्ड
6.	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) रेंज 4, अहमदाबाद	"एस आई सी-1 से 7 तक" के स्थान पर "एस आई सी 1 से 9 तक, अहमदाबाद" रखा जाएगा।
9.	सहायक आयकर आयुक्त (अपील), एस०भार० सुरत	प्रविष्टि सं० "3, सुरत सर्किल-3" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :- "4. एस आई सी 1 से 4 तक, सुरत।"
10.	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) भार० भार० रोजकोट	प्रविष्टि सं० "4. ई० डी सर्किल, राजकोट" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :- "3. एस० आई० सी० जूनागढ़"
12.	सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जे० भार० जामनगर	प्रविष्टि सं० "3 पोरबन्दर सर्किल" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :- "4. एस आई सी, जामनगर।"

यह अधिसूचना 15-1-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 813/फा० सं० 261/19/74-आई टी जे]

New Delhi, the 9th January, 1974

INCOME-TAX

S. O. 2332.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the schedule appended to its Notification No. 746 (F. No. 261/19/74-ITJ) dated 10-10-74 and No. 781 (F. No. 261/19/74-ITJ) dated 25-11-74 namely.

In the said schedule the following additions and alterations shall be made.

S. No.	Range	Income-tax Circle/Ward added
6.	A.A.C. Range-IV, Ahmedabad	"SIC.I to VII A' bad" may be substituted by "SIC.I to IX Ahmedabad."
9.	A.A.C.S.R. Surat	After entry No. "3, Surat Cir-III" the following shall be added :- "4. SIC. I to IV, Surat."
10.	A.A.C.R.R. Rajkot	After entry No. "4 E.D. Circle Rajkot" the following shall be added :- "5. SIC, Junagadh."
12.	A.A.C.J.R. Jamnagar	After entry No. "3 Porbandar Circle" the following shall be added :- "4. SIC, Jamnagar."

This Notification shall take effect from 15-1-1975.

[No. 813/F. No. 261/19/74-ITJ]

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1974

फा० सं० 2333.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों

का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 390 (फा० सं० 261/1/73 आई टी जे), तारीख 25-6-73 का उपांतर करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि उक्त अधिसूचना की अधिसूची में क्रम सं० 5 और 7 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी :

- विशेष रेंज, कानपुर। (1) विशेष सर्कल, कानपुर।
(2) ए-वार्ड, कम्पनी सर्कल, कानपुर।
(3) सम्पदा शुल्क एवम् आयकर सर्कल, कानपुर।
- रेंज-II, कानपुर। (1) सर्कल II कानपुर, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :-
सर्कल II(1), कानपुर, और
सर्कल II(6), कानपुर।
(2) आयकर अधिकारी, प्रशासन-II, कानपुर
(3) आयकर अधिकारी, संग्रहण-II, कानपुर
(4) बी-वार्ड, कम्पनी सर्कल, कानपुर
(5) सी-वार्ड, कम्पनी सर्कल, कानपुर
(6) इटावा।
(7) फतेहगढ़।

यह अधिसूचना 21 जनवरी, 1974 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण

यह संशोधन कानपुर स्थित सहायक आयकर आयुक्तों (अपील) के बीच कार्य के पुनर्वितरण के कारण आवश्यक हो गया है।

(यह टिप्पण इस अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकारक रूप में प्राणयित है)।

[सं० 544/फा० सं० 261/1/73-आई टी जे]

New Delhi, the 21st January, 1974

S. O. 2333.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in modification of Notification No. 390 (F. No. 261/1/73-ITJ) dated 25-6-1973, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the entries at Sl. Nos. 5 and 7 in the Schedule to the said Notification shall be substituted by the following entries :-

- Special Range, Kanpur (i) Special Circle, Kanpur.
(ii) Award, Company Circle, Kanpur.
(iii) Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Kanpur.
- Range-II, Kanpur (i) Circle II, Kanpur excluding :
Circle II(1) Kanpur and
Circle II(6) Kanpur.
(ii) I.T.O. Administration-II, Kanpur.
(iii) I.T.O. Collection-II, Kanpur.
(iv) B-Ward, Company Circle, Kanpur.
(v) C-Ward, Company Circle, Kanpur.
(vi) Etawah.
(vii) Fatehgarh.

This Notification shall take effect from 21-1-1974.

EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary on account of re-distribution of work amongst the Appellate Asstt. Commissioners of Income-tax at Kanpur.

(This note does not form part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 544 (F. No. 261/1/73-ITJ)]

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1974

का० प्रा० 2324.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने हुए तथा इस संबंध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकार के लिये निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

अनुसूची

रेंज	आयकर सफिल, वार्ड और जिले
(1)	(2)
1. अमृतसर रेंज :	अमृतसर स्थित सभी आयकर सफिल, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालय अमृतसर में थे या हैं, उनसे निम्न जो किसी अन्य सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के सामने स्तम्भ 2 में वर्णित हैं।
2. अम्बाला रेंज :	सभी आयकर सफिल, वार्ड और जिले जिनके मुख्यालय निम्नलिखित स्थानों में हैं :— (1) अम्बाला, (2) करनाल, (3) पानीपत, (4) सोनीपत, (5) यमुना नगर, (6) मन्डी, (7), शिमला, और (8) आयकर सफिल, चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, और ऊना जिले, पठानकोट।
3. जालन्धर रेंज :	सभी आयकर सफिल, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालय निम्नलिखित स्थानों में हैं :— (1) अम्बोहर, (2) भटिंडा, (3) फिरोजपुर, (4) होशियारपुर, (5) जालन्धर, (6) मोगा, और (7) संग्रहण वार्ड, चण्डीगढ़, उन व्यक्तियों के संबंध में जिनके कारबार का मुख्य स्थान या जिनका निवास आयकर अधिकारी, होशियारपुर की अधिकारिता में है।
4. जम्मू रेंज :	सभी आयकर सफिल, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालय निम्नलिखित स्थानों में हैं :— (1) बटाला, (2) गुरदासपुर, (3) जम्मू, (4) पठानकोट, (5) श्रीनगर (केन्द्रीय सफिल VII लुधियाना को छोड़कर जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है) तथा (6) जिले I (VIII) से () (XIV), अमृतसर।

(1)

(2)

5. लुधियाना रेंज

सभी आयकर सफिल, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालय निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—
(1) लुधियाना (केन्द्रीय सफिलों, लुधियाना को छोड़कर जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सफिल VII, लुधियाना भी है तथा जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है) तथा (2) खाना, (3) जिला I, अमृतसर, उनसे निम्न जो स्तम्भ 2 में सहायक आयुक्त (अपील), जम्मू के सामने वर्णित हैं।

6. पटिलाया रेंज :

सभी आयकर सफिल, वार्ड या जिले जिनके मुख्यालय निम्नलिखित स्थान पर हैं :—
(1) पटिलाया, (2) संगरूर, (3) मलेर-कोटला, (4) बरनाला और (5) चण्डीगढ़ (परन्तु होशियारपुर सफिलों के निर्धारितियों के बारे में आयकर अधिकारी, संग्रहण वार्ड, चण्डीगढ़ द्वारा पारित आदेशों के बारे में अधिकारिता उस सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के पास होगी जिसकी अधिकारिता होशियारपुर पर है)।

7. रोहतक रेंज :

सभी आयकर सफिल, वार्ड और जिले जिनके मुख्यालय निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—
(1) फरीदाबाद, (2) गुड़गांव, (3) मलेर-कोटला, (4) नारनौल, (5) रोहतक, (6) सिरसा, (7) जिनंद और (8) रेवाड़ी।

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तर्गत हो गया हो, वहां उस आयकर सफिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष सम्बित थीं। जिससे वह आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जायेगी, जो उसके संबंध में कार्यवाही करेगा।

जहां सभी सफिल, वार्ड और जिले जिनके किसी स्थान विशेष पर मुख्यालय है, किसी सहायक आयुक्त (अपील) को समनुदेशित कर दिए गए हैं, वहां वह अब समाप्त हो गये उन मुख्यालयों पर के सफिलों, वार्डों और जिलों की बाबत भी अधिकारिता रखेगा।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1974 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण

यह संशोधन सहायक आयुक्तों (अपील) के बीच कार्य के पुनः प्राबन्धन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया है।

(उपरोक्त टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकरण रूप में प्राशयित है)

[सं० 550/का० सं० 261/1/74—आई टी जे]

New Delhi, the 31st January, 1974

S.O. 2334.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 122 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Asstt. Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof :—

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles, Wards and Districts
1	2
1. Amritsar Range	All Income-tax Circles, Wards or Districts at Amritsar which had or have their headquarters at Amritsar other than those mentioned in column 2 against any other Appellate Assistant Commissioner of Income-tax.
2. Ambala Range	All Income-tax Circles, Wards and Districts having headquarters at :— (i) Ambala (ii) Karnal, (iii) Panipat, (iv) Sonapat, (v) Yamuna Nagar, (vi) Mandi, (vii) Simla & (viii) Income-tax Circle Chamba, Kangra, Hamirpur and Una District at Pathankot.
3. Jullundur Range	All Income-tax Circle, Wards or Districts having headquarters at :— (i) Abohar, (ii) Bhatinda, (iii) Ferozepur, (iv) Hoshiarpur, (v) Jullundur, (vi) Moga and (vii) Collection Ward, Chandigarh in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officer, Hoshiarpur.
4. Jammu Range	All Income-tax Circle, Wards or Districts having headquarters at :— (i) Batala, (ii) Gurdaspur, (iii) Jammu, (iv) Pathankot, (v) Srinagar (except Central Circle VII Ludhiana with headquarters at Srinagar) and (vi) Districts I(viii) to I(xiv), Amritsar.
5. Ludhiana Range	All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :— (1) Ludhiana (except Central Circles, Ludhiana including Central Circle VII, Ludhiana with headquarters at Srinagar) and (ii) Khana, (iii) Dist. I Amritsar other than those mentioned in Col. 2 against A.A.C., Jammu.

6. Patiala Range

All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at :—

(i) Patiala, (ii) Sangrur, (iii) Malerkotla, (iv) Barnala and (v) Chandigarh (provided that the jurisdiction in respect of the orders passed by the I.T.O., Collection Ward, Chandigarh in respect of the assessee of Hoshiarpur Circles would be with the A.A.C. of Income-tax holding jurisdiction over Hoshiarpur).

7. Rohtak Range

All Income-tax Circles, Wards and Districts having headquarters at :—

(i) Faridabad, (ii) Gurgaon, (iii) Hissar, (iv) Narnaul, (v) Rohtak, (vi) Sirsa, (vii) Jind and (viii) Rewari.

Where an Income-tax Circle, Ward and District or part thereof stands transferred by this notification from one range to another range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification shall take effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

Where all Circles, Wards and Districts having headquarters at a particular place have been assigned to an Appellate Assistant Commissioner he will have jurisdiction in respect of Circles, Wards and Districts at those headquarters since abolished also.

This Notification shall take effect from 1-2-1974.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent upon re-allocation of the work amongst the Appellate Assistant Commissioners.

(The above note does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 550/F. No. 261/1/74-ITJ]

का० प्रा० 2335.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अपनी अधिसूचना सं० 49 (261/13/72-आई०टी०जे०), तारीख 4-3-1972 से उपाबद्ध और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अनुसूची में

I. 'एफ' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा:—

1 जिला I (I) (ए से एक बार्ड और प्रथम अतिरिक्त सी-बार्ड, कलकत्ता) ।

II. 'आई' रेंज, कलकत्ता के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा:—

1 जिला VII (ए से एक बार्ड तथा प्रथम अतिरिक्त सबडिवीजन बार्ड), कलकत्ता ।

III. 'के' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 जिला V (I) (ए से ई वार्ड), कलकत्ता।

IV. 'एम' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 जिला II (2) (ए से एक वार्ड), कलकत्ता।

5 'एस' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 हावड़ा (ए से ई वार्ड), कलकत्ता।
- 2 सम्मिश्र जिला IV (1) (ए से जे वार्डों से भिन्न), कलकत्ता।

VI. 'एक्स' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा

- 1 जिला IV (3) (ए से एक वार्ड), कलकत्ता।
- 2 जिला IV (1) (ए से जी वार्डों से भिन्न), कलकत्ता।

VII. वार्ड, रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 समिश्र जिला IV (जी, एच, आई और जे वार्ड), कलकत्ता।

VIII. 'एबी' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 जिला V (1) (एक से जे-वार्ड), कलकत्ता।

IX. 'एजी' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 जिला I (2) (ए से इ वार्डों से भिन्न), कलकत्ता।

X. 'एआई' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 हुगली (ए, बी और सी-वार्ड), हुगली।

XI. 'एएम' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 जिला VI (ए से जी वार्डों से भिन्न), कलकत्ता।

XII. 'एएफ' रेंज, कलकत्ता के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 समिश्र वार्ड 1 (ए से जे वार्डों से भिन्न और अतिरिक्त एक वार्ड) कलकत्ता
- 2 बिदेगी अनुभाग, कलकत्ता।

XIII. उक्त अनुसूची में 'क्यू' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

- 1 हुण्डी सकिल, (ए, बी, सी, डी, एक, जी और एच-वार्ड), कलकत्ता।
- 2 विशेष सकिल-I, कलकत्ता।
- 3 विशेष सकिल-II, कलकत्ता।

XIV. उक्त अनुसूची में 'एफ' रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- 1 हुण्डी सकिल (इ आई, जे और के वार्ड), कलकत्ता।

XV. उक्त अनुसूची में (ए एच रेंज, कलकत्ता के सामने, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

- 1 जिला, III (2) ('जी' से 'के' वार्डों तक), कलकत्ता।
- 'बी' रेंज, जलपैगुड़ी के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—
- I 'एएस' रेंज, 1 जिला II (1), कलकत्ता।
- कलकत्ता। 2 विशेष सर्वेक्षण सकिल-III, कलकत्ता।
- 3 हुगली (डी, इ और एक-वार्ड), हुगली।

II 'एम्पार' रेंज, 1 जिला IV (2) (इ से एच वार्ड तक और अतिरिक्त जी-वार्ड), कलकत्ता।

III 'एटी' रेंज, 1 जिला II (2) (ए से एक वार्डों से भिन्न), कलकत्ता।

2 जिला VII, (ए से एक तथा प्रथम अतिरिक्त सर्वेक्षण वार्डों से भिन्न), कलकत्ता

यह अधिसूचना 1-2-1974 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण टिप्पण :

यह संशोधन पश्चिमी बंगाल में तीन नए रेंजों को बनाए जाने और उसके परिणामस्वरूप हुए सहायक आयुक्त (अपील) की अधिकारिता के पुनरीक्षण के कारण आवश्यक हो गया है।

(यह अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकारक रूप में प्राणित है)

[सं० 549/फा०सं० 271/4/74-आई०टी०जे०]

S.O. 2335.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its Notification No. 49 (261/13/72-ITJ) dated 4-3-72 as amended from time to time, viz.

IN THE SAID SCHEDULE

- I. Against 'F' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Dist. I (I) (A to F-Wards and 1st Addl. C-Ward, Calcutta.
- II. Against 'T' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Dist. VII (A to F-Wards & 1st Addl. Survey Ward), Calcutta.
- III. Against 'K' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Dist. V (I) (A to E-Wards), Calcutta.
- IV. Against 'M' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Dist. II (2) (A to F-Wards), Calcutta.
- V. Against 'S' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Howrah (A to E-Wards) Calcutta.
 2. Comp. Dist. IV (Other than A to J-Wards) Calcutta.
- VI. Against 'X' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Dist. IV (3) (A to F-Wards, Calcutta.
 2. Dist. IV (1) (other than A to G-Wards) Calcutta.
- VII. Against 'Y' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Com. Dist. IV (G, H, I & J-Wards), Calcutta.
- VIII. Against 'AB' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Dist. V (I) (F to J-Wards), Calcutta.
- IX. Against 'AG' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Dist. I (2) (Other than A to E-Wards), Calcutta.
- X. Against 'AI' Range, Calcutta, following shall be substituted —
 1. Hooghly (A, B & C-Ward), Hooghly.

XI. Against 'AN' Range, Calcutta, following shall be substituted —

1. Dist. VI (Other than A to G-Wards), Calcutta.

XII. Against 'AQ' Range, Calcutta, following shall be substituted —

1. Comp. Dist. I (Other than A to J-Wards and Addl. F-ward, Calcutta.

2. Foreign Section, Calcutta.

XIII. In the said Schedule against 'Q' Range, Calcutta, following shall be substituted—

1. Hindi Circle (A, B, C, D, F, G, and H-Wards), Calcutta.

2. Special Circle-I, Calcutta.

3. Special Circle-II, Calcutta.

XIV. In the said schedule against 'AF' Range, Calcutta following shall be substituted —

1. Hindi Circle (E, I, J and K-Wards), Calcutta.

XV. In the said schedule against 'AN' Range, Calcutta, following shall be substituted —

1. Dist. III (2) (From 'G' to 'K' Wards), Calcutta.

After 'B' Range, Jalpaiguri, following shall be added—

I. 'AS' Range, 1. Dist. II(I), Calcutta.

Calcutta. 2. Special Survey Circle-III, Calcutta.

3. Hooghly (B, E & F-Wards), Hooghly.

II. 'AR' Range, 1. Dist. IV(2) (From E to H-Wards Calcutta. and Addl. G-Ward, Calcutta

III. 'AT' Range, 1. Dist. II(2) (Other than A to Calcutta P-Wards), Calcutta.

2. Dist. VII (Other than A to F & 1st Addl. Survey Wards), Calcutta

This Notification shall take effect from 1-2-1974.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary on account of creation of three more Ranges and consequent revision of Appellate Assistant Commissioner's jurisdiction in West Bengal.

(This does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 549/F. No. 261/4/74-ITJ]

का० प्रा० 2336.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथा संशोधित बोर्ड की अधिसूचना सं० 98 (का० सं० 261/17/72-आईटीजे), तारीख 31-5-72 को भागतः उपान्तरित करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रेंज का सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर सर्कलों में आयकर या अधिकर के लिये निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कर्तव्यों का पालन करेगा :—

अनुसूची

रेंज (1)	आयकर सर्कल और आयकर अधिकारी (2)
1. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), विशेष रेंज (मुख्यालय), बंगलौर।	1. केन्द्रीय सर्कल I और II, बंगलौर 2. कम्पनी सर्कल I, II और III बंगलौर 3. सर्कल II, बंगलौर।

1

2

4. विशेष सर्वेक्षण सर्कल, बंगलौर।

5. वेतन सर्कल, बंगलौर।

2. सहायक आयकर आयुक्त (अपील, बंगलौर) रेंज, (मुख्यालय), बंगलौर।

1. सर्कल I, बंगलौर।

2. कोलार सर्कल।

3. तुमकूर सर्कल।

4. न्यास सर्कल एवं विदेशी अनुभाग, बंगलौर।

5. मैसूर सर्कल।

6. उषीपी सर्कल।

7. मंगलूर सर्कल।

8. कुर्ग सर्कल, मरकारा।

9. मण्ड्या सर्कल।

10. आयकर अधिकारी, चन्नायतना द्वारा आयकर अधिनियम के अधीन पारित आदेशों के बारे में।

11. बंगलौर सर्कल (पुराना) के आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के अधीन पारित आदेशों के बारे में।

12. हासन सर्कल।

13. चिकमगलूर सर्कल।

14. शिमोगा सर्कल।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1974 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण :

यह संशोधन बंगलौर स्थित सहायक आयुक्तों (अपील) के जीव कार्यभार को बराबर करने के लिये आवश्यक हो गया है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकारक के रूप में प्राशयित है)।

[सं० 551 (का० सं० 261/2/74—आई टी जे)]

S.O. 2336.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of Board's notification No. 98 (F. No. 261/17/72-ITJ) dated 31-5-1972 as amended from time to time the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the A.A.C. of Income-tax of the Range specified in Col. (1) of the Schedule below, shall perform his function in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles by the Income-tax Officers specified in the corresponding entry in Col. (2) thereof :—

SCHEDULE

New Delhi, the 8th November, 1974

Range	Income-tax Income-tax	Circles & Officers
1. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Special Range, (H. Qrs.), Bangalore.	1. Central Circles I and II, Bangalore	
	2. Company Circles I, II and III, Bangalore.	
	3. Circle II, Bangalore.	
	4. Special Survey Circle, Bangalore.	
	5. Salary Circle, Bangalore.	
2. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bangalore Range, (H. Qrs.), Bangalore.	1. Circle I, Bangalore.	
	2. Kolar Circle.	
	3. Tumkur Circle.	
	4. Trust Circle-cum-Foreign Section, Bangalore.	
	5. Mysore Circle.	
	6. Udipi Circle.	
	7. Mangalore Circle.	
	8. Coorg Circle, Mercara.	
	9. Mandya Circle.	
	10. In respect of orders passed under the I. T. Act by the I.T.O., Channarayana.	
	11. In respect of orders passed under the I. T. Act by the I.T.Os. of Bangalore Circle (Old).	
	12. Hassan Circle.	
	13. Chickmagalur Circle.	
	14. Shimoga Circle.	

This Notification shall take effect from 1st February, 1974.

EXPLANATORY NOTE:

The amendment has become necessary, to equalise the work-load among the A.A.Cs. at Bangalore.

(This does not form part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 551/(F. No. 261/2/74-ITJ)]

नई दिल्ली, 31 मई, 1974

आयकर

का० प्रा० 2337.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 95 (फा० सं० 261/6/72-आई० टी० जे०), तारीख 29 मई, 1972 से उपाख्य अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्

उक्त अनुसूची में तिरुचिरापल्ली रेंज, तिरुचिरापल्ली के सामने स्तम्भ 1 और 2 के अन्तर्गत क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- | | |
|---------------------|---|
| तिरुचिरापल्ली रेंज, | 1. तिरुचिरापल्ली सफिल |
| तिरुचिरापल्ली। | 2. सिटी सफिल 1 (सभी अनुभाग), तिरुचिरापल्ली |
| | 3. सिटी सफिल-2 (सभी अनुभाग), तिरुचिरापल्ली। |
| | 4. कम्पनी सफिल, तिरुचिरापल्ली। |
| | 5. डिजिटल सफिल (सभी अनुभाग) |
| | 6. पुटुकोट्टाई सफिल (सभी अनुभाग) |
| | 7. करुड़ सफिल (सभी अनुभाग) |

यह अधिसूचना 1-6-1974 से प्रभावी होगी।

[सं० 636/फा० सं० 261/9/74-आई० टी० जे०]

INCOME TAX

S.O. 2337.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its Notification No. 95 (F. No. 261/6/72-ITJ) dated 29th May, 1972 as amended from time to time, namely:—

In the said Schedule against Tiruchirappalli Range, Tiruchirappalli under Columns 1 and 2, the following shall be respectively substituted, namely:—

Tiruchirappalli Range,
Tiruchirappalli.

1. Tiruchirappalli Circle.
2. City Circle I (all Sections), Tiruchirappalli.
3. City Circle II (all Sections), Tiruchirappalli.
4. Companies Circle, Tiruchirappalli.
5. Dindigul Circle (all Sections).
6. Pudukottai Circle (all Sections).
7. Karur Circle (all Sections).

This Notification shall take effect from 1-6-1974.

[No. 636/F. No. 261/9/74-ITJ]

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1974

आयकर

का० प्रा० 2338.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आयकर सफिल, वार्ड और जिले
1	2	3
6. विशेष रेंज, लखनऊ	(1) क-वार्ड, सफिल 1, लखनऊ	
	(2) ख-वार्ड सफिल 1, लखनऊ	
	(3) ग-वार्ड, सफिल 1, लखनऊ	

1	2	3	1	2	3
		(4) क-वार्ड सफिल 2, लखनऊ (जो 31-5-68 तक और 1-8-68 1-6-69 तक और उसके पश्चात विद्यमान था।)			(2) मैनीताल (3) हलद्वानी (4) चन्दासी (5) रामपुर (6) शाहजंहापुर (7) बवायूं (8) काशीपुर (9) भल्मोड़ा (10) पीलीभीत
2. क-रेंज लखनऊ		(1) सफिल 1, लखनऊ, निम्नलिखित को छोड़कर— (i) क-वार्ड, सफिल 1, लखनऊ (ii) ख-वार्ड, सफिल 1, लखनऊ (iii) ग-वार्ड, सफिल 1, लखनऊ (iv) घ-वार्ड, सफिल 1, लखनऊ (2) सफिल 2, लखनऊ (जो 31-5-68 तक और 1-8-68 से 1-6-69 तक और उसके पश्चात विद्यमान था), क- वार्ड को छोड़कर, (3) सर्वेक्षण सफिल, लखनऊ (4) लखीमपुर खीरी (5) सीतापुर (6) हरदोई (7) ज-वार्ड, सफिल 1, लखनऊ (8) सम्पदा-शुल्क एवं आयकर सफिल इलाहाबाद			जहां कोई आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधि- सूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत हो जाता है वहां उस आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष, इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लम्बित अपीलें, उस तारीख जिससे यह अधिसूचना प्रभावी हो, उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी। यह अधिसूचना 5-11-1974 से प्रभावी होगी। [सं० 768/फा०सं० 261/11/74-आई०टी०जे०]
3. ख-रेंज, लखनऊ		(1) गोरखपुर (2) बस्ती (3) बहराइच (4) गोण्डा (5) फैजाबाद (6) भाजमगढ़ (7) बलिया (8) जौनपुर (9) बेतन सफिल, लखनऊ			
4. इलाहाबाद रेंज, इलाहाबाद		(1) इलाहाबाद (2) बेतन सफिल, इलाहाबाद			
5. वाराणसी रेंज, वाराणसी		(1) सफिल 1, वाराणसी (2) सफिल 2, वाराणसी (3) विशेष सफिल, वाराणसी (4) विशेष सर्वेक्षण सफिल, वाराणसी (5) परियोजना सफिल, वाराणसी (6) विशेष सफिल, वाराणसी (7) मिर्जापुर			
6. सहायक आयकर आयुक्त (अपील) मुरादाबाद		(1) बुलन्दशहर (2) मुरादाबाद (3) नजीबाबाद			
7. सहायक आयकर आयुक्त (अपील)		(1) बरेली सफिल			

New Delhi, the 2nd November, 1974

S.O. 2338.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other power enabling it in that behalf and in super-session of all previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—

SCHEDULE

S. No.	Ranges	Income-tax Circles, Wards Districts
1	2	3
1. Special Range, Lucknow.		(1) A-Ward, Circle-I, Lucknow. (2) B-Ward, Circle-I, Lucknow. (3) C-Ward, Circle-I, Lucknow. (4) A-Ward Circle-II, Lucknow (which existed upto 31-5-68 and from 1-8-68 to 1-6-69 and thereafter). (5) Company Circle, Lucknow. (6) Special Circle, Lucknow. (7) E-Duty-Cum- Income-tax Circle, Lucknow.
2. A-Range, Lucknow.		(1) Circle-I, Lucknow-excluding : (i) A-Ward, Circle-I, Luck- now. (ii) B-Ward, Circle-I, Luck- now. (iii) C-Ward, Circle-I, Luck- now. (iv) F-Ward, Circle-I, Luck- now.

1	2	3
		(2) Circle-II, Lucknow (which existed upto 31-5-1968 and from 1-8-68 to 1-6-69 and thereafter) excluding A-Ward.
		(3) Survey Circle, Lucknow.
		(4) Lakhimpur Kheri.
		(5) Sitapur.
		(6) Hardoi.
		(7) F-Ward Circle I, Lucknow.
		(8) Estate duty-cum-Income-tax Circle, Allahabad.
3. B-Range, Lucknow.		(1) Gorakhpur.
		(2) Basti.
		(3) Bahraich.
		(4) Gonda.
		(5) Faizabad.
		(6) Azamgarh.
		(7) Ballia.
		(8) Jaunpur.
		(9) Salary Circle, Lucknow.
4. Allahabad Range, Allahabad.		(1) Allahabad.
		(2) Salary Circle, Allahabad.
5. Varanasi Range, Varanasi		(1) Circle-I, Varanasi.
		(2) Circle-II, Varanasi.
		(3) Special Circle, Varanasi.
		(4) Special Survey Circle, Varanasi.
		(5) Project Circle, Varanasi.
		(6) Survey Circle, Varanasi.
		(7) Mirzapur.
6. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Moradabad.		(1) Bulandshahr.
		(2) Moradabad.
		(3) Najibabad.
7. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bareilly.		(1) Bareilly Circle.
		(2) Nainital.
		(3) Haldwani.
		(4) Chandausi.
		(5) Rampur.
		(6) Shahjahanpur.
		(7) Badaun.
		(8) Kashipur.
		(9) Almora.
		(10) Pilibhit.

Where an Income-tax Circle, ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward of District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 5-11-1974.

[No. 768/F.No 261/11/74-ITJ]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1974

क्र० प्र० 2339.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 749 (फा० सं० 261/2/74-आई टी जे) तारीख 10-10-1974 में निम्नलिखित शुद्धि की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ 1 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

सहायक आयकर आयुक्त (अपील), मैसूर रेंज (मुख्यालय) बंगलौर।

[सं० 770/फा० सं० 261/2/74-आई टी जे]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th November, 1974

S.O. 2339.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the following correction shall be made in the Schedule to its Notification No. 749 (F. No. 261/2/74-ITJ) dated 10-10-1974 viz :—

Against Sl. No. 3 for the existing entry at column 1 the following shall be substituted:—

ACC of Income-tax, Mysore Range, (HQ) Bangalore.

[No. 770/F. No. 261/2/74-ITJ]

क्र० प्र० 2340.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 655 (फा० सं० 261/13/74-आई टी जे) तारीख 21 जून, 1974 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अनुसूची में क्रम सं० 2 और 6 में, सहायक आयुक्त (अपील) ख-रेंज, जयपुर और उदयपुर रेंज उदयपुर के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी :-

मद सं०	रेंज	आयकर सफिल/वार्ड और जिले
2.	सहायक आयुक्त (अपील) ख-रेंज, जयपुर	1. सहायक आयुक्त (अपील), क-रेंज, जयपुर के सामने विनिर्दिष्ट वार्डों/मकिलों से भिन्न जयपुर के सभी वार्डों/सफिल
6.	सहायक आयुक्त (अपील) उदयपुर रेंज, उदयपुर	2. भीलवाड़ा के सभी वार्ड सफिल निम्नलिखित के सभी आयकर बोर्डों/सफिल — (1) उदयपुर (2) चित्तौड़गढ़

यह अधिसूचना 15-11-74 से प्रभावी होगी।

[सं० 771/फा० सं० 261/131/74-आई टी जे]

S.O. 2340.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (4 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule to its Notification No. 655 (F. No. 261/13/74-ITJ) dated 21st June 1974.

In the said Schedule at Sr. No. 2 and 6 against Appellate Assistant Commissioners of Income-tax B-Range, Jaipur and Udaipur Range Udaipur following entries shall be substituted namely :—

Item No.	Range	Income-tax Circles/Wards & Districts
2. Appellate Commissioner of Income-tax, B-Range, Jaipur.	Assistant	1. All wards/circles at Jaipur other than those specified against A.A.C. A-Range, Jaipur.
		2. All wards/Circles at Bhilwara.
6. Appellate Commissioner of Income-tax, Udaipur Range, Udaipur.	Assistant	1. All Income-tax Wards/Circles at : (i) Udaipur. (ii) Chittorgarh.

This notification shall take effect from 15-11-1974.

[No. 771/F. No. 261/13/74-ITJ]

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on redistribution of work between Appellate Assistant Commissioners of Income-tax B-Range, Jaipur and Udaipur Range, Udaipur.

(This note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 1975

क्र० प्र० 2341.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 728 (फा० सं० 261/5/74-आई टी जे) तारीख 30 सितम्बर, 1974 से उपाख्य अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अनुसूची में, विशेष रेंज 5 और "ठ" रेंज के सामने, स्तम्भ 3 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

क्रम सं०	रेंज	आयकर सर्किल/वार्ड और जिले
1	2	3
1. विशेष रेंज-5, नई दिल्ली		(1) विशेष सर्किल, 5, 6, 6 (अतिरिक्त), 10, 11, 12, 13 और 14, नई दिल्ली (2) जिला 8 (3), (4), (5) और (6), नई दिल्ली (3) जिला 10 (3), (4) और (11), नई दिल्ली (4) भविष्य निधि सर्किल, नई दिल्ली।
2. ठ-रेंज, नई दिल्ली		(1) जिला 3 (25), (25) (अतिरिक्त) (27), (28), (29), (30), (31) (32), (32) (अतिरिक्त) (33), (34) और (35), नई दिल्ली। (2) सर्वेक्षण सर्किल, नई दिल्ली।

1	2	3
		(3) जिला 3, वार्ड ज, झ, ज, ट, ठ, क (1), ग (1), ख (1), छ (1), झ (1), और ट (1), नई दिल्ली।
		(4) विशेष निर्धारण सर्किल 1, 2, 3, 6, 7, 8, और 10, नई दिल्ली।
		(5) विशेष सर्वेक्षण सर्किल 2, 3, 4 और 9, नई दिल्ली।
		(6) आयकर एवं धनकर सर्किल-2, नई दिल्ली।
		(7) ख-6, ख-7, ख-8 (अतिरिक्त), ख-9 और ख-9 (अतिरिक्त), नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 16-11-74 से प्रभावी होगी।

[सं० 773/फा० सं० 261/5/74-आई टी जे]

New Delhi, the 12th November, 1974

S.O. 2341.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its Notification No. 728 (F. No. 261/5/74-ITJ) dated the 30th September, 1974.

In the said Schedule the entries in column 3 against Special Range-V and 'L' Range, New Delhi shall be substituted by the following :—

S. No.	Range	Income-tax Circles/Wards and Districts.
1	2	3
1. Special Range-V, New Delhi.		(i) Special Circles V, VI, VI (Addl.), X, XI, XII, XIII and XIV, New Delhi. (ii) Districts VIII (3), (4), (5) and (6), New Delhi. (iii) District X(3), (4) & (11), New Delhi. (iv) Provident Fund Circle, New Delhi.
2. L-Range, New Delhi.		(i) District III (25), (25) (Addl.), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (32) (Addl.), (33), (34) and (35), New Delhi. (ii) Survey circle, New Delhi. (iii) District III, Wards H, I, J, K, L, A (I), C(I), E(I), G(I), I(I), and K(I), New Delhi. (iv) Special Assessment Circles I, II, III, VI, VII, VIII and X, New Delhi. (v) Special Survey Circles II, III, IV & IX, New Delhi. (vi) Income-tax-cum-Wealth-tax Circle II, New Delhi. (vii) B-VI, B-VII, B-VII (Addl.), B-IX & B-IX (Addl.), New Delhi.

This notification shall take effect from 16-11-1974.

[No. 773/F. No. 261/5/74-ITJ]

EXPLANATORY NOTE :—

The amendment has become necessary consequent on creation of new circles, namely, Dist. III (32) (addl.), Survey circle and Special Circle-XIV, New Delhi and redistribution of work among A. A. Cs Special Range-V and L-Range, New Delhi.

(The above note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory).

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1974

1

2

का० प्रा० 2342.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे सामर्थ्य बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, वार्डों या जिलों में आयकर या अधिकार के लिये निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे :

अनुसूची

रेंज	आयकर सफिल, वार्ड या जिले
1	2
केन्द्रीय रेंज 1, मद्रास	1. केन्द्रीय सफिल, 1 से 14 तक, मद्रास 2. विशेष अन्वेषण सफिल "क" और "ख" मद्रास 3. विशेष अन्वेषण सफिल 1, मद्रास
केन्द्रीय रेंज-2, मद्रास	1. केन्द्रीय सफिल 15 से 17 तक, मद्रास 2. केन्द्रीय सफिल 1 और 2, कोयम्बटूर 3. विशेष अन्वेषण सफिल, कोयम्बटूर 4. विशेष अन्वेषण सफिल 2, मद्रास
विशेष रेंज, मद्रास	1. कम्पनी सफिल 1, मद्रास (सभी अनुभाग) 2. नगर सफिल 5, मद्रास 3. हुण्डी सफिल-1, और 2, मद्रास
क-रेंज, मद्रास	1. कम्पनी सफिल 2, मद्रास (सभी अनुभाग) 2. नगर सफिल 2, मद्रास (सभी अनुभाग) 3. बेतन सफिल, मद्रास 4. बेतन सफिल 1, मद्रास 5. बेतन सफिल 2, मद्रास 6. कर वसूली सफिल, मद्रास
ख-रेंज, मद्रास	1. नगर सफिल 1, मद्रास 2. नगर सफिल 3, मद्रास 3. नागापट्टिनम सफिल (सभी अनुभाग)
ग-रेंज, मद्रास	1. नगर सफिल 4, मद्रास 2. कडलौर सफिल (सभी अनुभाग) 3. पाण्डिचेरी सफिल (सभी अनुभाग)

कोयम्बटूर रेंज, कोयम्बटूर

1. कम्पनी सफिल 1 से 5 तक, कोयम्बटूर
2. कोयम्बटूर सफिल
3. विशेष सर्वेक्षण सफिल, कोयम्बटूर
4. सफिल 1, कोयम्बटूर
5. नगर सफिल 1, कोयम्बटूर (सभी अनुभाग)
6. सफिल 2, कोयम्बटूर
7. नगर सफिल 2, कोयम्बटूर (सभी अनुभाग)
8. बेतन सफिल, कोयम्बटूर
9. उटकमण्ड सफिल (सभी अनुभाग)
10. पोल्साजी सफिल (सभी अनुभाग)
11. तिरुपुर सफिल
12. अतिरिक्त लाभ कर सफिल, कोयम्बटूर और एरोडे

सलेम रेंज, सलेम

1. सलेम सफिल
2. कम्पनी सफिल, सलेम
3. सफिल 1, सलेम
4. सफिल 2, सलेम
5. कृष्णागिरि सफिल
6. बैल्लोर सफिल
7. एरोडे सफिल (सभी अनुभाग)

जहां कोई आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है, वहां उस आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसके भाग में किये गये निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लंबित अपीलें उस तारीख से, जिससे यह अधिसूचना प्रभावी हो, उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जायेगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जायेगी।

यह अधिसूचना 1-10-1974 से प्रभावी होगी।

[सं० 777/का० सं० 261/9/74-आई टी जे]

New Delhi, the 22nd November, 1974

S.O. 2342.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards or Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof :

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles, Ward or Districts
1	2
Central Range I, Madras	1. Central Circles I to XIV, Madras. 2. Special Investigation Circles 'A' and 'B', Madras. 3. Special Investigation Circles I, Madras.
Central Range II, Madras.	1. Central Circles XV to XVII, Madras. 2. Central Circles I & II, Coimbatore. 3. Special Investigation Circle, Coimbatore. 4. Special Investigation Circle II, Madras.
Special Range, Madras	1. Companies, Circle I, Madras (all Sections). 2. City Circle V, Madras. 3. Hundi Circles I & II, Madras
A-Range, Madras	1. Companies Circle II, Madras (all Sections). 2. City Circle II, Madras (all sections) 3. Salaries Circle, Madras. 4. Salaries Circle I, Madras. 5. Salaries Circle II, Madras. 6. Tax Recovery Circle, Madras.
B-Range, Madras	1. City Circle I, Madras. 2. City Circle III, Madras. 3. Nagapattinam Circle (all sections).
C-Range, Madras.	1. City Circle IV, Madras. 2. Cuddalore Circle (all Sections). 3. Pondicherry Circle (all Sections).
Coimbatore Range, Coimbatore.	1. Company Circle I to V, Coimbatore. 2. Coimbatore Circle. 3. Special Survey Circle, Coimbatore. 4. Circle I, Coimbatore. 5. City Circle I, Coimbatore (all Sections). 6. Circle II, Coimbatore. 7. City Circle II, Coimbatore (all Sections). 8. Salary Circle, Coimbatore. 9. Ootacamund Circle (all Sections). 10. Pollachi Circle (all Sections). 11. Tirupur Circle. 12. Excess Profits Tax Circles, Coimbatore and Erode.
Salem Range, Salem.	1. Salem Circle. 2. Company Circle, Salem. 3. Circle I, Salem. 4. Circle II, Salem. 5. Krishnagiri Circle. 6. Vellore Circle. 7. Erode Circle (all Sections).

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this Notification shall take

effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from the 1-12-1974.

[No. 777/F. No. 261/9/74-ITJ]

EXPLANATORY NOTE :

These amendments have become necessary on account of re-organisation of the Appellate Assistant Commissioner's Ranges.

(The above note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1974

का० प्रा० 2343.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 715 (फा० सं० 261/14/74-आई० टी० जे०), तारीख 19-9-74 में निम्नलिखित शुद्धियाँ की जायेंगी, अर्थात् :—

सद (10) और (11) को (12) और (13) के रूप में रखा जायेगा।

[सं० 782/फा० सं० 261/14/74-आई० टी० जे०]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th November, 1974

S. O. 2343.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the following correction shall be made in the Schedule to its Notification No. 715 (F. No. 261/14/74-ITJ), dated 19-9-74 viz:—

Items (X) and (XI) shall be substituted as (XII) and (XIII)

[No. 782/F. No. 261/14/74-ITJ]

का० प्रा० 2344.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 746 (फा० सं० 261/19/74-आई० टी० जे०), तारीख 10-10-1974 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा

क्रम संख्या	रेंज	जोड़े गये या निकाले गये आयकर संचाल/वार्ड
1	2	3
6.	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) विशेष रेंज 6, अहमदाबाद	(1) सकल एस० आई० सी०, 1 से 7 तक, अहमदाबाद के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा : (2) केन्द्रीय सकल 1 और 2, अहमदाबाद

यह अधिसूचना 25-11-1974 से प्रभावी होगी।

[सं० 781/फा० सं० 261/19/74-आई० टी० जे०]

New Delhi, the 25th November, 1974.

S.O. 2344.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes, the following amendments in the schedule appended to its Notification No. 746 (F. No. 261/19/74-ITJ) dated 10-10-1974 namely:—

In the said schedule following additions shall be made.

Sl. No.	Range	Income-tax Circle/Ward added or deleted.
1	2	3
6.	A.A.C. Sl. Range VI, Ahmedabad.	(i) After Circle SIC. I to VII, Ahmedabad following shall be added. (ii) Central Circle I & II, Ahmedabad.

This Notification shall take effect from 25-11-1974.

EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary consequent on change of jurisdiction over Central Circle I and II from Bombay to Ahmedabad.

(The above note does not form a part of the notification but intended to be merely clarificatory).

[No. 781/F No. 261/19/74-ITJ]

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1974

का० प्रा० 2345:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 729, तारीख 30-9-1974 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में की तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकार के लिये निर्धारित सभी शक्तियों और आयों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

अनुसूची

क्रम संख्या	रेंज	आयकर सफिल, वार्ड और जिले
1	2	3
1.	ब-रेंज, कलकत्ता	कम्पनी जिला 2, कलकत्ता-क से च तक के वार्ड और अतिरिक्त च वार्ड
2.	ब-रेंज, कलकत्ता	(1) कम्पनी जिला 2, कलकत्ता, क से च तक के वार्डों और अतिरिक्त च वार्ड से भिन्न, (2) सिनेमा सफिल, कलकत्ता

जहां कोई आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत हो जाता है वहां उस आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसके भाग में किये गये निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व संवित्त अपीलें, उस तारीख से, जिससे यह अधिसूचना प्रभावी हो उस रेंज के जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत की जायेगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जायेगी।

जहां ऐसे सभी सफिल, वार्ड और जिले जिनके मुख्यालय किसी विशेष स्थान पर हैं, किसी सहायक आयुक्त (अपील) को समन्वेषित कर दिये गये हैं, वहां उसे उन मुख्यालयों, जो अब उन्मादिन कर दिये गये हैं, में के सफिलों, वार्डों और जिलों की बाबत भी अधिकारिता प्राप्त होगी।

यह अधिसूचना 2 दिसम्बर, 1974 से प्रभावी होगी।

[सं० 786-क का० सं० 261/4-प्राई०/टी०/जे०]

New Delhi, the 2nd December, 1974

S.O. 2345:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of Notification No. 729 dated 30-9-1974 in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof:—

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles, Ward and Districts
1	2	3
1.	B Range Calcutta	Companies Distt. II Calcutta—A to F Wards and Addl. B Wards.
2.	W Range Calcutta	1. Companies Dist-II Calcutta other than A to F Wards and Addl. B Wards. 2. Cinema Circle Calcutta.

Where an Income-tax Circle, Ward and District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

Where all Circles, Wards and Districts having headquarters at a particular place have been assigned to an Appellate Assistant Commissioner, he will have jurisdiction in respect of Circles, Wards and District at those headquarters since abolished also.

This Notification shall take effect from 2nd December, 1974.

EXPLANATORY NOTE:

The amendment has become necessary consequent upon the allocation of work amongst the two Appellate Assistant Commissioners concerned.

(The above note does not form a part of the notification but intended to be merely clarificatory)

[No. 786-A/F. No. 261/4/74-ITJ]

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1974

का० प्रा० 2346:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं० 765 (का० सं० 261/2/74-प्राई०/टी०/जे०) तारीख 30 अक्टूबर, 1974 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में की तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकार के लिये निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

अनुसूची

रेंज	आयकर सिकल और आयकर अधिकारी
1	2
2. सहायक आयकर आयुक्त (अपील), बंगलौर रेंज, 1 (मुख्यालय) बंगलौर	1. सिकल 1, बंगलौर 2. आयकर अधिकारी, चन्नापटना द्वारा, आयकर अधिनियम के अधीन, पारित प्रादेशों की बाबत। 3. आयकर अधिकारी, बंगलौर सिकल (पुराना) द्वारा, आयकर अधिनियम के अधीन, पारित प्रादेशों की बाबत। 4. माण्ड्या सिकल, माण्ड्या। 5. मैसूर सिकल, मैसूर 6. कोलार सिकल, कोलार 7. शिमोगा सिकल, शिमोगा 8. आयकर कार्यालय, न्यास सिकल, बंगलौर 9. आयकर सिकल विदेश अनुभाग, बंगलौर 10. चिकमगलूर सिकल, चिकमगलूर

यह अधिसूचना 16-12-1974 से प्रभावी होगी।

[सं० 791/फा० सं० 261/2/74-आई टी जे०]

New Delhi, the 13th December, 1974

S.O. 2346.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf and in partial modification of Board's Notification No. 765 (F. No. 261/2/74-ITJ dated 30th October, 1974, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in column (1) of the Schedule below shall perform his function in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or super-tax in the Income-tax Circles by the Income-tax Officers specified in the corresponding entry in column (2) thereof :

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles and Income-tax Officers.
1	2
2. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bangalore Range I (Hd. Qrs.) Bangalore.	1. Circle 1, Bangalore. 2. In respect of orders passed under the Income-tax Act by the Income-tax Officer, Channapatna. 3. In respect of orders passed under the Income-tax Act, by the Income-tax Officers, Bangalore Circle (Old). 4. Mandya Circle, Mandya. 5. Mysore Circle, Mysore. 6. Kolar Circle, Kolar. 7. Shimoga Circle, Shimoga. 8. Income-tax Office, Trust Circle, Bangalore. 9. Income-tax Office, Foreign Section, Bangalore. 10. Chikmagalur Circle, Chikmagalur.

This Notification shall take effect from 16-12-1974.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on the bifurcation of trust-circle-cum-Foreign-Section Bangalore into Income-tax Office, Trust Circle, Bangalore and Income-tax

Office, Foreign Section, Bangalore and to vest the jurisdiction over these newly created circles with the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bangalore Range-I, Bangalore.

(This does not form a part of Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 791/F. No. 261/2/74-ITJ]

का० प्रा० 2347—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उस समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिचनाओं को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सिकलों वाली और जिलों में आयकर या अधिकार के लिये निर्धारित सभी 'व्यक्तियों' और आयों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आयकर सिकल, बाई और जिले
1	2	3
1. क-रेंज, मुम्बई	1. कम्पनी सिकल-1(1) से 1(5) तक, केवल बाजं	
	2. आई टी ओ०, विशेष सिकल-1	
2. ख-रेंज, मुम्बई	1. कम्पनी सिकल-1, सिवाय 1(1) से 1(5) तक केवल बाजं के	
	2. फिल्म सिकल, और	
	3. मुम्बई सिकल, और	
	4. आई० टी० ओ०, विशेष सिकल-2	
3. ग-रेंज, मुम्बई	1. कम्पनी सिकल-2	
	2. य-2 बाई	
	3. निष्कांत सिकल-1 और	
	4. सम्पदा शुल्क सिकल	
4. घ-रेंज, मुम्बई	1. कम्पनी सिकल-3 और	
	2. भ-बाई	
5. ङ-रेंज, मुम्बई	1. कम्पनी सिकल-4	
	2. बी० प्रार० सी०	
	3. एन० प्रार० ओ० सी० और	
	4. विदेश अनुभाग	
6. च-रेंज, मुम्बई	1. कम्पनी सिकल-5, और	
	2. ख-2 बाई	
7. छ-रेंज, मुम्बई	1. कम्पनी सिकल, 6, और	
	2. क-4 बाई	
8. ज-रेंज, मुम्बई	1. क-1 बाई और	
	2. क-5 बाई	
9. झ-रेंज, मुम्बई	1. क-2 बाई	
	2. क-3 बाई और	
	3. एम० आई० बी० 1 से 7 तक के आई० टी० ओ०	
10. ञ-रेंज, मुम्बई	1. ख-1 बाई, और	
	2. निष्कांत सिकल-2	
11. ट-रेंज, मुम्बई	1. बाजार बाई	

1	2	3
		2. वेतन शाखा-1 और
		3. वेतन शाखा-2
12. ठ-रेंज, मुम्बई	ख-3 वार्ड	
13. ड-रेंज, मुम्बई	1. ग-3 वार्ड, और	
	2. ग-5 वार्ड	
14. ढ-रेंज, मुम्बई	घ-1 वार्ड	
15. ण-रेंज, मुम्बई	1. घ-2 वार्ड, और	
	2. ग-4 वार्ड	
16. त-रेंज, मुम्बई	1. बी०एस०डी० (पूर्व) और	
	2. बी० एस० डी० (दक्षिण)	
17. थ-रेंज, मुम्बई	1. ग-1 वार्ड	
	2. हुण्डी सक्ति अपीलें, और	
	3. छ-वार्ड	
18. द-रेंज, मुम्बई	1. ड-वार्ड, और	
	2. छ क वार्ड	
19. ध-रेंज, मुम्बई	बी० एस० डी० (पश्चिम)	

जहाँ कोई आयकर सक्ति, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत हो जाता है, वहाँ उस आयकर सक्ति, वार्ड या जिला या उसके भाग में किये गये निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के, जिससे वह आयकर सक्ति, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लिखित अपीलें, उस तारीख से, जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी हो, उस रेंज, के, जिसको उक्त सक्ति, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत की जायेगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जायेगी।

यह अधिसूचना 16-12-1974 से प्रभावी होगी।

[सं० 790/फा० सं० 261/3/74-आई टी जे]

S.O. 2347.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles/Wards and Districts, specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—

SCHEDULE

No.	Range	Income-tax Ward/Circle & District
1	2	3
1. A-Range, Bombay		1. Companies Circle-I(1) to I(5) charges only, and 2. I.T.O., Special Circle-I.
2. B-Range, Bombay		1. Companies Circle-I except I(1) to I(5) charges only. 2. Film Circle, and 3. Bombay Circle, and 4. I.T.O. Special Circle-II.
3. C-Range, Bombay		1. Companies Circle-II 2. C-II Ward 3. Evacuees Circle-I, and 4. Estate Duty Circle.
4. D-Range, Bombay		1. Companies Circle-III, and 2. X-Ward.

1	2	3
5. E-Range, Bombay		1. Companies Circle-IV 2. B.R.C. 3. N.R.R.C., and 4. Foreign Section.
6. F-Range, Bombay		1. Companies Circle-V, and 2. B-II Ward.
7. G-Range, Bombay		1. Companies Circle-VI, 2. A-IV Ward.
8. H-Range, Bombay		1. A-I Ward, and 2. A-V Ward.
9. I-Range, Bombay.		1. A-II Ward 2. A-III Ward, and 3. I.T.Os. of S.I.B. I to VII.
10. J-Range, Bombay.		1. B-I Ward, and 2. Evacuees Circle-II.
11. K-Range, Bombay		1. Market Ward. 2. Salaries Branch-I, and 3. Salaries Branch-II.
12. L-Range, Bombay		B-III Ward.
13. M-Range, Bombay		1. C-III Ward, and 2. C-V Ward.
14. N-Range, Bombay		D-I Ward.
15. O-Range, Bombay		1. D-II Ward, and 2. C-IV Ward.
16. P-Range, Bombay		1. B.S.D. (East) and 2. B.S.D. (South)
17. Q-Range, Bombay		1. C-I Ward. 2. Hundi Circle appeals, and 3. G-Ward.
18. R-Range, Bombay		1. E-Ward, and 2. GA-Ward.
19. S-Range, Bombay		B.S.D. (West).

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one range to another range appeals arising out of assessments made in that Income tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this Notification shall take effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 16-12-1974.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on the abolition of 2 Ranges and revision of jurisdiction among the 19 A.A.Cs. of I.T.

(This does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 790/F. No. 261/3/74-ITJ]

फा० नं० 2348.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 748 (फा० सं० 261/7/74-आई टी जे) तारीख 10 अक्टूबर, 1974 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्न-लिखित संशोधन करता है :

1. क्रम सं० 1 अर्थात् विशेष रेंज, इन्दौर के सामने स्तम्भ 3 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

1. आई टी ओ केन्द्रीय सक्ति, इन्दौर
2. आई टी ओ, क-वार्ड, इन्दौर
3. आई टी ओ ख-वार्ड, इन्दौर
4. आई टी ओ ग-वार्ड इन्दौर
5. आई टी ओ घ-वार्ड, इन्दौर

6. आई टी ओ, विशेष सम्पदा शुल्क एवं आयकर सक्ति, इन्दौर
 7. आई टी ओ, विशेष सम्पदा शुल्क सक्ति, इन्दौर
 8. आई टी ओ, ड०-वार्ड इन्दौर
 9. अनिरीकृत आई टी ओ, ड०-वार्ड, इन्दौर
 10. सहायक सम्पदा शुल्क नियन्त्रक, इन्दौर
 11. आयकर अधिकारी, सर्वेक्षण सक्ति, इन्दौर
 12. आई टी ओ, क-वार्ड, रतलाम
 13. आई टी ओ, ख-वार्ड, रतलाम
 14. आई टी ओ, ग-वार्ड, रतलाम
 15. आई टी ओ, क-वार्ड, मन्सौर
 16. आई टी ओ, ख-वार्ड, मन्सौर
 17. आई टी ओ, मन्सौर
 18. आई टी ओ, धार
 19. आई टी ओ, क-वार्ड, सक्ति-1, इन्दौर
 20. आई टी ओ, ख-वार्ड, सक्ति-1, इन्दौर
 21. आई टी ओ, ग-वार्ड, सक्ति-1, इन्दौर
 22. आई टी ओ, घ-वार्ड, सक्ति-2, इन्दौर
 23. आई टी ओ, ड०-वार्ड, सक्ति-1, इन्दौर
 24. अनिरीकृत आई टी ओ, ड०-वार्ड, सक्ति-1, इन्दौर"
2. क्रम सं० 2 अर्थात् इन्दौर रेंज, इन्दौर के सामने स्तम्भ 3 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—
- "1. आई टी ओ, च-वार्ड, इन्दौर
 2. आई टी ओ, छ-वार्ड, इन्दौर
 3. आई टी ओ, ज-वार्ड, इन्दौर
 4. आई टी ओ, झ-वार्ड, इन्दौर
 5. आई टी ओ, ट-वार्ड, इन्दौर
 6. आई टी ओ, ठ-वार्ड, इन्दौर
 7. आई टी ओ, ड-वार्ड, इन्दौर
 8. आई टी ओ, ड-वार्ड, इन्दौर
 9. आई टी ओ, त-वार्ड, इन्दौर
 10. आई टी ओ, थ-वार्ड, इन्दौर
 11. आई टी ओ, द-वार्ड, इन्दौर
 12. विशेष सर्वेक्षण सक्ति, इन्दौर
 13. आई टी ओ, ख-वार्ड इन्दौर (जैसा कि वह 15 जून, 1972 तक विद्यमान था)
 14. आई टी ओ, प्रशासन, इन्दौर
 15. आई टी ओ, खरगोन
 16. आई टी ओ, महु
 17. आई टी ओ, क-वार्ड, उज्जैन
 18. आई टी ओ, ख-वार्ड, उज्जैन
 19. आई टी ओ, ग-वार्ड, उज्जैन
 20. आई टी ओ, घ-वार्ड, उज्जैन
 21. आई टी ओ, ड०-वार्ड, उज्जैन
 22. आई टी ओ, च-वार्ड, उज्जैन
 23. आई टी ओ, देवास
 24. आई टी ओ, च-वार्ड, सक्ति-2, इन्दौर
 25. आई टी ओ, छ-वार्ड, सक्ति-1, इन्दौर
 26. आई टी ओ, ज-वार्ड, सक्ति-2, इन्दौर
 27. आई टी ओ, झ-वार्ड, सक्ति-2, इन्दौर
 28. आई टी ओ, ट-वार्ड, सक्ति-2, इन्दौर
 29. आई टी ओ, ठ-वार्ड, सक्ति-1, इन्दौर
 30. आई टी ओ, ड-वार्ड, सक्ति-2, इन्दौर

31. आई टी ओ, त-वार्ड, सक्ति-2, इन्दौर
32. आई टी ओ, थ-वार्ड, सक्ति-2, इन्दौर"

3. क्रम सं० 5 अर्थात् विशेष रेंज, जबलपुर के सामने स्तम्भ 3 के अधीन निम्नलिखित जोड़ा, जाएगा, अर्थात्:—

"11. आई टी ओ, सर्वेक्षण सक्ति, जबलपुर"

यह अधिसूचना 16-12-1974 से प्रभावी होगी।

[सं० 792 (फा० सं० 261/7/74-आई टी जे)]

S.O. 2348.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Sec. 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby make the following amendments in the Schedule appended to its Notification No. 748 (F. No. 261/7/74-ITJ), dated the 10th October, 1974.

1. The existing entries under Col. No. 3, against S. No. 1, viz. Special Range, Indore, shall be substituted by the following:—

- "1. ITO, Central Circle, Indore.
2. ITO, A-Ward, Indore.
3. ITO, B-Ward, Indore.
4. ITO, C-Ward, Indore.
5. ITO, D-Ward, Indore.
6. ITO, Special Estate Duty-cum-Incometax Circle, Indore.
7. ITO, Special Investigation Circle, Indore.
8. ITO, E-Ward, Indore.
9. Addl. ITO, E-Ward, Indore.
10. Assistant Controller of Estate Duty, Indore.
11. Income-tax Officer, Survey Circle, Indore.
12. ITO, A-Ward, Ratlam.
13. ITO, B-Ward, Ratlam.
14. ITO, C-Ward, Ratlam.
15. ITO, A-Ward, Mandsaur.
16. ITO, B-Ward, Mandsaur.
17. ITO, Mandsaur.
18. ITO, Dhar.
19. ITO, A-Ward, Circle I, Indore.
20. ITO, B-Ward, Circle I, Indore.
21. ITO, C-Ward, Circle I, Indore.
22. ITO, D-Ward, Circle II, Indore.
23. ITO, E-Ward, Circle I, Indore.
24. Addl. ITO, E-Ward, Circle I, Indore."

2. The existing entries under Col. No. 3, against S. No. 2 viz. Indore Range, Indore shall be substituted by the following:—

- *1. ITO, F-Ward, Indore.
2. ITO, G-Ward, Indore.
3. ITO, H-Ward, Indore.
4. ITO, I-Ward, Indore.
5. ITO, K-Ward, Indore.
6. ITO, L-Ward, Indore.
7. ITO, M-Ward, Indore.
8. ITO, N-Ward, Indore.
9. ITO, P-Ward, Indore.
10. ITO, Q-Ward, Indore.
11. ITO, R-Ward, Indore.

12. ITO Special Survey Circle, Indore.
13. ITO B-Ward, Indore (as existing upto 15th June, 1972).
14. ITO Administration, Indore.
16. ITO Mhow.
15. ITO Khargone.
17. ITO A-Ward, Ujjain.
18. ITO B-Ward, Ujjain.
19. ITO C-Ward, Ujjain.
20. ITO D-Ward, Ujjain.
21. ITO E-Ward, Ujjain.
22. ITO F-Ward, Ujjain.
23. ITO Dewas.
24. ITO F-Ward, Circle II, Indore.
25. ITO G-Ward, Circle I, Indore.
26. ITO H-Ward, Circle I, Indore.
27. ITO J-Ward, Circle II, Indore.
28. ITO K-Ward, Circle I, Indore.
29. ITO L-Ward, Circle I, Indore.
30. ITO M-Ward, Circle, II, Indore.
31. ITO P-Ward, Circle II, Indore.
32. ITO Q-Ward, Circle II, Indore.

3. Under Col. No. 3, against S. No. 5 viz., special Range, Jabalpur, the following shall be added, namely :—

"11. ITO Survey Circle, Jabalpur".

This Notification shall take effect from 16-12-1974.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary on the (i) re-distribution of work between AACs Special Range, Indore and Indore Range, Indore to rationalise their respective work loads; (ii) creation of two new circles and (iii) re-distribution of the ITO's circles at Indore.

(This does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 792 (F. No. 261/7/74-ITJ)]

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1975

का० प्रा० 2349:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निवेश देता है कि उनकी अधिसूचना सं० 777 (फा० सं० 261/9/74-आई० टी० जे०) तारीख 22-11-74 में निम्नलिखित शुद्धि की जाएगी, अर्थात्:—

ग-रेंज मद्रास और कोयम्बटूर रेंज, कोयम्बटूर के बीच में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

- | | |
|--------------|---|
| रेंज, मद्रास | <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर सफिल 6, मद्रास 2. नगर सफिल 7, मद्रास (सभी अनुभाग) 3. विशेष सर्वेक्षण सफिल मद्रास, (सभी अनुभाग) 4. विशेष अनुभाग, मद्रास 5. प्रतिदाय सफिल, मद्रास 6. ताम्बरम् सफिल (सभी अनुभाग) 7. कांचीपुरम् सफिल (सभी अनुभाग) 8. कुम्भकोणम् सफिल (सभी अनुभाग) |
|--------------|---|

9. सम्पदा-शुल्क-एवं आयकर सफिल, मद्रास
10. सम्पदा-शुल्क-एवं आयकर सफिल, तंजौर
11. सम्पदा-शुल्क-एवं आयकर सफिल, मदुराई
12. सम्पदा-शुल्क-एवं आयकर सफिल, कोयम्बटूर

तिरुचिरापल्ली रेंज
तिरुचिरापल्ली

1. तिरुचिरापल्ली सफिल,
2. नगर सफिल, 1, तिरुचिरापल्ली
3. नगर सफिल 2, तिरुचिरापल्ली (सभी अनुभाग)
4. कम्पनी सफिल, तिरुचिरापल्ली
5. फरर सफिल (सभी अनुभाग)
6. तंजौर सफिल (सभी अनुभाग)
7. पुडुकोट्टाई (सभी अनुभाग)

क-रेंज, मदुराई

1. कम्पनी सफिल, मदुराई
2. डिडीगुल सफिल (सभी अनुभाग)
3. कराकुडी सफिल (सभी अनुभाग)
4. रामनाथपुरम् सफिल
5. विरुदनगर सफिल
6. तिरुनेलवेली सफिल
7. विशेष सफिल, मदुराई

ख-रेंज, मदुराई

1. मदुराई सफिल
2. विशेष सर्वेक्षण सफिल मदुराई
3. टूटीकोरिन सफिल
4. नगरकोयल सफिल

[सं० 801 (फा० सं० 261/9/74-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 19th December, 1974.

CORRIGENDUM

Income-tax

S. O. 2349:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the following correction shall be made in its Notification No. 777 (F. No. 261/9/74-ITJ) dated 22-11-74 viz :—

Between C-Range, Madras and Coimbatore Range, Coimbatore following shall be added :—

D-Range, Madras.

1. City Circle VI, Madras.
2. City Circle VII, Madras (all Sections).
3. Special Survey Circle, Madras (all Sections)
4. Foreign Section, Madras.
5. Refund Circle, Madras.
6. Tambaram Circle (all Sections).
7. Kancheepuram Circle (all Sections).
8. Kumbakonam Circle (all Sections).
9. Estate Duty-cum-Income-tax, Circle, Madras.
10. Estate Duty-Cum-Income-tax, Circle, Thanjavur.
11. Estate Duty-Cum-Income-tax Circle, Madurai.
12. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Coimbatore.

Tiruchirapalli Range,
Tiruchirapalli.

1. Tiruchirapalli Circle.
2. City Circle I, Tiruchirapalli (all Sections).
3. City Circle II, Tiruchirapalli (all Sections).
4. Companies Circle, Tiruchirapalli.
5. Karur Circle (all Sections).
6. Thajnavur Circle (all Sections).
7. Pudukottai Circle (all Sections).

A-Range, Madurai.

1. Company Circle, Madurai.
2. Dindigul Circle (all Sections).
3. Karaikudi Circle (all Sections).
4. Ramanathapuram Circle.
5. Virudhunagar Circle.
6. Tirunelveli Circle.
7. Special Circle Madurai.

B-Range, Madurai.

1. Madurai Circle.
2. Special Survey Circle, Madurai.
3. Tuticorin Circle.
4. Nagercoil Circle.

[No. 801 (F. No. 261/9/74-ITJ)]

the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its Notification No. 777 (F. No. 261/9/74-ITJ) dated 22-11-74 namely :—

In the said Schedule, against A-Range, Madurai under columns 1 and 2, the following shall be respectively substituted, namely :—

A-Range, Madurai

1. Company Circle, Madurai.
2. Dindigul Circle (All Sections).
3. Karaikudi Circle (all Sections).
4. Ramanathapuram Circle.
5. Virudhunagar Circle.
6. Tirunelveli Circle.
7. Special Circle Madurai (Erstwhile Circle dealing with E.P.T. cases)
8. Special Circle, Madurai (New Income-tax Circle formed with effect from 2-12-1974).

This notification shall take effect from 20-12-1974.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary on account of formation of a new Income-tax Circle known as 'Special Circle' with headquarters at Madurai and assigning jurisdiction over the new Circle.

(The above note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 802 (F. No. 261/9/74-ITJ)]

का० प्रा० 2350.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 777 (फा० सं० 261/9/74-आई० टी० जे०) तारीख 22-11-74 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, क-रेंज, मदुराई के सामने स्तम्भ 1 और 2 के अधीन क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

क-रेंज, मदुराई

1. कम्पनी सर्किल, मदुराई
2. डिंडीगुल सर्किल (सभी अनुभाग)
3. कराईकुडी सर्किल (सभी अनुभाग)
4. रामनाथपुरम् सर्किल
5. विरुधनगर सर्किल
6. तिरुनेलवेली सर्किल
7. त्रिगुण सर्किल, मदुराई (तत्कालीन सर्किल जो ई० पी० टी० के मामलों की देखता-भालता था)
8. त्रिगुण सर्किल, मदुराई (2-12-1974 से बना नया आयकर सर्किल)

यह अधिसूचना 20-12-1974 के प्रभावी होगी।

[सं० 802 (फा० सं० 261/9/74-आई० टी० जे०)]

S. O. 2350.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf,

शुद्धि-पत्र

का० प्रा० 2351.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 754 (फा० सं० 261/12/74-आई० टी० जे०), तारीख 31-10-1974 में निम्नलिखित शुद्धि की जाएगी, अर्थात् :—

सहायक आयकर आयुक्त (अपील) रेंज-2, मेरठ के लिए ताल्फियत क्रम सं० 8 के सामने स्तम्भ 3 के अधीन क्रम सं० (11) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

“सर्किल-1 मेरठ” प्र० और ड० बार्ड, मेरठ को छोड़कर,।”

[सं० 803 (फा० सं० 261/9/74-आई० टी० जे०)]

CORRIGENDUM

S.O. 2351.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the following correction shall be made in its Notification No. 754 (F. No. 261/12/74-ITJ) dated 31-10-1974 viz.—

Against SI. No. 8 meant for A.C.C. Range-II, Meerut SI. (ii) under column 3 the present entry shall be substituted by “Circle-I, Meerut excluding A and E Wards Meerut”.

[No. 803 (F. No. 261/12/74-ITJ)]

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1974

क्रा० प्रा० 2352.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 728 (फा० सं० 261/15/74-आई० टी० जे०) तारीख 30 सितम्बर, 1974 से उपाखण्ड अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अनुसूची में, स्तम्भ 3 में, "छ" "ज", "ण" रेंज नई दिल्ली के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा :—

क्रम सं०	रेंज	आयकर सफिल/वार्ड और जिले
1.	"छ" रेंज, नई दिल्ली	(1) जिला 6 (11), (12), (13), (14), और (15), नई दिल्ली
2.	"ज" रेंज, नई दिल्ली	(1) जिला 6 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) और (10) अतिरिक्त, नई दिल्ली (2) आयकर एवं सम्पदा शुल्क सफिल, नई दिल्ली। (3) अतिरिक्त सम्पदा-शुल्क एवं आयकर सफिल नई दिल्ली। (4) जिला 6, वार्ड-क, क(अतिरिक्त), क(1), क(2), ख (अतिरिक्त), ग ग(अतिरिक्त), ग(1), ग(1) (अतिरिक्त), घ और ङ नई दिल्ली (5) आयकर-एवं-धनकर सफिल 4 और 11, नई दिल्ली।
3.	ण रेंज, नई दिल्ली	(1) सभी सरकारी वेतन सफिल नई, दिल्ली। (2) सभी प्राइवेट वेतन सफिल, नई दिल्ली। (3) आयकर अधिकारी (विशेष कार्य अधिकारी, कृषि-धनकर शाखा) नई दिल्ली। (4) जिला 2(9), (9) (अतिरिक्त), (10), (11), (11) अतिरिक्त, (12), (12) अतिरिक्त और (13), नई दिल्ली, (5) आयकर एवं धनकर सफिल 7, नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 26-12-1974 से प्रभावी होगी।

[सं 806(फा० सं० 261/5/74-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 26th December, 1974

O. 2352.—In exercise of the powers conferred by section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961

(43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its notification No 728 (F. No. 261/5/74-ITJ) dated the 30th September, 1974.

In the said Schedule the entries in column 3 against 'G' 'H' and 'O' Ranges, New Delhi shall be substituted by the following :—

S. No.	Range	Income-tax Circles/Wards and Districts
1.	G-Range, New Delhi	(i) District VI(11), (12), (13), (14) and (15), New Delhi.
2.	H-Range, New Delhi	(i) District VI(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and (10)(Addl.), New Delhi (ii) Income-tax-cum-Estate Duty Circle, New Delhi. (iii) Addl. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, New Delhi. (iv) District VI, Wards 'A, A(Addl.), A(I) A(II), B (Addl.), C, C(Addl.), C(I), C(I) (Addl.), D & E, New Delhi. (v) Income-tax-cum-wealth-tax Circles IV & XI, New Delhi.
3.	O-Range, New Delhi	(i) All Government Salary Circles New Delhi. (ii) All Private Salary Circles, New Delhi. (iii) Income-tax Officer (Officer on special Duty, Agricultural Wealth-tax Branch), New Delhi. (iv) District II(9), (9) (Addl.), (10), (11), (11) (Addl.), (12), (12) (Addl.) and (13), New Delhi. (v) Income-tax-cum-wealth-tax Circle-VII, New Delhi.

This notification shall take effect from 26-12-1974.

EXPLANATORY NOTE :—

The amendment has become necessary consequent on creation of New Circle namely, Distt. II(13) New Delhi under Delhi-V charge and also on change of jurisdiction over Distt. VI(14) & (15) from 'H' Range, New Delhi to 'C' Range, New Delhi.

(The above note does not form a part of the notification but intended to be merely clarificatory).

[No. 806 (F. No. 261/5/74-ITJ)]

नई दिल्ली 10 मार्च, 1975

आयकर

क्रा० प्रा० 2353.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्ववर्ती अधिसूचना सं० 747 (फा० सं० 261/15/74-आई० टी० जे०), तारीख 10-11-74 को आंशिक उपान्तरण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड निदेश करता है कि नीचे की अनुसूची

के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिल. वार्डों और जिलों में आयकर या अधिभार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे :-

अनुसूची

रेंज	आयकर सफिल, वार्ड और जिले
पूर्ण रेंज-1, पूर्ण	(1) क-वार्ड, पुणे (2) ग-वार्ड, पुणे (3) ख-वार्ड, पुणे (4) ङ-वार्ड, पुणे (5) च-वार्ड, पुणे (6) ज-वार्ड, पुणे (7) अतिरिक्त अ-वार्ड, पुणे (8) ट-वार्ड, पुणे (9) ठ-वार्ड, पुणे (10) ड-वार्ड, पुणे (11) संग्रहण सफिल-1, पुणे (12) संग्रहण सफिल-2, पुणे (13) संग्रहण सफिल-3, पुणे (14) संग्रहण सफिल-4, पुणे (15) संग्रहण सफिल-5, पुणे (16) धन-कर-एवं दान कर सफिल, पुणे (17) एस० एस० सी-1, पुणे (18) आ० क० घ० (प्रशासन) पुणे
थाना रेंज, थाना	(1) क-वार्ड, थाना (2) अतिरिक्त क-वार्ड, थाना (3) ख-वार्ड, थाना (4) अतिरिक्त ख-वार्ड, थाना (5) ग-वार्ड, थाना (6) घ-वार्ड, थाना (7) ङ-वार्ड, थाना (8) ज-वार्ड, थाना (9) छ-वार्ड, थाना (10) झ-वार्ड, थाना (11) ञ-वार्ड, थाना (12) ट-वार्ड, थाना (13) संग्रहण सफिल, -1, थाना (14) संग्रहण सफिल-2, थाना (15) एस० एस० सी०, थाना (16) अतिरिक्त एस० एस० सी०, थाना (17) वसूली सफिल-3, थाना (18) पलघट्ट सफिल, पलघट्ट (19) ठ-वार्ड, थाना (20) ड-वार्ड, पुणे (21) छ-वार्ड, पुणे (22) अतिरिक्त छ-वार्ड, पुणे

जहाँ कोई आयकर सफिल/वार्ड या जिला या उसका भाग हम अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत हो जाता है, वहाँ उस आयकर सफिल/वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाले और इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिससे वह आयकर सफिल/वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, के समक्ष लंबित अपील उस तारीख से, जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिसकी उक्त सफिल/वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा बरती जाएगी।

यह अधिसूचना 10-3-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 854 (फा० सं० 261/5/75-आई टी जे)]

New Delhi, the 10th March., 1975

INCOME TAX

S. O. 2353.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, and in partial modification of the previous notification No. 747 (F.No.261/15/74-ITJ) dated 10-11-74 the Central Board of Direct Taxes, hereby direct that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in column 1 of the schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circle, Wards and districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof:—

SCHEDULE

Range	Income-Tax Circles, Wards and Districts.
1.	2.
Poona Range-I, Poona.	(1) A-Ward, Poona. (2) C-Ward, Poona. (3) D-Ward, Poona. (4) E-Ward, Poona. (5) F-Ward, Poona. (6) J-Ward, Poona. (7) Addl. J-Ward, Poona. (8) K-Ward, Poona. (9) L-Ward, Poona. (10) M-Ward, Poona. (11) Collection Cir.I, Poona. (12) Collection Cir.II, Poona. (13) Collection Cir. III, Poona. (14) Collection Cir.IV, Poona. (15) Collection-Cir.V, Poona. (16) W.T. Gum-G.T., Circle, Poona. (17) S.S.C. I, Poona. (18) I.T.O. (Administration), Poona.
Thana Range, Thana.	(1) A-Ward, Thana. (2) Addl.A-Ward, Thana. (3) B-Ward, Thana. (4) Addl. B-Ward, Thana. (5) C-Ward, Thana. (6) D-Ward, Thana. (7) E-Ward, Thana. (8) F-Ward, Thana. (9) G-Ward, Thana.

- (10) H-Ward, Thana.
- (11) J-Ward, Thana.
- (12) K-Ward, Thana.
- (13) Collection Cir.I, Thana.
- (14) Collection Cir.II, Thana.
- (15) S.S.C. Thana.
- (16) Addl. S.S.C. Thana.
- (17) Recovery Circle-III, Thana.
- (18) Palghar Circle, Palghar.
- (19) L-Ward, Thana.
- (20) B-Ward Poona.
- (21) G-Ward, Poona.
- (22) Addl. G-Ward, Poona.

Where an Income-tax Circles/Wards or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range' appeal arising out of assessments made in that Income-tax Circle/Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Circle/Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said Circles/Ward or Districts or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 10-3-1975.

Explanatory Notes.

The amendment has become necessary on account of rationalisation of work-load & consequent readjustment of the jurisdiction of the five Appellate Assistant Commissioners.

(The above note does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 854(F.No.261/5/75-ITJ);]

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1975

का० प्रा० 2354—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों और उस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि इसकी अधिसूचना सं० 841 (फा० सं० 261/12/74-आई टी जे) तारीख 20-2-75 से निम्नलिखित शुद्धि की जाएगी, अर्थात्—

क्रम सं० 4 विशेष रेंज, कानपुर के सामने स्तम्भ सं० 3 के अन्तर्गत मब (V) को हटा दिया जाएगा।

[सं० 857 (फा० सं० 261/1/75-आई टी जे)]

New Delhi, the 18th March, 1975

S.O. 2354.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the following correction shall be made in its Notification No. 841 (F. No. 261/12/74-ITJ) dated 20-2-75 viz:—

Against S. No. 4 Spl. Range. Kanpur item (V) under column No. 3 shall be deleted.

[No. 857 (F. No. 261/1/75ITJ)]

नई दिल्ली, तारीख 1 मर्च, 1975

का० प्रा० 2355 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों और उस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्ववर्ती अधिसूचना सं० 747 (फा० सं० 261/15/74-आई टी जे, तारीख 10-10-74) और सं० 854 (फा० सं० 261/15/75-आई टी जे), तारीख 10-3-75 का आंशिक उपान्तरण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 2 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किल, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे :

अनुसूची	
रेंज	आयकर सर्किल, वार्ड और जिले
1	2
पूणे रेंज-1, पुणे	1 क-वार्ड, पुणे 2 ग-वार्ड, पुणे 3 ड-वार्ड, पुणे 4 च-वार्ड, पुणे 5 ज-वार्ड, पुणे 6 अतिरिक्त ज-वार्ड, पुणे 7 ट-वार्ड, पुणे 8 ड-वार्ड, पुणे 9 संग्रहण सर्किल-1, पुणे 10 संग्रहण सर्किल-2, पुणे 11 संग्रहण सर्किल-3, पुणे 12 संग्रहण सर्किल-4, पुणे 13 संग्रहण सर्किल-5, पुणे 14 धन-कर एवं वानकर सर्किल, पुणे 15 एस० एस० सी०-1, पुणे 16 आई० टी० प्रो० (प्रशासन), पुणे 17 ह-वार्ड, पुणे 18 त-वार्ड, पुणे 19 द-वार्ड, पुणे
याता रेंज, थाना	1 क-वार्ड, थाना 2 अतिरिक्त क-वार्ड, थाना 3 ख-वार्ड, थाना 4 अतिरिक्त ख-वार्ड, थाना 5 ग-वार्ड, थाना 6 घ-वार्ड, थाना 7 ङ-वार्ड, थाना 8 च-वार्ड, थाना 9 छ-वार्ड, थाना 10 ज-वार्ड, थाना 11 ञ-वार्ड, थाना 12 ट-वार्ड, थाना 13 संग्रहण सर्किल-1, थाना 14 संग्रहण सर्किल-2, थाना

1	2
	15. एस० एस० सी० थाना
	16. अतिरिक्त एस० एस० सी० थाना
	17. बसुली सर्किल-3, थाना
	18. पलघट सर्किल, पलघट
	19. ठ-वार्ड, थाना
	20. ख-वार्ड, पुणे
	21. छ-वार्ड, पुणे
	22. अतिरिक्त छ-वार्ड, पुणे
	23. घ-वार्ड, पुणे
पुणे रेंज-3, पुणे	1. अतिरिक्त ग-वार्ड, पुणे
	2. ज-वार्ड, पुणे
	3. एस० एस० सी०, पुणे
	4. अतिरिक्त एस०एस सी०, पुणे
	5. एस० एण्ड आर०, पुणे
	6. जी० एच० क्यू, पुणे
	7. क-वार्ड, शोलापुर
	8. ख-वार्ड, शोलापुर
	9. ग-वार्ड, शोलापुर
	10. घ-वार्ड, शोलापुर
	11. ङ-वार्ड, शोलापुर
	12. संग्रहण सर्किल, शोलापुर
	13. आई टी ओ, बारसी
	14. क-वार्ड, अहमदनगर
	15. ख-वार्ड, अहमदनगर
	16. ग-वार्ड, अहमदनगर
	17. एस० एस० सी०, शोलापुर
	18. एस० एस० सी०-2, पुणे
	19. ब-वार्ड, पुणे
	20. ठ-वार्ड, पुणे
	21. न-वार्ड, पुणे

जहाँ कोई आयकर सर्किल/वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किमी अन्य रेंज को अन्तर्गत हो जाना है, वहाँ उस आयकर सर्किल/वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिससे वह आयकर सर्किल/वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, के समक्ष संबद्ध अपील उस तारीख से, जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) जिसको उक्त सर्किल/वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा बरती जाएगी।

यह अधिसूचना 1-4-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 864 (फा० सं० 261/5/75 आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 1st, April, 1975

S. O. 2355.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, and in partial modification of the previous notifications No. 747 (F.No. 261/15/74-ITJ dt. 10-10-74) and No. 854 (F.No. 261/5/75-ITJ) dated 10-3-75, the Central Board of Direct Taxes,

hereby direct that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in column 1 of the schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circle, Wards and districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof:—

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles, Wards and Districts
1	2
Poona Range-I, Poona.	(1) A-Ward, Poona. (2) C-Ward, Poona. (3) E-Ward, Poona. (4) F-Ward, Poona. (5) J-Ward, Poona. (6) Addl. J-Ward, Poona. (7) K-Ward, Poona. (8) M-Ward, Poona. (9) Collection Circle I, Poona. (10) Collection Circle II, Poona. (11) Collection Circle III, Poona. (12) Collection Circle IV, Poona. (13) Collection Circle, V, Poona. (14) W.T.-Cum-G.T., Circle, Poona. (15) S.S.C. I, Poona. (16) I.T.O. (Administration), Poona. (17) N-Ward, Poona. (18) P-Ward, Poona. (19) R-Ward, Poona.
Thana Range, Thana.	(1) A-Ward, Thana. (2) Addl. A-Ward, Thana. (3) B-Ward, Thana. (4) Addl. B-Ward, Thana. (5) C-Ward, Thana. (6) D-Ward, Thana. (7) E-Ward, Thana. (8) F-Ward, Thana. (9) G-Ward, Thana. (10) H-Ward, Thana. (11) J-Ward, Thana. (12) K-Ward, Thana. (13) Collection Circle I, Thana. (14) Collection Circle II, Thana. (15) S.S.C. Thana. (16) Addl. S.S.C. Thana. (17) Recovery Circle-III, Thana. (18) Palghar Circle, Palghar. (19) L-Ward, Thana. (20) B-Ward, Poona. (21) G-Ward, Poona. (22) Addl. G-Ward, Poona. (23) S-Ward, Poona.
Poona Range-III, Poona.	(1) Addl. C-Ward, Poona. (2) H-Ward, Poona. (3) S.S.C., Poona. (4) Addl. S.S.C., Poona. (5) S & R., Poona. (6) G.H.Q., Poona.

1	2
	(7) A-Ward, Sholapur.
	(8) B-Ward, Sholapur.
	(9) C-Ward, Sholapur.
	(10) D-Ward, Sholapur.
	(11) E-Ward, Sholapur.
	(12) Collection Circle, Sholapur.
	(13) I.T.O., Barsi.
	(14) A-Ward, Ahmednagar.
	(15) B-Ward, Ahmednagar.
	(16) C-Ward, Ahmednagar.
	(17) S.S.C., Sholapur.
	(18) S.S.C. II Poona.
	(19) D-Ward, Poona.
	(20) L-Ward, Poona.
	(21) T-Ward, Poona.

Where an Income-tax Circles/Wards or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeal arising out of assessments made in that Income-tax Circle/Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Circle/Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said Circles/Ward or Districts or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-4-1975.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary on account of abolition of certain Wards, creation of certain wards and readjustment of the jurisdiction of the Appellate Assistant Commissioners.

[No.864(F.No.261/5/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1975

का० प्रा० 2356.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निवेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उनके स्तम्भ 2 में की सत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, बार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

अनुसूची

रेंज	आयकर सर्किल/बार्ड/जिले
1	2
केन्द्रीय रेंज-1, केन्द्रीय सर्किल	1, 10, 12, 13, 14, 15, 16 और 17
केन्द्रीय रेंज-2 केन्द्रीय सर्किल	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33

जहां कोई आयकर सर्किल/बार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत हो जाता है, वहां उस

आयकर सर्किल/बार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिससे वह आयकर सर्किल/बार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, के समक्ष संबंधित अपील उस तारीख से, जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिसको उक्त सर्किल/बार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा बरती जाएगी।

यह अधिसूचना 10-4-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 868 (फा० सं० 261/7/75-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 10th April, 1975

S. O. 2356.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or Super-tax in the income-tax circles, wards and districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof:—

SCHEDULE

Range	Income-tax Circle/Wards/Districts
1	2
Central Range-I, Central Circle.	I, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI and XVII.
Central Range-II, Central Circle.	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII and XXXIII.

Where an income-tax Circle, ward or district or part thereof stands transferred by this notification from one range to another range appeals arising out of assessments made in that income-tax circle, ward or district or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that income-tax circle, ward or district or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 10-4-1975.

EXPLANATORY NOTE :

The amendment has become necessary consequent on redistribution of work amongst the A.A.Cs. of Commissioners' charge.

[No.868(F.No. 261/7/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1975

का० प्रा० 2357.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 786-क (फा० सं० 261/4/74-आई० टी० जे०), तारीख

2-12-74 से उपायक अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है,
प्रस्तावः—

नई दिल्ली, 1 मई, 1975

उक्त अनुसूची में

I. "छ" रेंज, कलकत्ता के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

1. जिला III (1) कलकत्ता (उन बाड़ों से भिन्न जो ए० ए० सी०-ज रेंज, कलकत्ता को समनुदेशित किए गए हैं)

II. "ज" रेंज, कलकत्ता के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

1. जिला III (1), कलकत्ता (क से च तक के बाड़ और ड, ढ, ण, त, थ, और व बाड़)

III. "ड" रेंज, कलकत्ता के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

1. जिला III-क कलकत्ता
2. जिला V-क कलकत्ता
3. प्रतिदाय सफिल, कलकत्ता
4. बीमा अधिकर्ता सफिल, कलकत्ता
5. न्यास सफिल कलकत्ता,

यह अधिसूचना 23 अप्रैल, 1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 880 (फा० सं० 261/8/75-आई० टी० ज०)]

New Delhi, the 21st April, 1975

S.O. 2357.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its Notification No. 786-A (F. No. 261/4/74-ITJ) dated 2-12-74 as amended from time to time viz.

IN THE SAID SCHEDULE

I Against 'G' Range, Calcutta, following shall be substituted—

1. Dist. III(1) Calcutta (other than those wards assigned to the AAC-II Range, Calcutta).

II. Against 'H' Range Calcutta following shall be substituted—

1. Dist. III((1), Calcutta (A to D Wards and M, N, O, P, Q and R Words)

III. Against 'N' Range, Calcutta, following shall be substituted—

1. Dist. III-A, Calcutta.
2. Dist. V-A, Calcutta.
3. Refund Circle, Calcutta.
4. Insurance Agents Circle, Calcutta.
5. Trust Circle, Calcutta.

This notification shall take effect from 23rd April, 1975.

EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary consequent on transfer of jurisdiction over the Trust Circle, Calcutta from AAC, G-Range, Calcutta to AAC, N-Range, Calcutta and also on abolition of the functional scheme in Distt. III(1) Calcutta.

(The above note does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 880 (F. No. 261/8/75-ITJ)]

फा० प्रा० 2358-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निवेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसकी स्तम्भ 3 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, बाड़ों और जिलों में आयकर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों की जागत अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आयकर सफिल, बाड़ें और जिले
1	2	3
1.	केन्द्रीय रेंज, -1, नई दिल्ली	(क) केन्द्रीय सफिल-5, 7, 8, 9, 11 और 14, नई दिल्ली (ख) केन्द्रीय सफिल, श्रीनगर
2.	केन्द्रीय रेंज, -2 नई दिल्ली	(क) केन्द्रीय सफिल-1, 2, 3, 4, 10 और 13, नई दिल्ली
3.	केन्द्रीय रेंज, मेरठ	(क) केन्द्रीय सफिल-1, 2, 3, 4, मेरठ (ख) केन्द्रीय सफिल-3, 4 और 5, कानपुर (ग) केन्द्रीय सफिल-6 और 11, नई दिल्ली

जहां कोई आयकर सफिल/बाड़ें या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत हो जाता है, वहां उस आयकर सफिल/बाड़ें या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिससे वह आयकर सफिल/बाड़ें या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, के समक्ष लंबित अपील उस तारीख से, जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिसको उक्त सफिल/बाड़ें या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा बरती जाएगी।

जहां ऐसे सभी सफिल/बाड़ें और जिले, जिनके मुख्यालय किसी विशिष्ट स्थान पर हैं किसी सहायक आयुक्त (अपील) को समनुदेशित किए गए हैं, वहां उसे इन मुख्यालयों पर के सफिलों, बाड़ों और जिलों, जो अब उत्सादित भी हो चुके हैं, की बाबत अधिकारिता होगी।

यह अधिसूचना 1-5-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 887 (फा० सं० 261/8/75-आई० टी० ज०)]

New Delhi, the 1st May, 1975

S. O. No. 2358—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard the Central Board of Direct taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and District specified in the corresponding entry in column 3 there of :—

SCHEDULE

S.No.	Range	Income-tax Circles, Wards and Districts
1	2	3
1. Central Range-1, New Delhi.	(a) Central Circles-V, VII, VIII, IX, XII & XIV, New Delhi.	
	(b) Central Circles, Srinagar.	
2. Central Range II, New Delhi.	(a) Central Circles I, II, III, IV, X, and XIII, New Delhi.	
3. Central Range, Meerut.	(a) Central Circles 1, II, III, IV, Meerut.	
	(b) Central Circles III, IV and V, Kanpur.	
	(c) Central Circles VI and XI, New Delhi.	

Where an Income-tax Circle, Ward and District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

Where all Circles, Wards and Districts having Headquarters at a particular place have been assigned to an Appellate Assistant Commissioner, he will have jurisdiction in respect of Circles, Wards and Districts at these headquarters since abolished also

This Notification shall take effect from 1-5-75.

EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary consequent upon the re-allocation of the work amongst the Appellate Assistant Commissioners.

(The above note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 887(F. No. 261/6/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 5 मई, 1975

का० प्रा० 2359:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना सं० 748 (फा० सं० 261/7/74-आई० टी० जे०), तारीख 10 अक्टूबर, 1974 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में, ए० ए० सी० रायपुर रेंज, रायपुर (क्रम सं० 7) के सामने, स्तम्भ सं० 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

“34. आयकर अधिकारी,
निर्धारण 7,
रायपुर”

यह अधिसूचना 5-5-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 890 (फा० सं० 261/11/75-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 5th May, 1975

S.O. 2359.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments in the Schedule appended to its Notification No. 748 (F. N. 261/7/74-ITJ) dated the 10th October, 1974, as amended from time to time :

In the said Schedule against A. A. C., Raipur Range, Raipur (S. No. 7) there shall be added the following under column No. 3 :—

“34. Income-tax Officer,
Assessment VII,
Raipur”

This Notification shall take effect from 5-5-1975.

EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary consequent upon redesignation of I.T.O., Collection, Raipur as I.T.O., Assessment-VII, Raipur.

(The above note does not form part of the notification but it intended to be merely clarificatory).

[No. 890 (F. No. 261/11/75-ITJ)]

नई दिल्ली, 6 मई, 1975

का० प्रा० 2360:—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 6 मई, 1975 से अपनी अधिसूचना सं० 506 (फा० सं० 261/18/73-आई० टी० जे०) तारीख 30 नवम्बर, 1973 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अनुसूची में, कालीकट रेंज, कालीकट के सामने, स्तम्भ 2 में, क्रम सं० 1 में, आयकर सचिव कालीकट, शब्दों के पश्चात् “(जो अब उत्सादित कर दिए गए हैं)” शब्द जोड़ जायेंगे।

निम्नलिखित को स्तम्भ 2 में क्रम सं० 8 और 9 के रूप में जोड़ा जाएगा।

“8. आयकर कार्यालय, सचिव-1, कालीकट।

9. आयकर कार्यालय सचिव-2, कालीकट।”

यह अधिसूचना 6 मई, 1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 891 (फा० सं० 261/10/75-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 6th May, 1975

S.O. 2360.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments with effect from 6th May, 1975 in the Schedule appended to its Notification No. 506 (F. No. 261/18/73-ITJ) dated 30th November, 1973.

In the said schedule against Calicut Range, Calicut, column 2, in Sl. No. 1 after the word Income-tax Circle, Calicut the word "(since abolished)" may be added.

The following may be added as Sl. 8 and 9 in col. 2.

"8. Incometax Office, Circle-I, Calicut.

9. Incometax Office, Circle-II, Calicut."

This Notification shall take effect from 5-5-1975.

EXPLANATORY NOTE

The amendment has become necessary on account of the creation of two new Circle at Calicut, viz. Income-tax Office, Circle-I, Calicut and Income-tax Office, Circle-II, Calicut in Commissioner of Income-tax, Kerala-II Charge.

(The above note does not form part of the Notification but intended to be merely clarificatory).

[No. 891(F. No. 261/10/75-ITJ)]

नई दिल्ली,

12 मई, 1975

का.प्र. 2361.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में अधिसूचना सं. 763 (फा. सं. 261/11/74-आई टी जे), तारीख 2-11-74 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निवेश देता है कि मोचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसकी स्तम्भ 3 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आयकर सर्किल, वार्ड और जिले
----------	------	----------------------------

1. ख-रेंज लखनऊ

1. गोरखपुर

2. बस्ती

3. बह्रैच

4. गोंडा

5. फैजाबाद

6. अजमगढ़

7. बलिया

8. जौनपुर

9. वेतन सर्किल, लखनऊ

10. मुलतानपुर

11. सर्वेक्षण सर्किल, गोरखपुर

12. बेबरिया

2. इलाहाबाद रेंज,

इलाहाबाद

1. इलाहाबाद

2. वेतन सर्किल, इलाहाबाद

3. सर्वेक्षण सर्किल, इलाहाबाद

4. मिर्जापुर

3. वाराणसी रेंज,

वाराणसी

1. सर्किल-1, वाराणसी

2. सर्किल-2, वाराणसी

3. विशेष सर्किल, वाराणसी

4. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, वाराणसी

5. परियोजना सर्किल, वाराणसी

6. सर्वेक्षण सर्किल, वाराणसी

जहाँ कोई आयकर सर्किल/वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तर्गत हो जाता है, वहाँ उस आयकर सर्किल/वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिससे वह आयकर सर्किल/वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, के समक्ष संबंधित अपील उस तारीख से, जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), जिसको उक्त सर्किल/वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तर्गत हुआ है, को अन्तर्गत की जाएगी और उसके द्वारा बरती जाएगी।

यह अधिसूचना 15-5-1975 से प्रभावी होगी।

[सं. 895 (फा. सं. 261/12/75-आई टी जे)]

सी० बी० पदमनाभन, अवर सचिव

New Delhi, the 12th May, 1975

S.O. 2361.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of Notification No.768 (F.No. 261/11/74-ITJ) dated 2-11-74 in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof:—

SCHEDULE

S. No.	Ranges	Income-tax Circles, Wards & Districts
1	2	3
1. B-Range, Lucknow.	(1) Gorakhpur.	
	(2) Basti.	
	(3) Bahraich.	
	(4) Gonda.	
	(5) Faizabad.	
	(6) Azamgarh.	
	(7) Ballia.	
	(8) Jaunpur.	
	(9) Salary Circle, Lucknow.	
	(10) Sultanpur.	

- (11) Survey Circle, Gorakhpur.
(12) Deoria.
2. Allahabad Range, Allahabad.
(1) Allahabad.
(2) Salary Circle, Allahabad.
(3) Survey Circle, Allahabad.
(4) Mirzapur.
3. Varanasi Range, Varanasi.
(1) Circle I, Varanasi.
(2) Circle II, Varanasi.
(3) Special Circle, Varanasi.
(4) Special Survey Circle, Varanasi.
(5) Project Circle, Varanasi.
(6) Survey Circle, Varanasi.

Where an Incometax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one range to another range appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circles, Wards or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notifications takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Incometax of the Range to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 15-5-75.

Explanatory Note :

The amendment has become necessary because of creation of Survey Circles at Allahabad, Gorakhpur and new I.T. Circles at Sultanpur and Deoria.

(The above note does not form part of the Notification but intended to be merely clarificatory.)

[No. 895(F.No.261/12/75-ITJ)]

C.V.PADMANABHAN, Under Secretary.

नई दिल्ली, 22 नवम्बर 1974

शुद्धि पत्र

आयकर

क्रा० प्रा० 2362—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 750 (क्रा० सं० 261/9/74-प्राई० टी० जे०), तारीख 10-10-1974 में निम्नलिखित शुद्धि की जायेगी, अर्थात् :—

(i) “ब” रेंज, मद्रास के पश्चात् “कोयम्बटूर रेंज, कोयम्बटूर” और उसके सामने दशित सदिशों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

(iv) उक्त अधिसूची में, स्तम्भ 1 और 2 के अधीन, विद्यमान विशेष रेंज कोयम्बटूर और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों को निकाल दिया जायेगा :

(v) उक्त अधिसूची में, स्तम्भ 1 और 2 के अधीन विद्यमान विशेष रेंज, कोयम्बटूर के सामने निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

- कोयम्बटूर रेंज, कोयम्बटूर
1. कम्पनी सिकल 1 से 5 तक, कोयम्बटूर
 2. कोयम्बटूर सिकल
 3. विशेष सर्वेक्षण सिकल, कोयम्बटूर
 4. सिकल-1, कोयम्बटूर
 5. नगर सिकल 1 (सभी अनुभाग), कोयम्बटूर
 6. सिकल-2 कोयम्बटूर
 7. नगर सिकल 2, (सभी अनुभाग), कोयम्बटूर

8. सम्पदा शुल्क-एवं आयकर सिकल, कोयम्बटूर
9. वेतन सिकल, कोयम्बटूर
10. प्रतिरिक्त लाभ कर सिकल, कोयम्बटूर
11. उटकमण्ड सिकल (सभी अनुभाग)
12. पोल्साची सिकल (सभी अनुभाग)
13. तिरुपुर सिकल

(ii) उक्त अधिसूचना में, “यह अधिसूचना 11-10-1974 से प्रभावी होगी” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा :—

“संशोधन सं० 1 से 3, 11-10-1974 से और संशोधन सं० 4-5, 15-11-1974 से प्रभावी होंगे।”

[सं० 776 (क्रा० सं० 261/9/74-प्राई० टी० जे०)]

एस० एन० एल० अग्रवाल, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd November, 1974

INCOME-TAX

S.O. 2362.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the following correction shall be made in its Notification No. 750 (F. No. 261/9/74-ITJ) dated 10-10-1974 viz :—

(i) After D Range, Madras, for “Coimbatore Range, Coimbatore” and the Circles shown against it; the following shall be substituted :—

(IV) In the said Schedule, the existing Special Range, Coimbatore with corresponding entries under Column 1 and 2 shall be deleted :

(V) In the said Schedule, against Coimbatore Range Coimbatore, under Columns 1 and 2, the following shall be substituted, namely :—

- | | |
|----------------------------------|---|
| Coimbatore Range,
Coimbatore. | 1. Company Circles I to V
Coimbatore. |
| | 2. Coimbatore Circle. |
| | 3. Special Survey Circle, Coimbatore. |
| | 4. Circle I, Coimbatore. |
| | 5. City Circle I (All Sections)
Coimbatore. |
| | 6. Circle II, Coimbatore. |
| | 7. City Circle II, (All Sections),
Coimbatore. |
| | 8. Estate Duty-cum-Income-tax
Circle, Coimbatore. |
| | 9. Salary Circle, Coimbatore. |
| | 10. Excess Profits Tax Circles
Coimbatore and Erode. |
| | 11. Ootacamund Circle (All Sections). |
| | 12. Pollachi Circle (All Sections). |
| | 13. Tirupur Circle. |

(ii) In the said notification for the words “This notification shall take effect from 11-10-1974” the following shall be substituted :—

“The amendment Nos. I to III shall take effect from 11-10-1974 and Nos. IV and V from 15-11-1974.”

[No. 776 (F. No. 261/9/74-ITJ)]

S.N.L. AGARWALA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 1975

New Delhi, 28th May, 1975

आय-कर

INCOME TAX

क्र० आ० 2363.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 679 (फा० सं० 187/2/74-2 (ए० आई०)), तारीख 20-7-74, से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

क्रम सं० 5ख के सामने स्तम्भ 1, 2 और 3 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी :—

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
5ख मुम्बई नगर-3	मुम्बई	(1) कम्पनी सक्तिल-3 (2) क-1 वार्ड (3) क-3 वार्ड (4) भ-वार्ड (5) आयकर अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित सभी कम्पनियों जिनके कारबार, वृत्ति या व्यवसाय के प्रधान स्थान निम्नलिखित वार्डों/सक्तिलों/ जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता में हैं और जिस पर मुम्बई के किसी अन्य आयुक्त की इस समय अधिकारिता नहीं है : क-1 वार्ड क-2 वार्ड क-3 वार्ड क-4 वार्ड क-5 वार्ड (6) सड़क परिवहन आपरेटरों के रूप में कारबार करने वाले सभी व्यक्तियों के तथा चिकित्सा व्यवसाई विधिव्यवसाई, अधिवक्ता, सालि-सिटर, अटर्नी, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, रजिस्ट्रीकृत एकाउन्टेण्ट, कास्ट एकाउन्टेण्ट, आय-कर व्यवसायी को वृत्तिका चलाने में तथा बृहत्तर मुम्बई की क्षेत्रीय सीमाओं में इंजीनियर, वास्तुविद, और प्रबन्ध परामर्शी के रूप में वृत्ति में लगे हुए सभी व्यक्तियों के मामलों में कार्य करने वाला टी०पी० सक्तिल, मुम्बई।

S.O. 2363.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 679 (F. No. 187/2/74-II (AI) dated 20-7-74 as amended from time to time.

Existing entries under columns 1, 2 and 3 against S. No. 5B shall be substituted by the following entries :—

Commissioner of In- come-tax	Head- quarters	Jurisdiction
1	2	3
5B Bombay City-III	Bombay	(1) Companies Circle-III. (2) A-I Ward. (3) A-III Ward. (4) X-Ward. (5) All Companies as defined in the I.T. Act, 1961 having their principal place of business, profession or vocation in the territorial jurisdiction of the following Wards/Circles / Districts and over which no other Commissioner at Bombay holding jurisdiction at present ; A-I Ward A-II Ward. A-III Ward A-IV Ward. A-V Ward. (6) T.P. Circle, Bombay dealing with cases of all persons carrying on business as road transport operators and of persons engaged in the carrying on of profession as medical practitioners, Lawyers, advocates, solicitors, attorneys, Chartered Accountants, registered accountants, cost accountants, in ome-tax practitioners, and as engineers, architects and management consultants in the territorial limits of Greater Bombay.

यह आदेश 2-6-1975 से प्रभावी है।

This order takes effect from 2-6-1975.

[सा० 920 (फा० सं० 187/2/74-2 (ए०आई०))]
टी०पी० ज़ुनज़ुनवाला, सचिव

[No. 920 F. No. 187/2/74-II (AI)]
T.P. JHUNJHUNWALA, Secretary.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1974

का० आ० 2384—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जूतों के निर्यात से पूर्व निरीक्षण से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2384, ता० 17 जुलाई, 1967 को भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम-11 के उपनियम (2) द्वारा यथापेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ;

अतः अब उक्त उपनियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को एतद्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाली जनता की सूचना के लिये एतद्वारा प्रकाशित करती है।

2. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आपेक्ष या सुझाव भेजने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद, "बम्बे ट्रेड सेंटर", 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (सातवां तल), कलकत्ता-1 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

1. भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2384 ता० 17 जुलाई, 1967 में निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जाएगा अर्थात् :—

(1) उक्त अधिसूचना के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. इस अधिसूचना में "जूते" से इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार का जूता और उसके घटक (बनाए गए या बनाने से पूर्व) अभिप्रेत है।"

2. उक्त अधिसूचना के उपाबंध में, मव सं० 10 के पश्चात् निम्नलिखित मव संख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"11. जूते के घटक :—

(क) ऊपर के क्लिक किए हुए घटक।

(ख) दो पक्ष और कठोरक (स्टिफनर) सभी सामग्री को सम्मिलित करते हुए क्लिक किए हुए, तबो के घटक।

(ग) (चमड़े सिन्थैटीक/कैब्रिक) के बंध अर्पर।

(घ) (पी० बी० सी०/माइक्रो सैल्युलर/रबर/नियोलाइट/चमड़े आदि) के हाले हुए सोल। इन-सोल और अन्य घटक।

(ङ) तली घटकों को सम्मिलित करते हुए चपलों/सैंडलों की पी० बी० सी०/नियोलाइट/वोलेक्स/चमड़े की पट्टियाँ (स्ट्रैप्स)।

(च) रबड़ या चमड़े के सोल सहित या सोलिंग सामग्री रहित काष्ठ लट्ठा (लाग्स) उसकी पट्टियाँ और बंधकों के साथ।

12. जूते के घटक के अन्य प्रकार।"

[सं० 6 (16)/74-नि० नि० तथा नि० सं०]

MINISTRY OF COMMERCE

ORDERS

New Delhi, the 19th July, 1974

S.O. 2364.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2384, dated the 17th July, 1967 relating to footwear prior to their export, in the manner specified below for the development of the export trade of India :

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within thirty days from the date of publication of this order in the official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street, (7th floor), Calcutta-1.

PROPOSAL

1. The notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 2384 dated the 17th July, 1967, shall be amended as follows, namely :—

(1) for paragraph 3 to the said notification, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"3. In this notification "Footwear" shall mean any type of footwear and its components (fabricated or prefabricated) specified in the Annexure to this notification".

(2) in the Annexure to the said notification, after item No. 10, the following item No. shall be added namely :—

"11. Footwear Components :—

(a) Clicked upper components.

(b) Clicked bottom components including Toe-puff and stiffener (all materials).

(c) closed upper of (Leather/Synthetic/Fabric).

(d) Moulded sole, insole and other components of (PVC/Micro-Cellular/Rubber/Neolite/Leather etc).

(e) PVC/Neolite/Volex/Leather straps of chap-pals/sandals including bottom components.

(f) Wooden logs with rubber or leather soling or without soling materials alongwith its straps and fasteners.

12. Other sorts of footwear components."

[No. 6 (16)/74-EI&EP]

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1974

का० आ० 2365—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, भारत सरकार के मूलपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय

की सुझाई हुई मछली संबंधी अधिसूचना सं० का० आ० 2137, तारीख 5 जून, 1970 में नीचे दी गई रीति से संशोधन करना प्रावश्यक तथा समीचीन है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें नियत (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार नियत निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ;

अतः, अब उक्त उप-नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उससे प्रभावित होने के लिए सम्भाव्य लोगों की सूचना के लिए उक्त प्रस्तावों को प्रकाशित करती है ।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आप्रोप या सुझाव भेजने की बांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, नियत निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर", 14/1बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल), फ्लकसा-1 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2137, तारीख 5 जून, 1970 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

- (1) उपाबंध 1 में, "सुझाई हुई मछली की किस्में शीपक के नीचे, क्रम सं० 38 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—
"39. एंगुलुवा छोटी (दुबार) (एरियस)" ;
- (2) उपाबंध 11 में, "सुझाई हुई मछली के लिए विनिर्देश" शीपक के नीचे, क्रम सं० 38 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं०	किस्म	वैज्ञानिक नाम ! (जाति)	संक्षेप में संसाधन की पद्धति
1	2	3	4
"39.	एंगुलुवा छोटी (दुबार)	एरियस	लम्बाई में काटी गई, घाँसे निकासी तथा मछली काड़ कर खोली गई या कीलरा सिर सहित या सिर रहित सबण से संसाधित एवं सुझाई हुई ।

क्वालिटी के मानक

आकार	रूप	गंध	सूखापन	बाह्य पदार्थ	अन्य टिप्पणियाँ
5	6	7	8	9	10
15 से०मी० से अधिक	सफेद से हल्का भूरा	संसाधित मछली की ताजी मछली	35% से अधिक नमी	शून्य	शून्य

[सं० 6(11)/74-नि० नि० तथा नि० सं०]
के० बी० बालसुब्रह्मणियन, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 26th July, 1974

S. O. 2365—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the Notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2137, dated the 5th June, 1970, regarding dried fish, in the manner specified below, for the development of the export trade of India ;

And whereas the Central Government has formulated the proposals below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by the sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days from the date of publication of this Order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, "World Trade Centre", 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

PROPOSALS

The notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2137, dated the 5th June, 1970 shall be amended as follows, namely :—

In the said notification—

- (1) in Annexure I, under the heading "Varieties of dried fish", after Serial No. 38 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be added, namely
"39. Anguluwa Small (Dubar) (Arius)" ;
- (2) in Annexure II, under the heading "Specifications for dried fish", after Serial No. 38 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be added, namely :—

Sl. Variety No.	Scientific name (species)	Method of cure in brief
1	2	3
"39 Anguluwa Small (Dubar)	Arius	Cut open longitudinally entrails removed and fish split open, or keelams salted and dried with or without head.

Standards of Quality

Size	Appear- ance	Smell	Dryage	Foreign matters	Other Remarks
5	6	7	8	9	10
Above 15 cms	Whitish to dull brown	Fresh flavour of a cured fish	Moisture not excee- ding 35%	Nil	Nil. " "

[No. 6(11)/74-EI & EP]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Deputy Director

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

फरीदाबाद, 14 मार्च, 1975

लोहे और इस्पात

का०प्रा० 2366.—सर्वश्री लार्सन एंड टूब्रो लि० साकी बिहार रोड, बम्बई, बम्बई-400072 को अप्रैल-मार्च 1974 की अवधि के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राइम एवं ताप रोधक गोल इस्पात सिल्लियों आदि के आयात के लिए बम्बई पंजीयन पत्रन के साथ 37,500 रुपये का एक आयात लाइसेंस सं० पी/डी/8568025/सी/एक्स एक्स/52जे/37-38 दिनांक 5-8-74 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन प्रति पारगमन में खो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं० 8568025 दिनांक 5-8-74 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन प्रति खो गई है और निवेदन देता हूँ कि आवेदक को विषयाधीन आयात लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन प्रति को रद्द करते हुए अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन जारी की जानी चाहिए।

[संख्या० पी०/एल/2/ए एम-74/ई एक्स/एयू/एल सी आई/आई एम-2]
के० एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports)

(Iron & Steel)

Faridabad, the 14th March, 1975

CANCELLATION ORDER

S.O. 2366.—M/s. Larsen and Toubro Ltd; Saki Vihar Road, Powai, Bombay-400072 were granted an import licence No. P/D/8568025/C/XX/52/J/37-38, dated 5-8-74 for the item 'Prime Stainless and Heat Resisting Steel Round Bars etc. for Rs. 37,500/- under G. C. A. for April-March, 74 period with the Port of Registration as Bombay. They have applied for issue of duplicate Custom Clearance purpose copy of this licence on the ground that the original C.C.P. Copy of the licence has been lost in transit. It is further stated that the original licence was not registered with any customs authority.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original CCP copy of licence No. 8568025 dated 5-8-74 has been lost and direct that the duplicate CCP copy should be issued to the applicant in cancellation of the original CCP copy of the import licence in question.

[No. P/L2/AM-74/EX/AU/LCI/IM.II]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller

आदेश

बंगलौर, 31 मई, 1975

का०प्रा० 2367.—सर्वश्री विनास इन्डस्ट्रीज नं० 30, इंडस्ट्रियल एरिया, राजाजी नगर, बंगलौर-10 को सिनेमा प्रोजेक्टर पुर्जों के आयात के लिए 25,000 रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस संख्या पी/एस/1829572/आर/एम एल/50/एक्स 37-38 यू०के० क्रेडिट दिनांक 26-3-74 प्रदान किया गया था। अब उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि

प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिल्कुल भी उपयोग किए बिना ही खो गई है और यह कि अब उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति की आवश्यकता लाइसेंस के पूर्ण मूल्य 25,000/- रुपये के लिए है।

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निवेदन देता हूँ कि इस की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए। उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या आई टी सी/एम एस आई/सी० 447/एम 74/एम पी]

आर० जयराम नायडु, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Bangalore, the 31st May, 1975

S.O. 2367.—M/s. Venas Industries, No. 30, Industrial Area, Rajajinagar, Bangalore-10 were granted import licence No. P/S/1829572/R/ML/50/X/37-38 U. K. Credit dated 26-3-74 for Rs. 25,000/- for import of cinema projector parts. They have now applied for duplicate copy of Exchange Control Purposes copy of the above licence on the ground that the original of the above Exchange Control Purposes copy of the licence has been lost without having been utilised at all and that the duplicate copy of Exchange Control Purposes copy of the above licence now required is for the full value of the licence Rs. 25,000/-.

In support of the above contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the above licence has been lost and direct that a duplicate copy of Exchange Control Purposes copy of the above licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Purposes copy of the above licence is hereby cancelled.

[No. ITC/SSI/C. 447/AM 74/NP]

R. JAYARAM NAIDU, Dy. Chief Controller

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 1975

का० प्रा० 2368.—कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) नई दिल्ली को एयरिएट आक पोटाश के आयात के लिए 2,76,20,000 रुपये मूल्य के लिए लाइसेंस सं० जी/ए/1397997 दिनांक 1.3.74 प्रदान किया गया था। कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ने सूचना दी है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति अस्थानस्थ हो गई है और उसने उसकी अनुलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निवेदन देता है कि इसकी अनुलिपि जारी की जाए।

लाइसेंस की मूल प्रति रद्द कर दी गई है। उसकी अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सी ई एन टी/319/73-74/पी एल एस/बी]

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 17th June, 1975

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1975

S.O. 2368.—Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) New Delhi was granted a licence No. G/A/1397997 dated 1-3-74 for Rs. 2,76,20,000 for import of Muriate of Potash. Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) have reported that customs copy of the licence has been misplaced and requested to issue a duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the custom original copy of the licence has been lost and direct that the duplicate copy of the said customs copy of the licence be issued.

The original customs copy of the licence has been cancelled. A duplicate copy of the same is being issued separately.

[No. Cent/319/73-74/PLS/B]

आदेश

क्र० प्रा० 2369.—कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) को म्यूरिएट आफ पोटाश के लिए 7,04,80,000 रुपये मूल्य के लिए एक लाइसेंस सं० जी/ए/1398636 दिनांक 26-3-74 प्रदान किया गया था। कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ने सूचना दी है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति अस्थानस्थ हो गई है और उन्होंने उस की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दायित्व किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निवेश देती है कि इसकी अनुलिपि जारी की जाए।

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द कर दी गई है। इसकी अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या सेन्ट/361/73-74/पी एस एस/बी]

एस० के० उस्मानी, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 2369.—Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture) was granted Licence No. G/A/1398636/dated 26-3-74 for import of Muriate of Potash for Rs. 7,04,80,000. Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture) have reported that customs copy of the licence has been misplaced and requested to issue a duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the customs control copy of the licence has been lost and directs that the duplicate copy of the said customs copy of the licence be issued.

The original copy of the licence has been cancelled. A duplicate copy of the same is being issued separately.

[No. Cent/361/73-74/PLS/B]

S. K. USMANI, Dy. Chief Controller

क्र० प्रा० 2370.—भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० 1134 दिनांक 20-4-74, जो वस्त्र मशीनों के निर्माण अथवा उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद् की स्थापना करने के बारे में है और जिसे भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 20 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित किया गया, में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा :—

उक्त आदेश में क्रम सं० 3 के सामने दी गई प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी :—

अर्थात्:—

3. श्री अतुल के० भगवती,
मे० एसोसिएटेड टेक्स्टाइल इंजीनियर्स
प्रोप० ए० टी० ई० प्रा० लि०,
बम्बई।

[सं० 2-2/71-एच० एम० I]

एस० गणेशपण्डित, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Heavy Industry)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th July, 1975

New Delhi, the 9th July, 1975

Ministry of Heavy Industry No. 1134 dated 20-4-74, establishing a Development Council for the scheduled Industries engaged in the manufacture or production of Textile Machinery, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 20th April, 1974 the following amendment shall be made :—

In the said order, for the entry occurring against S. No. 3, the following entry shall be substituted; namely :—

3. Shri Atul K. Bhagwati,
M/s. Associated Textile Engineers,
Prop. A. T. E. Pvt. Ltd.,
Bombay.

[No. 2-2/71-HM II]

S. GANESAPANDIAN, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1975

क्र० प्रा० 2371.—आई० डी० आर० ए० 6/2/75—विकास परिषद् (क्रियाविधि) नियम, 1952 के नियम, 3, 4 तथा 5 के साथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को मानव निर्मित वस्त्र विकास के परिषद् के सदस्यों के रूप में इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा नियुक्त करती है, अर्थात्:—

मानव निर्मित वस्त्र विकास परिषद्

अध्यक्ष :

1. श्री बी० के० शाह,
प्रबंध निदेशक,
मैसर्स बड़ीवा रेयन निगम लि०,
130-132, ग्रोपोलो स्ट्रीट, बम्बई 1

- सदस्य :
2. अध्यक्ष,
मानव निमित्त रेशा उद्योग एसोसिएशन,
78, वीर नरीमन रेशम, भवन (5वीं मंजिल),
बम्बई।
 3. अध्यक्ष,
मानव निमित्त रेशा कत्तान एसोसिएशन,
मोती महल, 7वीं मंजिल, 195 चर्च गेट,
रिक्लेमेशन, बम्बई-20.
 4. अध्यक्ष,
सिलिस्ट रेशा उद्योग एसोसिएशन,
राजमहल, पहली मंजिल,
84 वीर, नरीमन रोड, बम्बई।
 5. अध्यक्ष,
पोलिस्टर रेशा उत्पावक एसोसिएशन,
मणिमहल, 11/21, मैथ्यू रोड,
बम्बई-400004.
 6. श्री के०के० मोदी,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
मैसर्स मोदी लि०,
मोदी नगर (उत्तर प्रदेश)।
 7. हथकरघा निदेशक,
विधान सौध,
तमिल नाडु सरकार, मद्रास।
 8. श्री नील कांतिया,
अध्यक्ष, काटन, सिल्क तथा रेयन टैक्सटाइल्स सहकारी समिति,
डोडाबल्लापुर, मैसूर।
 9. श्री जे० जी० बकारिया,
स्टैंडर्ड सिल्क मिल्स, सूरत।
 10. श्री आई० पी० पोद्दार,
कलकत्ता सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०,
135, विटलबी रास बिहारी बसु रोड,
कलकत्ता-1.
 11. प्रधान,
भारतीय हथकरघा फब्रिक्स मार्केटिंग सहकारी समिति,
पो० बा० नं० 1530, भारती भवन,
दूसरी मंजिल, 211/219, फेरे रोड, बम्बई।
 12. अध्यक्ष,
सिल्क एण्ड आर्टसिल्क मिल्स एसोसिएशन,
रेशम भवन, 78, वीर नरीमन रोड,
बम्बई-20.
 13. अध्यक्ष,
वार्प निटिंग उद्योग एसोसिएशन,
अभुतसर।
 14. अध्यक्ष,
सिल्क एण्ड रेयन टैक्सटाइल्स नियति संवर्धन परिषद्
रेशम भवन, 78, वीर नरीमन रोड,
बम्बई-20.
 15. श्री धीरूभाई एच० अम्बानी,
प्रबन्धक निदेशक,
रेलिंग्स वस्त्र उद्योग (प्रा०) लि०,
कोर्ट हाउस, चौथी मंजिल, तिलक मार्ग,
घोबी तालाब, बम्बई-400002.
 16. प्रधान, (श्री एच० के० जैन),
होजरी मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन
मूसा हाजी पतवाल,
20, हेयन्स रोड, महालक्ष्मी बम्बई-11.
 17. अध्यक्ष,
भारतीय इम्ब्रायडरी वस्त्र उत्पावक एसोसिएशन।
 18. डा० एस० वरधाराजन,
चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक,
भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लि०,
जवाहर नगर, जनपद बड़ौदा गुजरात।
 19. श्री डी० जी०, गानी
प्रबंध निदेशक,
गुजरात राज्य उर्वरक निगम लि०,
फटिलाइजर नगर, जनपद-बड़ौदा,
गुजरात।
 20. अध्यक्ष,
सिल्क तथा आर्टसिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन,
डा० एनी बिसेन्ट रोड, आर्ली बम्बई।
 21. श्री के० रामानुजम,
संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।
 22. श्री आर० पी० कपूर,
वस्त्र आयुक्त,
पो० बा० नं० 11500, बम्बई-20.
 23. श्री ए० के० चन्ना,
संयुक्त वस्त्र आयुक्त,
पो० बा० नं० 11500, बम्बई-20.
 24. श्री एन० जी० कृष्णामूर्ति,
सलाहकार,
पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
 25. श्री एम० पी० सिंह,
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।
 26. निदेशक (उद्योग),
योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
 27. श्री आई० महादेवम,
संयुक्त सचिव,
उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।
 28. श्री ए० टी० भौसेल,
महासचिव, इंडियन नेशनल टैक्सटाइल्स वर्क्स फैब्रिकेशन,
द्वारा राष्ट्रीय मिल्स मजदूर संघ,
जी० डी० अम्बेकर मार्ग, परेल,
बम्बई-12.

28. श्री किसान तुलपुले,
प्रध्यक्ष,
हिन्द मजदूर सभा,
57, शजाम साधना,
डी० बी० पी० जदन लि०, हिंरू कालोनी,
वावर बम्बई।

30. श्री एस० आर० दमानी,

सदस्य लोक, सभा,

13. जनपथ नई, दिल्ली-1.

2. विकास परिषद् (क्रियाविधि) नियम, 1952 के नियम 2 के खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार वस्त्र आयुक्त बम्बई, के कार्यालय में संयुक्त वस्त्र आयुक्त श्री ए० के० चन्द्रा को उक्त विकास परिषद् के सचिव का कार्य करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करती है।

[सं० 8/7/74-सी० डी० एन०]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

(Deptt. of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th July, 1975

S.O. 2371—INDRA/6/2/75.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industrial (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints for a period of two years effect from the date of issue of this order, the following persons to be members of the Development Council for Man-Made Textiles, Namely :—

DEVELOPMENT COUNCIL FOR MAN-MADE TEXTILES

Chairman,

1. Shri V. K. Shah,
Managing Director,
M/s. Baroda Rayon Corporation Limited,
130-132, Appollo Street, Bombay-1.
2. Members :
2. Chairman,
Association of Man-Made Fibre Industry,
78, Veer Nariman Road, Resham Bhavan (5th Floor),
Bombay.
3. Chairman,
Man-Made Fibre Spinning Association,
Moti Mahal, 7th/195 Churchgate reclamation
Bombay-20.
4. Chairman,
Association of Synthetic Fibre Industry,
Raj Mahal, 1st Floor, 84, Veer Nariman Road,
Fort, Bombay.
5. Chairman,
Polyester Fibre Manufacturers Association,
Mani Mahal, 11/12, Mathew Road,
Bombay-400004.
6. Shri K. K. Modi, Sr. Vice-President,
M/s. Modi Ltd., Modinagar, U.P.
7. Director of Handlooms, Government of Tamilnadu,
Madras.
8. Shri Neelkantiah,
President, Cotton Silk & Rayon Textiles,
Co-operative Society, Dodaballapur, Mysore.

9. Shri J. G. Vakaria,
M/s. Standard Silk Mills, Surat.
10. Shri I. P. Podar,
Calcutta Silk Manufacturing Company Limited,
135-A, Biplabi Rash Behari Basu Road,
Calcutta-1.
11. President,
All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative
Society, P. B. No. 1530, Bharti Bhavan, 2nd Floor,
211-219, Fere Road, Bombay.
12. Chairman,
Silk & Art Silk Mills Association, Resham Bhawan,
78, Veer Nariman Road, Bombay-20.
13. Chairman,
Warp Knitting Industries Association, Amritsar,
14. Chairman,
Silk & Rayon Textiles Export Promotion Council,
Resham Bhawan, 78, Veer Nariman Road, Bombay.
15. Shri Dhirubhai H. Ambani,
Managing Director,
M/s. Reliance Textile Industries (P) Ltd, Court House,
4th Floor Tilak Marg, Dhobi Talao, Bombay-400002.
16. President,
(Shri H. K. Jain)
Hosiery Manufacturers Association, Moosa Haji
Patrawala,
20, Haines Road, Mahalaxmi, Bombay-11.
17. Chairman,
All India Embroidered Textile Manufacturers,
Association, Bombay Cotton Mills Estate,
Kala Chowk, Road, Bombay-4003.
18. Dr. S. Varadarajan,
Chairman and Managing Director,
Indian Petro-Chemical Corporation Ltd; Jawahar
Nagar, Distt-Baroda, Gujarat.
19. Shri D. G. Gani,
Managing Director,
Gujarat State Fertiliser Corporation Ltd;
Fertiliser Nagar, Baroda (Gujarat).
20. Chairman, Silk & Art Silk Mills Research Association,
Dr. Annie Besant Road, Worly, Bombay.
21. Shri K. Ramanujam,
Joint Secretary, Ministry of Commerce,
Udyog Bhavan, New Delhi.
22. Shri R. P. Kapoor,
Textile Commissioner, P.B. No. 11500,
Bombay-20.
23. Shri A. K. Chandra, Joint Textile Commissioner,
P. B. No. 11500, Bombay-20.
24. Shri N. G. Krishnamurthi,
Adviser, Ministry of Petroleum & Chemicals,
Shastri Bhavan, New Delhi.
25. Shri M. P. Singh, Development Officer,
Directorate General of Technical Development,
Udyog Bhavan, New Delhi.
26. Director (Industry) Planning Commission,
Yojana Bhavan, New Delhi.
27. Shri I. Mahadevan, Joint Secretary,
Ministry of Industry & Civil Supplies,
Udyog Bhavan, New Delhi.
28. Shri A. T. Bhosle, General Secretary,
Indian National Textile Workers Federation,
C/o. Rashtriya Mill Mazdoor Sangh,
G. D. Ambedkar Marg, Parel,
Bombay-12.
29. Shri Kisan Tulpule, President, Hind Mazdoor Sabha,
57, Shzam Sadhana,
D. P. Pzadhan Ltd; Hindu Colony, Dadar, Bombay.
30. Shri S. R. Damani,
Member, Lok Sabha, 13 Janpath-I,
New Delhi.

2. In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 the Central Government hereby appoints Shri A. K. Chandra, Joint Textile Commissioner, Office of the Textile Commissioner, Bombay, to carry on the functions of Secretary to the said Development Council.

[F. No. 8/7/74-CDN]
PREM NARAIN, Under Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1975

क्र० आ० 2372.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कोसाम्बा जी० जी० एस०-7 (गांव कूबारडा) से सी० टी० एफ० (गांव पिलोदरा) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजनन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहत है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कोसाम्बा जी० जी० एस०-7 (गांव कूबारडा) से सी० टी० एफ० (गांव पिलोदरा) तक पाइपलाइन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : बरोदाखण्ड तालुका : हंसोत

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टर	ए० आई० सेन्टी ई० ए०आर० ई०	
1	2	3	4	5
गोडाडरा	102	0	11	60
	100	0	10	00
	101	0	06	60
	64	0	23	40
	103	0	13	40
	124(गांव पांड)	0	06	60
	125	0	10	00
	128	0	15	00
	129	0	03	00
	140	0	17	30
	147	0	01	50
	146	0	09	00
	148	0	05	80
	165	0	05	60

1	2	3	4	5
	164	0	08	20
	163	0	10	00
	182	0	06	50
	183	0	01	50
	181	0	09	50
	188	0	07	60
	189	0	10	00
	221	0	10	50
	228	0	07	30
	227	0	14	60
	226	0	02	10
	225	0	06	90
	222	0	02	80
	223	0	07	60
	217	0	21	00
	218	0	21	00
	193	0	08	80
	201	0	10	30

[संख्या 12016/8/75-एल० एंड एल/2]

टी० पी० सुब्रह्मनयम, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS
(Department of Petroleum)

New Delhi, the 3rd July, 1975

S.O. 2372.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. Kosamba GGS-7 (Village-Kuvarda) to CTF (Village-Pilodra) in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the RIGHT OF USER in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from Kosabma GGS-7 (Village Kuvarda) to CTF (Village Pilodra).

State : Gujarat District : Broach Taluka : Hansot

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Godadra	102	0	11	60
	100	0	10	00
	101	0	06	60
	64	0	23	40
	103	0	13	40
	124 (Village Pond)	0	06	60
	125	0	10	00
	128	0	15	00
	129	0	03	00
	140	0	17	30
	147	0	01	50
	146	0	09	00
	148	0	05	80
	165	0	05	60
	164	0	08	20
	163	0	10	00
	182	0	06	50
	183	0	01	50
	181	0	09	50
	188	0	07	60
	189	0	10	00
	221	0	10	50
	228	0	07	30
	227	0	14	60
	226	0	02	10
	225	0	06	90
	222	0	02	80
	223	0	07	60
	217	0	21	00
	218	0	08	30
	193	0	08	80
	201	0	10	30

[No. 12016/8/75—L & L/II]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

का० प्रा० 2373 :—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 968 तारीख 29-3-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित कर का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृत-51 GI/75—8

लिफ्ट गैस प्रयोग में, सभी संयंत्रों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : जामनगर	जिला : जामनगर	गुजरात राज्य		
गांव	संबर्धन संख्या	तक		
		एच	ए	वर्गमील
अलिया	188/पी/ए	0	23	60
	188/पी/बी	0	19	20
	190	0	44	20
	207	0	12	00
	258/पी/ए	0	14	20
	258/पी/बी	0	02	02
	258/पी/सी	0	13	60
	258	0	59	25
	289/पी/ए	0	42	10
	289/पी/बी	0	00	75
	288/1	0	22	00
मोदा	499 और 448	0	97	50
	402	0	25	50
	401	0	08	10
	529	0	42	10
	483/पी/ए	0	21	50
	395	0	27	45
	483/पी/बी	0	14	10
	370	0	27	90
	369	0	01	90
	368/ए	0	33	65
	368/बी	0	29	10
	345	0	20	30
	534	0	17	00
	343	0	40	05
गंगाजला	320	0	47	65
	318	0	22	75
	319	0	20	75
	309	0	15	55
	311	0	26	50
	312	0	25	75
	313	0	06	80
	223	0	17	56
	टरावरज पी	0	28	90
	81	0	37	05

[सं० 12017/3/75-एल एण्ड एल 2]

टी० पी० सुब्रह्मण्यम, चबर सचिव

(Department of Petroleum)
New Delhi, the 5th July, 1975

S.O. 2373.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 968 dated 29-3-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Taluka : Jamnagar District : Jamnagar Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
	188/P/A	0	23	60
	188/P/B	0	19	20
	190	0	44	20
	207	0	12	00
	258/P/A	0	14	20
	258/P/B	0	02	02
	258/P/C	0	13	60
	285	0	59	25
	289/P/A	0	42	10
	289/P/B	0	00	75
	288/1	0	22	00
Moda	449 and 448	0	97	50
	402	0	25	50
	401	0	08	10
	529	0	42	10
	483/P/A	0	21	50
	395	0	27	45
	483/P/B	0	14	10
	370	0	27	90
	369	0	01	90
	368/A	0	33	65
	368/B	0	29	10
	345	0	20	30
	534	0	17	00
	343	0	40	05
	320	0	47	65
	318	0	22	75
	319	0	20	75
	309	0	15	55
	311	0	26	50
	312	0	25	75
	313	0	06	80
	223	0	17	56
Gangajala	Trawers P	0	28	90
	81	0	37	05

[No. 12017/3/75-L&L/II]

का० आ० 2374— यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 967 तारीख 29-3-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघर्षों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : नानकानेर	जिला : राजकोट	गुजरात राज्य		
गांव	सर्वेक्षण संख्या	तक \		
		एच०	ए०	वर्ग मील
जेपुर	43	0	37	50

[सं० 12017/3/75-एल एण्ड एस/1]

S.O. 2374.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 967 dated 29-3-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Taluka : Nankaner District : Rajkot Gujarat State

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M.
Jepur	43	0	37	50

[No. 12017/3/75-L&L/I]

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1975

का० भा० 2375—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० भा० सं० 959 तारीख 29-3-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, भागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संघकों के मूल रूप से, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को सिद्ध होगा।

अनुसूची

तालुका : बीरमगाम जिला : अहमदाबाद गुजरात राज्य

गाँव	सर्वेक्षण संख्या	एक		
		ए०	ए०	वर्ग मील
1	2	3	4	5
सचना	937पी/1	0	19	50
	937 पी/11	0	32	00
	944	0	03	50

1	2	3	4	5
सचना—जारी	945	0	46	70
	850	0	01	30
	846	0	00	35
	847	0	27	60
	930	0	25	80
	926	0	24	30
	927	0	26	00
	965	0	24	90
	964	0	17	65
	966	0	08	70
	962	0	04	65
	972	0	30	10
	974	0	11	00
	976	0	19	60
	975	0	21	95
	977	0	10	70
	1024	0	23	20
	1022	0	00	45
	1021	0	16	00
	1020	0	18	75
	1019	0	20	90
	1018	0	01	10
	1031	0	00	45
	1014	0	55	90
	1107	0	02	65
	1108	0	14	45
	1109/पी/बी	0	23	40
	1109/पी/ए	0	00	40
	1110	0	23	50
	1115/पी/बी	0	00	70
	1115/पी/ए	0	14	50
	1114	0	01	75
	1128	0	14	60
	1124	0	06	80
	1125	0	11	50
	1126	0	03	55
	1123	0	00	55
	1129	0	08	50
	1170	0	12	10
कल्याणपुर	139	0	14	10
एलियस गीयाल	138	0	10	15
	136/पी०/बी०	0	03	80
	136 पी/ए	0	05	20
	137	0	12	20
	135	0	18	45
	146	0	15	37
	147	0	09	85
	148	0	38	55
	121	0	00	15
	120	0	06	50

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
कल्याणपुर एलियस	118	0	04	95	सीकाली—जारी	17/पी/सी	0	17	25
शियाल—जारी	117	0	14	90		17/पी/बी	0	17	30
	116	0	20	80		17/पी/ए	0	09	90
जबवाडा	503	0	08	05		177	0	03	50
	513	0	24	80		176/पी/बी	0	17	10
	514	0	15	00		176/पी/ए	0	30	05
	523	0	10	43		173	0	01	05
	524 पी/बी	0	23	50		174/पी/बी	0	14	18
	524/पी/ए	0	15	10		174/पी/ए	0	22	50
	528	0	29	05		160/पी/बी	0	03	09
	562	0	13	80		160/पी/सी	0	12	30
	566	0	17	20		160/पी/बी	0	01	86
	567/पी/डी	0	35	40		160/पी/ए	0	08	85
	567/पी/सी	0	16	65	हनसलपुर	677/1	0	02	10
	567/पी/बी	0	14	60	सुरेशवर	677/2	0	40	60
	567/पी/ए	0	11	80		668	0	03	50
	579	0	09	15		667/1	0	23	80
	570	0	45	00		666	0	05	60
	578	0	34	40		665	0	28	75
	575	0	06	40		664	0	30	90
	565	0	18	65		663	0	27	10
	666	0	26	70		645	0	21	15
	693	0	09	60		685	0	45	30
	667	0	13	00		686	0	29	45
	668	0	20	00		695	0	37	60
	691	0	07	60		698	0	12	35
	690/पी/सी	0	19	75		699	0	12	15
	690/पी/बी	0	06	65		700	0	31	85
	690/पी/ए	0	11	00		710	0	10	00
	689	0	22	40		714	0	12	60
	684	0	17	65		719	0	16	25
	783	0	16	10		720	0	28	45
	753	0	40	50		799	0	06	80
	757	0	09	20		798/1	0	37	35
	754	0	00	20		796	0	25	15
	736	0	21	00		825	0	04	10
	758	0	16	38		826	0	37	25
	780	0	00	10		829	0	22	50
	779	0	19	00		911	0	15	10
	775	0	02	80		920	0	26	15
	776	0	20	15		919	0	05	10
	777	0	18	75		936	0	23	92
	778	0	19	82		937	0	21	30
	769	0	24	70		938	0	29	80
सीकाली	187/पी/1	0	07	15		945	0	22	25
	187/पी/2	0	26	70		946	0	07	95
	184	0	22	50		28	0	11	20
	185	0	10	80		26	0	10	80
	182	0	05	00	वीरमगाम	1233	0	25	70
						1234/पी/1	0	26	10

New Delhi, 8th July, 1975

1	2	3	4	5
दीरमगास—जारी	1234/पी/2	0	33	10
	1235/पी/1	0	20	15
	1235/पी/2	0	02	40
	1224/पी/1	0	03	75
	1224/पी/2	0	26	45
	1203	0	21	41
	1202	0	26	80
	1204	0	15	65
	1136	0	03	85
	1135/पी/1	0	16	50
	1135/पी/2	0	16	25
	1134/पी/1	0	18	65
	1134/पी/2	0	32	20
	1129/2	0	05	00
	1129/1	0	26	35
	1128	0	29	90
	1127/3	0	18	95
	1126/3	0	23	50
रेहमलपुर	217	0	27	30
	216	0	24	85
	215	0	01	75
	208/2	0	47	40
	208/1 और 209	0	38	70
	207	0	25	60
	206	0	05	65
	205	0	21	95
	190	0	30	10
	191	0	10	70
	176	0	01	00
	201/5	0	70	55
	201/6	0	06	55
	106/पी/1	0	10	35
	106/पी/2	0	31	00
	105	0	07	40
	108	0	09	15
	104	0	31	55
	103	0	00	60
बनी	37/5	0	17	30
	37/9	0	24	50
	37/8	0	25	60
	38/ए/5	0	00	30
	36/2	0	28	75
	36/1/पी/1	0	22	90
	36/1/पी/2	0	10	35
	36/6	0	04	20
	36/7	0	21	40
	35/1	0	05	30
	34/3	0	18	65
	34/6	0	19	95
	34/5	0	25	80

S.O. 2375.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 959 Dated 29-3-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Taluka : Virangam District : Ahmedabad		Gujarat State		
Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq.M
1	2	3	4	5
Sachana	937P/1	0	19	50
	937P/2	0	32	00
	944	0	03	50
	945	0	46	70
	850	0	01	30
	846	0	00	35
	847	0	27	60
	930	0	25	80
	926	0	24	30
	927	0	26	00
	965	0	24	90
	964	0	17	65
	966	0	08	70
	962	0	04	65
	972	0	30	10
	974	0	11	00
	976	0	19	60
	975	0	21	95
	977	0	10	70
	1024	0	23	20
	1022	0	00	45
	1021	0	16	00
	1020	0	18	75
	1019	0	20	90
	1018	0	01	10
	1031	0	00	45
	1014	0	55	90
	1107	0	02	65
	1108	0	14	4
	1109/P/B	0	23	40
	1109/P/A	0	00	40
	1110	0	23	50
	1115/P/B	0	00	70
	1115/P/A	0	14	50
	1114	0	01	75
	1128	0	14	60
	1124	0	06	80

1	2	3	4	5
Rehmalpur—Contd.	191	0	10	70
	176	0	01	00
	201/5	0	70	55
	201/6	0	06	55
	106/P/1	0	10	35
	106/P/2	0	31	00
	105	0	07	40
	108	0	09	15
	104	0	31	35
	103	0	00	60
Vani	37/5	0	17	30
	37/9	0	24	50
	37/8	0	25	60
	38-A/5	0	00	30
	36/2	0	28	75
	36/1/P/1	0	22	90
	36/1/P/2	0	10	35
	36/6	0	04	20
	36/7	0	21	40
	35/1	0	05	30
	34/3	0	18	65
	34/6	0	19	95
	34/5	0	25	80

[No. 12017/1/75-L&L]

का० प्रा० 2376.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का प्रजन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०प्रा०सं० 969 तारीख 29-3-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में बिहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संघकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची				
तालुका : बघवान	जिला : सुरेन्द्र नगर	गुजरात	राज्य	
गांव का नाम	सर्वेक्षण सं०	तक		
		एच	ए	बर्मीस
1	2	3	4	5
चमारराज	152	0	33	30
	161	0	34	55
	162	0	20	93
	163	0	03	60
	143/1	0	26	30
	143/2	0	34	95
	143/3	0	27	45
रूधरेज	261	0	35	10
	260	0	34	50
	259	0	01	00
	234	0	40	60
	231	0	34	30
	230	0	11	00
	193	0	06	50
	194	0	15	00
	195	0	09	30
	192	0	31	10
	191	0	13	45
	190	0	14	40
	189	0	01	30
	184	0	40	40
	78	0	00	50
	77/पी/1	0	34	15
	77/पी/2	0	02	15
	76	0	21	30
	50	0	00	20
	75	0	26	60
	62	0	24	50
	58	0	23	45
	57	0	11	15
	969	0	11	70
	937	0	44	20
	936	0	01	10
	907	0	41	05
	908	0	19	30
	911	0	03	30
	910	0	09	95
	909	0	59	10
	967	0	00	25
बकरवाली	247	0	10	80
	248	0	11	10
	249	0	19	55
	250	0	19	10
	251	0	20	30
	252	0	31	00

1	2	3	4	5
बकरधाली—जारी	253	0	29	00
	284	0	15	15
	285	0	19	10
	292	0	21	75
	6	0	41	80
	7	0	24	95
	43	0	31	65
	44	0	15	60
	41	0	43	70
	40	0	28	10
	55	0	15	70
	39	0	34	73
राजपर	372	0	29	65
	371	0	16	40
	375	0	09	55
	376	0	09	65
	347	0	01	05
	346	0	15	60
	345	0	15	60
	332	0	37	63
	331	0	30	10
	334	0	13	45
	323/पी	0	44	10
	321	0	46	40
	243	0	01	75
	320	0	20	00
	319	0	09	05
	318	0	09	05

[सं० 12017/3/75-एल तथा एल/3]

S.O. 2376.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 969 dated 29-3-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publica-

tion of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

TALUKA : WADHWAN DISTRICT: SURENDRANAGAR
GUJARAT STATE

Name of Village	Survey No.	Extent			
		H.	A.	Sq.	M.
1	2	3	4	5	
Chamaraj	152	0	33	30	
	161	0	34	55	
	162	0	20	95	
	163	0	03	60	
	143/1	0	26	30	
	143/2	0	34	95	
	143/3	0	27	45	
	261	0	35	10	
	260	0	34	50	
	259	0	01	00	
Dudhrej	234	0	40	60	
	231	0	34	30	
	230	0	11	00	
	193	0	06	50	
	194	0	15	00	
	195	0	09	30	
	192	0	31	10	
	191	0	13	45	
	190	0	14	40	
	189	0	01	30	
	184	0	40	40	
	78	0	00	50	
	77/P/1	0	34	15	
	77/P/2	0	02	15	
	76	0	21	30	
	50	0	00	20	
	75	0	26	60	
	62	0	24	50	
	58	0	23	45	
	57	0	11	15	
	969	0	11	70	
	937	0	44	20	
	936	0	01	10	
	907	0	41	05	
	908	0	19	30	
	911	0	03	30	
	910	0	09	95	
	909	0	59	10	
Bakarthal	967	0	00	25	
	247	0	10	80	
	248	0	11	10	
	249	0	19	55	
	250	0	19	10	
	251	0	20	30	
	252	0	31	00	
	253	0	29	00	
	284	0	15	15	
	285	0	19	10	
	292	0	21	75	
	6	0	41	80	
	7	0	24	95	

1	2	3	4	5
Bakarthal-Contd.	43	0	31	65
	44	0	15	60
	41	0	43	70
	40	0	28	10
	55	0	15	70
	39	0	34	75
Rajpar	372	0	29	65
	371	0	16	40
	375	0	09	55
	376	0	09	65
	347	0	01	05
	346	0	15	60
	345	0	15	60
	332	0	37	65
	331	0	30	10
	334	0	13	45
	328/P	0	44	10
	321	0	46	40
	243	0	01	75
	320	0	20	00
	319	0	09	05
	318	0	09	05

[No. 12017/3/75-L&L/III]

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1975

का० आ० 2377.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"—33-बी, हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

तालुका : आनन्द	जिला : खोश	गुजरात राज्य		
1	2	3	4	5
गांव	सर्वेक्षण से सं०			तक
				एच ए वर्गमील
आनन्द		1098		0 01 50
		1099		0 00 66

51 GL/75-9

1	2	3	4	5
		1106/2		0 02 50
		1105/1		0 02 70
		1105/2		0 03 02
		1108		0 00 10
		1105/3		0 01 60
		1110		0 02 80

[संख्या 12017/1/74-एन एण्ड एल-]]

टी० पी० सुब्रह्मनयन, अनर सचिव

New Delhi, the 9th July, 1975

S.O. 2377.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

No, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project "DOLI" 3-B Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

TALUKA:ANAND DISTRICT : KHEDA GUJARAT STATE

Village	Survey No.	Extent		
		H.	A.	Sq. M
Anand	1098	0	01	50
	1099	0	00	66
	1106/2	0	02	50
	1105/1	0	02	70
	1105/2	0	03	02
	1108	0	00	10
	1105/3	0	01	68
	1110	0	02	80

[No. 12017/4/74-L&I.]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

का० आ० 2378.—यतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपापत्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा लिए जाने वाले खाद्यान्तों के क्रय, भण्डारण, संचालन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपापत्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिर्णित कृत्यों के पालन में सभी निम्नलिखित अधिकारियों और कर्म-

कारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय की उक्त अधिनियम की धारा 12 ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

प्रतः प्रद्व खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37), यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12 ए द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन जिस पद पर स्थायी है	स्थानान्तरण के समय के अधीन जिस पद पर थे	भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के पद पर तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री जी० के० शुगानी	उप निदेशक	संयुक्त निदेशक	1-3-69
2.	श्री पी० एम० इंगले	उप निदेशक	संयुक्त निदेशक	1-11-69
3.	श्री एस०एम० तन्दकोलियर	उप निदेशक	संयुक्त निदेशक	1-3-69
4.	श्री एस० मिन्ज	उप निदेशक	उप निदेशक	1-3-69
5.	श्री ओ० पी० गर्ग	उप निदेशक	उप निदेशक	3-4-75
6.	श्री ए० एम० मोहम्मद	सहायक निदेशक	—वही—	1-3-69
7.	श्री के० प्रार० नारायण राव	सहायक निदेशक	सहायक निदेशक	1-11-69
8.	श्री एस० एन० भवनामी	तकनीकी अधिकारी	सहायक निदेशक (तक)	1-3-69
9.	श्री धीरेन नाथ चक्रवर्ती	अधीक्षक	सहायक निदेशक	1-3-69
10.	श्री एम० के० प्रार० चारी	कार्यालय अधीक्षक	—वही—	1-3-69
11.	श्री बी० एन० शर्मा	गोदी निरीक्षक	महायक निदेशक	1-3-69
12.	श्री प्रार० के० जयप्रसन्न	—	सहायक निदेशक	1-3-69
13.	श्री पी० के० कालकर	—	तकनीकी सहायक	1-3-69
14.	श्री पी० प्रार० मेनन	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	1-3-69
15.	श्री एम० के० बानान	टैली क्लर्क	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	1-3-69
16.	श्री पी० डी० परमार	गोदाम क्लर्क	"	1-3-69
17.	श्री पी० एन० मिह	—	"	1-3-69
18.	श्री एम० प्रार० शिरके	गोदाम क्लर्क	"	1-3-69
19.	श्री एन० के० खारपडे	तोल क्लर्क	"	22-11-71
20.	श्री जे० बी० पुजारी	—	"	1-3-69
21.	श्री बी० सी० गुप्ता	—	"	1-3-69
22.	श्री ए० जी० वरधेसे	—	"	1-3-69
23.	श्री एस० सेलवाराम	लेखापाल	लेखापाल	1-3-69
24.	श्री जी० वी० मनबानी	कनिष्ठ क्लर्क	वरिष्ठ क्लर्क	1-3-69
25.	श्रीमती बी० के० बनसोडे	—	"	1-3-69

1	2	3	4	5
26.	श्री प्रार० एस० बोरकर	—	कनिष्ठ क्लर्क	1-3-69
27.	श्री बी० एन० जाधव	—	"	1-3-69
28.	श्री के० एस० भवसार	—	"	1-3-69
29.	श्री बी० बी० पगारे	—	"	1-3-69
30.	श्री जे० पी० बिट्टल राव	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	1-3-69
31.	श्री पी० ए० इहर	—	"	1-3-69
32.	श्री कालचन्द	—	"	1-3-69
33.	श्री बी० जी० पाटिल	—	"	1-3-69
34.	श्री नायक रतनाकर	—	"	1-3-69
35.	श्री के० बी० अग्रवाल	—	"	1-3-69
36.	श्री एम० डी० तान्त्रे	—	"	1-3-69
37.	श्री प्रार० एस० मोहर	—	"	1-3-69
38.	श्री डी० जी० भताविया	—	"	1-3-69
39.	श्री सी० के० मूर्ति	—	"	1-3-69
40.	श्री ए० जी० एस० मुकाबम	—	"	1-3-69
41.	श्री टी० के० वारमार	—	"	1-3-69
42.	श्री एन० के० बेलोणे	—	"	1-3-69
43.	श्री जी० प्रार० वाध	—	गोदाम क्लर्क	1-3-69
44.	श्री एम० ए० शेख	—	"	1-3-69
45.	श्री एल० जी० गाहीबाड	—	"	1-3-69
46.	श्री जे० के० भटनागर	—	"	23-3-75
47.	श्री डी० जी० देशपांडे	—	"	1-3-69
48.	श्री ए० एन० कसर	—	"	1-3-69
49.	श्री जी० डी० बंगेरा	गोदाम क्लर्क	"	1-3-69
50.	श्री प्रार० बी० भांडे	—	"	1-3-69
51.	श्री जी० एन० पवार	—	फोरमैन	1-3-69
52.	श्री ए० प्रार० मुखर्जी	टैली क्लर्क	गोदी निरीक्षक	30-5-75
53.	श्री जे० एस० रतरेकर	—	बायरमैन	1-3-69
54.	श्री बी० बी० धोके	—	ग्रेड- 2	1-3-69
55.	श्री डी० एस० बालेकर	शीट पर्यवेक्षक	शीट पर्यवेक्षक	1-3-69
56.	श्री टी० एल० चान्दानी	—	"	1-3-69
57.	श्री अलफी मेनजेज	—	सहायक पर्यवेक्षक	1-3-69
58.	श्री अब्दुल रहमान	—	शिफ्ट सुपर-वाइजर	1-3-69
59.	श्री एम० ए० इरानी	—	"	1-3-69
60.	श्री के० प्रार० संतोके	—	मेकेनिक	1-3-69
61.	श्री बी० एन० भोई	—	इंजिनर	1-3-69
62.	श्री प्रार० डी० पात्रिक	—	"	1-3-69
63.	श्री एस० फेरनांडेस	—	"	1-3-69
64.	श्री एफ० डेसोजा	—	"	1-3-69
65.	श्री ए० जी० कालघातगी	—	"	1-3-69
66.	श्री एफ० फेरनांडेस	—	"	1-3-69
67.	श्री एम० बामैन	—	"	1-3-69
68.	श्री तुलसी राम जावव	—	"	1-3-69
69.	श्री जी० बी० महात्रे	—	"	1-3-69

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
70.	श्री एस० डी० सारंग	---	ड्राइवर मेकेनिक	1-3-69	115.	श्री ए० बी० पवार	---	चौकीदार	1-3-69
71.	श्री जी० बी० घाटले	---	मेकेनिक	1-3-69	116.	श्री पी० धार० लेली	---	"	1-3-69
72.	श्री भाई० एच० चौगुले	---	मुख्य मेकेनिक	1-3-69	117.	श्री एस० एस० चिकनेर चौकीदार	---	"	1-3-69
73.	श्री वी० ए० अघोले	---	मैड टैलीमैन	1-3-69	118.	श्री के० डी० भगाने	---	"	1-3-69
74.	श्री डी० बी० गूजर	---	"	1-3-69	119.	श्री एस० एन० कदम	---	"	1-3-69
75.	श्री पी० बी० हलवनकर	---	"	1-3-69	120.	श्री ज्ञानबन्धु बायासराम चौकीदार	---	"	1-3-69
76.	श्री बी० एस० पराब	---	"	1-3-69	121.	श्री स्वामी एन० सिंह	---	"	1-3-69
77.	श्री ए० एस० भाधगाणे	---	"	1-3-69	122.	श्री बालीराम शम्भू	---	"	1-3-69
78.	श्री टी० धार० बंगेरा	---	"	1-3-69	123.	श्री जी० के० खराडे	---	"	1-3-69
79.	श्री एल० ए० जमनादास	---	"	1-3-69	124.	श्री हीरानन्द रामरख्यानल चौकीदार	---	"	1-3-69
80.	श्री एस० एस० पवार	---	"	1-3-69	125.	श्री ए० एम० शेख	---	"	1-3-69
81.	श्री जोधासिंह एस०	---	"	1-3-69	126.	श्री बाई० पी० वास्ले	---	"	1-3-69
82.	श्री बी० पी० ठाकुर	---	"	1-3-69	127.	श्री बी० बी० चवान चौकीदार	---	"	1-3-69
83.	श्री पी० एस० पिंगरे	---	"	1-3-69	128.	श्री भागिया जे० कवस	---	"	1-3-69
84.	श्री एस० जे० जाधव	---	"	1-3-69	129.	श्री जगबहादुर क्षापा	---	"	1-3-69
85.	श्री डी० एस० सावन्त चौकीदार	---	"	1-3-69	130.	श्री लक्ष्मण एन० नायक	---	"	1-3-69
86.	श्री डी० एस० वाभोलकर	---	"	1-3-69	131.	श्री गनपत जी० जाधव	---	"	1-3-69
87.	श्री जी० के० धवानी	---	"	1-3-69	132.	श्री डी० एस० पवार	---	"	1-3-69
88.	श्री एस० के० रयोंद	---	"	1-3-69	133.	श्री एच० एम० साहू	---	"	1-3-69
89.	श्री एस० एस० पाटिल	---	"	1-3-69	134.	श्री परमबहादुर बी०	---	"	1-3-69
90.	श्री पी० बी० देवकरन	---	स्टाफ कार	1-3-69	135.	श्री धन बहादुर राना	---	"	1-3-69
			ड्राइवर		136.	श्री जी० एस० माने	---	"	1-3-69
91.	श्री हरी नागसी	---	"	1-3-69	137.	श्री जी० बी० मोरे	---	"	1-3-69
92.	श्री एस० डी० अगले	---	"	1-3-69	138.	श्री जवालादत्त एस०	---	"	1-3-69
93.	श्रीमती गिरजाबाई लक्ष्मणसिपटर	---	मिपटर	5-3-69	139.	श्री जैकृष्ण राम एस०	---	"	1-3-69
94.	श्रीमती हंसाबाई किसान	---	"	1-3-69	140.	श्री एस० वी० जाधव	---	"	1-3-69
95.	श्री कोविदा तुकाराम	---	स्टीचर	1-3-69	141.	श्री एस० वी० चवान	---	"	1-3-69
96.	श्री सुहृद भली	---	"	1-3-69	142.	श्री रघुनाथ साखन चौकीदार	---	"	1-3-69
97.	श्री ए० एस० सोनबलकर	---	चपरासी	1-3-69	143.	श्री एन० जे० खतरी	---	"	1-3-69
98.	श्री जी० डी० भोसले	---	"	1-3-69	144.	श्री एस० जी० मोहिते	---	"	1-3-69
99.	श्री बी० धार० हिरलेकर	---	"	1-3-69	145.	श्री भोजी जाधव	---	स्वीपर	1-3-69
100.	श्री एस० ए० तुलासकर	---	"	1-3-69	146.	श्रीमती चन्द्रमान शोन्वारी	---	"	1-3-69
101.	श्री एम० एन० घोसाळ-कर	---	"	1-3-69	[फा० सं० 52/22/74-आ० नि०-3 (खण्ड-2)]				
102.	श्री एस० एस० सलवा	---	साइक०	1-3-69	एल० मिगलियाना, उप सचिव				
			प्रिन्ट						
103.	श्री बी० एल० खाडे	---	खलासी	1-3-69	MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION				
104.	श्री जी० एन० काले	---	"	1-3-69	(Department of Food)				
105.	श्री जे० जे० कदम	---	"	1-3-69	ORDER				
106.	श्री एस० एम० चवान	---	"	1-3-69	New Delhi, the 4th July, 1975.				
107.	श्री जगन्निहू यू० चौकीदार	---	इस्टींग प्रोपरेटर	1-3-69	S. O. 2378.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directors of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under section 18 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India ;				
108.	श्रीमती रामावेणी ठाकुर	---	उसिंटिंग	1-3-69					
			प्रोपरेटर		And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response				
109.	श्री एन० के० यूसफ चौकीदार	---	चौकीदार	1-3-69					
110.	श्री मोहद० खासिम	---	"	1-3-69					
111.	श्री बी० एल० रावत	---	"	1-3-69					
112.	श्री बी० जी० प्रसुलकर	---	"	1-3-69					
113.	श्री जे० धार० गूकला	---	"	1-3-69					
114.	श्री एस० एस० रायन	---	"	1-3-69					

to the circular of the Central Government dated the 16th April, 1971, intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (1) of section 12-A of the said Act ;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by section 12-A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them :—

Sl. No.	Name of the officer/employee	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt., at the time of Transfer	Date of transfer to the F.C.M.
1	2	3	4	5
1.	Shri. G.K. Chugani	Deputy Director	Joint Director	1-3-69 EZ
2.	„ P.M. Ingley	-do-	-do-	1-11-69 WZ
3.	„ S.M. Nandkeolyar	-do-	-do-	1-3-69 NZ
4.	„ S. Minj	-do-	Deputy Director	1-3-69 EZ
5.	„ P.O. Gerg	-do-	Dy. Director (Tech.)	3-4-75 NZ
6.	„ A.N. Moitra	Assistant Director	-do-	1-3-69 EZ
7.	„ K.R. Narayan Rao	Assistant Director	Asstt. Director	1-11-69 WZ
8.	„ M.N. Bhavanani	Technical Officer	Asstt. Director (Technical)	1-3-69 NZ
9.	„ Dhirendra Nath Chakraborty	Superintendent	Asstt. Director	1-3-69 EZ
10.	„ M.K.R. Ghary	Office Supdt.	-do-	1-3-69 EZ
11.	„ B.N. Chatterjee	Dock Inspector	-do-	1-3-69 EZ
12.	„ R.K. Jaywant	—	Asstt. Director	1-3-69 WZ
13.	„ P.K. Kalkar	—	Technical Asstt.	1-3-69 WZ
14.	„ P.R. Menon	Junior Godown Keeper	Senior Godown Keeper	1-3-69 WZ
15.	„ M.K. Balan	Tally Clerk	Junior Godown Keeper	1-3-69 SZ
16.	„ P.D. Parmar	Godown Clerk	-do-	1-3-69 WZ
17.	„ P.N. Singh	—	-do-	1-3-69 WZ
18.	„ S.R. Shirke	Godown Clerk	-do-	1-3-69 WZ
19.	„ N.K. Kharpude	Weighment Clerk	-do-	22-11-71 WZ
20.	„ J.B. Pujari	—	-do-	1-3-69 WZ
21.	„ B.C. Gupta	—	-do-	1-3-69 WZ
22.	„ A.G. Verghose	—	-do-	1-3-69 WZ
23.	„ S. Silvarangan	Accountant	Accountant	1-3-69 SZ
24.	„ G.V. Manwani	Junior Clerk	Senior Clerk	1-3-69 WZ
25.	„ Smt. V.K. Bansode	—	-do-	1-3-69 WZ
26.	„ Shri R.S. Borkar	—	Junior Clerk	1-3-69 WZ

1	2	3	4	5
27.	Shri V.H. Jadhav	—	Junior Clerk	1-3-69 WZ
28.	„ K.S. Bhavasar	—	-do-	1-3-69 WZ
29.	„ B.B. Pagare	—	-do-	1-3-69 WZ
30.	„ J.P. Vittal Rao	Godown Clerk	Godown Clerk	1-3-69 SZ
31.	„ P.A. Ahar	—	-do-	1-3-69 WZ
32.	„ Kalchandan	—	-do-	-do-
33.	„ V.G. Patil	—	-do-	-do-
34.	„ Nayak Ratnakar	—	-do-	-do-
35.	„ K.B. Agarwal	—	-do-	-do-
36.	„ M.D. Tambe	—	-do-	-do-
37.	„ R.S. Bhoir	—	-do-	-do-
38.	„ D.G. Bhataria	—	-do-	-do-
39.	„ C.K. Murthy	—	-do-	-do-
40.	„ A.G.S. Mukadam	—	-do-	-do-
41.	„ T.K. Darimar	—	-do-	-do-
42.	„ N.K. Beloshe	—	-do-	-do-
43.	„ C.R. Wagh	—	-do-	-do-
44.	„ M.A. Shaikh	—	-do-	-do-
45.	„ L.C. Gahiwad	—	-do-	-do-
46.	„ J.K. Bhatnagar	—	-do-	23-3-75 NZ
47.	„ D.G. Deshpande	—	-do-	1-3-69 WZ
48.	„ A.N. Kasar	—	-do-	-do-
49.	„ G.D. Bangera	Godown Clerk	-do-	-do-
50.	„ R.V. Bhande	-do-	-do-	-do-
51.	„ G.H. Pawar	—	Foreman	-do-
52.	„ A.R. Mukherjee	Tally Clerk	Dock Inspector	30-5-75 EZ
53.	„ J.S. Ratrekar	—	Wireman Gr. II	1-3-69 WZ
54.	„ B.B. Dhoke	—	-do-	-do-
55.	„ D.S. Balckar	Shed Supervisor	Shed Supervisor	-do-
56.	„ T.N. Chandanani	—	-do-	-do-
57.	„ Afli Menezes	—	Assistant Supervisor	-do-
58.	„ Abdul Reheman	—	Shift Suppervisor	-do-
59.	„ M.A. Irani	—	-do-	-do-
60.	„ K.R. Santoke	—	Driver	-do-
61.	„ V.H. Bhoi	—	Mechanic Driver	-do-
62.	„ R.D. Patrik	—	-do-	-do-
63.	„ X. Fernandes	—	-do-	-do-
64.	„ F. Disuza	—	-do-	-do-
65.	„ A.G. Kalghatgi	—	-do-	-do-
66.	„ F. Fernandes	—	-do-	-do-
67.	„ M. Waman	—	-do-	-do-
68.	„ Tulsiram Jadhav	—	-do-	-do-
69.	„ G.B. Mhatre	—	-do-	-do-
70.	„ S.D. Sarang	—	-do-	-do-
71.	„ G.B. Ghatle	—	Mechanic	-do-
72.	„ I.H. Chaugule	—	Head Mechanic	-do-
73.	„ V.A. Adhoughle	—	Shed Tallyman	-do-
74.	„ D.B. Gujar	—	-do-	-do-
75.	„ P.B. Haldankar	—	-do-	-do-
76.	„ B.S. Parab	—	-do-	-do-

1	2	3	4	5
77. „	A.S. Adhangale	—	Shed Tallyman	1-3-69 WZ
78. „	T.R. Rangera	—	-do-	-do-
79. „	L.A. Jamanadas	—	-do-	-do-
80. „	S.S. Pawar	—	-do-	-do-
81. „	Jodha Singh S.	—	-do-	-do-
82. „	B.P. Thakur	—	-do-	-do-
83. „	P.S. Pingre	—	-do-	-do-
84. „	S.J. Jadhav	—	-do-	-do-
85. „	D.S. Sawant	Watchman	-do-	-do-
86. „	D.S. Dabholkar	—	-do-	-do-
87. „	G.K. Thadani	—	-do-	-do-
88. „	M.K. Rathod	—	-do-	-do-
89. „	S.S. Patil	—	-do-	-do-
90. „	P.V. Devakaran	—	Staff Car Driver	-do-
91. „	Hari Nagai	—	-do-	-do-
92. „	S.D. Agle	—	-do-	-do-
93. Smt.	Girijabai Laxman	Sifter	Sifter	5-8-69 WZ
94. „	Harisabai Kisan	-do-	-do-	1-3-69 WZ
95. Shri	Kandiba Tukaram	—	Stitcher	-do-
96. „	Mohmed Ali	—	-do-	-do-
97. „	A.S. Sonwadkar	—	Peon	-do-
98. „	G.B. Bhosle	—	-do-	-do-
99. „	B.R. Hirlekar	—	-do-	-do-
100. „	S.A. Tulaskar	—	-do-	-do-
101. „	M.N. Ghosalkar	—	-do-	-do-
102. „	S.S. Salva	—	Cyc. Attendant	-do-
103. „	V.L. Khade	—	Khalasi	-do-
104. „	G.N. Kale	—	-do-	-do-
105. „	J.J. Kadam	—	-do-	-do-
106. „	M.M. Chavan	—	-do-	-do-
107. „	Jagatsing U.	Watchman	Dusting Operator	-do-
108. Smt.	Ramadevi Thakur	Sweeper	-do-	-do-
109. Shri	S. K. Usuf Ali	Watchman	Watchman	-do- SZ
110. „	Mohd. Khasim	—	-do-	-do- SZ
111. „	B.L. Rawat	—	Watchman	-do- W
112. „	B.G. Ansulkar	—	-do-	-do- WZ
113. „	J.R. Shukla	—	-do-	1-3-69 WZ
114. „	S.S. Rawat	—	-do-	-do-
115. „	A.B. Pawar	—	-do-	-do-
116. „	P.R. Feli	—	-do-	-do-
117. „	S.S. Chikne	Watchman	-do-	-do-
118. „	K.D. Bhagane	—	-do-	-do-
119. „	S.N. Kadam	—	-do-	-do-
120. „	G.yanchand Bayasram	Watchmen	-do-	-do-
121. „	Swani N. Singh	—	-do-	-do-
122. „	Baliram Jhabhu	—	-do-	-do-
123. „	G.K. Kharande	—	-do-	-do-
124. „	Hiranand Ram rakhyanal	Watchman	-do-	-do-
125. „	A.M. Shaikh	—	-do-	-do-
126. „	Y.P. Warule	—	-do-	-do-
127. „	V.S. Chavan	Watchman	-do-	-do-
128. „	Bhagiya J. Kadam	-do-	-do-	-do-
129. „	Jagbahadur Thapa	-do-	-do-	-do-
130. „	Laxman N. Naik	-do-	-do-	-do-
131. „	Ganpat G. Jadhav	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5
132. „	D.S. Pawar	Watchman	Watchman	1-3-69 WZ
133. „	H.M. Sahu	-do-	-do-	-do-
134. „	Padambahadur	-do-	-do-	-do-
135. „	Dhanbahadur Rana	—	-do-	-do-
136. „	G.S. Mane	—	-do-	-do-
137. „	G.V. More	—	-do-	-do-
138. „	Jawaladutt L.	—	-do-	-do-
139. „	Jaikrishan Ram S.	—	-do-	-do-
140. „	S.V. Jadhav	—	-do-	-do-
141. „	S.B. Chavan	—	-do-	-do-
142. „	Raghunath Lakhan	Watchman	-do-	-do-
143. „	M.J. Khatri	-do-	-do-	-do-
144. „	S.G. Mohite	-do-	-do-	-do-
145. „	Bhonji Jadhav	—	Sweeper	-do-
146. Smt.	Chandrabhan Bonwari	—	-do-	-do-

[File No. 52/22/74-FC. III (Vol. II).
L. HIMINGLIANA, Deputy Secy.]

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1975

का० प्रा० 2379.—भारतीय दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 10) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में एतद्द्वारा आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है—नामत:—

उक्त अनुसूची के भाग 1 में मेसूर विष्वक्विद्यालय से संबंधित प्रविष्टि 15 में विद्यमान मद को मद सं० (1) कहा जाएगा तथा मद सं० (1) के बाद, जैसी कि संख्या दी गई है, निम्नलिखित मद अंतर्स्थापित की जाएगी नामत:—

“(ii) मास्टर आब डेंटल सर्जरी एम० डी० एस्० (आर्थो०)
(आर्थोडॉन्सिया) मेसूर”

[सं० बी० 12017/1/75-एम० पी० टी०]

मती नायर, अवर सचिव,

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING
(Department of Health)

S.O. 2379.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consulting the Dental Council of India, hereby makes the following further amendment in the Schedule to the said Act, namely :—

In Part I of the said Schedule, in entry 15 relating to the Mysore University, the existing item shall be numbered as (1) and after item (i) as so numbered the following item shall be inserted, namely :—

“(ii) Master of Dental Surgery (Orthodontia).
M.D.S. (Ortho.) Mysore.”

[No. V. 12017/1/75-MPT]
MRS. SATHI NAIR, Under Secy.

नीवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1975

का० आ० 2380.—नायिक भविष्य निधि योजना 1966 के पैरा 44 के साथ पठित नायिक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में तथा भारत सरकार नीवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना का० आ० सं० 1933 दिनांक 9.6.1975 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निवेश बेती है कि भविष्य निधि अंशदान, व्याज तथा अन्य प्राप्तियाँ, जो अनिवार्य भुगतान की राशि घटा कर हुई, में से संवयन निम्नलिखित ढंग से लगाया जायेगा, अर्थात् :—

- i. केन्द्र सरकार की जमानतें -- 45 प्रतिशत
- ii. राज्य सरकार की जमानतें तथा राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार की गारंटी शुदा जमानतें -- 25 प्रतिशत
- iii. डाकघर सावधिक जमा तथा भ्रम्य बजत -- 30 प्रतिशत

उपरोक्त ढंग एक जून, 1975 से 30 जून, 1975 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा।

2. भविष्य निधि संवयन धन (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी तथा सृजित जमानतों में लगाया गया हो अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बचत प्रमाणपत्रों अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई और सृजित जमानतों में लगाया गया हो) का निवेश भी उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित ढंग से किया जायेगा।

[सं० एम० डब्ल्यू० एस० (10)/75-(म टो)]

डी० सी० ग्रहीर अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 9th July, 1975

S.O. 2380.—In pursuance of sub-section (3) of Section 4 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), read with paragraph 44 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 1933 dated 9th June, 1975, the Central Government hereby directs that accumulations out of provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern namely :—

- (i) Central Government securities—45 per cent.
- (ii) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities—25 per cent.
- (iii) Post Office Time Deposits and Small Savings—30 per cent.

The above pattern will be in force for the period from the 1st June, 1975 to 30th June, 1975.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[No. MWS(10)/75-MT]

D. C. AHIR, Under Secy.

नई दिल्ली, 10.6.5 जुलाई, 1975

का० आ० 2381.—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क के अधीन स्थापित विशाखा-

पत्तनम डाक श्रम बोर्ड के सदस्य श्री के० पोलराजू के बारे में यह समझा जाता है कि उन्होंने अपना पाद डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (5) के खण्ड (v) के अधीन रिक्त कर दिया है ;

और इस प्रकार उक्त डाक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हो गई है ; अतः, उक्त नियमों के नियम, 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[सं० बी-15021/1/74 एल डी (i)]

New Delhi, the 10th July, 1975

S.O. 2381.—Whereas Shri K. Polaraju, a member on the Visakhapatnam Dock Labour Board established under section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) has been deemed to have vacated his office under clause (v) of sub-rule (5) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

And whereas a vacancy has thus occurred in the said Dock Labour Board;

Now, therefore, in pursuance of rule 4 of the said Rules, the Central Government hereby notifies said vacancy.

[No. V-15021/1/74-LD (i)]

का० आ० 2682.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एम० नोकराजू को श्री के० पोलराजू के स्थान पर विशाखापत्तनम डाक श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और यह निवेश करती है कि भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3582, तारीख 28 सितम्बर, 1968, में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "डाक कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य" शीर्षक के नीचे मद (3) के सामने "श्री के० पोलराजू" प्रविष्टि के स्थान पर "श्री एम० नोकराजू" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं० बी-15021/1/74 एल० डी० (ii)]

S.O. 2382.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, (9 of 1948) the Central Government hereby appoints Shri M. Nookaraju as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board vice Shri K. Polaraju and directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3582, dated the 28 September, 1968, Namely :—

In the said notification, under the heading "Members representing the Dock Workers" against item (3) for the entry "Shri K. Polaraju" the entry "Shri M. Nookaraju" shall be substituted.

[No. V-15021/1/74-LD (ii)]

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1975

का०प्रा० 2383.—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार मुम्बई खाद्यान्न हस्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1975 का प्रारम्भ भारत का राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) तारीख 29 मार्च, 1975 के पृष्ठ 1324 से 1340 पर नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०प्रा० 0983, तारीख 30 नवम्बर, 1974 के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक, आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है,

उक्त राजपत्र तारीख 14 दिसम्बर, 1974 को उसके लगभग जन साधारण को उपलब्ध करा दिया गया था।

उक्त प्रारूप पर जनसाधारण से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मुम्बई पत्तन के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मुम्बई खाद्यान्न हस्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1975 है (इसमें इसके पश्चात् 'स्कीम' कहा गया है)।

(2) यह स्कीम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. उद्देश्य और लागू होना : (1) इस स्कीम का उद्देश्य मुम्बई पत्तन में रजिस्ट्रीकृत खाद्यान्न हस्तन कर्मकारों के लिए नियोजन की अधिक नियमितता सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना है कि डाक कार्य के दक्ष पालन के लिए डाक कर्मकारों को पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो जाए।

(2) यह स्कीम मुम्बई पत्तन की बाबत है और यह डाक कार्य न के उन प्रकारों और डाक कर्मकारों के उन वर्गों को लागू होती है जो इस स्कीम की अनुसूची 1 में दी गई है।

(3) यह स्कीम रजिस्ट्रीकृत खाद्यान्न हस्तन कर्मकार और रजिस्ट्रीकृत नियोजकों को लागू होगी।

(4) इस स्कीम की कोई भी बात भारतीय नौसेना डाक याई मुम्बई के डाक कार्य के किसी प्रकार और डाक कर्मकारों के किसी वर्ग को लागू नहीं होगी।

3. परिभाषाएं :—इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) अभिप्रेत है,

(ख) "प्रशासनिक निकाय" से खण्ड 4 के अधीन प्रशासनिक निकाय अभिप्रेत है,

(ग) "बोर्ड" से अधिनियम के अधीन गठित मुम्बई डाक श्रम बोर्ड अभिप्रेत है,

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ङ) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है,

(च) "दैनिक कर्मकार" से ऐसा रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार अभिप्रेत है, जो मासिक कर्मकार नहीं है,

(छ) "डाक नियोजक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई डाक कर्मकार नियोजित किया जाता है या नियोजित किया जाता है और उसके अंतर्गत डाक नियोजकों का वह समूह भी आता है जो खण्ड 15(1) (छ) के अधीन गठित किया जाता है,

(ज) डाक कार्य से उन स्थानों या परिमणों में जिनसे यह स्कीम संबंधित है, ऐसे वर्गों या विवरणों के डाक कर्मकारों द्वारा जिनको यह स्कीम लागू होती है, सामान्यतः की गई संक्रियाएं अभिप्रेत हैं,

(झ) "नियोजक रजिस्टर" से डाक नियोजकों का ऐसा रजिस्टर अभिप्रेत है जो स्कीम के अधीन रखा जाता है,

(ञ) "श्रम अधिकारी" से खण्ड 12 के अधीन प्रशासनिक निकाय द्वारा किया गया श्रम अधिकारी अभिप्रेत है,

(ट) "मासिक कर्मकार" से ऐसा रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार अभिप्रेत है, जिसे किसी ऐसी संविदा जिसकी समाप्ति के लिए किसी भी पक्ष की ओर से कम से कम एक मास की सूचना अपेक्षित होती है, के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक या ऐसे नियोजकों के समूह द्वारा मासिक आधार पर नियुक्त किया गया है,

(ठ) "कार्मिक अधिकारी" से खण्ड 5 के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त कार्मिक अधिकारी अभिप्रेत है,

(ड) "रजिस्टर या अभिलेख" से डाक कर्मकारों का ऐसे रजिस्टर या अभिलेख अभिप्रेत है, जो इस स्कीम के अधीन रखा गया है,

(प) "रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार" से ऐसा रजिस्ट्रीकृत खाद्यान्न हस्तन कर्मकार अभिप्रेत है, जिसका नाम तत्समय रजिस्टर या अभिलेख में दर्ज है,

(ण) "रजिस्ट्रीकृत खाद्यान्न हस्तन कर्मकार" से वह रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार अभिप्रेत है जिसका नाम तत्समय रजिस्टर में या अभिलेख में इस स्कीम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट डाक कार्य करने के लिए दर्ज किया गया है,

(त) "रजिस्ट्रीकृत नियोजक" से ऐसा डाक नियोजक अभिप्रेत है, जिसका नाम तत्समय नियोजक रजिस्टर में दर्ज है,

(थ) "प्रारक्षित पूल" से ऐसे रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार का पूल अभिप्रेत है, जो काम के लिए उपलब्ध हों और जो तत्समय किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक या डाक नियोजक के किसी समूह में नियोजन में मासिक कर्मकारों के रूप में नहीं है,

(द) "नियम" से डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1965 अभिप्रेत है,

(घ) "जलयाम" से ऐसा सागरीय जलयाम या पोत अभिप्रेत है, जिसका सकल रजिस्ट्रीकृत टन भार 350 टन से कम नहीं है और इसके अन्तर्गत ऐसी नौकाएं भी आती हैं, जो किसी लैण पोत से छोड़ी जाती हैं या लैण पोत में लदी जाती हैं किन्तु इसमें मुम्बई पत्तन न्यास की नौकाएं सम्मिलित नहीं हैं,

(न) "सप्ताह" से वह अवधि अभिप्रेत है, जो शनिवार की मध्य रात्रि से प्रारम्भ होकर आगामी शनिवार की मध्य रात्रि को समाप्त होती है।

4. प्रशासनिक निकाय—(1) केन्द्रीय सरकार, स्कीम के विन प्रतिदिन के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक प्रशासनिक निकाय नियुक्त कर सकती है जिसमें डाक कर्मकार के ऐसे रजिस्ट्रीकृत नियोजक अथवा अन्य प्राधिकारी होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) प्रशासनिक निकाय, बोर्ड और अध्यक्ष के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा खण्ड 44 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्कीम का दैनिक प्रशासन चलाएगा।

(3) केन्द्रीय, सरकार पर्याप्त कारण से उपखण्ड (1) के अधीन नियुक्त किसी प्रशासनिक निकाय को हटा सकेगी :

परन्तु प्रशासनिक निकाय को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

5. बोर्ड के कार्मिक अधिकारी और अन्य सेवक : बोर्ड एक कार्मिक अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी और सेवक नियुक्त कर सकेगा और उन्हें ऐसे वेतन और भत्ते दे सकेगा और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जैसा वह ठीक समझता है :—

परन्तु ऐसा कोई भी पद जिसकी अधिकतम मासिक वेतन भत्तों को छोड़कर 1250 रु० और उससे अधिक है, सृजित नहीं किया जाएगा और ऐसे पद पर बोर्ड द्वारा कोई भी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी ऐसी किसी नियुक्ति की वास्तविक केन्द्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी जो तीन मास से अतः अधिक अवधि की अवकाश रिक्ति में की जाती है।

6. बोर्ड के कृत्य :—(1) बोर्ड ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह खण्ड 2 में दिए गए स्कीम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वांछनीय समझे ; इसमें निम्नलिखित के लिए उपाय भी सम्मिलित हैं :—

(क) जलयानों के शोध और मितव्ययितापूर्ण विराम काल और पत्तन के संबंध में माल के ह्रास अभिवहन को सुकर बनाने के लिए डाक श्रम का पर्याप्त प्रदाय और उसके पूर्ण और उचित उपयोग सुनिश्चित करना,

(ख) स्कीम के अंतर्गत भर्ती और प्रविष्टियां और उनसे उन्मुक्ति को विनियमित करने तथा आरक्षित पूल के रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का रजिस्ट्रीकृत नियोजकों को आबंटित करना,

(ग) प्रशासनिक निकाय के परामर्श से रजिस्ट्रारों या अभिलेखों में समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की संख्या को अवधारित करने और पुनर्विलोकन के अधीन रखने के लिए ऐसे रजिस्ट्रार या अभिलेख की संख्याओं में वृद्धि या कटौती करना,

(घ) नियोजक रजिस्ट्रार रखना, समायोजित करना और उसकी देखभाल करना और उसमें किसी डाक नियोजक का नाम दर्ज करना या पुनः दर्ज करना और जहां परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, वहां रजिस्ट्रार से किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक के नाम को या तो उसके निवेदन पर या इस स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण में हटाना,

(ङ) उन रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की बाबत जो डाक कार्य के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं हैं और जिनकी अनुपस्थिति प्रशासनिक निकाय द्वारा अनुमोदित कर दी गई है, किन्हीं रजिस्ट्रारों या अभिलेखों सहित समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के बारे में ऐसे रजिस्ट्रार या अभिलेख रखना, समायोजित करना देखभाल करना और जहां परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें वहां किसी रजिस्ट्रार या अभिलेख में किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार का नाम या तो उसके निवेदन पर या इस स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण में हटाना,

(च) सब रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों को ऐसे समूह में जहां बोर्ड द्वारा प्रशासनिक निकाय से परामर्श करने के पश्चात् अवधारित किया जाए, समूहित या पुनः समूहित करने और तत्पश्चात् प्रशासनिक निकाय या रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार के आवेदन पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार के समूहन का पुनर्विलोकन करना,

(छ) रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार के प्रशिक्षण और कल्याण के लिए व्यवस्था करना जिसमें चिकित्सीय सेवाएं भी उस सीमा तक सम्मिलित हैं जहां तक कि ऐसे व्यवस्था स्कीम से असंगत न हो ,

(ज) स्कीम के व्ययों की वास्तविक रजिस्ट्रीकृत नियोजकों से अभिदाय उपगृहीत करना और वसूल करना,

(झ) ऐसे स्थानों में जहां रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार नियोजित हैं, उस सीमा तक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना, जहां तक कि ऐसी व्यवस्था स्कीम के असंगत न हों,

(ञ) डाक कर्मकार कल्याण निधि रखना और उसका प्रबन्ध करना और सभी रजिस्ट्रीकृत नियोजकों से निधि की बाबत अभिदाय वसूल करना।

(ट) रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के लिए विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ सृजित भविष्यनिधि, उपदान निधि, स्वच्छता निवृत्ति निधि और कोई अन्य निधि या निधियों को रखना या प्रबन्ध करना,

(ठ) धन उधार लेने और एकत्रित करने, विवेचन या अन्य प्रतिभूतियां जारी करने और किसी ऋण या बाध्यता की सुरक्षा के हेतु बोर्ड की सभी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का बन्धक रखना या उसे प्रभारित करना।

(2) बोर्ड को धाय और सम्पत्ति, चाहे वह किसी भी स्त्रोत से व्युत्पन्न हो, केवल स्कीम के उद्देश्यों के लिए उपयोजित किए जायेंगे। जिसमें रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार के स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण के उपाय भी शामिल हैं (इसमें वह सहायता शामिल है जो एकमात्र बोर्ड के डाक कर्मचारी और कर्मचारी बन्द के फायदे के लिए अनुदान द्वारा या अन्यथा उनके लिए बनाई गई सहकारी समितियों को उधार के रूप में दी गयी और उसका कोई भी भाग, बोर्ड के सदस्यों के फायदे के रूप में लाभान, बोनस या अन्य रूप में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संवत या अनुवत्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इसमें की कोई बात उन युक्तियुक्त और उचित पारिश्रमिक और व्ययों के संदाय को नहीं रोकती जो वह किसी अधिकारी या सेवक या बोर्ड के किसी सदस्य को उसके द्वारा बोर्ड के लिए वास्तविक रूप से दी गयी सेवा के बदले में हो और न ही वह किसी व्याज के संदाय को निवारित करेगी जो बोर्ड को उसके किसी सदस्य

द्वारा उधार दिए गए धन पर युक्तियुक्त रूप से है या पट्टाकृत या किराए पर दिए गए परिसरों के लिए युक्तियुक्त और ठीक किराया है और न ही यह बोर्ड के कर्मचारीवाद के लिए किन्हीं कल्याणकारी उपायों पर यदि कोई हों, उपगत व्यय को निवारित करेगी।

(3) बोर्ड स्कीम में प्रचालन लागत और उसके अधीन प्राप्तियों और व्ययों की बाबत समुचित लेखा रखवाएगी।

(4) बोर्ड केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :—

(1) प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् यथास्थानीय और प्रकृतिकर के इकतीसवें दिन तक, 31 मार्च, को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान स्कीम के कार्यकरण के बारे में लेखा परोक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक रिपोर्ट और,

(2) बोर्ड के अधिवेशनों की कार्यवाहियों की प्रति।

7. अधिवेशन में बोर्ड के उत्तरदायित्व और कर्तव्य

अधिवेशन में बोर्ड निधि संबंधी सभी विषयों पर विचार करने के लिए उत्तरदायी होगा और विशिष्टतः वह :—

(क) विभिन्न वर्गों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मचारियों की संख्या नियत करेगी ;

(ख) समय-समय पर रजिस्टर पर किसी प्रवर्ग के कर्मचारियों की संख्या में रजिस्टरी और प्रत्याशित आवश्यकताओं के नियत कालिक पुनर्विलोकन के पश्चात् ऐसी वृद्धि या कमी करेगा जो आवश्यक हो।

(ग) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी प्रवर्ग के कर्मचारियों की विनिर्दिष्ट संख्या व अस्थायी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा,

(घ) अध्यक्ष की सिफारिश पर अन्य नियोजकों के रजिस्ट्रीकरण पर विचार करेगा ;

(ङ) स्कीम के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित प्रारूप, अभिलेख, रजिस्टर, विवरण आदि विहित करेगा,

(च) मजदूरी भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों का अवधारण करेगा और वार्षिक पुनर्विलोकन के पश्चात् किसी मास के लिए गारंटीकृत न्यूनतम मजदूरी को पुनः नियत करेगा ;

(छ) खण्ड 52(1) के अधीन उद्ग्रहण की दर नियत करेगा ;

(ज) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा डाक कर्मकार कल्याण निधि और स्वैच्छिक निवृत्ति निधि में किए जाने वाले अभिदाय की दर नियत करेगा।

(झ) खण्ड 36 के अधीन समितियां नियुक्त करेगा, रद्द करेगा या पुनर्गठित करेगा।

(ड) वार्षिक बजट मंजूर करेगा।

(ट) कालिक अधिकारी नियुक्त करेगा।

(ठ) खंड 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पदों का सृजन मंजूर करेगा और ऐसे पदों पर नियुक्ति करेगा।

(ड) इस स्कीम की अनुसूची I में परिचर्तनों की बाबत केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा,

(ढ) स्कीम में किन्हीं उपात्तरणों की बाबत केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा।

(ण) उन विवादों को तय करने का प्रयास करेगा जिनकी बाबत संबंध पक्षकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन किया गया हो और ऐसे प्रयास के परिणामों के बारे में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देगा।

(त) श्रमिकों के उत्पादन और पोलों के विराम काल प्रांकड़ों पर विचार करेगा और अपने पर्यवेक्षण और निदेश अभिलिखित करेगा।

(थ) ऐसे अनुसूचित वर्गों में खाता खोलने की मंजूरी देगा जैसे वह निदेश वे और ऐसे खातों का प्रचालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा कराएगा जिनके बारे में बोर्ड समय-समय पर निदेश दें, और

(व) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निधि या निधियां मंजूर करेगा और उनका सृजन करेगा।

8. वार्षिक प्राक्कलन

अध्यक्ष, प्रत्येक वर्ष फरवरी की समाप्ति से पूर्व होने वाले विशेष अधिवेशन में, इस स्कीम के खण्ड 11(1) के अधीन प्रशासनिक निकाय से प्राप्त वार्षिक बजट बोर्ड के समक्ष रखेगा जो अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए होगा और उस में ऐसे व्यय होंगे और वह ऐसे प्रारूप में होगा जैसा वह समय-समय पर विहित करे। अपने समक्ष प्रस्तुत किए प्राक्कलन पर बोर्ड विचार करेगा और उसके प्रस्तुतीकरण के चार सप्ताह के भीतर उसको या तो अपरिचित रूप में या ऐसे परिवर्तनों सहित मंजूर करेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

9. अध्यक्ष के उत्तरदायित्व और कर्तव्य—(1) अध्यक्ष को, स्कीम के दैनिक प्रशासन में संबंधित सभी विषयों पर विचार करने के लिए पूर्ण प्रशासनिक और कार्यपालक शक्तियां प्राप्त होंगी और विशिष्टतः निम्नलिखित के लिए शक्तियां प्राप्त होंगी :—

(क) यह सुनिश्चित करना कि कर्मकार रजिस्ट्रों के समायोजन के बारे में बोर्ड के विनिर्देशों का शीघ्रता से पालन किया जा रहा है ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कर्मकार के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की बाबत मंजूरी का पालन अविलम्ब किया जाता है ;

(ग) (1) प्रशासनिक निकाय के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना ;

(2) उस दशा में उचित कार्यवाही करना जबकि उसके द्वारा कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं या उसकी जानकारी में लायी जाती हैं ;

(घ) पोल स्वामी या नौवहन अभिकर्ताओं के परामर्श से यह सुनिश्चित करना कि क्या रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा उनके पोलों पर नियोजित कर्मचारियों की बाबत उचित और पर्याप्त पर्यवेक्षण किया जा रहा है ;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि क्या कर्मचारियों के अन्तरण और प्रोन्नति की बाबत स्कीम के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है ;

(च) जब अपेक्षित हो तब भिक्तीय बोर्ड गठित करना ;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि नियोजकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्कीम में अधिकृत शर्तों का उनके द्वारा पालन किया जा रहा है ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि स्कीम के अधीन कथित सभी प्रारूप रजिस्टर, विवरणियां और दस्तावेज ठीक ढंग से रखे जा रहे हैं ;

(अ) यह सुनिश्चित करना कि अधिकों के कार्य की मात्रा और पदों के विरामकाल के बारे में उचित कार्य का संकल्प किया जा रहा है और न तब तक तिसाही में समुचित टिप्पणों और स्पष्टीकरणों सहित बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं ;

(आ) (1) ऐसे पदों का सृजन मंजूर करना जिनका अधिकतम वेतन भत्तों को छोड़कर एक हजार रुपये प्रतिमास तक है ;

(2) ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना जिनका अधिकतम वेतन भत्तों को छोड़कर एक हजार रुपये प्रतिमास तक है ;

(इ) स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण में कर्मकारों और नियोजकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना ;

(ई) कर्मकार की प्रति सप्ताह और प्रतिमास पारियों की अधिकतम संख्या के बारे में छूट देना और ऐसे मामलों में बोर्ड की रिपोर्ट देना ;

(उ) यह घोषित करना कि कार्यमन्दन पद्धति अपनाई गई है और ऐसी कार्यवाही करना जैसी स्कीम के अधीन प्राधिकृत हो ;

(ऊ) 'भ्रष्टाचार स्थिति' घोषित करना और ऐसी कार्यवाही करना जो स्कीम के अधीन प्राधिकृत हो ;

(ण) जब आवश्यक हो तब डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना ;

(त) स्कीम की व्यवस्था के अनुसार, नियोजक या कर्मकार के निवेदन पर किसी मासिक कर्मकार का अनुसरण आरक्षित पूल के लिए मंजूर करना ;

(थ) खण्ड 47 और 48 के अधीन कर्मकारों या नियोजकों की अपीलों पर कार्यवाही करना ;

(द) एक मास से कम की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के पद पर अत्रत्यस्थित रिक्ति की पूर्ति करना और इस विषय में केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए रिपोर्ट देना ; और

(ध) ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जो स्कीम के अधीन अध्यक्ष में विनिर्दिष्ट न लिख दिए गए हैं ।

(2) अध्यक्ष, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वह ठीक समझे, उपाध्यक्ष को लिखित रूप में सब (अ 1), (अ 2), (इ), (उ), (ए), (ए), (व), और (घ) में उल्लिखित मर्कों को छोड़कर उपखण्ड (1) के अधीन कृत्यों में से किन्हीं का प्रत्यायोजन कर सकेगा, तथापि यह कि ऐसा प्रत्यायोजन से अध्यक्ष अपनी शक्तियों से निरहित नहीं होगा ।

10. उपाध्यक्ष के उत्तरदायित्व और कर्तव्य :—उपाध्यक्ष बोर्ड का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह अध्यक्ष को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करेगा और विनिर्दिष्ट : वह,

(क) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी कृत्यों का खण्ड 44 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक निर्वहन करेगा ;

(ख) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्रत्यायोजित किए जाएं ;

(ग) बोर्ड की उन समितियों के अध्यक्ष के रूप में कृत्य करेगा जिसके सदस्य के रूप में उसे नाम निर्देशित किया जा सकता है ;

(घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड के अधिवेशनों का सभापतिस्थ करेगा ;

(ङ) ऐसे पदों पर नियुक्तियां करेगा जिनका अधिकतम वेतन भत्तों को छोड़कर 750 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है ।

11. प्रशासनिक निकाय के कृत्य—बोर्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रशासनिक निकाय स्कीम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और विनिर्दिष्ट : वह,

(क) नियोजक रजिस्टर रखने, समायोजित करने, देखभाल करने, उसमें डाक नियोजकों के नाम दर्ज करने और पुनः दर्ज करने और जहां परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें वहां रजिस्टर से किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक का नाम या तो उसके निवेदन पर या स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण में हटाने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ख) डाक कर्मकारों की बाबत समय-समय पर ऐसे रजिस्टर या अभिलेख जो आवश्यक हों, जिसमें ऐसे डाक कर्मकार के रजिस्टर और अभिलेख भी शामिल हैं, जो अस्थायी रूप से डाक पर काम के लिए उपलब्ध नहीं हैं, और जिनकी अनुपस्थिति प्रशासनिक निकाय द्वारा अनुमोदित की गयी है, रखने, समायोजित करने और देखभाल करने के लिए और जहां परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें वहां किसी रजिस्टर या अभिलेख से किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार का नाम या तो उसके निवेदन पर या स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण में हटाने के लिए, उत्तरदायी होगा ;

(ग) काम के लिए उपलब्ध रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के नियोजन और नियन्त्रण के लिए उस दशा में उत्तरदायी होगा, जबकि स्कीम के अनुसरण में उन्हें अन्यथा नियोजित नहीं किया जाता है ;

(घ) बोर्ड से प्राप्त अनुदेशों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का ऐसे समूहों में समूहन करने या पुनः समूहन करने के लिए उत्तरदायी होगा जो बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए ;

(ङ) आरक्षित पूल में ऐसे डाक कर्मकारों के आवंटन के लिए उत्तरदायी होगा जो रजिस्ट्रीकृत नियोजकों को काम के लिए उपलब्ध हों और इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक निकाय—

(1) नियोजक के अधिकारों के रूप में कार्य करने वाला समझा जाएगा ;

(2) आरक्षित पूल में रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का अधिकतम सम्भव उपयोग करेगा ;

(3) रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की बाबत काल स्टेण्ड और नियन्त्रण स्थलों पर हाजिरी का अभिलेखित करेगा ;

(4) नियोजन और उपाजनों की बाबत अभिलेख रखे जाने की व्यवस्था करेगा ;

(5) खण्ड 29(3) के अधीन चक्रानुक्रम से कार्य के आवंटन के अधीन रहते हुए कर्मकारों का आरंभ खण्ड 19 और 30 के अनुसरण में करेगा ।

(6) आरक्षित पूल के कर्मकारों की हाजिरी फाई और सजदूरी पत्रों में खण्ड 27 में अधिकृत रूप में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ;

(च) (1) डाक कर्मकार कस्याण निधि में किए गए अभिवाय या नियोजकों द्वारा किसी ऐसे अन्य अभिवाय के जो स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए, उद्ग्रहण का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(2) भविष्य निधि, बीमा निधि या किसी अन्य निधि से जो स्कीम के अधीन गठित की जाए कर्मकारों द्वारा किए गए अभिवाय का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(3) प्रत्येक दैनिक कर्मकार को रजिस्ट्रीकृत नियोजक के अधिकारों के रूप में ऐसे सभी उपयोगों का संदाय करने के लिए जो नियोजक से कर्मकार को उचित रूप से देय हों और बोर्ड द्वारा उन कर्मकारों को स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण में देय सभी धन का ऐसे सभी कर्मकारों को संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(छ) बजट व्यवस्था के अधीन रहते हुए समय-समय पर ऐसे अधिकारी और सेवक नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगा जो आवश्यक हों :

परन्तु ऐसे पदों का जिनका अधिकतम वेतन भत्ते को छोड़कर 575 रु० प्रतिमास से अधिक है सृजन और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति खण्ड 6(1) और 9(1) (अ) के अधीन रहते हुए होगी ;

(ज) स्कीम के प्रचालन की लागत, और उसके अधीन सूची प्राप्तियों और देयों की वास्तव समुचित लेखा रखने और वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित तुलनपत्र तैयार करने और उसे बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(झ) वार्षिक रूप से बजट बनाने, उसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के 15वें दिन को या उससे पूर्व बोर्ड को प्रस्तुत करने और बोर्ड द्वारा उसे अनुमोदित कराने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ञ) सभी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की वास्तव पूर्ण सेवा अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ट) स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे सभी कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा जो कि समय-समय पर उसे बोर्ड, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं ;

12. श्रम अधिकारी :—प्रशासनिक निकाय बोर्ड के अनुमोदन से उस दशा में एक या अधिक श्रम अधिकारी नियुक्ति करेगा जबकि उम में डाक कर्मकारों के नियोजक भी हों। श्रम अधिकारी, प्रशासनिक निकाय के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन स्कीम के उपबन्धों से संगत कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे उस निकाय द्वारा सौंपे जाएं।

13. कार्मिक अधिकारी के कृत्य :—कार्मिक अधिकारी साधारणतः उपाध्यक्ष को उसके बातचीतों के निर्वहन में सहायता करेगा और विशिष्टतः स्कीम के खण्ड 44 के अधीन उसमें निहित कृत्यों का पालन करेगा।

14. स्कीम के उचित कार्यकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी :—(1) खण्ड, 4, 5, 11 और 13 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, स्वविवेकानुसार समय-समय पर बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श करके एक या अधिक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, ऐसे कृत्य सौंप सकेगा जो वह स्कीम के उचित कार्यकरण के लिए ठीक समझे।

(2) उपखण्ड (1) के अधीन नियुक्ति अधिकारी अध्यक्ष के साधारण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन रहेंगे और उन्हें बोर्ड की निधि से संदाय किया जाएगा। ऐसे अधिकारी ऐसी अवधिपर्यन्त और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार अवधारित करे।

15. रजिस्टर आवि का रखा जाना :—(1) नियोजक रजिस्टर—

(क) नियोजकों का एक रजिस्टर होगा ;

(ख) जहां तक इस स्कीम का खाद्यान्न हस्ताई कर्मकारों को लागू होने का सम्बन्ध है, प्रत्येक नियोजक को, जिसे स्कीम के प्रारम्भ की तारीख को मूम्बई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1957 के अधीन सूचीकृत किया गया है, स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।

(ग) उन व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को जो मद (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझे गए हैं, तब तक खाद्यान्न हस्तन नियोजक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड ऐसा करना समीचीन और आवश्यक न समझे और किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उसे मूम्बई पतन न्यास द्वारा उस निमित्त अनुज्ञात नहीं कर दिया जाता है ;

(घ) बोर्ड, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस निमित्त विहित करे, मद (ख) और (ग) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को एक या अधिक समूह बनाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार बनाए गए प्रत्येक समूह को केवल मासिक कर्मकारों के नियोजन की वास्तव एक ही नियोजक के रूप में माना जाएगा ;

परन्तु बोर्ड को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विहित शर्तों में ऐसे परिवर्तन या उपान्तरण करने की शक्ति प्राप्त होगी जिसे वह समय-समय पर आवश्यक समझे :

परन्तु यह और कि यदि नियोजक समूह को प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दिखलाने का अवसर देने के पश्चात् तथा उसके अभ्यावेदनों यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे समूह के बनाने के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों का भागतः या पूर्णतः पालन करने में नियोजकों का समूह असफल रहा है, बोर्ड ऐसी तारीख से जिसे वह विनिर्दिष्ट करे नियोजकों के किसी समूह को दी गयी अनुज्ञा का प्रतिसंहरण कर सकेगा और तदुपरि ऐसी तारीख से उक्त समूह विघटित हो जाएगा।

(2) कर्मकार रजिस्टर—(क) कर्मकार रजिस्टर इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में रखा जाएगा।

(ख) खाद्यान्न हस्तन कर्मकारों का रजिस्टर निम्नलिखित प्रकार का होगा, प्ररूपः—

(1) मासिक रजिस्टर—ऐसे कर्मकारों का रजिस्टर जो प्रत्येक खाद्यान्न हस्तन नियोजक द्वारा मासिक आधार पर संविदा पर लगाए गए हैं और जो मासिक कर्मकार के रूप में ज्ञात हैं ;

(2) प्रारम्भित पूल रजिस्टर—मासिक रजिस्टर के कर्मकारों से जो प्रारम्भित पूल कर्मकार के रूप में ज्ञात हैं, भिन्न कर्मकारों का रजिस्टर। इस रजिस्टर में विभिन्न प्रवर्गों की आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए खाद्यान्न कर्मकारों का उपपूल शामिल

होगा। ऐसे उपपूल में शामिल कर्मकार छूटी पर आरक्षित कर्मकार कहे जाएंगे।

16. रजिस्टर में कर्मकारों का वर्गीकरण :—

- (1) बोर्ड रजिस्ट्रारों में कर्मकारों के प्रवर्गानुसार वर्गीकरण की व्यवस्था करेगा।
- (2) स्कीम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे—
 - (क) मुकुद्म
 - (ख) टिबल
 - (ग) लदान करने वाले
 - (घ) भराई करने वाले
 - (ङ) सीयक
 - (च) पल्लावाला
 - (छ) पल्लेवालिया
 - (ज) मशीन मजदूर
 - (झ) टैंक मजदूर
 - (ञ) डाक मजदूर

17. रजिस्टर पर कर्मकारों की संख्या का नियत किया जाना :—

- (1) बोर्ड, प्रशासनिक निकाय से परामर्श करने तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी प्रवर्ग में रजिस्ट्रीकरण प्रारम्भ करने से पूर्व उस प्रवर्ग में अपेक्षित कर्मकारों की संख्या अवधारित करेगा। बोर्ड प्रशासनिक निकाय से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित कर्मकारों की संख्या कालिकतः अवधारित करेगा और तदनुसार कर्मकार रजिस्टर के समायोजन की व्यवस्था करेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकृत नियोजक या नियोजकों की समूह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा निमित विनिर्दिष्ट की जाए, आरक्षित पूल में से कर्मकारों का चयन करके मासिक रजिस्ट्रारों के कर्मकारों की संख्या में वृद्धि कर सकेगा।

18. विद्यमान और नए कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण :—(1) (क) ऐसे डाक कर्मकार को, जो स्कीम के प्रारम्भ की तारीख की मुम्बई अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1957 के अधीन पहले से ही सूचीकृत है, इस स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा ;

(ख) नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आयु संबंधी अर्हता ऐसी होगी जो स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा विहित की जाए किन्तु यह चालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी। केवल ऐसे भारतीय राष्ट्रिक हो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, योग्य हैं और जिनके पास अनुभव है, रजिस्ट्रीकरण के पात्र होंगे ;

परन्तु भूतपूर्व सैनिक कामिकों की दशा में आयु-सीमा डाक श्रम बोर्ड द्वारा 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी ;

(ग) किसी नए प्रवर्ग में कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे कर्मकारों में से किया जाएगा जिन्होंने ऐसी तारीख को जिसे इस निमित्त बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, पत्तन पर काम किया है या जो काम कर रहे हैं और रजिस्ट्रीकरण के लिए चयन यथासंभव ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा। जैसा कि किसी कर्मकार द्वारा उस प्रवर्ग में की गयी सेवा की अवधि अवधारित की जाए और बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए। ऐसे मामलों में जहां उक्त ज्येष्ठता सूची उपलब्ध नहीं होती है, चयन ऐसे अन्य आधार पर किया जाएगा जैसी बोर्ड अवधारित करे, परन्तु शर्त यह होगी कि कर्मकार स्वस्थ है और चालीस वर्ष से अधिक नहीं है।

(2) बोर्ड समय-समय पर कर्मकारों और अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिये और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा ;

परन्तु अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत कर्मकार खण्ड 32 के अधीन हाजिरी भरता पाने के हक्कादार होंगे और उनकी वही बाध्यतायें होंगी जो आरक्षित पूल के रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की होती हैं।

(3) किसी प्रवर्ग में जिसमें डाक कर्मकार पहले से ही स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, नई भर्ती, चाहे वह अस्थायी तौर पर हो या स्थायी तौर पर हो, उन कर्मकारों में से की जायेगी जो स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हैं। परन्तु यदि अध्यपेक्षा की तारीख पर रोजगार कार्यालय के रजिस्टर पर उपलब्ध योग्य व्यक्तियों की संख्या से अपेक्षित संख्या से अधिक है तो रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में योग्य व्यक्तियों को आमेलित करने के पश्चात् सीधी भर्ती की जा सकेगी।

(4) खण्ड I के उपखण्ड (i) में मद (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नये कर्मकारों को स्थायी तौर पर रखने से पूर्व तीन मास की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा।

(5) स्कीम के किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, जहां बोर्ड की यह राय हो कि किसी डाक कर्मकार ने अपने आवेदन में मिथ्या जानकारी देकर या उसमें अपेक्षित जानकारी न देकर अपना रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या जहां उसे यह प्रतीत होता है कि कर्मकार अनुचित रूप से या गलत ढंग से रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां अधिवेशनरत बोर्ड रजिस्ट्रारों में से उसके नाम को हटाने के लिये निदेश दे सकेगा ;

परन्तु ऐसा निदेश देने से पूर्व बोर्ड उसे यह हेतुक वसित करने का अवसर देगा कि प्रस्थापित निदेश क्यों न जारी किया जाये।

(6) अन्य प्रवर्गों में, जो स्कीम के प्रारम्भ के पश्चात् अनुसूची I में सम्मिलित किया जाये, रजिस्ट्रीकरण की बाबत निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे—

(क) उपरोक्त प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के किसी कर्मकार को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व बोर्ड, उस प्रवर्ग के कर्मकारों की संख्या का प्राक्कलन करने की दृष्टि से खण्ड 17(i) के अधीन विस्तृत अन्वेषण करेगा जोकि उस प्रवर्ग में जो तत्समय डाक पर कार्य कर रहे हों, सभी सद्मासिक कर्मकारों में से अपेक्षित किये जाने वाले हैं ;

(ख) प्रत्याशित अपेक्षाओं पर आधारित एक अनन्तिम रजिस्टर होगा तथा केवल यह तथ्य कि किसी पत्तन में पहले कोई कर्मकार कार्य करता रहा है उसे रजिस्ट्रीकरण के लिये स्वतः ही हक्कादार नहीं बनायेगा ;

(ग) अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण पूरा करने के पश्चात् उस प्रक्रम पर ऐसी मजदूरियां जो स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों को प्रोद्भूत होती हैं, से भिन्न किन्हीं वित्तीय फायदों को संजूर किये बिना चक्रानुक्रम से प्रारंभ होगी ;

(घ) अनन्तिम रूप से रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों द्वारा प्राप्त वास्तविक नियोजन की दृष्टि में रखते हुए 6 मास के पश्चात् आवश्यकता का पुनर्निर्धारण किया जायेगा तथा तत्पश्चात् अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण को तदनुकूल समायोजित किया जायेगा। खण्ड 32 के अधीन हाजिरी भरने का संवाय तभी प्रारम्भ होगा ;

(ङ) उन दिनों की संख्या जिनके लिये खण्ड 31 के अधीन प्रत्याभूत न्यूनतम मजदूरियां दी जानी चाहियें, नियत करने की दृष्टि से चक्रानुक्रम प्रारम्भ करने के एक वर्ष के पश्चात्

इन परिस्थितियों में कार्यकरण की परीक्षा की जायेगी। उसी समय से आगे के लिये भी कर्मकार स्कीम के अधीन सब फायदों के हकदार होंगे;

(च) किसी मास में दिनों की वह न्यूनतम संख्या जिसके लिये पहले से ही रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के प्रवर्ग के लिये खण्ड 31 के अधीन मजदूरियां प्रत्याभूत हैं वे स्कीम के प्रवर्तन की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत होने वाले प्रवर्गों के कर्मकारों द्वारा स्वतः ही वांछित नहीं की जायेगी।

भिन्न-भिन्न प्रवर्गों की बाबत ऐसे न्यूनतम दिनों की संख्या में अन्तर होगा जैसा कि उपर्युक्त पद (ऊ) के अधीन अवधारित किया गया है;

(छ) उन प्रवर्गों के कर्मकारों जो स्कीम के प्रवर्तन के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किये जायें, की मजदूरियां ऐसे होंगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जायें।

19. कर्मकारों की निवृत्ति आय, प्रोन्नति या स्थानान्तरण :—(1) स्कीम के अधीन निवृत्ति की आय 58 वर्ष होगी :

परन्तु जहां कर्मकारों के किसी प्रवर्ग की बाबत विद्यमान निवृत्ति आय 60 वर्ष है वहां वर्तमान पदधारी के लिये वह पद्धति जारी रहेगी;

(2) किसी आरक्षित पूल रजिस्टर में डाक कर्मकारों के किसी प्रवर्ग में आकस्मिक रिक्ति से भिन्न किसी रिक्ति की पूर्ति सामान्यतया उससे ठीक निम्नले प्रवर्ग के कर्मकारों में से प्रोन्नति द्वारा की जायेगी;

(3) मासिक कर्मकारों के किसी प्रवर्ग में आकस्मिक रिक्ति से भिन्न किसी रिक्ति की पूर्ति उसी नियोजक या नियोजकों के समूह के मासिक कर्मकारों के निम्नतर प्रवर्गों में से प्रोन्नति द्वारा ही या यदि उसी नियोजक या नियोजकों के समूह के मासिक कर्मकारों के निम्नतर प्रवर्गों में से कोई व्यक्ति योग्य नहीं है तो आरक्षित पूल के उसी प्रवर्ग या बरिष्ठ प्रवर्ग के किसी ऐसे डाक कर्मकार, जिसे रजिस्ट्रीकृत नियोजक या नियोजकों के समूह द्वारा चुना जाये, के स्थानान्तरण द्वारा की जायेगी।

स्पष्टीकरण :—प्रोन्नति के लिये साधारणतः निम्नलिखित मापदण्ड होंगे—

(क) उद्येष्टता,

(ख) उस प्रवर्ग में जिसमें प्रोन्नति की जाती है, काम के लिये योग्यता और उपयुक्तता और,

(ग) पिछली सेवा का अभिलेख।

टिप्पण :—आरक्षित पूल रजिस्टर से उसी प्रवर्ग के मासिक रजिस्टर में स्थानान्तरण या उसी प्रवर्ग के मासिक रजिस्टर से आरक्षित पूल रजिस्टर में स्थानान्तरण को प्रोन्नति नहीं समझा जायेगा।

(4) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, पर्याप्त और विधिमान्य कारणों से नियोजक या कर्मकार के लिखित आवेदन पर स्थानान्तरण के कारणों का पूर्णतः स्पष्टीकरण करते हुए, किसी मासिक कर्मकार का स्थानान्तरण आरक्षित पूल में करने की आज्ञा दे सकेगा।

परन्तु यह तब जब कि ऐसा स्थानान्तरण किसी ऐसी संविदा की पूर्ति के अधीन रहते हुए होगा जो नियोजन की समाप्ति की बाबत मासिक कर्मकार और उसके नियोजक के बीच है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई स्थानान्तरण नहीं होगा।

(5) यदि अनुशासनहीनता या अव्यवहार के किसी कार्य के कारण किसी मासिक कर्मकार की सेवाएं नियोजक द्वारा समाप्त की जाती हैं तो

वह आरक्षित पूल में नियोजन के लिये बोर्ड को आवेदन कर सकेगा। बोर्ड की ओर से उपाध्यक्ष तत्पश्चात् मामले के गुणावगुण के आधार पर यह विनिश्चित करेगा कि क्या कर्मकार को नियोजित किया जाना चाहिये या नहीं और यदि ऐसा हो तो उसी या उससे न्यूनतम प्रवर्ग में नियोजित किया जाना चाहिये।

(6) यदि किसी मासिक कर्मकार का स्थानान्तरण या नियोजन, यथास्थिति उपखण्ड 3 या उपखण्ड 4 के अधीन आरक्षित पूल में किया जाता है तो आरक्षित पूल के सभी फायदों के लिये उसकी पिछली सेवा को गिना जायेगा और नियोजक बोर्ड को वे सभी फायदे अन्तरित करेगा जो किसी कर्मकार को पिछली सेवा की बाबत प्रोद्भूत हुए हैं मानों ऐसी सेवा का अन्तरण नहीं किया गया हो। नियोजन विशिष्टतः बोर्ड को ऐसी राशि का अभिदाय करेगा जो कर्मकारों की छुट्टी, भविष्य-निधि या उपदान जो उसे ऐसे अन्तरण की तारीख को देय हो, की बाबत समुचित हो।

20. चिकित्सीय परीक्षा :—(1) रजिस्ट्रीकृत होने से पूर्व किसी नये कर्मकार की शारीरिक स्वस्थता संबंधी चिकित्सा परीक्षा इस प्रयोजन के लिये अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी द्वारा निःशुल्क होगी। चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो कर्मकार चिकित्सीय रूप से अयोग्य पाया जाये वह अध्यक्ष को चिकित्सीय बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिये लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा। अध्यक्ष, ऐसे नियोजन की प्राप्ति पर चिकित्सीय बोर्ड गठित करेगा। चिकित्सीय बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसा कर्मकार जो चिकित्सीय रूप से अयोग्य है, रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार नहीं होगा;

(2) यदि प्रशासनिक निकाय आवश्यक समझता है तो अध्यक्ष द्वारा गठित चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किसी कर्मकार की निःशुल्क चिकित्सा परीक्षा की जायेगी। चिकित्सीय बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा यदि कर्मकार को चिकित्सीय बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य पाया जाये तो अध्यक्ष तत्काल उसकी सेवा समाप्त करेगा।

21. प्रशिक्षण के लिये सुविधाएँ :—डाक कर्मकारों से प्रशिक्षण के लिये बोर्ड ऐसी व्यवस्था करेगा जो वह आवश्यक समझे।

22. रजिस्ट्रीकरण फीस :—स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के समय प्रत्येक कर्मकार द्वारा बोर्ड को दो रुपये रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में संदेय होंगे।

23. काडों का दिया जाना :—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कर्मकार को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूपों में पहचान काडें, हाजिरी काडें और मजबूरी पर्ची निःशुल्क दी जायेगी;

(2) किसी कार्ड के खोजने की वशा में नया कार्ड जाली किया जायेगा किन्तु उसकी लागत जो बोर्ड द्वारा नियत की जायेगी, संबंध कर्मकार द्वारा संदेय होगी।

24. रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के लिये सेवा अभिलेख :—प्रत्येक मासिक और दैनिक कर्मकार के लिये प्रशासनिक निकाय द्वारा ऐसे प्ररूप में सेवा अभिलेख रखा जायेगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट होगा और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मकारों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों का पुरा अभिलेख, प्रोन्नति, प्रच्छेद काम के लिये प्रशंसाएं तथा अन्य बातें होंगी। रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा मासिक कर्मकार की बाबत ऐसे विवरण प्रशासनिक निकाय को दिये जायेंगे।

25. रजिस्ट्रीकृत नियोजकों के लिये अभिलेख पत्र :—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत नियोजक की बाबत कार्मिक अधिकारी ऐसे प्ररूप में अभिलेख पत्र रखेगा

जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये और जिसमें अन्य बातों के साथ साथ रजिस्ट्रीकृत नियोजक के विरुद्ध किये गये प्रशासनिक कार्यवाहियों का पूरा अभिलेख होगा।

26. पहिचान कार्डों का अभ्यर्पण :—कर्मकार का पहिचान कार्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रशासनिक निकाय को अभ्यर्पित किया जायेगा, अर्थात् :—

- (क) जब कि वह तीन या अधिक दिनों की छुट्टी पर जा रहा हो,
- (ख) जब कि वह सेवा निवृत्त हो रहा हो,
- (ग) जब कि उसे पदच्युत किया गया हो या सेवा मुक्त किया गया हो,
- (घ) जब कि उसे अस्थायी रूप से निर्लेखित किया गया हो,
- (ङ०) मृत्यु की वशा में।

परन्तु मासिक कर्मकार का नियोजन भी मद (क), (ङ) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में प्रशासनिक निकाय को कर्मकार का कार्ड अभ्यर्पित करेगा।

27. हाजिरी कार्ड और मजदूरी पर्ची में प्रविष्टि :—(1) आरक्षित पूल का रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार अपना हाजिरी कार्ड उस समय प्रशासनिक निकाय को देगा जब कि उसे किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक को काम के लिये आवंटित हो। कर्मकार द्वारा किये गये काम की अवधि की बाबत हाजिरी कार्ड में प्रशासनिक निकाय आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उसकी नियुक्ति की समाप्ति से पूर्व उसका प्रशासनिक निकाय प्रत्येक दिन के काम के लिये यथासंभव शीघ्र एक मजदूरी स्लिप देगा जिसमें कर्मकार द्वारा उपाजित मजदूरी दिखलाई जायेगी।

(2) मासिक कर्मकार अपने नियोजक को उस समय अपना हाजिरी कार्ड देगा जबकि उसे काम के लिये पत्र आवंटित किया जाता है। उक्त नियोजक कर्मकार द्वारा किये गये काम की अवधि की बाबत कार्ड में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे आवंटित काम के पूरे होने से पहले उसे उसको वापस कर देगा। नियोजक प्रत्येक काम के दिन के लिये यथासंभव शीघ्र एक मजदूरी स्लिप देगा जिसमें कर्मकार द्वारा उपाजित मजदूरियां दिखलाई जायेगी।

28. कर्मकारों का नियोजन : (1) किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक या नियोजकों के समूह से संलग्न किसी विशिष्ट प्रवर्ग का मासिक कर्मकार नियोजक या नियोजकों के समूह द्वारा उस प्रवर्ग में काम पर नियोजित होने का आरक्षित पूल के उसी प्रवर्ग के किसी कर्मकार के अभिमान में हकदार होगा।

(2) यदि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के मासिक रजिस्टर पर कर्मकारों की संख्या उपलब्ध काम के लिये पर्याप्त नहीं है तो उस प्रवर्ग में आरक्षित पूल रजिस्टर के कर्मकारों को नियोजित किया जायेगा।

(3) किसी नियोजक या नियोजकों के समूह के किसी मासिक कर्मकार को अन्य नियोजक या नियोजकों के समूह द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अनुमोदन के बिना नियोजित नहीं किया जायेगा।

29. पारियों में नियोजन :—(1) डाक कर्मकारों को पारियों में नियोजित किया जायेगा।

(2) (क) किसी डाक कर्मकार को सामान्यतः दो आनुक्रमिक दिनों में दो क्रमवर्ती पारियों में नियोजित नहीं किया जायेगा। किसी डाक कर्मकार को किसी भी वशा में तीन क्रमवर्ती पारियों में नियोजित नहीं किया जायेगा।

(ख) आरक्षित पूल में किसी डाक कर्मकार को सप्ताह में 9 पारियों या मास में 33 पारियों से अधिक के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा।

(ग) सामान्यतया किसी मासिक कर्मकार को एक सप्ताह में 6 पारियों से या मास में 27 पारियों से अधिक के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा किन्तु जब आरक्षित पूल से कोई कर्मकार जिसने मद (ख) में परिनिश्चित नियोजन की अधिकतम अवधि पूरी नहीं की है उपलब्ध न हो तब किसी मासिक कर्मकार को सप्ताह में 9 पारियों तक या मास में 33 पारियों तक के लिये नियोजित किया जा सकेगा।

(घ) विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष, मद (ख) और (ग) के अधीन निर्बंधनों की आवश्यक सीमा तक अस्थायी रूप से भिन्न कर सकेगा।

(ङ) एक दिन में एक पारी से अधिक कार्य करने वाले कर्मकार प्रत्येक पारियों में काम के लिये सामान्य प्रमजदूरी की दर पाने के हकदार होंगे।

(3) आरक्षित पूल रजिस्टर के प्रत्येक प्रवर्ग के कर्मकारों को चक्रानुक्रम द्वारा काम आवंटित किया जायेगा।

(4) जहां किसी गैंग द्वारा काम किया जाता है वहां चक्रानुक्रम द्वारा कर्मकारों को आवंटन की गैंगों में होगा।

30. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना : (1) मासिक कर्मकारों की आकस्मिक रिक्तियों को निम्नलिखित रूप से भरा जायेगा, अर्थात् :

(1) जब कोई टिडल गैरहाजिरी रहे तो रिक्ति की पूर्ति नियोजक के नियोजन में अन्य गैंग के टिडल से की जायेगी परन्तु यह तब होगा जबकि टिडल को कोई अन्य काम आवंटित नहीं किया जाता है। यदि ऐसा टिडल उपलब्ध न हो तो काम के लिये उपलब्ध उसी गैंग के ज्येष्ठतम खाद्यान्न हस्त कर्मकार पारी में टिडल के रूप में काम करेगा।

(2) खाद्यान्न हस्तन मजदूरों की रिक्ति की पूर्ति नियोजक के नियोजन में अन्य गैंग के खाद्यान्न हस्तन मजदूरों में की जायेगी, परन्तु यह तब होगा जबकि ऐसा मजदूरों को कोई अन्य काम आवंटित नहीं किया गया है। जब ऐसे कर्मकार उपलब्ध न हों तब आरक्षित पूल के उसी प्रवर्ग के कर्मकारों द्वारा रिक्तियों की पूर्ति की जायेगी।

2. आरक्षित पूल के गैंगों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति निम्नलिखित रूप से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) जब कोई टिडल गैर हाजिर हो, तब हाजिरी पत्र पर किसी टिडल से उस रिक्ति की पूर्ति की जाएगी यदि हाजिरी भत्ते पर कोई टिडल न हो तो काम के लिये उपलब्ध उसी गैंग का ज्येष्ठतम खाद्यान्न हस्तन मजदूर टिडल के रूप में काम करेगा।

(ख) खाद्यान्न हस्तन मजदूरों की रिक्तियों की पूर्ति हाजिर भत्ते पर के खाद्यान्न हस्तन मजदूरों द्वारा या छुट्टी पर आरक्षित कर्मकारों यदि कोई हो, द्वारा की जाएगी।

(ग) उसी गैंग में प्रोक्षित से भिन्न रूप में रिक्तियों की पूर्ति करने में चक्रानुक्रम के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाएगा : परन्तु यह तब जब कि जहां काम किसी गैंग द्वारा किया जा रहा हो वहां चक्रानुक्रम द्वारा कर्मकारों का आवंटन भी गैंगों द्वारा ही होगा।

31. किसी मास में प्रत्याभूत न्यूनतम मजदूरियां :—(1) आरक्षित पूल रजिस्टर में किसी कर्मकार को एक मास में मजदूरी कम से कम 12 दिनों के लिये मजदूरी दर पर दी जाएगी जिसमें उस प्रवर्ग जिसका वह अस्थायी रूप से सदस्य है, के समुचित बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट संहर्षाई भत्ते भी हैं शामिल होंगे चाहे किसी मास में कम से कम 12 दिन के लिये उसे काम

नहीं दिया जाता है। वे दिन जिनको कर्मकार को काम आवंटित किया जाता है, ऊपर लिखित 12 दिनों में गिने जाएंगे किसी काम में प्रत्याभूत न्यूनतम मजदूरियाँ :-

- (क) उन दिनों की संख्या के लिये जिनके लिये किसी मास में मजदूरियाँ प्रत्याभूत की गई हैं, इस गणन के अधीन रहते हुए होंगी कि प्रशासन निकाय द्वारा यथानिर्दिष्ट मास के सभी दिनों पर कर्मकार काम के लिये हाजिर हुआ, या
- (ख) उन दिनों की संख्या जिन दिनों कर्मकार भाग के लिये हाजिर हुआ के भ्रानुपातिक होगी परन्तु यह तब तककि उसे मास के समस्त शेष दिनों पर हाजिरी से माफ किया गया हो।

(2) उपखण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मास में न्यूनतम दिनों की संख्या जिनके लिये मजदूरियाँ प्रत्याभूत की गई हैं, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान खाद्यान्न हस्तान्तरण कर्मकारों के न्यूनतम प्रवर्गों के आरक्षित पूल के कर्मकारों द्वारा प्राप्त मासिक अस्थायी नियोजन के आधार पर नियत की जा सकेगी : परन्तु:—

- (1) किसी भी दशा में इस प्रकार नियुक्त संख्या 21 से अधिक और 12 से कम नहीं होगी,
- (2) भूमि रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1957 के अधीन पहले से ही सूचीकृत कर्मकार उसी न्यूनतम प्रत्याभूत मजदूरी के पात्र बने रहेंगे और जो उन्हें स्कीम के प्रारम्भ के पूर्व अनुज्ञेय थी।

टिप्पण :- औसत नियोजन के निधिरण की पद्धति का व्यौरा अनुसूची 2 में दिया गया है।

(3) उन दिनों की जिनके लिये उपखण्ड (1) और (2) के अधीन मजदूरी प्रत्याभूत होगी, न्यूनतम संख्या उन अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों को जो स्कीम के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हों, स्वतः ही लागू नहीं होगा। उन दिनों की जिनके लिये इन प्रवर्गों को मजदूरी प्रत्याभूत होगी, न्यूनतम संख्या खण्ड 18 (6) (ड) के अधीन अवधारित की जायेगी। उपखण्ड (2) के अधीन दिनों की न्यूनतम संख्या का वार्षिक पुनः नियतन उनके मामले में भी स्वतंत्र रीति से किया जायेगा। स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजन के लिये,

- (क) दिन से एक पारी अभिप्रेत है, और
- (ख) मास में साप्ताहिक छुट्टी के दिन शामिल नहीं होंगे।

32. हाजिरी भत्ता: स्कीम के अन्य उपलब्धों के अधीन रहते हुए आरक्षित पूल रजिस्टर का कर्मकार जो काम के लिये उपलब्ध है किन्तु जिसके लिये कोई काम नहीं पाया जाता है, मंहगाई भत्ते को छोड़कर एक रुपया प्रति दिन की दर से उतने दिनों के लिये जिनके दौरान वह प्रशासनिक निकाय द्वारा यथानिर्दिष्ट काम के लिये हाजिर हुआ था और उसके लिये कोई काम नहीं पाया गया था, हाजिरी भत्ता दिया जायेगा :

परन्तु बोर्ड हाजिरी भत्ते का संवाय मंहगाई भत्ते को छोड़कर दो रुपये से अनाधिक ऐसी उच्चतर दर पर अनुज्ञात कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।

परन्तु यह और कि किसी दिन के लिये जिसके लिये मंहगाई भत्ते सहित पूरी मजदूरी खण्ड 31 या अन्यथा या खण्ड 34 के अधीन दी गई है, कोई हाजिरी भत्ता संवेय नहीं होगा।

33. पारी पर नियोजन: आरक्षित पूल रजिस्टर का कोई कर्मकार एक पारी से कम की अवधि के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा और

जहां वह कार्य जिनके लिये कोई कर्मकार नियुक्त किया गया हो, पारी के कार्यकरण की अवधि के दौरान पूरा हो जाता है, वहां वह ऐसे अन्य काम उसी समय उसी जलयान या किसी अन्य जलयान या वर्ष में जैसा कि उसी नियोजक द्वारा शेष अवधि के लिये अपेक्षित किया जाये, सम्भाल लेगा और यदि ऐसा अन्य काम उसे उपलब्ध न किया जाये तो उसे समस्त पारी के लिये संवाय किया जायेगा :

परन्तु यदि वह रजिस्ट्रीकृत नियोजक और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार के बीच किये किसी करार के अधीन या बोर्ड के किसी विनिश्चय के अनुसार मात्रानुपातिक दर मजदूरी या प्रोत्साहन मजदूरी के अधीन है तो उसमें अधिकृत दरों पर संवाय किया जायेगा।

34. उस दशा में मजदूरियों की संवाय जब कि नियुक्ति के पश्चात् काम उपलब्ध न किया जा सके; जब आरक्षित पूल का कोई कर्मकार काम के लिये हाजिर होता है और किसी कारणवश वह काम जिसके लिये वह हाजिर हुआ है, प्रारम्भ या चालू नहीं किया जा सकता है और उसके लिये कोई दूसरा काम नहीं है, तब वह उस प्रवर्ग जिससे उसका संबंध है, के लिये समुचित मजदूरी दर जिसमें सभी भत्ते भी सम्मिलित होंगे, का हकदार होगा, परन्तु यह तब जबकि पारी के शेष भाग के दौरान वह काम के लिये उपलब्ध रहता है और ऐसा दूसरा नियोजन स्वीकार कर लेता है जो उसे प्रशासकीय निकाय द्वारा दिया गया है :

परन्तु ऐसे कर्मकारी की दशा में जो मजदूरियों की मात्रानुपातिक दर के अधीन है, इस खण्ड के अधीन उसे देय संवाय, यदि कोई हो, में उसी अवधि के बावत किए गए खाली समय के लिए संवाय, यदि कोई हो, की रकम कम की जाएगी।

35. अवकाश दिन : प्रत्येक वर्ष प्रत्येक डाक कर्मकार अवकाश दिनों की ऐसी संख्या वेतन सहित और ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा खण्ड 41 के अधीन निर्दिष्ट किया जाए पाने का हकदार होगा। इस खण्ड के अधीन कोई संवाय उस संवाय को छोड़ कर होगा जो खण्ड 31 के अधीन परिकल्पित है।

36. समितियाँ : बोर्ड एक या अधिक समितियाँ नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह स्कीम के उपबन्धों के अनुपालन को सुकर बनाने के लिए अपने ऐसे कृत्यों को सौंप सकेगा और जिन्हें वह आवश्यक समझे उन्हें समाप्त या पुनर्गठित कर सकेगा। यदि आवश्यक हो तो वह व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्य नहीं है समिति के सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

37. रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की बाध्यताएं : (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार की बावत यह समझा जाएगा कि उसने स्कीम की बाध्यता को स्वीकार कर लिया है।

(2) आरक्षित पूल के किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को जो काम के लिए उपलब्ध रहता है, बोर्ड के नियोजन में समझा जाएगा।

(3) आरक्षित पूल का कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार जो काम के लिए उपलब्ध हो, स्वयं रजिस्ट्रीकृत नियोजक के अधीन नियोजन में तब तक नहीं लगेगा जब तक कि प्रशासकीय निकाय द्वारा उसे उस नियोजक का आवंटित नहीं कर दिया जाता है।

(4) आरक्षित पूल का रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार जो काम के उपलब्ध हो, प्रशासकीय निकाय के निदेशों का पालन करेगा और —

(क) ऐसे काल स्टैंडों या नियंत्रण स्थानों पर ऐसे समयों पर रिपोर्ट करेगा जो प्रशासकीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे काल स्टैंडों या नियंत्रण बिन्दुओं पर —

(1) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रतिधारण भत्ते के संदाय पर उस दशा में जब कि प्रशासकीय निकाय द्वारा इस आशय का अनुदेश किया गया हो पारी की अवधि पर्यन्त रहेगा, या

(2) एक घंटे से अधिक ऐसी अवधि तक रहेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए, और

(ख) वह डाक कार्य से संबंधित कोई नियोजन स्वीकार करेगा, जो वह उस प्रथम में जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत है या उस प्रथम में है जो बोर्ड द्वारा चालू की गई किसी अन्य स्कीमों में रजिस्ट्रीकृत है और जिसके लिए उसे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से उचित समझा गया है।

(5) रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार जो प्रशासकीय निकाय द्वारा नियोजन के लिये किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक के अधीन काम के लिए आवंटित किये जाने पर उपलब्ध रहता है। ऐसे रजिस्ट्रीकृत नियोजक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या पर्यवेक्षक के निदेशों तथा उस पद या स्थान जहाँ वह काम कर रहा है, के नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

38. रजिस्ट्रीकृत नियोजकों की बाध्यताएं : (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत नियोजक स्कीम की बाध्यताओं को स्वीकार करेगा।

(2) खण्ड 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक ऐसे डाक कर्मकार से जिसे खण्ड 11 (ऊ) के उपबन्धों के अनुसरण में प्रशासकीय निकाय द्वारा उसको आवंटित किया गया है, भिन्न कर्मकार को नियोजित नहीं करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत नियोजक प्रशासकीय निकाय द्वारा किये गये इंतजाम के अनुसार अपने खाल और अविष्य भ्रम आवश्यकताओं की बाबत सभी उपलब्ध जानकारी देगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत नियोजक प्रशासकीय निकाय को, जब तक कि अन्यथा निदेश न दिया जाए समय पर या मातानुगतिक त्र पर डाक कर्मकारों द्वारा किये गये काम की विनिर्दिष्टियां तथा ऐसे अन्य सांख्यिकीय आंकड़े देगा जो उसके द्वारा नियुक्त किये गये डाक कर्मकारों की बाबत अपेक्षित हों।

(5) (i) रजिस्ट्रीकृत नियोजक प्रशासकीय निकाय को ऐसी रति से और ऐसे समयों पर जो बोर्ड निदेश दे, खण्ड 52(1) के अधीन संदेय उद्ग्रहण तथा दैनिक कर्मकारों को वेतन सकल मजदूरी देगा।

(ii) रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार कल्याण निधि के प्रति अभिदायों के रूप में संवाय करेगा।

(6) रजिस्ट्रीकृत नियोजक ऐसे अभिलेख रखेगा जिनकी बोर्ड अपेक्षा करे और बोर्ड जहाँ ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें बोर्ड द्वारा पदाभिहित किया जाए, युक्तियुक्त सूचना पर ऐसे अभिलेख रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार और उस काम जिसके लिये उन्हें नियोजित किया गया है से सम्बन्धित अन्य प्रकार के किसी भी दस्तावेजों को पेश करेगा और उनके सम्बन्ध में ऐसी जानकारी देगा जो बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से जारी की गई किसी सूचना या निदेश में वर्णित हो।

39. नियोजन पर निबन्धन : (1) रजिस्ट्रीकृत नियोजक से भिन्न कोई भी व्यक्ति तब तक किसी कर्मकार को न तो डाक कार्य पर नियोजित करेगा और न ही कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक नियोजन के लिये किसी कर्मकार को डाक कार्य पर नियुक्त या नियोजित करेगा जब तक कि वह कर्मकार रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार न हो।

(2) इस खण्ड के पुर्बगामी उपबन्धों के होते हुए भी :—

(क) जहाँ प्रशासकीय निकाय का समाधान हो जाता है कि—

(1) डाक कार्य का शीघ्रता से किया जाना अपेक्षित है,

(2) उस कार्य के लिये कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार पाना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है,

जहाँ प्रशासकीय निकाय बोर्ड द्वारा अधिरोपित किन्ही सीमाओं के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को जो कि रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक को आवंटित कर सकेगा ऐसे कर्मकारों का चयन करने में स्थानीय रोजगार कार्यालय संगठन से सहायसम्भव परामर्श किया जाएगा,

परन्तु जब कभी किन्ही अरजिस्ट्रीकृत कर्मकारों को नियोजित किया जाना हो तब यदि सम्भव हो तो प्रशासकीय निकाय ऐसे कर्मकारों के नियोजन की बाबत अध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा और जहाँ तक सम्भव न हो वहाँ 24 घंटे के भीतर अध्यक्ष को उस समस्त परिस्थितियों की बाबत रिपोर्ट देगा जिसके अधीन ऐसे कर्मकारों को नियोजित किया गया था और अध्यक्ष अगले अधिवेशन में ऐसे नियोजन की बाबत बोर्ड को सम्यक्ता सूचित करेगा।

(ख) बोर्ड ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, उस दशा में किसी अवकाश दिन को रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों की नियोजित करने की अनुज्ञा उस सीमा तक देगा जिस सीमा तक काम के लिये रजिस्ट्रीकृत कर्मकार उपलब्ध न हों। और जब कि डाक कार्य का उसी दिन किया जाना आवश्यक हो,

(ग) मग (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट काम की दशा में खण्ड 38 (4), (5) और (6) और खण्ड 41 के प्रयोजनों के लिये रजिस्ट्रीकृत नियोजक द्वारा उपर्युक्त रूप में नियोजित व्यक्तियों को उस डाक कार्य की बाबत ऐसा माना जाएगा मानो वह दैनिक कर्मकार हो।

(3) आरक्षित पूल का कोई रजिस्ट्रीकृत कर्मकार, यदि वह खण्ड 37 के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूर्ण रूप से पूरा करता है, उन दिनों में जिन दिनों उसे प्रशासकीय निकाय द्वारा काम के लिये आवंटित न किया गया हो, स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नियोजकों से भिन्न नियोजकों के अधीन आकस्मिक नियोजन ग्रहण कर सकेगा।

40. वे परिस्थितियां जिनमें स्कीम का लागू होना बन्द हो जाता है :

(1) स्कीम का रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को लागू होना उस दशा में बन्द हो जाएगा जबकि उसका नाम स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण में रजिस्टर या अभिलेख से हटा दिया गया है।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक को स्कीम का लागू होना उस दशा में बन्द हो जाएगा जब कि स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण में उसका नाम नियोजक रजिस्टर से हटा दिया गया है।

(3) इस खण्ड की कोई भी बात ऐसे किसी समय जबकि वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार या रजिस्ट्रीकृत नियोजक था, के दौरान उपगत बाध्यता या प्रोद्भूत अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

41. कर्मकारों की मजदूरी भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें : नियोजक और रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के बीच किये गए किसी करार के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्कीम में जब तक कि उसके लिये विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबन्धित नहीं किया गया है, किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (चाहे वह आरक्षित पूल का हो या मासिक रजिस्टर का) और रजिस्ट्रीकृत नियोजक के बीच संविदा की विवक्षित शर्तें होंगी कि—

(क) मजदूरी भत्ते और अतिरिक्त काम की दरें, काम के घंटे, आराम अन्तराल, अवकाश दिन और उनकी बाबत वेतन और

सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो कर्मचारियों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी;

(ख) मजदूरी अवधि का नियतन मजदूरी के संदाय का समय और मजदूरी में कटौतियाँ मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के उपबन्धों के अनुसरण में होगी।

42. नियोजन या अधूरे नियोजन की बावत मंहगाई भत्ता, मजदूरी और अन्य भत्तों के बकाए का संदाय : (1) इस खण्ड और खण्ड 43 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए जब किसी मजदूरी अवधि के दौरान आरक्षित पूल का कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार काम के लिये उपलब्ध है किन्तु उसे कोई नियोजन या पूर्ण नियोजन नहीं किया जाता, तो वह बोर्ड से ऐसी रकम जो खण्ड 31, 32 और 34 के अधीन उसे अनुशेष हो, पाने का हकदार होगा।

(2) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार का उक्त संदाय, यदि कोई हो, बोर्ड से पाने का हकदार है वे शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(क) यह कि वह काल स्टेप्सों या नियंत्रण स्थानों पर निर्देशानुसार हाजिर हुआ था; और

(ख) यह कि उसकी हाजिरी अभिलिखित की गई थी।

(3) रजिस्ट्रीकृत नियोजक और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के बीच किये गए किसी करार या बोर्ड के किसी विनिश्चय या बोर्ड या बनाए गए किसी निकाय की सिफारिश या केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गए किसी आदेश के अनुसरण में भूलभरी प्रभाव से मंहगाई भत्ता या पुनरीक्षित मजदूरी की मंजूरी या अन्य भत्तों की पुनरीक्षण की दशा में, बोर्ड अपनी निधियों में से रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों को रजिस्ट्रीकृत नियोजक और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के बीच किये गए किसी करार या यथास्थिति बोर्ड के किसी विनिश्चय या सिफारिश या आदेश की तारीख तक उस दशा में बकाया दे सकेगा जब कि बोर्ड ऐसा विनिश्चय करे।

43. संदाय से वंचित करना : (1) आरक्षित पूल का कोई रजिस्ट्रीकृत कर्मकार जो खण्ड 37(4)(क) या (ख) के उपबन्धों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है या बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से विधिपूर्ण आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उनके विरुद्ध उपखण्ड (3) के अनुसरण में कार्यवाई की जा सकेगी।

(2) आरक्षित पूल का कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार जो उस नियोजन में रहते हुए जिसमें प्रशासनिक विकास द्वारा उसको आवंटित किया गया था, खण्ड 37(5) के उपबन्धों का पर्याप्त कारणों के बिना पालन करने में असफल रहता है या अपने नियोजक द्वारा दिये गए किन्हीं विधिपूर्ण आदेशों का पालन करने में असफल रहता है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी और उसे आरक्षित पूल को वापस भेज दिया जाएगा और श्रम अधिकारी को लिखित रूप में यह रिपोर्ट की जा सकेगी कि क्या उसे उस प्रकार वापस किया गया है या नहीं। जब किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को आरक्षित पूल में इस प्रकार वापस भेजा जाता है तब प्रशासनिक निकाय उसके हाजिरी कार्ड को तबतक पूर्णतः निलंबित करेगा।

(3) श्रम अधिकारी खण्ड 1 और 2 के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी मामले पर विचार करेगा और यदि मामले की अन्वेषण करने के पश्चात् वह रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को अधिसूचित करता है कि उसका समाधान हो गया है कि रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों ने उपर्युक्त प्रकार को विधिपूर्ण आदेश का पालन नहीं किया है तो वह रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार संदाय या खण्ड 42 के अधीन किसी संदाय का कोई भाग पाने का हकदार नहीं होगा जैसा कि उस मजदूरी अवधि की बावत जिसके दौरान ऐसी असफलता हुई या खालू रहती है, श्रम अधिकारी उचित समझता है।

44. अनुशासनिक प्रक्रिया : (1) (1) कामिक अधिकारी, जो शिकायत पर या अन्यथा सूचना पाने पर कि रजिस्ट्रीकृत नियोजक स्कीम के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहा है, मामले में अन्वेषण करने के पश्चात् लिखित रूप में उसे चेतावनी दे सकेगी, या

(2) जहां उसकी यह राय हो कि अधिकतम शक्ति उचित है, वहां वह मामले की रिपोर्ट उपाध्यक्ष को करेगा जो तत्पश्चात् ऐसा अतिरिक्त अन्वेषण करवाएगा जिसे वह आवश्यक समझे और उस नियोजक के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कार्य कदम उठा सकेगा, अर्थात् वह :—

(क) उसकी परिनिष्ठा कर सकेगा तथा उसकी अभिलेख पत्र में परिनिष्ठा अभिलिखित कर सकेगा; या

(ख) बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए तथा रजिस्ट्रीकृत नियोजक को लिखित रूप में एक मास की सूचना देने के पश्चात् प्रशासनिक निकाय को सूचित कर सकेगा कि नियोजक का नाम नियोजक रजिस्टर से ऐसी अवधि के लिये जो बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए, या गम्भीर अपराध की दशा में स्थाई रूप से हटा दिया जाएगा।

(2) आरक्षित पूल का रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार जो, स्कीम के किसी उपबन्ध का पालन करने में असफल रहता है या अनुशासनहीनता या अव्यवहार का कोई कार्य करता है, की बावत श्रम अधिकारी को लिखित रूप में रिपोर्ट की जा सकेगी, जो मामले में अन्वेषण करने के पश्चात् उस कर्मकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठा सकेगा, अर्थात् वह

(क) यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझता हो वह कर्मकार खण्ड 42 के अधीन कोई संदाय का भाग पाने का हकदार नहीं होगा।

(ख) लिखित रूप में यह चेतावनी दे सकेगा; या

(ग) उसे तीन दिन से अधिक अवधि के लिये बिना वेतन के निलम्बित कर सकेगा।

(3) (क) जहां उपखण्ड 2 के अधीन श्रम अधिकारी को रिपोर्ट किये गए मामले में उसकी यह राय है कि अनुशासनहीनता या अव्यवहार का कार्य दृष्टान्त गम्भीर है कि डाक कर्मकार को अपने काम के लिये अनुशासित नहीं करना चाहिये तो श्रम अधिकारी मामले का अन्वेषण संज्ञित रहते के दौरान उस कर्मकार को निलंबित कर सकेगा और उपाध्यक्ष को अतिरिक्त रिपोर्ट कर सकेगा जो मामले में प्राथमिक अन्वेषण करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा कि कर्मकार को अन्तिम आदेश देने तक निलंबित रखा जाए या नहीं।

(ख) जहां कोई डाक कर्मकार मद (क) के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित किया गया हो वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम 90 दिन के लिये उसे निर्वाह भत्ता, आधार्मिक मजदूरी, मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तों के आदेश के बराबर जिनका वह उस दशा में हकदार होता जब कि वह मजदूरी सहित छुट्टी पर रहता, के आधे के बराबर निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा और तत्पश्चात् उपाध्यक्ष विनिश्चित मामले में ऐसे आधार्मिक मजदूरी या अन्य भत्तों के तीन चौथाई से अधिक उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा।

परन्तु जहां ऐसी जांच कर्मकार के प्रत्यक्ष कारणों से 90 दिन की अवधि के पश्चात् भी खालू रहती है वहां 90 दिन से अधिक अवधि के लिये निर्वाह भत्ता से आधार्मिक मजदूरी के मंहगाई या अन्य भत्तों के एक चौथाई रकम की कटौती की जाएगी।

(ग) इस प्रकार संदेन निर्वाह भत्ता किसी भी वषा में वसूलीय या समयपरणीय नहीं होगा।

(घ) जहाँ किसी डाक कर्मकार को बोधी नहीं पाया जाता है, वहाँ वह ऐसा संदाय पाने का हकदार होगा जिनके बारे में प्रमाणित करता है कि यदि डाक कर्मकार को निलंबित नहीं किया जाता तो वह बाल दर के आधार पर या खण्ड 32 के अधीन उसे प्राप्त करता, परन्तु इस प्रकार संदेय रकमों में किसी विशिष्ट अवधि के दौरान या पहले से ही संदेन निर्वाह भत्ता की रकम की कमी की जाएगी।

(4) जहाँ श्रम अधिकारी की यह राय है कि उपखण्ड (2) और (3) में उपबिन्दित वण्ड के उच्चतर वण्ड देना उचित है, वहाँ मामले की रिपोर्ट उपाध्यक्ष को पेश करेगा।

(5) उपखण्ड 4 के अधीन श्रम अधिकारी से या नियोजकों या किसी अन्य व्यक्ति से यह रिपोर्ट पाने पर कि आरक्षित पूल का रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार स्कीम के किन्हीं उपबन्धों का पालन करने में असफल रहा है या उसने अनुशासनहीनता या अव्यवहार का कार्य किया है या वह मानक या प्रमाण का काम मात्रा पूरी करने में लगातार असफल रहा है या किसी अन्य रीति से अक्षम रहा है, तो उपाध्यक्ष ऐसा अतिरिक्त अन्वेषण कर सकेगा या करवा सकेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् सम्बद्ध कर्मकार की बाबत निम्नलिखित कदमों में से कोई कदम उठा सकेगा अर्थात् वह निम्नलिखित शक्तियों में से कोई शास्त्र अधिरोपित कर सकेगा :—

(क) यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसी अवधि के लिये जो वह ठीक समझता है कर्मकार खण्ड 42 के अधीन किसी संदाय या संदाय का भाग पाने का हकदार नहीं होगा।

(ख) लिखित रूप में उसे चेतावनी दे सकेगा।

(ग) तीन मास में अनधिक अवधि के उसे घेतन के बिना निलंबित कर सकेगा।

(घ) चौदह दिन कम सूचना देकर, या उसके बरबस चौदह दिनों की मजदूरी जिसमें संहवाई भत्ता भी सम्मिलित है, देकर उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा।

(ङ) पदच्युत कर सकेगा।

(6) इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को यह दशित करने का अवसर दिया जाएगा कि उसके विरुद्ध क्यों न प्रस्थापित कार्यवाही की जाए और ऐसा व्यक्ति, यदि वह ऐसी बांछा करता है ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में साक्ष्य दे सकेगा।

(7) प्रशासनिक निकाय को इस खण्ड के अधीन की गई कार्यवाही की बाबत माध-माध सूचित किया जाएगा।

(8) इस खण्ड और खण्ड 43 में अन्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी में निहित शक्तियों उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भी ऐसे मामले में प्रयुक्त की जा सकेंगी जैसी कि पूर्व वर्णित प्राधिकारी इस निमित्त लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करे।

सारणी

कार्यवाही करने के लिये मणन प्राधिकारी	स्कीम के उपबन्ध	विनिर्दिष्ट मामलों में कार्यवाही करने के लिये मणन प्राधिकारी
श्रम अधिकारी	खण्ड 13 और 44	प्रशासनिक निकाय
कार्मिक अधिकारी	खण्ड 44	उपाध्यक्ष या अध्यक्ष
उपाध्यक्ष	खण्ड 44	अध्यक्ष

(9) खण्ड 45 या 51 के अधीन अध्यक्ष की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रजिस्ट्रीकृत डाक नियोजक को अपने अधीन नियोजित मामिक कर्मकारों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

45- अध्यक्ष की विशेष अनुशासनिक शक्तियाँ: (1) इस स्कीम में किसी बान के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के किसी गैंग या किसी विशिष्ट कर्मकार द्वारा 'कार्य मंवन रीति' का सहारा लिया गया है या लिया जा रहा है या कर्मकार को उसी गैंग द्वारा या विभिन्न गैंगों या उसी या विभिन्न पोटों के कर्मकारों द्वारा उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है तो वह इस घ्राणय की लिखित रूप में घोषणा कर सकेगा।

(2) जब उपखण्ड (1) के अधीन घोषणा की जाती है तब अध्यक्ष के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह—

(1) मासिक कर्मकारों की दशा में रजिस्ट्रीकृत नियोजकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे कर्मकारों के विरुद्ध पदच्युति सहित ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करे जो वह ठीक समझे; ।

(2) आरक्षित पूल के डाक कर्मकारों की दशा में ऐसे कर्मकारों के विरुद्ध पदच्युति सहित ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही की जो वह ठीक समझे तथा उनको गारंटीकृत न्यूनतम मजदूरी या उस मजदूरी अवधि या उन मजदूरी अवधियों जिनके दौरान 'कार्यमन्दन प्रवृत्ति' का सहारा लिया गया है, के लिए हाजिरी भत्ते के समग्रहण का आदेश करे।

(3) अध्यक्ष निम्नलिखित दशाओं में अनुशासनिक कार्यवाही कर सकेगा :—

(i) जहाँ किसी गैंग द्वारा 'कार्य मन्द प्रवृत्ति' का सहारा लिया जाता है वहाँ उस गैंग के सभी सदस्यों के विरुद्ध; और

(ii) जहाँ किसी विशिष्ट कर्मकार द्वारा 'कार्य मन्दनप्रवृत्ति' का सहारा लिया जाता है वहाँ संबंध कर्मकार के विरुद्ध।

(4) इस खण्ड के अधीन किसी डाक कर्मकार या डाक कर्मकारों के गैंग के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने से पूर्व ऐसे कर्मकार या गैंग को यह दशित करने का अवसर दिया जाएगा कि उसके विरुद्ध प्रस्थापित कार्यवाही क्यों न की जाए:

परन्तु अध्यक्ष इस उपखण्ड के अधीन कारण दशित करने का अवसर देने से पूर्व किसी कर्मकार या कर्मकारों के गैंग को उपखण्ड 1 के अधीन घोषणा करने के तुरन्त पश्चात् निलंबित कर सकेगा।

(5) (क) जहाँ किसी कर्मकार को जांच के दौरान निलंबित किया गया है वहाँ उसे निलंबन की तारीख से प्रथम 90 दिन के लिए उसे आधारीक मजदूरी, संहवाई और अन्य भत्तों के जिनका वह उस दशा

में हकदार होता जब कि वह छुट्टी पर रहता, के आर्ध के बराबर निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और भत्तावात अध्याक्ष विनिर्दिष्ट मामले में ऐसे आध्याक्ष मजदूरी मंहगाई या भत्ते के तीन-चौथाई से अधिक उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा :

परन्तु जहां कर्मकार के प्रत्यक्ष कारणों से ऐसी जांच 90 दिन के पश्चात विस्तारित होगी है वहां 90 दिन से अधिक अवधि में निर्वाह भत्ते की आध्याक्ष मजदूरी और अन्य भत्तों की एक चौथाई रकम की कमी की जाएगी ।

(ख) इस प्रकार दिए गए निर्वाह भत्ते किसी भी दशा में वसूलीय या समपहुरणीय नहीं होंगे ।

(ग) जहां किसी डाक कर्मकार को दोषी नहीं पाया जाता है वहां अपने-अपने निलम्बन की बाबत वह ऐसे संदाय पाने का हकदार होगा जिनके बारे में प्रशासनिक निकाय प्रमाणित करे कि यदि कर्मकार को निलम्बित न किया जाता तो वह काल दर के आधार पर या खण्ड 32 के अधीन उन्हें पाना :

परन्तु इस प्रकार देय रकमों में उस अवधि के दौरान पहले से ही संदत निर्वाह भत्ते की रकम कम कर दी जाएगी ।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत कर्मकार जो उपखण्ड 2 के अधीन अध्यक्ष के किसी आदेश से व्यथित है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

46. नियोजन की समाप्ति : (1) आरक्षित पूल के किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार के नियोजन को इस स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण के सिवाय समाप्त नहीं किया जाएगा ।

(2) आरक्षित पूल के रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार, बोर्ड को 14 दिन की लिखित सूचना या उसके बक्से मंहगाई भत्ते सहित 14 दिन की मजदूरी का समपहुरण कराए बिना बोर्ड में अपने नियोजन का त्याग नहीं करेगा ।

(3) जब बोर्ड द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार का नियोजन उपखण्ड (1) या (2) के अधीन समाप्त हो जाता है तब प्रशासनिक निकाय द्वारा रजिस्टर या अभिलेख से उसका नाम तत्काल हटा दिया जाएगा ।

47. कर्मकारों द्वारा अपील :—(1) इस खण्ड में उपबंधित में अन्यथा के सिवाय आरक्षित पूल का कोई कर्मकार जो निम्नलिखित कारणों के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त कारणों के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन पारित आदेश से व्यथित है, उक्त कारणों के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा ।

सारणी

आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी	स्कीम के उपबन्ध	अपील प्राधिकारी
अन्य अधिकारी या प्रशासनिक निकाय	खण्ड 43 या 44	उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष	खण्ड 44	अध्यक्ष
अध्यक्ष	खण्ड 44	केन्द्रीय सरकार

(2) कोई कर्मकार जो ऐसे आदेश से व्यथित है --

- जिसके द्वारा उसे रजिस्टर या अभिलेख में किसी विनिर्दिष्ट समूह में रखा गया है ; या
- जिसके द्वारा खण्ड 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया गया है ; या
- जिसके द्वारा उससे खण्ड 37(4)(ख) के अधीन ऐसा कोई कार्य करने की अपेक्षा की गई है जो उस प्रवर्ग का नहीं है जिसका वह है,

अध्यक्ष को अपील कर सकेगा ।

(3) कोई डाक कर्मकार जो खण्ड 19(4) के अधीन आदेश से व्यथित है अध्यक्ष को अपील कर सकेगा ।

(4) जहां बोर्ड के अनुदेशों के अनुसरण में रजिस्टर या अभिलेख से किसी रजिस्ट्रीकृत कर्मकार का नाम हटाने की बाबत सम्यक सूचना दी गई है वहां उस दशा में कोई अपील नहीं होगी जबकि हटाए जाने का आधार यह है कि रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार डाक कर्मकारों के ऐसे वर्ग या वर्णन में आता है जिनका नाम उनकी संख्या में कमी करने के उद्देश्य से रजिस्टर से या अभिलेख से हटाया जाता है :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार यह अभिकथित करता है कि वह डाक कर्मकारों के उस वर्ग या वर्णन का सदस्य नहीं है जिसे बोर्ड के अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां वह अध्यक्ष को अपील होगी ।

(5) उपखण्ड (1) (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्राप्ति के 14 दिन के भीतर की जाएगी :

परन्तु अपील प्राधिकारी लिखित कारणों के आधार पर 14 दिन की समाप्ति के पश्चात, की गई अपील को ग्रहण कर सकेगा ।

(6) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को मुनबाई का अवसर देने के पश्चात्, यदि उसकी यह इच्छा हो तो लिखित कारणों के आधार पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझता है ।

(7) उपखण्ड (6) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश अपीलार्थी को समूचित किया जाएगा ।

(8) अपीलार्थी अपील प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने का हकदार नहीं होगा किन्तु वह उस पर रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ जिसका वह सदस्य है, के प्रतिनिधि या किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार द्वारा प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा ।

48- नियोजकों द्वारा अपील : (1) (क) रजिस्ट्रीकृत नियोजक जो कार्मिक अधिकारी के खण्ड 44(1) (i) के अधीन किसी आदेश से व्यथित है, उपाध्यक्ष को अपील कर सकेगा जो उसका विनिश्चय करेगा ।

(ख) यदि रजिस्ट्रीकृत नियोजक उपाध्यक्ष के खण्ड 44 (i) (ii) के अधीन आरम्भिक आदेश से व्यथित है तो वह अध्यक्ष को अपील कर सकेगा जो उसका विनिश्चय करेगा खण्ड 44(i) (ii) (ख) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, अध्यक्ष मामले को तुरन्त केन्द्रीय सरकार को निविष्ट करेगा । केन्द्रीय सरकार अपील में ऐसा आदेश करेगी जैसा वह ठीक समझती है ।

(2) वह नियोजक जिसे खण्ड 15(i)(ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से हटका दिया गया है, अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगी। केन्द्रीय सरकार ऐसा आदेश करेगी जैसा वह ठीक समझती है।

(3) यदि खण्ड 44 के अधीन अध्यक्ष द्वारा अपने विरुद्ध पारित किसी आदेशिक आदेश में कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक व्यथित है तो वह केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगी। अपील में केन्द्रीय सरकार ऐसा आदेश करेगी जैसा वह ठीक समझती है।

(4) उपखण्ड (1) (2) और (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्राप्ति के 14 दिन के भीतर की जायेगी :

परन्तु अपील प्राधिकारी लिखित कारणों से 14 दिन की समाप्ति के पश्चात् की गई अपील ग्रहण कर सकेगा।

(5) कोई अपीलार्थी अपील प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व पाने का हकदार नहीं होगा किन्तु वह उस रजिस्ट्रीकृत नियोजक संगम जिसका वह सदस्य है, के प्रतिनिधि द्वारा या किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक द्वारा प्रतिनिधित्व पाने का हकदार होगा।

49-अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पुनरीक्षण की शक्ति : स्कीम में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, खण्ड 44 के अधीन उपाध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, अध्यक्ष या उक्त खण्ड के अधीन कार्मिक अधिकारी या श्रमिक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में उपाध्यक्ष किसी भी समय किसी भी कार्यवाही जिसमें, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या कार्मिक अधिकारी या श्रमिक अधिकारी ने आदेश पारित किया है, का अभिलेख उसकी वैधता या श्रौचित्य की बाबत अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए माग सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

7 परन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना इस खण्ड के अधीन ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

50-कृतिपय अपीलों की दशा में स्थगन आदेश : जहां किसी डाक कर्मकार द्वारा 14 दिन की सूचना पर सेवा की समाप्ति के किसी आदेश के विरुद्ध खण्ड 47 के उपबन्धों के अनुसरण में अपील की जाती है पर खण्ड 44(i) (ii) (ख) के अधीन नियोजक रजिस्ट्रार से उसका नाम हटाये जाने के आदेश के विरुद्ध खण्ड 49 के उपबन्धों के अनुसरण में किसी नियोजन द्वारा अपील की जाती है, वहां अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई और निपटारा होने तक उस आदेश का प्रवर्तन जिसके विरुद्ध अपील की गई है, निलम्बित कर सकेगा।

51-आपात की दशा में कार्यवाही के लिए विशेष उपबन्ध : (1) यदि किसी भी समय अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि आपात की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे पतन के कार्यकरण पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ेगा तो वह लिखित आदेश द्वारा और ऐसी अवधि के लिये जो वह समय समय पर उसमें विनिर्दिष्ट करे, इस आशय की घोषणा कर सकेगा,

परन्तु ऐसी कोई घोषणा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी।

(2) जब तक उपखण्ड (i) के अधीन आदेश प्रवृत्त रहती है तब तक निम्नलिखित उपलब्ध लागू होंगे, अर्थात् :—

(i) यदि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि रजिस्ट्रीकृत नियोजक स्कीम के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहा है तो

अध्यक्ष उस आरोप की बाबत संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् उस नियोजक के बारे में निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकेगा, अर्थात्, वह

(क) लिखित रूप में रजिस्ट्रीकृत नियोजक को चेतावनी दे सकेगा ;

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि नियोजक रजिस्ट्रार से या तो स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो वह अवधारित करे, रजिस्ट्रीकृत नियोजक का नाम तुरन्त हटाया जाएगा;

परन्तु उपमव (ख) के अधीन इस प्रकार का हटाया जाना नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जाएगा।

(ii) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार के विरुद्ध अनुशासनहीनता, 'कार्यमंदन' या अवधार का आरोप लगाया जाता है तो अध्यक्ष जांच के लंबित रहने तक उसे तुरन्त निलंबित कर सकेगा। आरोप की बाबत संक्षिप्त जांच कर सकेगा और उस कर्मकार के विरुद्ध निम्नलिखित में से एक या अधिक कदम उठा सकेगा, अर्थात्, वह

(क) यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझता है, वह कर्मकार खण्ड 42 के अधीन कोई संदाय पाने का अधिकारी नहीं होगा ;

(ख) उसे लिखित रूप में चेतावनी दे सकेगा ;

(ग) तीन मास से अधिक अवधि के लिए बिना वेतन के उसे निलंबित कर सकेगा ;

(घ) 14 दिन की सूचना और उसके बदले मंहगाई भत्ते सहित 14 दिन की मजदूरी देकर उसकी सेवायें समाप्त कर सकेगा ; या

(ङ) उसे पदच्युत कर सकेगा ;

परन्तु उपमव (घ) के अधीन सेवा समाप्ति या उपमव (ङ) के अधीन पदच्युति, कर्मकार की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं की जायेगी।

(iii)(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लंबित होने के दौरान निलंबित किया जाता है वहां उसे निलंबन की तारीख से 90 दिन के लिए प्राधारित मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के जिनका वह उस दशा में हकदार हो तो जब कि वह वेतन सहित छुट्टी पर रहता, के आधे के बराबर निर्वाह भत्ता संवत् किया जाएगा और तत्पश्चात् अध्यक्ष विनिर्दिष्ट मामलों में ऐसे प्राधारिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों की तीन-चौथाई से अधिक उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा,

परन्तु जहां कर्मकार के प्रत्यक्ष कारणों से ऐसी जांच 90 दिन की अवधि के पश्चात् विस्तारित की जाती है वहां 90 दिन से अधिक निर्वाह भत्ते में प्राधारिक मजदूरी, मंहगाई या अन्य भत्तों के एक-चौथाई रकम की कमी की जाएगी।

(ख) इस प्रकार संवत् निर्वाह किसी भी दशा में वसूलीय या रामपहणीय नहीं होगा ;

(ग) जहां किसी डाक कर्मकार को दोषहीन पाया जाता है वहां वह अपने निलंबन की अवधि की बाबत ऐसे संदाय पाने का हकदार होगा जिनकी बाबत प्रशासनिक निकाय यह प्रमाणित करे कि यदि कर्मकार को निलंबित नहीं किया जाता तो वह कालांतर के आधार पर या खण्ड 32 के अधीन उन्हें पाता,

परन्तु इस प्रकार संवेय रकम में उस अधि के दौरान पहले से ही संवत निर्वाह करने की रकम की कटौती की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मचारों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित स्कीम के उपबन्ध उपखण्ड (2) के अधीन अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश को लागू नहीं होंगे।

(4) कोई भी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार या रजिस्ट्रीकृत नियोजक जो उपखण्ड 2 के अधीन अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(5) स्कीम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक उपखण्ड (1) के अधीन आदेश प्रवृत्त रहता है, अध्यक्ष रजिस्ट्रीकृत नियोजकों को सीधे ही रजिस्ट्रीकृत कर्मकार को संदत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

52-स्कीम के प्रचालन की लागत: (1) स्कीम के प्रचालन की लागत को व्यय रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा बोर्ड को किए गए संदाय द्वारा चुकाया जाएगा। प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत नियोजक बोर्ड को आरक्षित पूल के कर्मचारों की बाबत खण्ड 38(5)(1) के अधीन उससे शोध्य सकल मजदूरियों का संदाय जिसे बोर्ड समय समय पर रजिस्ट्रीकृत नियोजकों को लिखित सूचना देकर विनिर्दिष्ट करे, सहित तथा उद्ग्रहण के रूप में संदत करेगा। ऐसे उद्ग्रहण के रूप में संदत रकम ऐसी रकम से कम न होगी जिसे बोर्ड प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत नियोजक द्वारा संवेय रकम के रूप में नियत करे। यदि आवश्यक समझा जाए तो बोर्ड किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि मासिक कर्मकार की बाबत ऐसी दर पर जैसी वह अवधारित करे उद्ग्रहण के रूप में ऐसी रकम संदत करे।

(2) यह अवधारित करने में कि रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा उपखण्ड (1) के अधीन कौन से संदाय किए जाने हैं, बोर्ड विभिन्न काम या कर्मकार के प्रवर्गों की विभिन्न दरें विहित कर सकेगा, परन्तु उद्ग्रहण इस प्रकार नियत की जाएगी कि सभी डाक नियोजकों, जो समान परिस्थितियों में हों, को उद्ग्रहण की एक ही दर लागू हो।

(3) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दैनिक मजदूरी दर के आधार पर प्राक्कलित कुल मजदूरी बिल के शत-प्रतिशत से अधिक मंजूर नहीं करेगा।

(4) मांग पर रजिस्ट्रीकृत नियोजक उपखण्ड (1) में निश्चित रकम का निक्षेप द्वारा बोर्ड को संदाय करेगा या उसके सम्यक संदाय के लिए ऐसी अन्य प्रतिभूति की व्यवस्था करेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(5) प्रशासनिक निकाय समय-समय पर बोर्ड को ऐसे आंकड़े और अन्य जानकारी देना जो स्कीम के प्रचालन और वित्त पोषण के सम्बन्ध में युक्तिमत् रूप से अग्रहित हों।

(6) यदि रजिस्ट्रीकृत नियोजक उपखण्ड (1) के अधीन देय संदाय या अन्य देय रकम जो किसी अन्य हेतियत में बोर्ड को संदेय हो या प्रशासनिक निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो प्रशासनिक निकाय नियोजक को इस आशय को एक सूचना तामील करेगा, जब तक वह सूचना की प्राप्ति तारीख से तीन दिन के भीतर देय संदाय नहीं कर देता है तब तक उसे रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मचारों का दिया जाना निलंबित रहेगा। सूचना अधि की समाप्ति पर प्रशासनिक निकाय व्यक्तिगती नियोजक को रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार देना तब तक निलंबित रखेगा जब तक उपर्युक्त देय का संदाय नहीं कर दिया जाता है।

53-भविष्यनिधि, उपदान और स्वैच्छिक निवृत्ति निधि: (1) रजिस्ट्रीकृत नियोजक और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मचारों के बीच किए गए किसी करार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आरक्षित पूल के कर्मचारों की बाबत बोर्ड और अपने मासिक कर्मचारों की बाबत रजिस्ट्रीकृत नियोजक अभिदायी भविष्यनिधि की दर की व्यवस्था होगी। ये नियम कर्मचारों और नियोजकों की अभिदाय दर, संदाय की रीति और पद्धति और ऐसी अन्य बातों के जो आवश्यक समझी जाएं, के बारे में व्यवस्था करेंगे:

परन्तु मासिक कर्मचारों को लागू होने वाले नियम आरक्षित पूल के कर्मचारों से संबंधित नियमों से कम अनुकूल नहीं होंगे।

(2) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मचारों के बीच किए गए करार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड रजिस्ट्रीकृत कर्मचारों को उपदान के लिए जाने के लिए नियम बना सकेगा।

(3) यदि आवश्यक हो तो बोर्ड स्वैच्छिक निवृत्ति निधि के लिए यथोचित उपबन्ध कर सकेगा और उसके लिए नियम बना सकेगा।

54-डाक कर्मकार कल्याण निधि: डाक कर्मकार कल्याण निधि के नाम से ज्ञात सुखसुविधाएं, कल्याण और स्वास्थ्य उपायों की लागत का खर्च बोर्ड द्वारा चलाया जाएगा। इस निधि में अभिदाय सभी रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा उसी दर पर किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए। बोर्ड निधि संबंधी अभिदाय, उसके अनुरक्षण और प्रचालन के लिए नियम बनाएगा।

55-शक्ति: खण्ड 39 का उल्लंघन ऐसे का रावाम से जो प्रथम उल्लंघन की बाबत तीन मास और पश्चात्पूर्वी उल्लंघन की बाबत 6 मास से अनधिक अधि के लिए होंगी दंडनीय होगा या ऐसे जुर्माने से जो प्रथम उल्लंघन की बाबत पांच सौ रुपये या पश्चात्पूर्वी उल्लंघन की बाबत एक हजार रकम से अनधिक होंगी दंडनीय होगा या जुर्माने से यथा अपर्युक्त का रावाम या जुर्माना दोनों से दण्डनीय होगा।

56-निरमन और व्यावृत्ति: इस स्कीम के प्रारम्भ पर मुम्बई अर-जिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजक का विनियमन) स्कीम, 1957 निरमन की जाती है:

परन्तु उक्त स्कीम के अधीन किए गए किसी आदेश, प्रोद्भूत किसी अधिगार, उागन शांति या की गई किसी बात या कार्यवाही के बारे में आवश्यक यह समझी जाएगी कि वह इस स्कीम के अधीन किए गए प्रोद्भूत अपगत या की गई है और उक्त स्कीम के किसी उपबन्ध की बाबत किसी निश्चित के प्रति निर्देश को इस स्कीम के तत्स्था नी उपबन्ध के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

अनुसूची 1

[खण्ड 2(2) देखिये]

उन डाक कार्यों और डाक कर्मचारों के वर्ग या विवरण जिनकी स्कीम लागू है।

(1) डाक कार्य:

(क) खाद्यान और अन्नरकों का हस्तन तथा

(ख) भारतीय खाद्य निगम के लेखा मद्दे आयातित/निर्यातित अन्य स्थानों का हस्तन।

(2) डाक कर्मकार:

(क) मुकदम

- (ख) टिडल
(ग) लदान करने वाले
(घ) भराई करने वाले
(ङ) सीवक
(च) पल्लावाने
(छ) पल्लेवालियां
(ज) मशीन मजदूर
(झ) टैंक मजदूर
(ञ) डाक मजदूर

अनुसूची 2

(अण्ड 31 देखिए)

किसी मास में न्यूनतम दिनों की संख्या जिसके लिये मजदूर गारंटीकृत है, पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान औसत नियोजन के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाएगी :—

- (क) मान लें कि अक्टूबर, 1976 के मास में निर्धारण किया जा रहा है तो पहली अक्टूबर, 1975 और 31 अक्टूबर, 1975 को आरक्षित पूल के गैर कर्मचारियों को (जिनमें छुट्टी पर आरक्षित कर्मकार भी सम्मिलित हैं किन्तु मुकदम सम्मिलित नहीं हैं) की कुल संख्या अभिनिश्चित की जानी चाहिये, रजिस्टर में प्रवर्गों की औसत संख्या दोनों अंकों को जोड़कर और दो से भाग देकर अभिनिश्चित किया जाना चाहिये।
- (ख) किसी मास के दौरान (क) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के गैर कर्मचारियों द्वारा चलाए गए श्रम पारियों की कुल संख्या दैनिक नियोजन आंकड़े से निश्चित की जानी चाहिये।
- (ग) उपर्युक्त कर्मचारियों द्वारा ली गई प्राधिकृत या अप्राधिकृत छुट्टी के श्रम दिनों की कुल संख्या अभिनिश्चित की जानी चाहिये। छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या अभिनिश्चित करने के लिये मास में कार्य करने की संख्या द्वारा इस अंक को विभाजित किया जाना चाहिये।
- (घ) (ग) में अभिनिश्चित अंकों को मास के दौरान उपलब्ध कर्मचारियों की वास्तविक संख्या निकालने के लिये (क) से प्राप्त औसत से घटाना चाहिये।
- (ङ) (ख) के अधीन अभिनिश्चित श्रम पारियों की संख्या को (घ) की अभिनिश्चित वास्तविक संख्या से विभाजित करना होगा। इस प्रकार जो संख्या आएगी वह अक्टूबर, 1975 के मास के दौरान नियोजन की औसत दिन संख्या होगी।
- (च) नवम्बर, 1975 से सितम्बर, 1976 तक के शेष 11 मास के लिये उपर्युक्त प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिये।
- (छ) 12 मास की औसत नियोजन संख्या का योग करना होगा और 12 द्वारा विभाजित करना होगा।
- (ज) जो संख्याएं उपर्युक्त (ज) से निकले उनको उन दिनों की न्यूनतम दिनों की संख्या से नियत करना होगा जिनके लिये 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त होने वाले आगामी 12 मास के लिये मजदूरी गारंटीकृत होगी।

निम्न उदाहरण दृष्टांत देगा :—

कर) और छुट्टी पर आरक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या	2,000
31 अक्टूबर, 1975 यथावत	1,950

	3,950

रजिस्टर पर मास की औसत संख्या	3,950

	= 1,975
	2
अक्टूबर, 1975 में उपर्युक्त प्रवर्गों के कर्मचारियों द्वारा चलाई गई श्रम पारियों की कुल संख्या	36,000
कर्मचारियों द्वारा ली गई प्राधिकृत या अप्राधिकृत के छुट्टी श्रम दिनों की कुल संख्या	5,250
उक्त मास में कार्य दिनों की संख्या (मास के 31 दिनों में अवकाश दिन घटाया)	30
छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या	5,250

	30

	= 175
मास के दौरान उपलब्ध वास्तविक संख्या	1,975-175

	= 1,800
1975 के अक्टूबर, मास के लिये औसत नियोजन	36,000

	1,800

	= 20 दिन

शेष 11 मास के औसत नियोजन निकालने के लिये उसी रीति का अनुसरण किया जाएगा। यह मान लें कि अंक निम्नलिखित हैं :—

अक्टूबर, 1975	20
नवम्बर, 1975	21
दिसम्बर, 1975	18
जनवरी, 1976	20
फरवरी, 1976	18
मार्च, 1976	19
अप्रैल, 1976	20
मई, 1976	19
जून, 1976	18
जुलाई, 1976	19
अगस्त, 1976	20
सितम्बर, 1976	16

योग	228

उन दिनों की संख्या जिनके लिये 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त होने वाले अवधि 12 मास के लिये मजदूरी गारंटीकृत होगी—

228

----- = 19 दिन।

12

मान लें कि आरक्षित पूल में यथा पहली अक्टूबर, 1975 को गैर कर्मचारियों (मुकदम को छोड़-

(सं०बी-11025/4/74/पी एण्ड डी/एल०डी)

डी० शंकरलिंगम, अवर सचिव।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 12th July, 1975

S.O. 2383.—Whereas the draft of the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1974, was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), at pages 3582-94 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th December, 1974, under the notification of the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No S. O. 3282, dated the 30th November, 1974 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 14th December, 1974;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme for the port of Bombay, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1975 (hereinafter referred to as "the Scheme").

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Objects and application.—(1) The objects of the Scheme are to ensure greater regularity of employment for the registered food-grain handling workers in the port of Bombay and to secure that an adequate number of dock workers is available for the efficient performance of dock work.

(2) The Scheme relates to the Port of Bombay and applies to the classes or descriptions of dock work and dock workers set out in Schedule I to this Scheme;

(3) The Scheme shall apply to registered foodgrain handling workers and registered employers.

(4) Nothing in this Scheme shall apply to any class or description of dock work and dock workers in the Indian Naval Dockyard, Bombay.

3. Definitions.—In this Scheme, unless the context otherwise requires.—

- (a) "the Act" means the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948);
- (b) "Administrative Body" means the Administrative Body appointed under clause 4;
- (c) "Board" means the Bombay Dock Labour Board constituted under the Act;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (e) "Deputy Chairman" means the Deputy Chairman of the Board;
- (f) "Daily worker" means a registered dock worker who is not a monthly worker;
- (g) "dock employer" means the person by whom a dock worker is employed or is to be employed and includes a group of dock employers formed under clause 15(1)(d);
- (h) "dock work" means operations at places or premises to which the Scheme relates, ordinarily performed by dock workers of the classes or descriptions to which the Scheme applies;

- (i) "employers' register" means the register of dock employers maintained under the Scheme;
- (j) "Labour Officer" means the Labour Officer appointed by the Administrative Body under clause 12;
- (k) "monthly worker" means a registered dock worker who is engaged by a registered employer or a group of such employers on monthly basis under a contract which requires for its termination at least one month's notice on either side;
- (l) "Personnel Officer" means the Personnel Officer appointed by the Board under clause 5;
- (m) "register or record" means the register or record of dock workers maintained under the Scheme;
- (n) "registered dock worker" means a registered food-grain handling worker, whose name is for the time being entered in the register or record;
- (o) "registered foodgrain handling worker" means a registered dock worker whose name is for the time being entered in the register or record for carrying out dock work specified in Schedule I to this Scheme;
- (p) "registered employer" means a dock employer whose name is for the time being entered in the employers' register;
- (q) "reserve pool" means a pool of registered dock workers who are available for work, and who are not for the time being in the employment of a registered employer or a group of dock employers as monthly workers;
- (r) "rules" mean the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;
- (s) "vessel" means an ocean-going vessel or ship whose gross registered tonnage is not less than 350 tons and shall include barges discharged from a LASH ship or loaded into a LASH Ship but shall not include the Bombay Port Trust crafts;
- (t) "week" means the period commencing from the midnight of Saturday and ending on the midnight of the next succeeding Saturday.

4. Administrative Body.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a body consisting of such registered employers of dock workers or any other authority as the Central Government may nominate in this behalf to be the Administrative Body for the purpose of carrying on the day-to-day administration of the Scheme.

(2) The Administrative Body shall, subject to the supervision and control of the Board and the Chairman and subject to the provisions of clause 44, carry on the day-to-day administration of the Scheme.

(3) The Central Government may for sufficient cause remove any Administrative Body appointed under sub clause (1):

Provided that the Administrative Body shall not be removed unless it has been given a reasonable opportunity of being heard.

5. Personnel Officer and other servants of the Board.—The Board may appoint a Personnel Officer and such other officers and servants and pay them such salaries and allowances and specify such terms and conditions of service as it deems fit:

Provided that no post the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand two hundred and fifty and above per mensem shall be created, and no appointment to such post shall be made by the Board except with the previous approval of the Central Government;

Provided further that the sanction of the Central Government shall not be necessary to any appointment in a leave vacancy of a duration of not more than three months.

6. Functions of Board.—(1) The Board may take such measures as it may consider desirable for furthering the objectives of the Scheme set out in clause 2, including measures for :

- (a) ensuring the adequate supply and the full and proper utilisation of dock labour for the purpose of facilitating the rapid and economic turn-round of vessels and the speedy transit of goods through the Port;
- (b) regulating the recruitment and entry into and the discharge from the Scheme and the allocation of registered dock workers in the reserve pool to registered employers;
- (c) determining and keeping under review in consultation with the Administrative Body the number of registered employers and registered dock workers from time to time on the registers or records and the increase or reduction to be made in the numbers in any such register or record;
- (d) keeping, adjusting and maintaining the employers' registers, entering or re-entering therein the name of any dock employer and, where circumstances so require, removing from the register the name of any registered employer, either at his own request or in accordance with the provisions of the scheme;
- (e) keeping, adjusting and maintaining from time to time such registers or records, as may be necessary, of registered dock workers including any register or records of registered dock workers who are temporarily not available for dock work and whose absence, has been approved by the Administrative Body and, where circumstances so require removing from any register or record the name of any registered dock worker either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;
- (f) the grouping or regrouping of all registered dock workers into such groups as may be determined by the Board after consultation with the Administrative Body and thereafter reviewing the grouping of any registered dock worker on the application of the Administrative Body or of the registered dock worker;
- (g) making provisions for the training and welfare of registered dock workers including medical services in so far as such provision does not exist apart from the Scheme;
- (h) levying and recovering from registered employers contributions, in respect of the expenses of the Scheme;
- (i) making provision for health and safety measures in places where registered dock workers are employed in so far as such provision does not exist apart from the Scheme;
- (j) maintaining and administering the Dock Workers welfare Fund and recovering from all registered employers contribution towards the Fund;
- (k) maintaining and administering a Provident Fund, a Gratuity Fund, a Voluntary Retirement Fund and any other fund or funds created for specific purposes for registered dock workers;
- (l) borrowing or raising money and issuing debentures or other securities and, for the purpose of securing any debt or obligation, mortgaging or charging all or any part of the property of the Board.

(2) The income and property of the Board from whatever source derived shall be applied solely towards the objects of the Scheme including, health, safety, training and welfare measures for registered dock workers (including assistance by way of grant of loan or otherwise to co-operative societies formed for the exclusive benefit of dock workers and the staff of the Board) and no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend, bonus or otherwise by way of benefit to the members of the Board; provided that nothing herein shall prevent the payment of reasonable and proper remuneration and expenses to any officer or servant of the

Board or to any member of the Board in return for any service actually rendered to the Board, nor prevent the payment of interest at a reasonable rate on money lent or reasonable and proper rent for premises demised or let, by any member to the Board nor prevent the incurring of expenditure on welfare measures, if any, for the staff of the Board.

(3) The Board shall cause proper accounts to be kept of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under the Scheme.

(4) The Board shall submit to the Central Government:—

(i) as soon as may be after the first day of April in every year and not later than the thirty-first day of October an annual report on the working of the Scheme during the preceding year ending the thirty-first day of March together with an audited balance sheet; and

(ii) copies of proceedings of the meetings of the Board.

7. Responsibilities and duties of the Board in meeting.—The Board in meeting shall be responsible for dealing with all matters of policy and in particular may—

(a) fix the number of workers to be registered under various categories;

(b) increase or decrease the number of workers in any category on the register from time to time as may be necessary after a periodical review of the registers and anticipated requirements;

(c) sanction the temporary registration of a specific number of workers in any category for a specific period;

(d) consider registration of new employers on the recommendation of the Chairman;

(e) specify forms, records, registers statements and the like required to be maintained under the Scheme;

(f) determine the wages, allowances and other conditions of service, and re-fix the guaranteed minimum wages in a month after annual review;

(g) fix the rate of levy under clause 52 (1);

(h) fix the rate of contribution to be made by registered employers to the Dock Workers Welfare Fund and the Voluntary Retirement Fund;

(i) appoint, abolish or reconstitute Committees under clause 36;

(j) sanction the annual budget;

(k) appoint the Personnel Officer;

(l) subject to the provisions of clause 5 sanction creation of posts and make appointments to such posts;

(m) make recommendations to the Central Government about changes in Schedule I to this Scheme;

(n) make recommendations to the Central Government about any modifications in the Scheme;

(o) endeavour to settle disputes about which a request for adjudication has been made to the Central Government by the parties concerned and report to the Government the results of such endeavours;

(p) discuss statistics of output of labour and turn-round of ships and record its observations and directions;

(q) sanction the opening of accounts in such scheduled Banks as it may direct and the operation of such accounts by such persons as the Board may from time to time direct; and

(r) sanction and create fund or funds for specific purposes.

8. Annual Estimates.—The Chairman shall, at a special meeting to be held before the end of February in each year lay before the Board the annual budget as received from the Administrative Body under clause 11(i), for the year commencing on the first day of April then next ensuing in such details and form as the Board may, from time to time, specify. The Board shall consider the estimate so presented to it and shall, within four weeks of its presentation, sanction the same either unaltered or subject to such alterations as it may deem fit.

9. Responsibilities and duties of Chairman.—(1) The Chairman shall have full administrative and executive powers to deal with all matters relating to the day-to-day administration of the Scheme and in particular—

- (a) to ensure that the decisions of the Board in regard to the adjustment of the workers' registers are carried out expeditiously;
- (b) to ensure that the sanctions for temporary registration of workers are carried out without delay;
- (c) (i) to supervise and control the working of the Administrative Body;
- (ii) to take suitable steps if any irregularities are detected by him or brought to his notice;
- (d) to ensure in consultation with ship-owners or shipping agents that proper and adequate supervision is provided by the registered employers over the workers employed on their ships;
- (e) to ensure that the provisions of the Scheme in regard to transfer and promotion of workers are carried out;
- (f) to contribute Medical Boards when required;
- (g) to ensure that conditions, laid down in the Scheme, for the registration of employers are complied with by them;
- (h) to ensure that all forms, registers, returns and documents, stated under the Scheme, are properly maintained;
- (i) to ensure that suitable statistics in regard to the output of labour and the turn-round of ships are compiled and placed before the Board every quarter with appropriate remarks and explanations;
- (j) (i) to sanction the creation of posts the maximum salary of which exclusive of allowances is upto rupees one thousand per month;
- (j)(ii) to make appointments to posts the maximum salary of which exclusive of allowances is up to rupees one thousand per month;
- (k) to take disciplinary action against workers and employers in accordance with the provisions of the Scheme;
- (l) to allow relaxation in the maximum number of shifts per worker per week or per month, and to report such cases to the Board;
- (m) to declare that there has been a 'go-slow' and to take action as authorised under the Scheme;
- (n) to declare a 'state of emergency' and to take action as authorised under the Scheme;
- (o) to make a report, when necessary, to the Central Government under rule 5 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;
- (p) to sanction the transfer of a monthly worker to the reserve pool at the request of the employer or the worker, as provided for in the Scheme;
- (q) to deal with appeal from workers and employers under clauses 47 and 48;
- (r) to fill an, unexpected vacancy in the post of Deputy Chairman for a period of less than one month and report such matter to the Central Government for approval; and

(s) to discharge all other duties and responsibilities specifically vested in the Chairman under the Scheme.

(2) The Chairman may, subject to such conditions as he may think fit, delegate in writing to the Deputy Chairman any of the functions under sub-clause (1) excepting those mentioned in items (ji), (jii), (m), (n), (o), (q), (r) and (s), so however that such delegation shall not divest the Chairman of his powers.

10. Responsibilities and duties of the Deputy Chairman.—The Deputy Chairman shall be a whole-time officer of the Board and shall assist the Chairman in the discharge of his functions and in particular shall—

- (a) discharge all functions relating to disciplinary action against registered employers and registered dock workers to the extent permitted under clause 44;
- (b) exercise such other functions as are delegated to him in writing by the Chairman;
- (c) function as Chairman of Committees of the Board of which he may be nominated as a member;
- (d) preside over the meetings of the Board in the absence of the Chairman; and
- (e) make appointments to the posts, the maximum salary of which exclusive of allowances is not more than seven hundred and fifty rupees per mensem.

11. Functions of the Administrative Body.—Without prejudice to the powers and functions of the Board, the Chairman and the Deputy Chairman, the Administrative Body shall be responsible for the administration of the Scheme and shall in particular be responsible for—

- (a) keeping, adjusting and maintaining the employers' register, entering or re-entering therein the name of any dock employer and, where circumstances so require, removing from the register the name of any registered employer, either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;
- (b) keeping, adjusting and maintaining from time to time such registers or records as may be necessary, of dock workers, including any registers or records of dock workers who are temporarily not available for dock work and whose absence has been approved by the Administrative Body and where circumstances so require removing from any register of record the name of any registered dock worker either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;
- (c) the employment and control of registered dock workers available for work when they are not otherwise employed in accordance with the Scheme;
- (d) the grouping or regrouping of registered dock workers in accordance with the instruction received from the Board in such groups as may be determined by the Board;
- (e) the allocation of registered dock workers in the reserve pool who are available for work to registered employers and for this purpose, the Administrative Body shall—
 - (i) be deemed to act as an agent for the employer,
 - (ii) make the fullest possible use of registered dock workers in the reserve pool,
 - (iii) keep the record of attendance at call stands or control points of registered dock workers;
 - (iv) provide for the maintenance of records of employment and earnings;
- (v) subject to the allotment of work by rotation under clause 29(3), allocate workers in accordance with clause 19 and 30, and

- (vi) make necessary entries in the Attendance Card and Wage Slip of workers in the reserve pool as laid down in clause 27;
- (f) (i) the collection of levy, contribution to the Dock Workers Welfare Fund or any other contribution from the employers as may be specified under the Scheme;
- (ii) the collection of workers' contribution to the Provident Fund Insurance Fund or any other fund which may be constituted under the Scheme;
- (iii) the payment as agent of the registered employer to each daily worker of all earnings properly due to the worker from the employer and the payment to such workers of all monies payable by the Board to those workers in accordance with the provisions of the Scheme;
- (g) appointing, subject to budget provision, such officers and servants from time to time as may be necessary

Provided that the creation of posts the maximum salary of which exclusive of allowances is above rupees five hundred and seventy-five per month and appointment of persons to such posts shall be subject to clauses 6(1) and 9(1)(j).

- (h) the keeping of proper accounts of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under it and making and submitting to the Board an annual report and audited balance-sheet;
- (i) the framing of the Budget annually, submitting the same to the Board on or before the 15th day of February in each year and getting it approved by the Board;
- (j) maintaining complete service records of all registered dock workers; and
- (k) such other functions as may from time to time, subject to the provisions of the Scheme, be assigned to it by Board, the Chairman or the Deputy Chairman.

12. Labour Officer.—The Administrative Body when it consists of employers of dock workers shall appoint a Labour officer or Labour Officers with the approval of the Board. The Labour Officer shall, under the supervision and control of the Administrative Body, carry out such functions as may be assigned to him by that Body consistent with the provisions of the Scheme.

13. Functions of the Personnel Officer.—The Personnel Officer shall assist the Deputy Chairman generally in the discharge of his duties and shall in particular carry out the functions vested in him under clause 44 of the Scheme.

14. Officers appointed by the Central Government for proper working of the Scheme.—(1) Notwithstanding the provisions of Clauses 4, 5, 11 and 13, the Central Government may in its discretion appoint, from time to time, in consultation with the Chairman of the Board one or more officer and entrust to such officer or officers such functions as it may deem fit for the proper working of the Scheme.

(2) The officer or officers appointed under sub-clause (1) shall be subject to the general supervision and control of the Chairman and be paid from the funds of the Board. Such officer or officers shall hold office for such period and on such terms and conditions as the Central Government may determine.

15. Maintenance of Registers, etc.—(1) Employers' Register :

- (a) There shall be a register of employers.
- (b) In so far as the application of the Scheme to foodgrain handling workers is concerned, every employer who on the date of commencement of the Scheme is listed under the Bombay Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, shall be deemed to have been registered under the Scheme.

(c) Persons other than those who are deemed to have been registered under item (b) shall not be registered as foodgrain handling employers unless the Board considers it expedient and necessary to do so, and in no case shall a person be registered until he has been licensed in that behalf by the Bombay Port Trust.

(d) The Board may, subject to such conditions as it may with the previous approval of the Central Government specify in this behalf, permit persons registered under items (b) and (c), to form one or more groups, and each group so formed shall be treated as one employer only for employment of monthly workers:

Provided that the Board shall have power to make with the previous approval of the Central Government such alterations or modifications in the conditions specified, as it may deem necessary from time to time:

Provided further that the Board may revoke, from such date as it may specify, the permission given to any group of employers, if, after giving an opportunity to the group of employers to show cause against the proposal and after considering its representations, if any, the Board is satisfied that the group of employers has failed to comply, in part or in full with the conditions specified for the formation of such groups and thereupon the said group shall stand dissolved from such date.

(2) Workers' Registers.—(a) The workers' registers shall be maintained in the forms specified by the Board for this purpose.

(b) The registers of foodgrain handling workers shall be as under namely :—

- (i) Monthly Register—Register of workers who are engaged by each foodgrain handling employer on contract or monthly basis and who are known as monthly workers.
- (ii) Reserve Pool Register—Register of workers other than those on the monthly register and known as Reserve Pool Workers. This register shall include a sub-pool of foodgrain workers to fill casual vacancies in categories. The workers included in such a sub-pool shall be known as leave reserve workers.

16. Classification of worker's in Registers.—(1) The Board shall arrange for the classification of workers by categories in the registers.

(2) Dock workers registered under the Scheme shall be classified into :

- (a) Mukadams;
- (b) Tindals;
- (c) Loaders;
- (d) Fillers;
- (e) Stitchers;
- (f) Palawalas;
- (g) Palawalls;
- (h) Machine Mazdoors;
- (i) Jank Mazdoors;
- (j) Dock Mazdoors.

17. Fixation of number of workers on the register.—(1) The Board shall in consultation with the Administrative Body and with the previous approval of the Central Government determine, before the commencement of registration in any category, the number of workers required in that category.

(2) The Board shall in consultation with the Administrative Body and subject to the approval of the Central Government periodically determine the number of workers required in each category and arrange to adjust the workers' registers accordingly.

(3) A registered employer or a group of employers may, subject to such conditions as may be specified by the Board

in this behalf, increase the number of workers on the monthly registers by selecting workers from the reserve pool.

18. Registration of existing and new workers.—(1) (a) Any dock worker who, on the date of commencement of the Scheme, is already listed under the Bombay Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, shall be deemed to have been registered under this Scheme.

(b) The qualification for new registration shall be such age as may be specified by the Board having regard to the local conditions but not exceeding 40 years. Only Indian nationals who are physically fit, capable and having experience shall be eligible for registration:

Provided that in the case of ex-service personnel the age limit may be relaxed up to 45 years by the Dock Labour Board.

(c) Registration of workers in any new category shall be done from among workers who have been or were working in the Port on any such date as the Board may specify in this behalf and selection for registration shall be made as far as possible on the basis of seniority, as determined by the length of service rendered by a worker in that category and notified by the Board. In cases where the said seniority list is not available, selection shall be made on such other basis as the Board may determine, provided that the worker is medically fit and is not more than 40 years of age.

(2) The Board may from time to time permit the registration of workers temporarily for such period and on such terms and conditions of service as the Board may specify:

Provided that the workers registered temporarily shall be entitled to attendance allowance under clause 32 and shall have the same obligations as registered dock workers in the reserve pool.

(3) Any fresh recruitment, whether on a temporary or permanent basis in any category in which dock workers have already been registered under the Scheme shall be done from amongst workers registered with the local Employment Exchange. If, however, the requirement exceeds the number of suitable men available on the register of the Employment Exchange on the day of the requisition, direct recruitment after absorbing suitable men from the Employment Exchange register may be made.

(4) New Workers registered under item (b) of sub-clause (1) will be on probation for a period of three months before being placed on a permanent basis on the registers.

(5) Notwithstanding any other provision of the Scheme, where the Board is of opinion that a dock worker has secured his registration by furnishing false information in his application or by withholding any information required therein, or where it appears that a worker has been registered improperly or incorrectly, the Board in meeting may direct the removal of his name from the registers;

Provided that before giving such direction, the Board shall give him an opportunity of showing cause why the proposed direction should not be issued.

(6) The following principles shall apply in respect of registration in either categories which may after the commencement of the Scheme be included in Schedule I to this Scheme—

(a) Before a worker is registered in any of the above categories, the Board shall under clause 17(1) make a thorough investigation with a view to arriving at an estimate of the number of workers in that category that are likely to be required out of all the bona fide workers in that category who may then be working in the docks.

(b) There shall be a provisional registration based on the anticipated requirements and the mere fact that a worker has been working before in the port shall not automatically entitle him to registration.

(c) After the provisional registration has been completed, the booking in relation shall start without allowing,

at that stage any financial benefits other than wages which accrue to registered workers under the Scheme.

(d) A re-assessment of the requirement shall be made after six months in the light of the actual employment obtained by workers provisionally registered and the provisional registration shall then be adjusted accordingly. The payment of attendance allowance under clause 32 shall commence only from that time.

(e) The working under these conditions shall be examined after a year of introduction of the rotational booking with a view to fixing the number of days for which the guaranteed minimum wages under clause 31 should be paid.

From then onwards the workers shall be entitled to all the benefits under the Scheme.

(f) The minimum number of days in a month for which wages are guaranteed under clause 31 to categories of workers previously registered shall not automatically be claimed by workers of the categories to be registered after the date of enforcement of the Scheme.

Such minimum number of days may vary from category to category as determined under item (e) above.

(g) The wages of the workers in categories which may be registered after the enforcement of the Scheme, shall be such as may be fixed by the Board from time to time.

19. Age of retirement, promotion and transfer of workers.—(1) The age of retirement under the Scheme shall be 58 years :

Provided that where the existing age of retirement for any category of workers is 60 years that practice shall continue for the present incumbents.

(2) A vacancy, other than a casual vacancy, in any category of dock workers in a reserve pool register shall ordinarily be filled by promotion of a worker from the next lower category.

(3) A vacancy other than a casual vacancy, in any category of monthly workers may be filled only by promotion from lower categories of monthly workers of the same employer or group of employers, or, if no person is suitable for promotion from lower categories of monthly workers of the same employer or group of employers, by transfer of a dock worker in the same or a superior category from the reserve pool who may be selected by a registered employer or a group of employers.

Explanation—The criteria for promotion shall ordinarily be:—

(a) seniority,

(b) merit and fitness for work in the category to which promotion is to be made, and

(c) record of past service.

NOTE:—A transfer from the reserve pool register to the monthly register in the same category or vice versa shall not be deemed to be a promotion.

(4) The Chairman or the Deputy Chairman may for sufficient and valid reasons allow the transfer of a monthly worker to the reserve pool on a request in writing of the employer or the worker explaining fully the reasons for the transfer provided that such transfer shall be subject to the fulfilment of any contract subsisting between the monthly worker and his employer regarding termination of employment. No transfer shall take place without the prior approval of the Chairman or the Deputy Chairman.

(5) If the services of a monthly worker are terminated by any employer for an act of indiscipline or misconduct, he may apply to the Board for employment in the reserve pool. The Deputy Chairman on behalf of the Board shall then decide on

the merits of the case whether or not the worker should be employed and if so, whether in the same or a lower category.

(6) If a monthly worker is transferred to or employed in the reserve pool under sub-clause (3) or sub-clause (4), as the case may be, his previous service shall be reckoned for all benefits in the reserve pool and the employer shall transfer to the Board all benefits that have accrued to the worker in respect of his previous service as if such service had not been transferred. The employer shall in particular contribute to the Board such amount as may be appropriate towards the workers' leave, Provident Fund or gratuity that may be due to him on the date of such transfer.

20. Medical Examination.—(1) A new worker before registration shall undergo, free of charge, a medical examination for physical fitness by a Medical Officer, nominated, by the Chairman for this purpose. A worker found medically unfit by a Medical Officer may apply in writing to the Chairman for examination by a Medical Board. On receipt of such a request, the Chairman shall set up a Medical Board. The decision of the Medical Board shall be final and a worker who is medically unfit shall not be entitled to registration.

(2) If the Administrative Body deems it necessary, a worker shall undergo free of charge, a medical examination by a Medical Board to be constituted by the Chairman. The decision of the Medical Board shall be final. If a worker is found permanently unfit by the Medical Board the Chairman shall terminate his services forthwith.

21. Facilities for training.—The Board shall make such provision for training of dock workers as it may deem necessary.

22. Registration fee.—A registration fee of rupees two shall be payable to the Board by each worker at the time of registration under the Scheme.

23. Supply of cards.—(1) Every registered worker shall be supplied free of cost an Identity Card, an Attendance Card and Wage slips in the forms specified by the Board.

(2) In case of loss of a card, a fresh card shall be issued but the cost thereof which will be fixed by the Board, shall be payable by the worker concerned.

24. "Service Records" for registered workers: A "Service Record" for every monthly and daily worker shall be maintained by the Administrative Body in a form, to be specified by the Board which shall contain, among other things, a complete record of disciplinary actions taken against the worker, promotions, commendations for good work and other matters. Such details in respect of monthly workers shall be supplied to the Administrative Body by the registered employers.

25. "Record Sheets" for registered employers: The Personnel Officer shall maintain a "Record Sheet" in respect of each registered employer in a form to be specified by the Board which shall contain, among other things, a complete record of disciplinary actions taken against the registered employer.

26. Surrender of identity cards: A worker's identity card shall be surrendered to the Administrative Body in the following circumstances, namely :—

- (a) when proceeding on leave for three days or more;
- (b) when retiring from service;
- (c) when dismissed or discharged from service,
- (d) when temporarily suspended; or
- (e) on death.

Provided that the employer of a monthly worker will also surrender the card of the worker to the Administrative Body in circumstances specified at items (a) to (e).

27. Entries in Attendance Card and Wage Slip: (1) A registered dock worker in the reserve pool shall hand over to the Administrative Body at the time he is allocated for work to a registered employer his Attendance Card. The Administrative Body shall make necessary entries in the Attendance Card in respect of the period of work done by

the worker and return it to him before the expiry of his engagement. For each day of work, the Administrative Body shall supply as soon as possible a wage slip showing the wages earned by a worker.

(2) A monthly worker shall hand over to his employer at the time he is allotted work on a ship his Attendance Card. The said employer shall make necessary entries in the card in respect of the period of work done by the worker and return it to him before the conclusion of his allotted work. For each day of work, the employer shall supply as soon as possible a wage slip showing the wages earned by a worker.

28. Employment of workers: (1) A monthly worker of a particular category attached to a registered employer or a group of employers shall be entitled to be employed for work in that category by that employer or group of employers, in preference to any worker of the same category in the reserve pool.

(2) If the number of workers on the monthly register in a particular category is not sufficient for the work available, the workers on the reserve pool register in that category shall be employed.

(3) A monthly worker of one employer or a group of employers shall not be employed by another employer or group of employers except with the previous approval of the Chairman or the Deputy Chairman.

29. Employment in shifts: (1) Dock workers shall be employed in shifts.

(2) (a) A dock worker shall not ordinarily be employed in two consecutive shifts on each of the two successive days. In no case shall a dock worker be employed in three consecutive shifts.

(b) A dock worker in the reserve pool shall not be employed for more than 9 shifts in a week or 33 shifts in a month.

(c) Normally a monthly worker shall not be employed for more than 6 shifts in a week or 27 shifts in a month, but when a worker in the reserve pool who has not reached the maximum limit of employment defined in item (b) is not available, a monthly worker may be employed upto 9 shifts in a week or 33 shifts in a month.

(d) In special circumstances, the Chairman may relax temporarily the restrictions under items (b) and (c) to the extent necessary.

(e) Workers working more than one shift in a day will be entitled to the normal rate of wages for work in each shift.

(3) Workers of each category on the reserve pool register shall be allotted work by rotation.

(4) Where work is carried on by a gang, the allotment of workers by rotation shall be by gangs.

30. Filling up of casual vacancies: (1) Casual vacancies in monthly gangs shall be filled up in the following manner, namely :—

(i) When a Tindal is absent, the vacancy shall be filled by a Tindal of another gang in the employment of the employer, provided such Tindal is not allocated to any other job. If no such Tindal is available, the seniormost foodgrain handling worker in the same gang available for work shall work as a Tindal for the shift.

(ii) Vacancies of foodgrain handling mazdoors shall be filled by foodgrain handling mazdoors of another gang in the employment of the employer, provided such mazdoors are not allocated to any other job. When no such workers are available, the vacancies shall be filled by workers of the same category from the reserve pool.

(2) Casual vacancies in the reserve pool gangs shall be filled up in the following manner, namely :—

(a) When a Tindal is absent, the vacancy shall be filled by a Tindal on attendance allowance. If no Tindal

is on attendance allowance, the senior-most food-grain handling mazdoor in the same gang available for work shall work as a Tindal.

- (b) Vacancies of foodgrain handling mazdoors shall be filled by foodgrain handling mazdoors on attendance allowance, or by leave reserve workers if any.
- (c) In filling up vacancies otherwise than by promotion in the same gang, the principle of rotation shall be followed : Provided that where work is carried on by a gang, the allotment of workers by rotation shall be by gangs.

31. Guaranteed Minimum Wages in a month :— (1) A worker in the reserve pool register shall be paid wages at least for twelve days in a month at the wage rate, inclusive of dearness allowance as specified by the Board appropriate to the category to which he permanently belongs, even though no work is found for him for the minimum number of twelve days in a month. The days on which work is allotted to the worker shall be counted towards the twelve days mentioned above. The guaranteed minimum wages in a month shall be :—

- (a) for the number of days for which the wages are guaranteed in a month subject to the condition that the worker attended for work on all days of the month as directed by the Administrative Body ; or
- (b) proportionate to the number of days on which the worker attended for work provided he was excused from attendance on all the remaining days of the month.

(2) Subject to the provisions of sub-clause (1), the minimum number of days in a month for which wages are guaranteed may be fixed by the Board for each year on the basis of the monthly average employment obtained by the workers in the reserve pool in the lowest categories of food-grain handling workers during the preceding year :

Provided that—

- (i) the number so fixed shall not in any case be more than 21 and not less than 12 ;
- (ii) the workers already listed under the Bombay Un-registered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, shall continue to be eligible for the same minimum guaranteed wages as admissible to them before the commencement of the Scheme.

NOTE.—The method of assessing the average employment is detailed in Schedule II to this Scheme.

(3) The minimum number of days for which wages shall be guaranteed under sub-clauses (1) and (2) shall not automatically apply to workers in new categories that may be registered after the date of enforcement of the Scheme. The minimum number of days for which wages shall be guaranteed to these categories shall be determined under clause 18(6)(e). The annual refixation of the minimum number of days as under sub-clause (2) shall be done independently in their case also.

Explanation.—For the purpose of this clause,—

- (a) "day" shall mean a shift ; and
- (b) "month" shall not include the days of weekly off.

32. Attendance Allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid attendance allowance exclusive of dearness allowance at the rate of one rupee per day for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him :

Provided that the Board may allow payment of attendance allowance exclusive of dearness allowance at such higher rate not exceeding rupees two as it may deem necessary :

Provided further that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 31 or otherwise or under clause 34.

33. Employment for a shift : No worker in the reserve pool register shall be employed for a period of less than a shift and where the work for which a worker has been engaged is completed during the working period of the shift he shall undertake such other work in or at the same or another vessel or berth as may be required by the same employer for the remainder of the period and if no such other work is made available to him, he shall be paid for the entire shift :

Provided that if he is subject to piece-rate wages or incentive wages under any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers or any decision of the Board he shall be paid at the rates laid down therein.

34. Payment of wages when work is not made available after engagement : When a worker in the reserve pool presents himself for work and for any reason the work for which he has attended cannot commence or proceed and no alternative work can be found for him he shall be entitled to daily wage rate appropriate to the category to which he belongs inclusive of all allowances, provided he continues to be available throughout the remainder of the shift and accepts such alternative employment as may be offered to him by the Administrative Body :

Provided that in the case of a worker who is subject to the piece rate system of wages, the payment, if any, due to him under this clause, shall be reduced by the amount of idle time payment made, if any, in respect of the same period.

35. Holidays : Each dock worker shall be entitled in a year to such number of holidays with pay and at such rates as may be specified by the Board under clause 41. Any payment made under this clause shall be exclusive of the payment calculated under clause 31.

36. Committees : The Board may appoint one or more committees to whom it may entrust such of its functions as it may deem necessary to facilitate compliance with the provisions of the Scheme and may abolish or reconstitute them as it may deem necessary. Persons who are not members of the Board may, if necessary, be nominated as co-opted members of a committee. Such co-opted members, however, shall not have any right to vote.

37. Obligations of registered dock workers : (1) Every registered dock worker shall be deemed to have accepted the obligations of the Scheme.

(2) A registered dock worker in the reserve pool who is available for work shall be deemed to be in the employment of the Board.

(3) A registered dock worker in the reserve pool who is available for work shall not engage himself for employment under a registered employer unless he is allocated to that employer by the Administrative Body.

(4) A registered dock worker in the reserve pool who is available for work shall carry out the directions of the Administrative Body and shall,—

(a) report at such call stands or control points and at such times as may be specified by the Administrative Body and shall remain at such call stands or control points—

(i) throughout the period of the shift, if instructed by the Administrative Body to that effect, on payment of such retention allowance as may be specified by the Board ; or

(ii) for such period, not exceeding one hour, as may be specified ; and

(b) accept any employment in connection with dock work, whether in the category in which he has been registered or in any other category registered in other schemes administered by the Board for which he is considered suitable temporarily or permanently.

(5) A registered dock worker who is available for work when allocated by the Administrative Body for employment under a registered employer shall carry out his duties in accordance with the directions of such registered employer or his authorised representative or supervisor and the rules of the port or place where he is working.

38. Obligations of registered employers.—(1) Every registered employer shall accept the obligations of the Scheme.

(2) Subject to the provisions of clause 28, a registered employer shall not employ a worker other than a dock worker who has been allocated to him by the Administrative Body in accordance with the provisions of clause 11(e).

(3) A registered employer shall in accordance with arrangements made by the Administrative Body submit all available information of his current and future labour requirements.

(4) A registered employer shall lodge with the Administrative Body, unless otherwise directed, particulars of work done by dock workers on time-rate or piece-rate and such other statistical data as may be required in respect of the dock workers engaged by him.

(5) (i) A registered employer shall pay to the Administrative Body in such manner and at such times as the Board may direct the levy payable under clause 52(1) and the gross wages due to daily workers.

(ii) A registered employer shall make payments as contributions to the Dock Workers Welfare Fund.

(6) A registered employer shall keep such records as the Board may require, and shall produce to the Board or to such persons as may be designated by the Board upon reasonable notice all such records and any other documents of any kind relating to registered dock workers and to the work upon which they have been employed and furnish such information relating thereto as may be set out in any notice or direction issued by or on behalf of the Board.

39. Restriction on employment.—(1) No person other than a registered employer shall employ any worker on dock work nor shall a registered employer engage, for employment or employ a worker on dock work unless that worker is a registered dock worker.

(2) Notwithstanding the foregoing provisions of this clause.

(a) where the Administrative Body is satisfied that—

(i) dock work is emergently required to be done; and

(ii) it is not reasonably practicable to obtain a registered dock worker for that work;

the Administrative Body may, subject to any limitations imposed by the Board, allocate to a registered employer a person who is not a registered dock worker. In collecting such workers the local Employment Exchange organisation shall, as far as possible, be consulted;

Provided that, whenever, unregistered workers have to be employed, the Administrative Body shall obtain, if possible, the prior approval of the Chairman to the employment of such workers, and where this is not possible, shall report to the Chairman within 24 hours the full circumstances under which such workers were employed and the Chairman shall duly inform the Board of such employment at the next meeting;

(b) the Board may, subject to such conditions as it may specify, permit employment of unregistered workers on a holiday, if dock work is required to be done on that day, to the extent registered workers are not available for work;

(c) in the case referred to in items (a) and (b), the person so employed as aforesaid by a registered employer shall, for the purposes of clause 38 (4), (5) and (6) and clause 41 be treated in respect of that dock work as if he were a daily worker.

(3) A registered dock worker in the reserve pool may, provided the fulfils fully his obligations under clause 37, take up occasional employment under employers other than those registered under the Scheme on those days on which he is not allocated for work by the Administrative Body.

40. Circumstances in which the Scheme ceases to apply.—
(1) The Scheme shall cease to apply to a registered dock worker when his name has been removed from the register or record in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) The Scheme shall cease to apply to a registered employer when his name has been removed from the employer's register in accordance with the provisions of the Scheme.

(3) Nothing in this clause shall affect any obligation incurred or right accrued during any time when the person was a registered dock worker or a registered employer.

41. Wages, allowances and other conditions of service of workers.—Without prejudice to the provisions of any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers it shall be, unless otherwise specifically provided for in the Scheme, an implied condition of the contract between a registered dock worker (whether in the reserve pool or on the monthly register) and registered employer that—

(a) The rates of wages, allowances and overtime, hours of work, rest intervals, holidays, and pay in respect thereof and other conditions of service shall be such as may be specified by the Board for each category of workers; and

(b) the fixation of wage period, time for payment of wages and deductions from wages shall be in accordance with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).

42. Pay in respect of unemployment or under-employment and payment of arrears of Dearness Allowance, wages and other allowances.—Subject to the conditions set out in this clause and clause 43 when, in any wage period, a registered dock worker in the reserve pool is available for work but is not given employment or full employment, he shall be entitled to receive from the Board such amounts as may be admissible to him under clauses 31, 32, and 34,

(2) The conditions subject to which a registered dock worker is entitled to the said payment, if any, from the Board are that—

(a) he attended as directed at the call stands or control points; and

(b) his attendance was recorded.

(3) In case of any revision of dearness allowance or grant of revised wages or other allowances, with retrospective effect, in pursuance of any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers or any decision of the Board or recommendation of any Board or body set up or of any order made, by the Central Government, the Board may, out of its funds, pay the registered workers arrears upto the date of the agreement entered into between the registered employers and registered dock workers or any decision of the Board or, as the case may be of the recommendation or order, if the Board so decides.

43. Disentitlement to payment.—(1) A registered dock worker who while in the reserve pool fails without adequate cause to comply with the provisions of clause 37(4)(a) or (b), or fails to comply with any lawful order given to him by or on behalf of the Board, may be proceeded with in accordance with sub-clause (3).

(2) A registered dock worker in the reserve pool, who, while in employment to which he has been allocated by the Administrative Body, fails without any adequate cause to comply with the provisions of clause 37(5) or fails to comply with any lawful orders given to him by his employer, may have his engagement terminated and may be returned to the reserve pool and whether or not he is so returned may be reported in writing to the Labour Officer. When a registered dock worker is so returned to the reserve pool, the Administrative Body shall endorse his Attendance Card accordingly.

(3) The Labour Officer shall consider any matter arising under sub-clause (1) or (2) and if, after investigating the matter, he notifies the registered dock worker that he is satisfied that the registered dock worker has failed to comply with a lawful order as aforesaid, the registered dock worker shall not be entitled to any payment, or to such part of

any payment under clause 42 as the Labour Officer thinks fit in respect of the wage period in which such failure occurred or continues.

44. Disciplinary Procedure.—(1) (i) The Personnel Officer on receipt of the information whether on a complaint or otherwise, that a registered employer has failed to carry out the provisions of the Scheme may after investigating the matter, give him a warning in writing, or

(ii) Where in his opinion, a higher penalty is merited, he shall report the case to the Deputy Chairman, who may then cause such further investigation to be made as he may deem fit and take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—

(a) censure him and record the censure in his record sheet; or

(b) subject to the approval of the Board and after one month's notice in writing given to the registered employer, inform the Administrative Body that the name of the employer shall be removed from the employers' register for such period as determined by the Board or permanently in case of grave offence.

(2) A registered dock worker in the reserve pool, who fails to comply with any of the provisions of the Scheme, or commits any act of indiscipline or misconduct, may be reported in writing to the Labour Officer who may after investigating the matter take any of the following steps as regards that worker, that is to say, he may :

(a) determine that, for such period as he thinks proper, that worker shall not be entitled to any payment or part payment under clause 42;

(b) give him a warning in writing; or

(c) suspend him without pay for a period not exceeding three days.

(3) (a) Where in a case reported to the Labour Officer under sub-clause (2) he is of the opinion that the act of indiscipline or misconduct is so serious that the dock worker should not be allowed to work any longer, the Labour Officer may, pending investigation of the matter, suspend the worker and report immediately to the Deputy Chairman, who after preliminary investigation of the matter shall pass orders thereon whether the worker should, pending final orders, remain suspended or not:

(b) Where a dock worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance equivalent to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances :

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(c) The subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever;

(d) Where a registered dock worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments as the Administrative Body certifies that the worker would have received on the time-rate basis or under clause 32 had he not been suspended, provided that the amounts so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance payable or already paid during a particular period.

(4) Where, in the opinion of the Labour Officer a higher punishment than that provided in sub-clauses (2) and (3) is merited, he shall report the case to the Deputy Chairman.

(5) On receipt of the written report from the Labour Officer under sub-clause (4) or from the employer or any other person that a registered dock worker in the serve pool has failed to comply with any of the provisions of the Scheme or has committed an act of indiscipline or misconduct or has consistently failed to produce the standard or datum output or has been

inefficient in any other manner, the Deputy Chairman may make or cause to be made such further investigation as he may deem fit, and thereafter take any of the following steps, as regards, the worker concerned, that is to say, he may impose any of the following penalties:—

(a) determine that for such period as he thinks proper, the worker shall not be entitled to any payment or part payment under clause 42;

(b) give him a warning in writing;

(c) suspend him without pay for a period not exceeding three months;

(d) terminate his services after giving 14 days' notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof; or

(e) dismiss him.

(6) Before any action is taken under this clause the person concerned shall be given an opportunity to show cause why the proposed action should not be taken against him, and such person may, if he so desires, adduce evidence in respect of such action.

(7) The Administrative Body shall be informed simultaneously about the action taken under this clause.

(8) Notwithstanding anything contained in this clause and in clause 43, the powers vested in the authority specified in column (1) of the Table below under the provisions specified in column (2) of the said Table, shall also be exercisable by the authority specified in the corresponding entry in column (3) of the said table in such cases as the last named authority may specify in writing in this behalf.

TABLE

Authority empowered to take action	Provisions of the scheme	Authority empowered to take action in specified cases
(1)	(2)	(3)
1. Labour Officer	Clauses 43 and 44	Administrative Body.
2. Personnel Officer	Clause 44	Deputy Chairman or Chairman
3. Deputy Chairman.	Clause 44	Chairman

(9) Without prejudice to the powers of the Chairman under clauses 45 and 51, a registered employer shall have full powers to take disciplinary action against monthly workers employed under him.

45. Special Disciplinary powers of Chairman.—(1) Notwithstanding anything contained in the Scheme, if the Chairman is satisfied that a 'go-slow' has been resorted to by any gang of registered dock workers or by any such individual worker and is being continued or repeated by the same gang of workers, or workers, of different gangs or workers on the same or different ships, he may make a declaration in writing to that effect.

(2) When a declaration under sub-clause (1) has been made, it shall be lawful for the Chairman—

(i) in the case of monthly workers, to take, without prejudice to the rights of the registered employers, such disciplinary action including dismissal against such workers, as he may consider appropriate; and

(ii) in the case of registered dock workers in the reserve pool to take such disciplinary action including dismissal against such workers as he may consider appropriate and also to order forfeiture of their guaranteed minimum wages and attendance allowance for the wage period or periods in which the 'go-slow' has been resorted to.

3. The Chairman may take disciplinary action—

(i) Where the 'go-slow' is resorted to by a gang, against all the members of the gang; and

- (ii) where the 'go-slow' is resorted to by a worker, against the worker concerned.

(4) Before any disciplinary action is taken under this clause against any dock worker or gang of dock workers such worker or gang shall be given an opportunity to show cause why the proposed action should not be taken against him or it:

Provided that the Chairman may, before giving an opportunity to show cause under this sub-clause suspend from work any worker or gang of workers immediately after a declaration has been made under sub-clause (1).

(5) (a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance equivalent to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker; the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(b) the subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever;

(c) where a dock worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 32 had he not been suspended; provided that the amounts so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during that period.

(6) Any registered dock worker who is aggrieved by an order of the Chairman under sub-clause (2) may, within 30 days of the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

46. Termination of employment.—(1) The employment of a registered dock worker in the reserve pool shall not be terminated except in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) A registered dock worker in the reserve pool shall not leave his employment with the Board except by giving fourteen days' notice in writing to the Board or forfeiting fourteen days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof.

(3) When the employment of a registered dock worker with the Board has been terminated under sub-clause (1) or (2) above, his name shall forthwith be removed from the register or record by the Administrative Body.

47. Appeals by workers.—(1) Save as otherwise provided in this clause, a worker in the reserve pool who is aggrieved by an order passed by an authority specified in column (1) of the table below under the provisions specified in column (2) of the said Table may prefer an appeal against such order to the authority specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Authority passing Order	Provision of the Scheme	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)
Labour Officer or Administrative Body	Clause 43 or 44	Deputy Chairman
Deputy Chairman	Clause 44	Chairman
Chairman	Clause 44	Central Government

(2) A worker who is aggrieved by an order—

- (i) placing him in a particular group in the register or record; or
- (ii) refusing registration under clause 18; or

- (iii) requiring him under clause 37 (4) (b) to undertake any work which is not in the same category to which he belongs,

may prefer an appeal to the Chairman.

(3) Any registered dock worker who is aggrieved by an order under clause 19(4) may prefer an appeal to the Chairman.

(4) No appeal shall lie where due notice has been given of the removal of the name of a registered dock worker from the register or record in accordance with the instructions of the Board, if the ground of removal is that the registered dock worker falls within a class or description of dock workers whose names are to be removed from the register or record in order to reduce the size thereof;

Provided that an appeal shall lie to the Chairman where the registered dock worker alleges that he does not belong to the class or description of dock workers referred to in the instructions of the Board.

(5) Every appeal referred to in sub-clauses (1), (2) (3) and (4) shall be in writing and preferred within 14 days of receipt of the order appealed against :

Provided that the appellate authority may for reasons to be recorded, admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(6) The appellate authority may after giving an opportunity to the appellant to be heard, if he so desires, and reasons to be recorded in writing, pass such order as it thinks fit.

(7) Every order passed under sub-clause (6) shall be communicated to the appellant.

(8) An appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the registered trade union of which he is a member or by a registered dock worker.

48. Appeals by employers.—(1)(a) A registered employer who is aggrieved by an order of the Personnel Officer under clause 44(1)(i) may appeal to the Deputy Chairman, who shall decide the same.

(b) If a registered employer is aggrieved by an original order of the Deputy Chairman under clause 44(1)(ii), he may appeal to the Chairman, who shall decide the same. In the case of an appeal against an order under clause 45(1)(ii)(b) the Chairman shall forthwith refer the matter to the Central Government. The Central Government shall make such an order on the appeal as it thinks fit.

(2) An employer who has been refused registration under clause 15(1)(c) may appeal to the Central Government through the Chairman. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(3) If a registered employer is aggrieved by any original order of the Chairman against him under clause 44, he may prefer an appeal to the Central Government. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(4) Every appeal referred to in sub-clauses (1), (2) and (3) shall be in writing and preferred within 14 days of the receipt of the order appealed against:

Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded, admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(5) An appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the association of registered employers of which he is a member or by a registered employer.

49. Power of revision of the Chairman and Deputy Chairman.—Notwithstanding anything contained in the Scheme, the Chairman, in the case of an order passed by the Deputy Chairman under clause 44, or the Deputy Chairman, in the case of an order passed by the Personnel Officer or the Labour Officer, as the case may be, under the said clause, may, at any time, call for the record of any proceeding in which the Deputy Chairman or the Personnel Officer or the

Labour Officer, as the case may be, had passed the order, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety thereof and may pass such order in relation thereto as he may think fit:

Provided that the Chairman or the Deputy Chairman shall not pass any order under this clause which may prejudicially affect the interest of any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard.

50. Stay of order in case of certain appeals.—Where an appeal is lodged by a dock worker in accordance with the provisions of clause 47 against an order of termination of service on 14 days' notice or where an appeal is lodged by an employer in accordance with the provisions of Clause 48 against an order removing his name from the employer's register under clause 44(1)(ii)(b), the appellate authority may suspend the operation of the order appealed from pending the hearing and disposal of the appeal.

51. Special provisions for action in an emergency.—(1) If at any time the Chairman is satisfied that an emergency has arisen which will seriously affect the working of the port, he may, by order in writing and for such period as he may from time to time specify therein, make a declaration to that effect:

Provided that no such declaration shall be made except with the previous approval of the Central Government.

(2) So long as an order under sub-clause (1) is in force, the following provisions shall apply, namely:—

- (i) if any allegation is made that a registered employer has failed to carry out the provisions of the Scheme, the Chairman may, after holding a summary inquiry into the allegation, take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—
 - (a) give the registered employer a warning in writing; or
 - (b) direct that the name of the registered employer shall be removed forthwith from the employers' register either permanently or for such period as he may determine;

Provided that no such removal under sub-item (b) shall be made except after giving the employer a reasonable opportunity of being heard.

(ii) if any allegation of indiscipline, "go-slow" or misconduct is made against a registered dock worker, the Chairman may suspend him forthwith pending inquiry hold a summary inquiry into the allegation and take any one or more of the following steps against that worker, that is to say, he may—

- (a) determine that for such period as he thinks proper that worker shall not be entitled to any payment under clause 42;
- (b) give him a warning in writing;
- (c) suspend him without pay for a period not exceeding three months;
- (d) terminate his services after giving 14 days' notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof; or
- (e) dismiss him.

Provided that no such termination under sub-item (d) or dismissal under item (e) shall be made except after giving the worker a reasonable opportunity of being heard.

(iii) (a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance equivalent to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances;

Provided that where such inquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

51 GI/75—13

(b) the subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever;

(c) where a dock worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 32 had he not been suspended, provided that the amount so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during that period.

(3) The provisions of the Scheme relating to disciplinary action against registered employers and registered dock workers shall not apply to any order passed by the Chairman under sub-clause (2).

(4) Any registered dock worker or registered employer who is aggrieved by an order passed by the Chairman under sub-clause (2) may within 30 days of the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

(5) Notwithstanding anything contained in the Scheme, so long as an order under sub-clause (1) is in force, the Chairman may authorise the employment of the unregistered workers directly by registered employers and payment to such unregistered workers, directly.

52. Cost of operating the Scheme.—(1) The cost of operating the Scheme shall be defrayed by payments made by registered employers to the Board. Every registered employer shall pay to the Board such amount by way of levy in respect of reserve pool workers together with and at the same time as the payment of gross wages due from him under clause 38(5)(i), as the Board may, from time to time, specify by a written notice to registered employers and the amount payable by way of such levy shall not be less than such amount as the Board may fix as the minimum payable by every registered employer. If considered necessary, the Board may require any registered employer to pay such amount by way of levy in respect of monthly workers at such rate as it may determine.

(2) In determining what payments are to be made by registered employers under sub-clause (1), the Board may fix different rates of levy for different categories of work or workers, provided that the levy shall be so fixed that the same rate of levy will apply to all dock employers who are in like circumstances.

(3) The Board shall not sanction any levy exceeding hundred per cent of the estimated total wage bill calculated on the basis of the daily wage rate without the prior approval of the Central Government.

(4) A registered employer shall on demand make a payment to the Board by way of deposit, or provide such other security for the due payment of the amount referred to in sub-clause (1), as the Board may consider necessary.

(5) The Administrative Body shall furnish from time to time to the Board such statistics and other information as may reasonably be required in connection with the operation and financing of the Scheme.

(6) If a registered employer fails to make the payment due from him under sub-clause (1) or any other amount due and payable to the Board in any other capacity or amount within the time specified by the Administrative Body, the Administrative Board shall serve a notice on the employer to the effect that, unless he pays his dues within three days from the date of receipt of the notice, the supply of registered dock workers to him shall be suspended. On the expiry of the notice period, the Administrative Body shall suspend the supply of registered dock workers to defaulting employer until he pays his dues.

53. Penalties.—A contravention of clause 39 shall be punishable with imprisonment for a period not exceeding three months in respect of a first contravention or six months in respect of any subsequent contravention or with fine not exceeding five hundred rupees in respect of a first contravention or one thousand rupees in respect of any subsequent contravention or with both imprisonment and fine as aforesaid.

54. Repeal and savings.—The Bombay Un-registered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, is hereby repealed :

Provided that any order made, right accrued, penalty incurred or anything done or any action taken under the said Scheme shall so far as may be, deemed to have been made, accrued, incurred or done or taken under this Scheme and any reference in any instrument to any provision of the said Scheme shall be deemed to be a reference to the corresponding provision of this Scheme.

SCHEDULE I

[See clauses 2(2), 3 (e) and 18(b)]

Classes or descriptions of dock work and dock workers to which the Scheme applies—

(1) Dock Work Handling of—

- (a) Foodgrains and fertilisers and
- (b) Other cargoes imported or exported on Food Corporation of India's account.

(2) Dock Workers :—

- (a) Mukadams;
- (b) Tindals;
- (c) Leaders;
- (d) Fillers;
- (e) Stitchers;
- (f) Palawalas;
- (g) Palawalis;
- (h) Machine Mazdoors;
- (i) Tank Mazdoors;
- (j) Dock Mazdoors;

SCHEDULE II

[See clause 31(2)]

The minimum number of days in a month for which wages are guaranteed should be assessed on the basis of average employment during the preceding 12 months according to the following procedure :—

- (a) Supposing an assessment is being made in the month of October, 1976, the total number of gang workers in the reserve pool (including Leave Reserve Workers but excluding Mukadams) as on the 1st October 1975 and the 31st October 1975 should be ascertained. The average strength on the register, of these categories should be ascertained by adding the two figures and dividing by 2.
- (b) The total number of man-shifts worked by gang workers of the categories referred to in item (a) during the month should be ascertained, from the daily employment statistics.
- (c) The total number of man-days of authorised or unauthorised leave taken by the above workers should be ascertained. This figure should be divided by the number of working days in the month to ascertain the average number of workers away on leave.
- (d) The figures ascertained as in item (c) should be deducted from the average obtained as in item (a) to arrive at the effective strength of workers available during the month.
- (e) The figure of man-shifts ascertained under item (b) should be divided by the effective strength ascertained as in item (d). The figure arrived at will be the average number of days of employment during the month of October, 1975.
- (f) The above process should be repeated for the remaining 11 months from November, 1975 to September, 1976.

(g) The average employment figures for the 12 months should be added and divided by 12.

(h) The figures arrived at in item (g) above should be fixed as the minimum number of days for which wages will be guaranteed for the following 12 months ending the 30th September, 1977.

The following example will illustrate :—

Suppose the total number of gang workers (excluding Mukadams and leave Reserve Workers

In the reserve pool as on the 1st October 1975	2,000	
In the reserve pool as on the 31st October, 1975	1,950	
	<u>3,950</u>	
Average strength on the register for the month	3,950	
	2	= 1,975
Total number of man-shifts worked by the workers of the above categories in the October, 1975	36,000	
Total number of man-days of authorised or unauthorised leave taken by the workers	5,250	
Number of working days in the said month (31 days of the month less one non-working day)	38	
Average number of workers away on leave	<u>5,250</u>	
	30	= 175
Effective strength available during the month	1975-175	= 1,800
Average employment for the month of October, 1975	<u>36,000</u>	
	1,800	= 20 days

The same procedure will be followed to arrive at the average employment for the remaining 11 months. Let us assume the figures are as follows :—

October, 1975	20
November, 1975	21
December, 1975	18
January, 1976	20
February, 1976	18
March, 1976	19
April, 1976	20
May, 1976	19
June, 1976	18
July, 1976	19
August, 1976	20
September, 1976	16
TOTAL	<u>228</u>

The number of days for which wages will be guaranteed for the next 12 months ending 30th September, 1977 will be $228/12 = 19$ days.

[No. V. 11025/4/74-P & D/LD]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1975

क्रा० प्रा० 2384:—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली मुख्य योजना में निम्न-लिखित संशोधन करने का विचार कर रही है। इसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। इन संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति/सुझाव इस आपन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आपत्ति/सुझाव दें वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधन:

1. "मुख्य योजना में इंजिनियरिंग कालेज (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महारोली रोड) के दक्षिण में लगभग 41.68 हेक्टर (103 एकड़) का भूमि उपयोग 'विशेष उद्योगों' (यूज जोन एम-3) के लिए विचाराया गया था 41.68 हेक्टर (103 एकड़) में से 25.5 हेक्टर (63 एकड़) को मुख्य योजना के भूमि उपयोग में 'विशेष उद्योगों' (यूज जोन एम-3) से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं' (यूज जोन-एफ-विशेष संस्थान) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"

2. "लगभग 0.607 हेक्टर (1.5 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर-पूर्व में 64.92 मीटर (213 फुट) चौड़ा गंकर मार्ग तथा दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम (जोन डी-6) में 'जिला उद्यान तथा खुले स्थानों' से घिरा हुआ है, इस क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजन" (जिला उद्यान तथा खुले स्थान) से "सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (धार्मिक) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"

3(अ) "लगभग 2.4 हेक्टर (6 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर-पश्चिम में 61 मीटर (200 फुट) चौड़े सरदार पटेल मार्ग, दक्षिण-पश्चिम में जिला उद्यान तथा दक्षिण-पूर्व एवं उत्तर-पूर्व में आवासीय भूमि द्वारा घिरा हुआ है। इसे अब 'आवासीय' से 'व्यवसायिक' (होटल्स) में अधिकतम 200 एफ० ए० आर० सहित परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"

(ब) "लगभग 2.4 हेक्टर (6 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर-पश्चिम में 61 मीटर (200 फुट) चौड़े सरदार पटेल मार्ग, दक्षिण-पश्चिम में रेलवे ट्रैक्स, तथा दक्षिण-पूर्व एवं उत्तर-पूर्व में आवासीय भूमि द्वारा घिरा हुआ है। इसे अब "आवासीय" से "व्यवसायिक" (होटल्स) में अधिकतम 200 एफ० ए० आर० सहित परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली, विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधनों के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

[संख्या एफ० 3(156)/71-एम० पी०]

हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th July, 1975

S.O. 2384.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objections or suggestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address

Modifications :—

1. "In the Master Plan, the land use of an area measuring about 41.68 hec. (103 acres) located in the south of Engineering College (Indian Institute of Technology, Mehrauli Road) was shown for 'Special Industries' (Use Zone M-3). It is proposed to change the land use of the Master Plan of about 25.5 Hec. (63 acres), out of 41.68 Hec. (103 acres) from 'special industries' (Use Zone M-3) to 'Public and Semi-public Facilities' (Use Zone F-Special Institutions)".
2. "The land use of an area measuring about 0.607 hec. (1.5 acres), bounded by 64.92 metres (213 ft.) wide Shankar Road in the north-east, and district parks and open spaces in the south-east, south-west and north-west (Zone D-6), is proposed to be changed from "Recreational" (District parks and open spaces) to "Public and Semi-public Facilities" (Religious)".
3. (a) "The land use of an area measuring about 2.4 hec. (6 acres), bounded by 61 metres (200 ft. wide) Sardar Patel Marg in the north-west, District park in the south-west and residential land in the south-east and north-east, is proposed to be changed from "residential" to "Commercial" (Hotels) to be developed with a maximum F.A.R. of 200".
- (b) "The land use of an area measuring about 2.4 hec. (6 acres), bounded by 61 metres (200 ft. wide) Sardar Patel Marg in the north-west, railway tracks in the south-west and the residential land in the south-east and north-east is proposed to be changed from "residential" to "Commercial" (Hotels) to be developed with a maximum F.A.R. of 200."

The plans indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3 (156)/71-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

क्रा० प्रा० 2385:—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) के साथ पठित उस धारा की उपधारा (1) और धारा 30 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवेषकारी विकासों का हटाया जाना) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपक्षमें प्रकाशन की तारीख को प्रबुद्ध होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(1) "अधिनियम" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) अभिप्रेत है;

(2) "प्रशासक" से संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली का प्रशासक अभिप्रेत है;

(3) "सक्षम प्राधिकारी" से, यथास्थिति दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगरपालिका समिति या दिल्ली छावनी बोर्ड अभिप्रेत है;

(4) "मास्टर प्लान" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित दिल्ली का मास्टर प्लान अभिप्रेत है तथा

(5) "क्षेत्रीय विकास योजना" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित किसी की विकास योजना अभिप्रेत है।

3. हेतुक दर्शित करने की सूचना का जारी किया जाना :—(1) यदि किसी विकास क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में कोई विकास, मास्टर प्लान या विकास योजना के उल्लंघन में, या अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट अनुमोदन या मंजूरी के बिना, या किन्हीं ऐसी शर्तों के उल्लंघन में जिनके अधीन रहते हुए ऐसा अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है या पूरा कर लिया है तथा सक्षम प्राधिकारी उस विकास को उतने समय के भीतर जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट किया जाए, हटाने या ब हटवाने में असफल रहा है तो प्रशासक उसके स्वामी या उस व्यक्ति से जिसकी प्रेरणा पर वह विकास प्रारम्भ किया गया है या चलाया जा रहा है या पूरा कर लिया गया है, सात दिन के भ्रम्यत और सोस दिन से अधिक की अवधि के भीतर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इस बात का कारण दर्शित करने की मांग करने वाली सूचना की तामील करेगा कि इस बात का निवेश क्यों किया जाये कि ऐसी विकास भंजन द्वारा या अन्यथा हटा दिया जाये।

(2) ऐसी सूचना इन नियमों से अनुलग्न प्ररूप 'क' में होगी और अधिनियम की धारा 43 द्वारा विहित रीति में उसकी तामील की जायेगी।

4. सुनवाई का नियत करना—(1) जहाँ नियम 43 के उपनियम (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पहले कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो वहाँ प्रशासक उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन पर ऐसे आक्षेप हैं वहाँ प्रशासक उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन पर ऐसे आक्षेप या अभ्यावेदन के बारे में सूचना की तामील की गई है, सुनने के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा।

(2) उक्त सुनवाई में, यदि कोई हो, आक्षेप या अभ्यावेदन करने वाला या बाले व्यक्ति, प्रशासक के स्वविवेक पर किसी परामर्शी के माध्यम से मामला प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया या किए जा सकेंगे।

(3) प्रशासक आक्षेप या अभ्यावेदन पर विचार करने और उस पक्षकार को सुनने के पश्चात् जिसने आक्षेप या अभ्यावेदन फाइल किया है, ऐसा निवेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे, तथा उस निवेश की एक प्रति की उस व्यक्ति पर जिस पर सूचना की तामील की गई है, निवेश दिए जाने के ठीक पश्चात् तामील करवाएगा।

5. आक्षेप या अभ्यावेदन पर विनिश्चय :—नियम 3 के उपनियम

(1) के अधीन सूचना के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए आक्षेप या अभ्यावेदन तथा नियम 4 के उपनियम (1) में वर्णित सुनवाई में आप्रह की गई बातों तथा किसी अन्य विषय या जानकारी पर जो उसके पास हों या उसके ज्ञान में आए, विचार करने के पश्चात् प्रशासक या तो यह निवेश दे सकेगा कि सूचना वापस ले ली जाए या

किसी अधिकारी को जिसका नाम उल्लिखित किया जाए, उस विकास को भंजल द्वारा या अन्यथा इतने समय के भीतर जो निवेश में विनिर्दिष्ट किया जाए या इतने बढ़ाए गए समय के भीतर जो उक्त अधिकारी से इस निमित्त अनुरोध के प्राप्त होने पर अनुज्ञात करे, हटाने या हटवाने का निवेश देगा।

प्रास 'क'

नियम 3

दिल्ली विकास प्राधिकरण (प्राक्षेपकारी विकासों का हटाया जाना) नियम, 1975 के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन सूचना सेवा में,

सं० दिल्ली, तारीख 197

यतः यह बात मेरी जानकारी में आई है कि दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका समिति/छावनी बोर्ड की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले प्लॉट सं० ————— पर निम्नलिखित विकास प्रारम्भ किया गया है/चलाया जा रहा है/पूरा कर लिया गया है, अर्थात्, —————

और यतः ऐसा विकास—

दिल्ली के मास्टर प्लान के उल्लंघन में

* इस का वर्णन * () क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका समिति/छावनी बोर्ड के, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अधीन

अनुमोदन या मंजूरी के बिना, उन शर्तों के उल्लंघन में जिनके अधीन रहते हुए दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका समिति/छावनी बोर्ड के अनुमोदन या मंजूरी का दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 12 के अधीन अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, प्रारम्भ किया गया है/चलाया जा रहा है या पूरा कर लिया गया है।

और यतः दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका समिति/छावनी बोर्ड उक्त विकास को अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस निमित्त अनुज्ञात किए गए समय के भीतर हटाने में असफल रहा है।

और यतः आप उक्त विकास के स्वामी या वह व्यक्ति है जिसकी प्रेरणा पर उक्त विकास प्रारम्भ किया गया है/ चलाया जा रहा है/ पूरा कर लिया गया है।

अतः, अब अधोहस्ताक्षरी दिल्ली विकास प्राधिकरण (प्राक्षेपकारी विकासों का हटाया जाना) नियम, 1975 के नियम 3 के अधीन आप को सूचना देता है कि आप 197— ————— के मास के— ————— दिन को या उसके पहले इस बात का कारण दर्शित करें कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 30 की उपधारा (1-क) के अधीन यह निवेश क्यों न जारी किया जाए कि उक्त विकास को भंजन द्वारा या अन्यथा हटा दिया जाए।

यदि आप पूर्वोक्त तारीख तक कारण दर्शित करने में असफल रहते हैं तो मामले का एक पक्षीय विनिश्चय किया जाएगा।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का प्रशासक

[सं० के०-11011/6/71-यू० डी० 1]

एस० महादेव अय्यर, अव्वर सचिव]

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 30th June, 1975

S.O. 2385.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), read with clause (j) of sub-section (2) of that section and sub-section (1A) of section 30, of the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Removal of Objectionable Developments) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (1) "Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957);
- (2) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Delhi;
- (3) "competent authority" means the Municipal Corporation of Delhi or the New Delhi Municipal Committee or the Delhi Cantonment Board, as the case may be;
- (4) "master plan" means the master plan of Delhi approved by the Central Government under sub-section (2) of section 9 of the Act; and
- (5) "zonal development plan" means the zonal development plan of a zone approved by the Central Government under sub-section (2) of section 9 of the Act.

3. Issue of show-cause notice.—(1) If any development in an area other than a development area has been commenced or is being carried on or has been completed in contravention of the master plan or zonal development plan, or without the approval or sanction referred to in section 12 of the Act, or in contravention of any conditions subject to which such approval or sanction has been granted and the competent authority has failed to remove or cause to be removed the development within such time as may be specified in this behalf by the Administrator of the Union territory of Delhi, the Administrator shall serve a notice calling upon the owner thereof, or the person at whose instance the development has been commenced or is being carried on or has been completed, to show cause within a period of not less than seven days and not more than thirty days as may be specified therein, as to why a direction be not issued that such development be removed by demolition or otherwise.

(2) Such notice shall be in a form 'A' appended to these rules and shall be served in the manner prescribed by section 43 of the Act.

4. Fixation of hearing.—(1) Where any objection of representation has been received before the expiry of the period specified in the notice under sub-rule (1) of rule 3, the Administrator shall fix a date, time and place for hearing the person or persons on whom notice has been served, in regard to such objection or representation.

(2) At the said hearing, if any, the person or persons making the objection or representation may, at the discretion of the Administrator, be permitted to present the case through a counsel.

(3) The Administrator shall, after considering the objection or representation and hearing the party who has filed the objection or representation, give such direction as he deems fit and cause a copy of the said direction to be served on the person, on whom the notice had been served immediately after the giving of the direction.

5. Decision on objection or representation.—After consideration of the objection or representation submitted in pursuance of the notice under sub-rule (1) of rule 3, and the points urged at the hearing mentioned in sub-rule (1) of

rule 4, and any other matter or information which may be in his possession or which may come to his knowledge, the Administrator may either direct that the notice shall be withdrawn, or direct an officer, who shall be named, to remove or cause to be removed the development by demolition or otherwise within such time as may be specified in the direction or within such extended time as the Administrator may, upon receipt of a request from the said officer in this behalf, allow.

FORM A

(Rule 3)

Notice under sub-rule (1) of rule 3 of the
Delhi Development Authority (Removal of
Objectionable Developments) Rules, 1975

To

No. _____ dated, Delhi, the _____ 197

Whereas it has come to my notice that on plot No. _____ falling within the jurisdiction of the Delhi Municipal Corporation/New Delhi Municipal Committee/Cantonment Board, the following development has been commenced/is being carried on/has been completed namely,—

And whereas such development has been commenced/is being carried on/has been completed in contravention of the Master Plan of Delhi in contravention of the zonal development plan of zone * () without the approval or sanction of the Municipal Corporation of Delhi/New Delhi Municipal Committee/Cantonment Board under section 12 of the Delhi Development Act, 1957 in contravention of the conditions subject to which approval or sanction of the Municipal Corporation of Delhi/New Delhi Municipal Committee/Cantonment Board under section 12 of the Delhi Development Act has been granted.

*to be described.

And whereas the Municipal Corporation of Delhi/New Delhi Municipal Committee/Cantonment Board has failed to remove the said development within the time allowed by the undersigned in this behalf.

And whereas you are the owner of the said development, or the person at whose instance the said development has been commenced/is being carried on/has been completed.

Now, therefore, the undersigned hereby gives you notice, under rule 3 of the Delhi Development Authority (Removal of Objectionable Developments) Rules, 1975, to show cause on or before the _____ day of _____ 197 _____ as to why a direction be not issued under sub-section (1-A) of section 30 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) that the said development be removed by demolition or otherwise.

If you fail to show cause by the date aforesaid, the matter will be decided exparte.

Administrator of the Union Territory of Delhi.

[No. K-11011/6/71-UD-1]

S. MAHADEVA AYYAR, Under Secy.

अम संवायल

भावेन

नई दिल्ली, 31 मई, 1975

का० प्रा० 2386.—यल: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्वय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और मत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

मत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 क. 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एल० मलिक होंगे जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची;

- (1) क्या पंजाब नेशनल बैंक, कलकत्ता के प्रबंधन के लिए कटक शाखा के सर्वश्री गुणनिधि नायक और एम० के० साहू, राउरकेला शाखा के श्री सी० एम० शर्मा, और सम्बलपुर शाखा के श्री कृष्ण बहादुर की सेवाओं की स्थाई कर्मचारियों के रूप में विनियमित न करना न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?
- (2) क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन के लिए उनकी कटक और भुवनेश्वर शाखाओं में दो विशेष सहायकों के पदों को उड़ीसा राज्य में तैनात उसके कर्मचारियों में से न भरना न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं?

[सं० एल-12011/3/75-डी-2(ए)]

भार० कुंजीधापदम, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st May, 1975

ORDER

S.O. 2386.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri L. Mallick shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

- (1) Whether the management of the Punjab National Bank, Calcutta is justified in not regularising the services of Sarvashri unidhi Nayak and M.K. Sahu of Cuttack Branch, Shri C. M. Sharma of Rourkela Branch and Shri Krishna Bahadur of Sambalpur Branch as permanent employees? If not, to what relief, the workmen are entitled?
- (2) Whether the management of Punjab National Bank are justified in not filling up the post of two Special Assistants in their branches at Cuttack and Bhubaneswar from amongst their employees posted in the State of Orissa? If not, to what relief the concerned employees are entitled?

[No.L.12011/3/75-DII/A]

New Delhi, the 14th July, 1975

S.O. 2387.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th July 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

PRESENT

SHRI E. K. MOIDU.—Presiding Officer.

Reference No. 21 OF 1974

PARTIES :

Employers in relation to the Allahabad Bank, Calcutta.

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers.—Sri G. D. Maheswari, Law Officer.

On behalf of Workmen.—Sri D. L. Sen Gupta, Advocate.

STATE : West Bengal

Industry : Banking

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L. 12012/50/74/LR/III, dated 21st November 1974, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the Allahabad Bank, Calcutta and their workmen, to this tribunal, for adjudication. The reference reads as follows :

"(1) Whether the existing wages of Sarvashri Jadu Polai, K. Appu, Sadhu Naik, Dhruve Charan Pusti, Murlidhar Pradan, Bamandev Naik and Nalini Ranjan Barua deserve upward revision? If so, from what date and with what details ?

(2) Whether the above workmen concerned are entitled for the benefit of provident fund ? If so, from what date and at what rate ?"

2. The Commercial Establishments Staff Union, 19/2A, Pitambar Ghatak Lane, Calcutta espoused the cause of the seven persons mentioned in the reference for their enhanced wages and their right to contribute towards the Provident fund. These persons are working at No. 1. Ronaldshay Rd., Calcutta-27 which is the residence of the Chairman and the Managing Director of the Allahabad Bank which is a nationalised bank. The union raises the contention that these persons are really the members of the Sub-staff in the Bank and as such they are entitled to get fixed scales of pay, dearness allowance and other service benefits as determined by the Desai award. The rates of salary which they draw are described in Annexure A to the written statement. They contend that the salary shall be as that of a sub-staff as described in Annexure D to the written statement. These persons made a request to the Bank to enhance their salary by their letter dated 25-1-1974. But the bank did not take any steps. The matter was, therefore, referred to the Regional Labour Commissioner (C), Calcutta by their letter dated 19-3-1974 for intervention, but due to the resistance of the Bank no conciliation could be effected and hence the matter was referred to this Tribunal for adjudication.

3. The management in their written statement raises the contention that the Commercial Establishments Staff Union, Calcutta has no representative character to espouse the cause of these persons. It is alleged that neither these persons nor the union made any demand prior to the reference to redress their grievances and as such the management stated that there is no industrial dispute which came into existence between the

parties. On merits they raise the contention that these seven persons have never been the members of the Staff of the bank; on the other hand, they have been domestic servants employed in the residence of the Officers of the bank and that they are, therefore, not entitled to any relief as they do not come under the ambit of the definition of workman in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. They state that these domestic servants have been excluded from the operation of the Desai award as they were not found to be workers of the bank. They further contend that the Bank having not appointed these persons as bank's employees and having no supervision and control over their work and having not made any payment of wages to these persons by the bank, these persons would not be regarded as workmen much less that they are allied to any industry. On these grounds the Bank state that the reference has to be rejected. The management has also filed a rejoinder reiterating their stand and denying the major allegations made by the union in their written statement.

4. Out of the contentions of the parties the following points arise for determination, (i) whether the seven persons referred to in the reference are workmen of Allahabad Bank within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947 or they are only domestic servants of the General Manager of the Bank in his residential bungalow; (ii) whether the reference itself is incompetent as no industrial dispute existed between the parties prior to the reference, (iii) whether the Commercial Establishments Staff Union, Calcutta is competent to espouse the cause of these seven persons in a representative capacity independently of the union of the Employees of the Bank establishment or of an appreciable number of such employees and (iv) to what relief are these seven persons entitled?

5. Point No. (i) :

The seven persons mentioned in the reference are :

1. Jadu Polai
2. Sadhu Naik
3. Murlidhar Pradan
4. Dhruba Charan Pusti
5. Bamandev Naik
6. K. Appu
7. Nalini Ranjan Barua.

Of these persons Nos. 1 and 2 are Gate-men, Nos. 3 and 4 are Garden Mails, No. 5 Sweeper, No. 6 House bearer and No. 7 cook. They all work at 1, Ronaldshay Road, Calcutta-27 which is the residential house and compound of the Chairman and the Managing Director of the Allahabad Bank. The persons mentioned in sl. Nos. 1 and 5 have been in service for about 20 years while Nos. 2 and 6 for about 7 years while Nos. 3 and 4 for 10 years and No. 7 has only put in 4 years service. The residential bungalow where the Chairman lives is a little away from the bank premises. He is given accommodation free as a condition of his service as Chairman. The case of these persons is that they are bank employees while the case of bank is that they are only domestic servants working in the residential bungalow of the Chairman.

6. On behalf of the Bank two of its officers were examined at witnesses Nos. 1 and 2 and on behalf of these persons three witnesses were examined; the first witness was one Sri Roy Choudhury who was the President of the Commercial Establishments Staff Union. The second witness on their behalf was Murlidhar Pradan who is one of the Garden mails and the last witness was Jadu Pelai who is one of Gate-men. The parties have also produced some documents in support of their respective contentions. It is, therefore, necessary to consider the relevant contentions of both the parties.

7. The oral evidence in the case does not make much advance in the contention of these persons to prove that they are bank employees. There was no evidence either oral or documentary to prove that these persons have been appointed by the Bank. It is the definite case of the bank that these persons have been appointed either by the Manager or the custodian or the Chairman as and when they required domestic servants without any reference

to the bank. In the absence of any material on record it is difficult in the first instance to hold that the bank made the appointments of these persons. Evidently these persons have been working only in the bungalow of the Chairman. Their day to day work is supervised and managed at the bungalow of the Chairman and not by any officers of the bank. There was no regular attendance register maintained in the Bank or at the bungalow as regards their day to day attendance. There was also no acquittance roll or pay bill register in which the salaries of these persons have been paid through the bank. There was no occasion for the bank to exercise any disciplinary action against these persons. The bank has produced Ext. M-6 to M-17 debit accounts to show that the wages of these persons were being paid by the Chairman and the Managing Director as domestic servants. The evidence is that after the payment was made the Chairman has to get the amount recouped through bills and the bank made these payments to the Chairman. Apart from these documents there was nothing else produced on the part of these persons to show that they received any salary from the bank direct. The witness No. 2 on behalf of the bank denied that salary was paid to these persons from the bank direct. These persons were not in a position to produce any other document or reliable evidence to show that they had been receiving their salary from the bank. However, they have produced some documents and one such document is marked as Ext. W-9. No attempt had been made to prove this document. It was said to have been signed by one Mr. M. J. MacLaren on 27-5-1959 sanctioning extension of leave to one Jadu Polai who was one of the Gate-men in this case. The paper on which this Ext. W-9 is typed appears to be very fresh. It has not got a look of an old letter. It is significant that Ext. W-9 was typed at the Bank House and was purported to have been despatched from that place. That was an indication that bank had nothing to do with the extension of leave granted to Jadu Polai. They have relied upon Exts. W-10 and W-10(a), prescriptions by one Dr. Guha, who was said to be a part-time doctor of the bank. But Ext. W-7 a photo-stat copy of a Debit entry in respect of medical charges was not proved to have any connection with Exts. W-10 or W-10(a) much less that the original of Ext. W-7 was issued by any officer of the bank. In the absence of convincing proof the genuineness of Ext. W-7 cannot be accepted. The next letter is Ext. W-12. Second witness of the management has denied the genuineness of this letter though he admitted that Ext. W-12 is typed in a letter-head sheet of the bank giving in it also a reference number. But, there is no evidence as to the person who signed this letter. The purport of this letter was to authorise Dhruba prusty, Garden-mali in this case to purchase 10 items of vegetable seeds for the bank's garden with a direction that the bank would pay for it in due course. It was addressed to The Agri-Horticultural Society, Alipore, Calcutta-27. The letter is dated 15th December, 1972. The purchase of seeds for the purpose of the garden by itself was not a circumstance to show that the Garden-mali Pusti was an employee of the bank. Apart from these suspicious documents and unreliable oral evidence there is nothing in this case to show that these persons had been employed by the bank and the continued in service as its employees. I went through the evidence of the three witnesses examined in this case on behalf of Labour and I find that on the basis of their evidence no conclusion is possible that they are bank employees.

8. A series of decisions beginning from D. N. Banerjee v. P. R. Mukherjee, 1953 I LLJ, 195, Supreme Court and ending with Madras Gymkhana Club Employees Union v. Gymkhana Club, 1967 II LLJ, 720 and the Management of the Federation of Chambers of Commerce and Industry v. R. K. Mittal, 1971 II LLJ, 630, laid down certain characteristics of industry as defined in Section 2(f) wherefrom it can be said that a crystallisation has been reached regarding its attributes by the dictum of the Supreme Court. Those attributes are :

1. The activity should be undertaken systematically or habitually for the production or distribution of goods or for rendering of material services to the community at large or a part of such community.
2. The activity should not be casual nor must it be for oneself nor for pleasure.

3. The activity should be organised or arranged in a manner in which trade or business is generally organised or arranged. In other words, it must bear the definite character of trade or business, or manufacture or calling or must be capable of being described as an undertaking resulting in material goods or material services.
4. The activity should be carried on with the cooperation of the employer and the employees.
5. The activity should fall within the denotation of the definition of "industry" in Section 2(j) in the first part, the 2nd part then will show what will be included from the angle of the employees.
6. The object of the activity should be the satisfaction of material human needs i.e. corporeal needs not spiritual.
7. The activity must not be in exercise of merely governmental functions.
8. The activity should not bear the character of administrative service of public officials.
9. The activity should not be of the character of personal service rendered by domestic or other servants.
10. The activity should not be of the nature of professional service such as those of Doctors, Teachers, Lawyers and Solicitors, etc.
11. The activity should not be educational or of cultural nature.

In the case of the Management of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry v R. K. Mittal, 1971 (2) L.L.J., 630, the Supreme Court observed that "there is no warrant to allow any other element to be added to the criteria laid down for determining what industry is." It will be seen that the Supreme Court excluded the personal service rendered by domestic and other servants from the purview of industry. The activities which appertain to an industry must be an organised one and not that which pertains to provide personal employment. The activity should have predominantly been carried on by employer of organised labour force for production or distribution of goods or for rendering material services to the community at large or a part of such community. Such activity should be involving the co-operation between employer and employees for the object of satisfying material human needs but not for oneself nor for pleasure. In other words, where the services are to the employer themselves for their own pleasure and the material goods are for their own consumption and services are their own pleasure and amusement, the activity cannot be an industry. Hence, an activity pertaining to or in relation to a private and personal employment has to be excluded from the definition of the industry.

9. Domestic employment cannot be regarded as "in the course of the industry" because the employment of domestic servant has no resemblance to trade, business or industry. Domestic servants have a calling or an occupation but cannot be said that their employment is an industry. Nor are the private house-holder employers who carry on an industry as contemplated by the Act. There is no cooperation between capital and labour which is necessary to constitute an industry. The domestic servant renders services purely of a personal nature. The question, however, may depend upon the facts and circumstances of a particular case to ascertain whether the work of an employee is of a domestic nature or industrial nature.

10. The definition of workman in Section 2(s) like the definition of "employee" in Section 4 of the Australian Commonwealth Conciliation and Arbitration Act, refers to the nexus of the person being employed in an industry. In other words, unless the person is employed in an activity which is an industry, he will not be a workman within the meaning of the definition of Sec. 2(s). The expression "employed in any industry" in Sec. 2(s) may take in employees who are employed in connection with operations incidental to the main industry. But, what is the scope of such incidental operation has yet to be known. In *J. K. Cotton Spinning and Weaving Mills Co., Ltd., v. Labour Appellate Tribunal*, 1963 (2) L.L.J. 436 the Supreme Court cautioned the

need to prescribe a limit in dealing with the question of incidental relationship in the main industrial operation so as to exclude the operation or activities whose relation with the main industrial activity may be remote, indirect and far-fetched. In that case the question was whether the malis employed in the residential bungalows of the officers or Directors of a Textile Mill as required by the terms and conditions of the employment of such officers and Directors fell within the definition of workman in Sec. 2(s) of the Act. That was a peculiar case where the facts and circumstances were different from the instant case. The Court found as a matter of fact in that case, "It is also clear that the malis are appointed by the Appellant (Textile Mill) . . . the names of the malis are borne on a register maintained by the clerk of the Appellant who supervises their work. This clerk notes their attendance day to day. Their appointment is made by the Appellant. Their work is supervised and controlled by the Appellant and they are liable to be dismissed by the Appellant." None of these circumstances exist in the instant case. It was in the peculiar facts and circumstances of that case that the Supreme Court held that like transport amenity provided by the factory to the employees, bungalows and gardens are also a kind of amenity supplied by the employer to his officers and the drivers looked after the cars and the malis looked after the gardens must, therefore, be held to be in connection with the operation which was incidentally connected with the main industry carrying on by the employer. The later case reported in *University of Delhi v. Ramnath*, 1963 (2) L.L.J., 335 and *Safdarjung Hospital v. Kuldeep Sethy*, 1970 (2) L.L.J. 266, adopted a different line of argument holding that there shall be some correlation between the activities carried on by a person and the main activity of the industry carried on by the employer to make him a worker within Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947.

11. Reliance has been placed by both sides on the Sastry award as well as on Desai award. But these awards did not take into account the conditions of service of those employees who are engaged in the residential bungalows of the officers of the bank. In paragraph 334 of Sastry award, however, the following observations are made :

"Another minor point raised by the Imperial Bank of India relates to the class of employees described as domestic servants. The Bank states that they are by way of amenities to officers. It claims that they are not workmen within the definition of the Act. It is admitted, however, that they are all appointed and paid by the Bank. Their names appear on the Bank's pay roll. When officers leave the premises, they generally act as caretakers of the Bank's property and premises. We hold accordingly that they are workmen and cannot be excluded from our jurisdiction."

But this conclusion has been the subject matter of consideration in Desai award. In Desai award in paragraph 5.194 the following observations has been made :

"It sometimes happens that banks pay for persons who are employed as cooks and domestic servants to do the work exclusively for officers of the bank at the residence of such officers. By reason of the fact that they have been employed by the bank, they may be liable to be regarded as workmen. In paragraph 334 of its award the Sastry Tribunal has held that domestic servants who are appointed and paid by the bank are workmen. Some of them may be provided with a place of residence free of charge and some of them may be provided with free food. I have not before me the exact terms and conditions under which they work. Even if they were workmen, I am unable to lay down any scales of pay for them in the absence of any material on which the same could be laid

down. The scales of pay herein provided are not intended to apply to them. The banks will be at liberty to fix such emoluments for them as they consider reasonable and just."

Again at page 256, paragraph 16.9 a further remarks have been made. These observations will make clear that there was no occasion for fixation of the wages of the various persons who were employed in the residential bungalows of the officers of the bank. So, the observation in these awards will not help us in any manner. It is for the persons who assert that they were workmen of the bank to satisfy the conditions so as to enable the tribunal to come to a conclusion that they are workmen within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act. Satisfactory evidence was not forthcoming in this case. The evidence laid on the side of these persons was not sufficient to establish that they were workmen. On the other hand, the bank established that they were domestic servants working in the bungalow of the Chairman of the Bank. This point is therefore found against the persons mentioned in the Reference.

12. Point No. (ii):

This point arises out of the contention that without a demand by the workmen raising first with the management as to the dispute and rejected by them, there cannot be an industrial dispute to arise and to exist and that to make such a demand to the conciliation officer and its communication by him to the management and then the management to reject the demand is not sufficient to construe it as an industrial dispute. There is a direct authority on this point which finds a place in Messrs Andrew Yule & Co., Ltd., vs. Fifth Industrial Tribunal, West Bengal and Others, 1974 (29) Indian Factories and Labour Reports, p. 280. The decision reads

"If no dispute at all has been raised by the workmen with the Management, any request sent by them to the Government would only be a demand by them and not an industrial dispute between them and without a dispute being raised by the workmen their employer. A mere demand to a Government, with their employer, cannot become an industrial dispute . . . the workmen must first raise a demand on the Management and in the absence of any such prior demand, there cannot be an industrial dispute which can be said to arise and exist. Even if a demand is made to a Conciliation Officer, and the communication by him to the Management cannot constitute an industrial dispute."

This decision is based upon an earlier decision of the Delhi High Court reported in the case of Fedders Lloyd Corporation (P) Ltd., v. Lt. Governor, Delhi, A.I.R. 1970, p. 60(1970 Labour I.C., 421). However, it distinguished another case reported in the management of Radio Foundation Engineering Ltd. and another v. State of Bihar 1970 Labour I.C. 1119 (A.I.R. 1970, Patna, 295). But these decisions do not refer to the Supreme Court decision in the case of Bombay Union of Journalists v. The Hindu, 1961, 1 L.L.J., 13. It is stated in the written statement of these persons facts of the present case as it has been proved that there had been a demand on the employers at the instance of these persons as well as by the union antecedent to the reference.

13. It is stated in the written statement of these persons that they sent their demand to the employers first in a letter which is Annexure B to their written statement. That letter was dated 11-1-1974. That was followed by a letter of the union which is Annexure C to their written statement dated 25-1-1974. These letters are sought to be proved through the Union President who is the first witness on their side. In response to the demand the Assistant Labour Commissioner (C), Calcutta called upon the parties to appear before him for a conciliation. A similar copy like the letter Annexure B was sent to the Assistant Labour Commissioner by these persons. It was on the strength of this letter that conciliation proceeding was held and both parties appeared before the Conciliation Officer. The final hearing was on 3-6-1974. The management was not amenable to conciliation. Therefore the Assistant Labour Commissioner sent his failure report dated 7th June, 1974 to the Government. The question is whether there was sufficient proof in support of the case of these persons that they made a demand to the employer at any time prior to the reference was made by the Government for adjudication. The evidence on the side of

these persons was conclusive to prove that a demand had been made. The witness examined on behalf of the bank were not able to give any counter evidence in this regard except saying that they were not aware of any such application having been made by these persons to the Bank on the basis of Annexure B or Annexure C. The case of the union was that these letters had been sent by registered post. It is true that the union did not produce the Postal acknowledgement receipts in the case sufficiently early to enable the Bank to trace out the letters which were sent in support of these acknowledgement receipts. The acknowledgement receipts were marked Exts. W 8 and W 8 (a). Ext. W 8 purports to be an acknowledgement of the letter Annexure B and Ext. W8(a) purports to be the acknowledgement of the letter in Annexure C. Both the Exts. W8 and W8 (a) contain the seal of the Allahabad Bank as well as a signature. The signature in Ext. W 8 is dated 24-1-1974 and the signature in Ext. W 8 (a) is dated 5-3-1974. The Bank has no explanation as to the letter which they received on the basis of Exts. W 8 and W 8(a). The evidence of the union President is that both these exhibits represent the real acknowledgement by the Bank of their two Annexures B and C. Though the union played a little hide and seek with regard to Ext. W 8 and W8(a) regarding their production in the Court, the circumstances show that they would have connected the letters Annexure B, and C. Exts. W 8 and W(a) were produced by the witness during cross-examination. Yet, the Bank was given time to produce documents to show whether Exts. W 8 and W 8(a) were not the genuine documents. It is significant to note that a copy of the demand letter just like Annexure B finds a place in the file of the Assistant Labour Commissioner. That was an indication that the original of Annexure B would have been prepared for sending to the employer. The evidence on the side of the union was, therefore, conclusive that the demand had been made to the employer before the reference so as to constitute an industrial dispute between the parties. This point is found in favour of the seven persons.

14. Point (iii) :

The difficulty that arises in this case is because of the fact that the cause of the workmen in the bank establishment which an industrial is sponsored by a Union which is not of workmen of that establishment but it is one of which membership is open to workmen of the establishments in that industry. This question came up for consideration in Bombay Union of Journalists v. The Hindu, 1961 (2) L.J. 436. In that case it was revealed that during the relevant time there were 9 employees in the Bombay office of "Hindu" of which 7 were on the administrative side and 3 on the working journalists section. The employees of Head office had a common union. But two out of three on the working journalist joined a different union which is Bombay Union of Journalists. One of these employees who joined the Bombay Union of Journalists, who had been dismissed from the Hindu management prevailed upon his Union to espouse his cause. The question arose whether the union can espouse his cause. The Supreme Court laid down (1) the industrial dispute Act excluded its application to an individual dispute as distinguished from a dispute involving a group of workmen unless such a dispute is made a common cause by a body from a considerable section of workmen and (2) the members of a union who are not workmen of the employers against whom the dispute is sought to be raised, cannot by their support convert an individual dispute into an industrial dispute. In other words persons who seek to support the cause must themselves by directly and substantially involved in the dispute and persons who are not the employees of the same employer cannot be regarded as so interested. The Bombay Union of Journalists not being a Union of the employees of the Hindu, Bombay but union of employees in the industry of journalism in Bombay its support of an individual dispute could not convert it into an industrial dispute. The members of such a union cannot be said to be the persons substantially and directly interested in the dispute between the workmen concerned and his employer. The decision in Workmen v. Dharampal Premchand (Sanghandi) 1965 (1) L.J., 668 does not run counter to the above decision. However, in Workmen of Indian Express Newspapers (P) Ltd., v. The management, 1970 (2) L.J., 132, the evidence was 31 out of 68 working journalists. 132, the evidence was 31 out of 68 working journalists. The Supreme Court held relying on Premchand's case that 31 persons becoming members of the union gave to it representative character qua the working journalists employed in the company.

A representative character of the union has to be gathered from the strength of the actual number of co-workers sponsoring the dispute. The Calcutta High Court case reported in *Air France v. Miss Kotwall*, 1970 (2) LLJ 68, did not touch upon this point as the case was remanded to the Single Judge who disposed it first on question of fact. There again it was a case of dismissal of a workman, which can be made into an industrial dispute because of Section 2A of the Industrial Disputes Act.

15. These decisions do not help us to decide the issue in the instant case. Here the seven persons mentioned in the reference constitute a section of the bank employees. When there is a section working separately it is open to that section to join another union and get their cause espoused to constitute an industrial dispute. There is clear evidence that these seven persons are members of the union. Ext. W 1 is the Rules of the union. The seven persons have been enlisted as members. Ext. W 2 and W 2(a) are receipt books, Ext. W 3 is the register of members. Item 214 to 220 are the seven persons who became members of the union. Ext. W 5 series are the applications which these persons made to the union to become members. On 31-1-1974 a meeting of the Executive Committee was held in the presence of the seven persons and they decided to sponsor the workers as members of the union and take up their cause for conciliation or adjudication. The evidence was therefore conclusive that the seven persons are members of the union. When there is a union for a section, it is not necessary that the other employees of the establishment or union of that establishment should espouse the cause of these persons. There is a direct ruling on this point reported in 1959 (2) LLJ, p. 781. *Buckingham and Carnatic Company, Ltd. and Its Staff Union* and another. The relevant portion of the judgment reads as follows :

"Mr. Rajah Ayyar was unable to cite any decision in which it has been expressly held that to decide whether there is an industrial dispute or not within the meaning of the definition the establishment should be taken as one unit, though there may be several well-defined sections of workmen employed in the establishment, and that in ascertaining whether the cause of a particular aggrieved workman has been taken up by a union or a substantial number of workmen, only one union should be taken into account and the total number of workmen employed in all the sections should be taken as a single individual unit. If that position is applied to the industrial establishment in question it would mean that there can be no industrial dispute unless the cause of a particular workman or a number of workmen is taken up by a substantial number of the entire body of workmen employed in the establishment. There is a union called the Madras Labour Union in which a large number of employees of the establishment are members. According to Mr. Rajah Ayyar this is the only union which could take up the cause of any workmen in the establishment. In the first place there is no provision of which we are aware which precludes there being more than one union of workmen employed in an establishment. There is nothing to prevent each section of workmen having a union or association of their own, to safeguard the interests of the workmen employed in that section. Section 2(s) of the Industrial Disputes Act contemplates workmen being employed to do manual, supervisory, technical or clerical work in the establishment. There may be peculiar demands from workmen employed in the different sections of an establishment. Suppose there is a large industrial establishment carrying on the business of mining; there may be a large clerical section employed in the office of the establishment in a city, whereas there may be hundred of workmen employed at the mines which may be even several miles away from the office of the establishment. It seems most unreasonable to say that the grievances of persons employed in the mining section cannot give rise to an industrial dispute unless the majority of the employees in all the sections of the establishment takes up their grievance."

The above observation is conclusive in the case to show that the union in question has a representative character to espouse the cause of these persons independently of the other employees of the establishment or their union. This point is found against the Bank.

16. Point No. (iv).

In view of my finding in Point No. (i), the reference fails; the persons mentioned in the Reference are not entitled to any relief and as such the reference is rejected.

An award is passed accordingly.

Dated, Calcutta,

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

The 2nd July, 1975.

[No. L. 12012/50/74/LRIII]

K. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

प्रादेश

नई दिल्ली, 12 जून, 1975

का० प्रा० 2388.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध धनुसूची में विनिश्चित विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की दक्षिण गोविन्दपुर कोलियरी, शाकघर सोनारडिह, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

प्रतः, जब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रतिकरण संस्था 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

धनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की दक्षिण गोविन्दपुर कोलियरी, शाकघर सोनारडिह जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, श्री घननाथ गोप टिम्बर मिस्त्री को 3 फरवरी, 1975 से स्वतन्त्रता करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस धनुसूची का हकदार है ?

[संख्या एल-20012/29/75-डी-3(ए)]

ORDER

New Delhi, the 12th June, 1975

S.O. 2388.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of South Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of South Govindpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad, in transferring Shri Ajnath Gope, Timber Mistry, from 3rd February, 1975 is justified? If not to what relief is the said workman entitled?

[No. L-20012/29/75-D.III(A)]

आवेश

नई दिल्ली, 16 जून, 1975

का० प्रा० 2389.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाख्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की जोगीडिह कोलियरी, डाकघर टुण्डू, जिला धनबाद के प्रबन्धन से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकार के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की जोगीडिह कोलियरी डाकघर टुण्डू, जिला धनबाद से सम्बद्ध नियोजकों का श्री गौरी शंकर सिंह, मुन्शी को 20 सितम्बर, 1974 से पदच्युत करना म्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है?

[संख्या एल-20012/24/75-डी-3(ए)]

एल० के० नारायणन्, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 16th June, 1975

S.O. 2389.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jogidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Tundoo, District Dhanbad, and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the employers in relation to Jogidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Tundoo, District Dhanbad, are justified in dismissing Shri Gouri Shanker Singh, Munshi, from service, with effect from 20th September, 1974? If not, to what relief is the workman entitled and from what date?

[No. L-20012/24/75/D.III(A)]

New Delhi, the 16th July, 1975

S.O. 2390.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Golukdih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Jharia and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th July, 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri K. K. Sarkar, Judge, Presiding Officer.

Reference No. 32 of 1974

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Golukdih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Jharia, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employer.—Shri Prasanta Burman, Legal Assistant.

On behalf of the workmen.—Shri J. D. Lal, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union, Dhanbad.

State : Bihar

Industry : Coal.

Dhanbad, the 5th July, 1975

AWARD

The Government of India Ministry of Labour, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Golukdih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Jharia, Dist. Dhanbad and their workmen, by their Order No. L-2012/161/73-LRII dt. 16-12-1974 referred the same to this Tribunal under section 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act. for adjudication on the issue mentioned in the schedule below :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Golukdih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Jharia, Dist. Dhanbad, in stopping Shri Kisto Gorai, Pump Khalasi from work is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled and from what date?"

On receipt of the Order of reference notices were duly issued to and served on the parties. The parties appeared and filed their respective written statements in due course. The reference proceeded along its course and thereafter the parties took one or two adjournments for filing a settlement. Ultimately on 30-6-75 the learned Advocate for the workman and the learned representative of the Bharat Coking Coal Ltd. appeared and filed a Memorandum of settlement. I heard parties on the memorandum of settlement and both side submits before me that industrial dispute has been amicably settled and that an award may be passed by the Court in terms of the memorandum of settlement. The settlement has been signed by Shri A. V. Brahma, Sub-Area Manager, Jharia Golukdih Sub-Area on behalf of the management and by Shri J. D. Lal, the Secretary of the Bihar Colliery Kamgar Union representing the workman. The terms of the settlement are reasonable and proper and,

therefore, nothing stands in the way of an award being passed in this case.

Accordingly I pass an award in respect of the industrial dispute referred to me in terms of the memorandum of settlement filed which do form a part of the award as annexure A.

Sd/-

K. K. SARKAR, Presiding Officer.
Tribunal (No. 2), Dhanbad.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD**

In reference No. 32 of 1974

Employees in relation to Central Golukdih Colliery and their workmen.

Petition for Compromise settlement.—

The humble petitioners on behalf of the parties in the above matter most respectfully sheweth.

1. That the parties have voluntarily agreed to amicably settle the above noted dispute on the terms and condition stated below :—

Terms of settlement:

(a) The management agrees to reinstate the concerned workman, Shri Kristo Gorai in any job in Category 'II' in any colliery of No. C.C.L. men Golukdih Colliery within 15 days of his reporting for work to the Sub-Area Manager.

(b) It is agreed that if the workman fails to report for duty within 15 days of the date of settlement he will forfeit his right to employment.

(c) The management agrees to maintain the continuity of service of the workman for the purpose of gratuity from 29-1-1973.

(d) The Union and the workman agree not to claim any wages or bonus or any monetary benefit, etc. for the period of his idleness, relating to the present dispute i.e. prior to the date of this settlement.

(e) The management agrees to pay to the Union Representative, Rs. 100 (Rupees one hundred) only as cost of proceedings on the date of settlement.

(f) It is agreed that the above terms of settlement fully and finally resolve the above dispute, and parties shall have no other claim against each other in this matter. It is further agreed that the settlement is to come into effect immediately.

The humble petitioners submit that the above terms of settlement are reasonable and proper and pray that the Hon. Tribunal may be pleased to approve of the same, and pass award in terms herein above

Sd/-

Shri J. D. LAL, Secy.

Bihar Colliery Kamgar Union,

For the employer :

A. V. BRAHMA, Sub-Area Manager.
[No. L-20012/161/73/LRII/DIIIA]

S.O. 2391.—In pursuance of section 17 of the industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kusunda Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th July, 1975.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL (No. 2) AT DHANBAD**

PRESENT :

Shri K. K. Sarkar, Judge, Presiding Officer.

Reference No. 14 of 1975

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kusunda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad,

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers.—Shri P. K. Burman, Legal Assistant.

On behalf of the workmen.—Shri Lalit Burman, Secretary, United Coal Workers' Union.

State : Bihar.

Industry: Coal.

Dhanbad, the 5th July, 1975

AWARD

The Government of India Ministry of Labour, being of opinion that an Industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kusunda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad and their workmen, by their Order No. L-2012/107/74-LR. II dt. 10-2-1975 referred the same to this Tribunal under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act. for adjudication on the issue mentioned in the schedule below :

SCHEDULE

"Whether the management of Kusunda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad, were justified in stopping the employment of Shri Badruddaja, Attendance Clerk/Chargeman, Kusunda Colliery, with effect from the 13th November, 1971. If not, to what relief is the workman entitled?"

On receipt of the Order of reference notices were duly issued to and served on both the sides who appeared in this Tribunal and filed their respective written statements. The learned representative representing the workman and the employers parried for time for settlement in this case which was allowed. Then on 30-6-1975 a memorandum of settlement signed by both sides were filed. I heard bothsides on the memorandum of settlement and it is submitted by both of them that the industrial dispute has been amicably settled. It is further prayed that an award may be passed in this case on the basis of the terms and conditions as embodied in the memorandum of settlement. The settlement has been signed by Shri Lalit Burman, Secretary, United Coal Workers' Union representing the workman and by Shri R. N. Mishra, Sub-Area Manager, Kusunda Sub-Area of the management. The terms of settlement appear to be just and proper and, therefore, nothing stands in the way of an award being passed accordingly.

I, therefore, pass an award in respect of the Industrial Dispute referred to me on the basis of the terms as embodied in the memorandum of settlement which do form a part of the award as Annexure A.

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

ANNEXURE A

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

Reference No. 14 of 1975

Employers in relation to Kusunda Colliery of M/s. Bbarat Coking Coal Ltd.

AND
Their Workmen

Joint Petition of Compromise

The parties-Employers and workmen-concerned in the above matter beg to jointly submit as follows :—

1. That the parties have mutually discussed and have amicably settled the dispute on the following terms and conditions :—

- That the management of the Kusunda Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. hereby agree to give employment to Shri Badruddoza, the workman concerned, as C.M.P.F. Clerk at Kusunda Colliery with immediate effect.
- That Shri Badruddoza shall be deemed to be in continuous employment of the Kusunda Colliery from 9-1-1971 for the purposes of Gratuity only but shall not be paid any wages for the period of his idleness from 13-11-1971 till the date of his joining as per clause (a).
- That as a gesture of goodwill, the management shall pay to Shri Badruddoza a lump sum amount of Rs. 900 as exgratia payment within 30 (thirty) days from date.
- That the management shall pay to the Union a sum of Rs. 100 (Rupees one hundred) only as cost.

2. That the parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to hold that the above terms of Settlement as fair and reasonable.

3. That the parties further pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an award on the basis of the above terms of settlement.

And for this, the parties shall pray.

Dated 26th June, 1975.

For the Employers.

For the Workmen.

R. N. MISHRA, Sub-Area
Manager Kusunda Sub-areaLALIT BURMAN, Secy.
United Coal Workers Union.

Witnesses :

(1) A. K. Pal

(2) R. R. P. Singh.

[No. L-20012/107/74/LRII/DIIIA]
L. K. NARAYANAN, Section Officer (spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जून, 1975

का० प्रा० 2392.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाययुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में हुट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड, हुट्टी डाकघर (रायचूर जिला) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या हुट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड, हुट्टी डाकघर (रायचूर जिला) के प्रबन्धतंत्र की, कम्पनी के सुरक्षा निरीक्षक-श्री सुरेश बाबू की सेवाएँ 18 दिसम्बर, 1973 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-29012/27/74-एल० प्रार०-4-डी-4(बी)]

New Delhi, the 13th June, 1975

ORDER

S.O. 2392.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Hutti Gold Mines Company Limited, Hutti Post Office (Raichur District) and their workman in respect of the matter specified in the Schedule here-to annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narasinga Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Hutti Gold Mines Company Limited, Hutti Post Office (Raichur District) was justified in terminating the services of Shri Suresh Babu, the Security Inspector of the Company with effect from the 18th December, 1973? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-29012/27/74-LR-IV-D-IV(B)]

आदेश

का० प्रा० 2393.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाययुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजप के प्रबन्धतंत्र से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजन के प्रबंधन में की 19 अप्रैल, 1969 से श्री ए० एफ० लोबो, ओवरसीयर की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है?

[संख्या एल-30012/1/75-डी-4(बी)]

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

S.O. 2393.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Oil India Limited, Duliagan and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Oil India Limited, Duliagan in terminating the services of Shri A. F. Lobo, overseer with effect from the 19th April, 1969 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-30012/1/75-D-IV (B)]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जून, 1975

का० घा० 2394.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री सुरेन्द्र सिंह मथारु, खान स्वामी स्टेशन रोड, कोटा, राजस्थान की पातपादा बलुआ पत्थर की खानों के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है;

अतः, अध, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री सुरेन्द्र सिंह मथारु, खान स्वामी, स्टेशन रोड, कोटा-2, राजस्थान की पातपादा बलुआ पत्थर की खानों में नियोजित कर्मकार, संवेतन राष्ट्रीय और त्योहारी अवकाश दिनों की स्वीकृति के हकदार हैं? यदि हाँ, तो कितने और किन-किन अवसरों पर?

[संख्या एल-29011/9/75-डी० ओ० 3(बी)]

एस० एच० एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 19th June, 1975

S.O. 2394.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Patpada Sand Stone Mines of Shri Surendra Singh Matharu, Mine Owner, Station Road, Kota, Rajasthan, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in Patpada Sand Stone Mines of Shri Surendra Singh Matharu, Mine Owner, Station Road, Kota-2, Rajasthan are entitled for grant of paid national and festival holidays? If so, how many and on what occasions?

[No.L-29011/9/75-D. O.3 (B)]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1975

का० घा० 2395.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 71G की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व भ्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० घा० 2430 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को रेल श्रमिकों के 'पर्यवेक्षकों' के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:—

- (i) मुख्य भ्रम-आयुक्त (केन्द्रीय)
- (ii) सभी उप भ्रम-आयुक्त (केन्द्रीय)
- (iii) सभी प्रादेशिक भ्रम-आयुक्त (केन्द्रीय)
- (iv) सभी सहायक भ्रम-आयुक्त (केन्द्रीय)
- (v) सभी भ्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)

[सं०-66025/4/71-एफ ए सी]

एस० एन० सक्सेना, विशेष कार्य अधिकारी

New Delhi, the 11th July, 1975

S.O. 2395.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 71G of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), and in supersession of the Notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S. O. 2430, dated the 19th August, 1963, the Central Government hereby appoints the following persons to be 'supervisors' of railway labour, namely:—

- (i) The Chief Labour Commissioner (Central)
- (ii) All Deputy Chief Labour Commissioners (Central)
- (iii) All Regional Labour Commissioners (Central)
- (iv) All Assistant Labour Commissioners (Central)
- (v) All Labour Enforcement Officers (Central)

[No. S-66025/4/71-FAC.]

S. N. SAXENA, Officer on Spl. Duty.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1975

का० प्रा० 2396.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि क्वाटिजाइट, क्वाट्स और सिलिका खानों में नियोजन की बाबत मजदूरी की न्यूनतम वरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन नियत की जानी चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सूचना देती है कि वह उक्त नियोजन को उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग I में सम्मिलित करना चाहती है।

केन्द्रीय सरकार उक्त नियोजन को सम्मिलित करने की बाबत उन सभी सुझावों या आक्षेपों पर विचार करेगी जो किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार मास की अवधि की समाप्ति के दिन या उससे पूर्व प्राप्त होंगे।

[एस-32017(2)/74-उद्योग ई (एम इन्ड्यु)]

हंस राज छाबड़ा, उप-सचिव

New Delhi, the 11th July, 1975

S.O. 2396.—Whereas the Central Government is of opinion that the Minimum rates of wages should be fixed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in respect of employment in Quartzite, Quartz and Silica Mines;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 27 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment to Part I of the Schedule to the said Act.

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition on or before the expiry of a period of four months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, will be considered by the Central Government.

[S-32017 (2)/74-WE (MW)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1975

का० प्रा० 2397.—बिहार राज्य के गिरडीह जिले में 22 फरवरी, 1975 को माइल खदान के सामने कोयले का खनन करते समय एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें कई व्यक्तियों को जीवन से हथ धोना पड़ा; और चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि उक्त दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की एक औपचारिक जांच की जानी चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सेवा निवृत्त सचिव श्री पी० एम० नायक को उक्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को भी जांच में असेसर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, अर्थात्:—

- (1) श्री बी० के० खरबंहे
जनरल मैनेजर,
सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड,
- (2) प्रो० जी० बी० मिश्र,
इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, खड़गपुर,
- (3) श्री दामोदर पाण्डे (संसद सचिव)
सचिव,
कोलियरी मजदूर संघ
डाकखाना, भरकुन्दा कोलियरी
जिला हजारीबाग (बिहार)

(4) श्री शफीक खान,

युनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन, नं० 4 एरिया,
डाकखाना बेरमो, जिला हजारीबाग,
(बिहार)।

[सं० एन० 11015/1/75-एम० 1]

टी० एस० कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

New Delhi, the 11th July, 1975

S.O. 2397.—Whereas an accident occurred while mining coal opposite Mael Colliery in District Giridih, State of Bihar on the 22nd February, 1975 causing loss of lives;

And whereas the Central Government is of opinion that a formal inquiry into the causes of and circumstances attending the accident ought to be held;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri P. M. Nayak, retired Secretary to the Government of India, to hold such inquiry and also appoints the following persons as assessors in holding the inquiry, namely:—

- (1) Shri V. K. Karwande,
General Manager,
Singareni Collieries Company Limited.
- (2) Prof. G. B. Mishra,
Indian Institute of Technology,
Kharagpur.
- (3) Shri Damodar Pandey, M.P;
Secretary,
Colliery Mazdoor Sangh,
P.O. Bhurkuna Colliery,
District Hazaribagh (Bihar).
- (4) Shri Shafique Khan,
United Coal Workers, Union, No. 4 Area,
Post Office Bermo, District Hazaribagh
(Bihar).

[No. N. 11015/1/75-MI]

T.S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

New Delhi, the 11th July, 1975

S.O. 2398.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Alleppey in the industrial dispute between the employers in relation to the Production Centre, Ettumanur and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th July, 1975.

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
ALLEPPEY

Dated this the 28th day of the June, Nineteen hundred and
Seventy five

Present

Shri K. P. M. Sheriff, BSc; B.L;

Presiding Officer of the Industrial Tribunal Constituted by
the Central Government

Industrial Dispute No. 1/1974 (Central)

BETWEEN

The Director, Production Centres, Ettumanur, Kerala State

AND

The Workmen represented by the Secretary, Central
Government Small Scale Industries Organisation

Employees Union, Ettumanur, Kerala State.
Representations :—

Shri K. Prabhakaran.—For Management.

Jr. Central Government

Standing Council, Ernakulam.

Shri C. K. Parameswara Panicker.—For Union.

Advocate, Alleppey.

AWARD

This industrial dispute between the above parties was referred for adjudication, by the Government of India (Bharat Sarkar), Ministry of Labour/Shram Mantralaya for adjudication, constituting an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan was the Presiding Officer with Head quarters at Madras. The issue referred for adjudication is as follows :—

“Whether the Director, Production Centres, Ettumanur, is justified in deying temporary status, regular scales of pay and other benefits to 35 casual workmen employed at the various production centres in the State of Kerala, if not, to what relief are the workmen entitled and from what date?”

2. Pursuant to summons both the parties appeared before the Industrial Tribunal, Madras and the Central Government Small Scale Industries Organisation Employees Union Ettumanur submitted their claim statement on 29-3-1974. The case was thereafter posted for the counter statement of the Management for which the Management was obtaining several adjournments. In the meantime the Government of India, Ministry of Labour issued an order on 27th June, 1974 withdrawing the proceedings in relation to this dispute from Thiru T. Palaniappan, Industrial Tribunal, Madras and transferring the same to the Industrial Tribunal, Alleppey constituting an Industrial Tribunal with Shri K. P. M. Sheriff as the Presiding Officer with Headquarters at Alleppey, as per Sec. 7A and Sub-sec. (1) of Sec. 33B of the I.D. Act, 1947.

3. On receipt of the order, this Tribunal has called for the files and registered the industrial dispute as no. 1 of 1974 (Central) posting the case to 30-9-74 for appearance of parties and for the reply statement of the Management. On 30-9-74 the Union was absent and the Management applied for time for filing reply statement and the case was posted to 14-10-74. On 14-10-74 also the Management applied for time and the Union was absent again. Therefore the application for time was rejected and the Union was declared ex-parte, issuing registered notice to the Union and posting the case to 12-11-74. On 12-11-74 the Management and their counsel appeared and filed a petition and an affidavit to set aside the disposal order against them which was allowed. They have also submitted their reply statement. The Union filed a petition and an affidavit to set aside the ex-parte order and since there was no objection from the side of the Management the ex-parte order against the Union was also set aside posting the case for the replication of the Union and schedule of witnesses and documents of both parties to 27-11-74. On 27-11-74 the General Secretary of the Union submitted that the Union has no replication and the Management submitted their schedule of witnesses and list of documents. The case was then posted for the evidence of the Union posting to 9-12-74. On 9-12-74 the Union filed a fresh Vakalath and applied for time which was granted as a last chance, posting the case to 24-12-74 for the evidence of the Union. On 24-12-74 the case was adjourned since it was a holiday, posting the case to 1-1-75. On 1-1-75 the Union examined WW1, marked Exts. W1 to W 10 and Ext. M1. The case was then posted for further evidence of the Union, if any or for Management's evidence to 25-1-75. On 25-1-75 the Union declared that they have closed their evidence and the Management prayed for time which was granted, posting the case to 6-2-75 for Management's evidence. On 6-2-75 the learned counsel for the Management applied for time which was

granted posting the case to 26-2-75 for the Management's evidence and hearing. On 26-2-75 the Management examined MW1, marked Exts. M2 to M4 and closed their evidence. The case was then posted to 22-3-75 for hearing declaring that no further chances will be given to the parties for the same. On 22-3-75 the parties agreed to submit argument notes and the case was taken up for award. The Management has submitted their argument notes on 26-4-75.

4. In the claim statement, the Union has set up their case as follows :—

“Government of India, Production and Extension Centres in Kerala functioning under the administrative control of the Director of Production Centres at Ettumanur is a permanent Department of the Central Government, i.e. Central Government Small Scale Industries Organisation under the Ministry of Industrial Development. The workers represented by this Union are employed regularly in various centres, paid from the contingency fund and has been working for more than 12 years. These workers are designated as casual labourers till this date, even though most of them have completed more than 12 years of continuous service, but all the benefits deriving out, for a regular employee are denied to these workers. These employees are to be classified as the regular employees vide Government of India, Ministry of Finance O.M. No. F. 1 (10) Ect. SPI/49, dated 16-6-49 and 16-10-49.

Considering the past long continuous service over 12 years the so called category of workmen are to be absorbed in the regular establishment. This point has been stressed in Office Memorandum of Govt. of India, Min. of Finance, Nos. F. 8(2) Est. (Spl) 60, dated 24-1-1961, F. 11 (5) E. 111/61, dated 10-2-61 and F. 11(5) E. 111/61, dated 15-12-1962. As these workers are treated in pari with the N.M.R. workers of the Kerala Government and the Kerala Government has accepted the N.M.R. workers as regular employees with the pensionary benefits, gratuity, regular scales of pay, holidays etc, vide, Kerala Government G. O. No. (MS) 166/PW, dated 10-10-69, all the benefits granted thereunder by the Kerala Government are to be extended to these employees. In either case these workers are eligible to be absorbed in the regular establishment in a regular scale of pay. Pay and allowances, weekly holidays and overtime allowance are to be regulated in accordance with the provisions contained in Office Memorandum, dated 16-6-49 and their wages were governed vide para 2 (2) (c) of the said O.M. till 10-2-61 and thereafter in accordance with the provisions contained in Office Memorandum of the Ministry of Finance No. F. (2) Est. (Spl) 60, dated 24-1-1961, II(5) E. 111, dated 10-2-61 and 15-12-62. Accordingly they are eligible for fixed pay of Rs. 70/- plus D.A. as applicable to the Class IV employees belonging to the regular establishment. These benefits are denied to them.

The concerned workers are to be treated on a par with the N.M.R. workers of the State Government and they are to be paid the scale of pay of Rs. 75-85-3-100, plus D.A. at Re. 1 for every 5 point of increase in the cost of living index above 500 points and Rs. 5/- per mensem as H.R.A. besides retirement benefits, compensatory allowance, holidays, uniforms, washing allowance etc. In either case these workers are eligible for regular scales of pay and other benefits as to that of a regular employee. After every 48 hours of work a week these workers are eligible for a days rest with wages, since the benefits provided by Rules 23-25 of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950 has been made applicable to these workers vide O.M. of Ministry of Finance No. F. 8 (2) Est. SPL. 60 dated 24-1-61. All the holidays available to the N.M.R. workers of the Kerala Government are to be given to these employees. These employees are entitled to all kinds of leave enumerated in O.M. of Ministry of Finance No. 7 (84) E. N. (A) 60, dated 17-11-61, as amended by F. 8 (41) E. 111 (a) 64, dated 29-8-1964, 8 (1) E. IV (A) 70, dated 27-3-1971. This benefit is also denied to them.”

The Secretary of the Union concluded with a prayer that this court may be pleased to decide that these employees are eligible to be made permanent and that they are entitled to regular scale of pay, dearness allowance, compensatory allowance, washing allowance, uniforms, holidays, rest day with wages, over time allowances, leave and all other benefits.

5. In the counter statement submitted by the Management they have contended as follows :—

"Casual labourers are employed by the Small Industries Development Organisation (Government of India) at the Extension Centres, Production Centres and Central Workshop all over India, working under the above organisation. The main dispute referred for adjudication relates to regularisation of these casual labourers as regular class IV and other establishment. Absorption of this category of employees in regular establishment is of an All India character and cannot be dealt with piece-meal or production unit-wise. This involves naturally, question of national importance and the industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested and affected by such dispute. It is, therefore, necessary that this would attract the Provisions under 7B of the Industrial Disputes Act and the competent authority to adjudicate upon such dispute is a National Tribunal. The Secretary of the Union has already filed a petition before the Labour Court, Quilon as P.W.A. 64/69 under Payment of Wages Act for dearness allowance, rest day wages, etc. This petition is still pending before that Court. Hence the Union cannot bring forth the present claim statement for payment of dearness allowance and rest day wages, etc. before the Tribunal for adjudication.

Apart from this the only claim of the Applicant in this case is the regularisation of the casual labourers as Class IV or similar categories. In this connection, it is submitted that the Government is already seized with the question of absorbing casual labourers in regular establishment. The matter is under consideration.

The Management admitted that paragraphs 1 and 2 of the claim statement are substantially correct. With reference to the averments in para: 3 to 6 of the claim statement, the Management contended as follows :—

The contention of the workmen that casual labourers are to be classified as regular employees and their wages may be fixed on a par with regular employees on the basis of various office memorandum issued by the Ministry of Finance is not sustainable. Office Memorandum, dated 16-10-49 relied on by the workmen cannot be made applicable to the workmen in the various Production Centres under this Management. The casual labourers employed under this management are paid wages according to the market rates. The question of further claim by way of dearness allowance and other allowances does not arise in view of paragraph 2(2) (d) of the above said office memorandum. The wages of the casual labourers under this management are renewed from time to time and suitable increase in wages is given having due consideration to the following matters:

1. Wages of similar category of workers doing comparable work in State and other autonomous bodies.
2. Rise in the price index. The statement of wages presently in force in regard to 25 persons listed in Ext. A of the Union is produced. The said statement also indicates the wages prevalent as on 1-1-73 and the increase in Wages effected during the span of just over an year. The statement of the Union does not therefore merit any consideration as the Director is acting consistent with the provisions in para. 2(2) (d) of the O.M. referred to.

The afore-mentioned memorandum further lays down that the Finance Ministry would evolve certain general criteria and standards for absorption of various categories of contingency staff into the regular establishment. So far no rules or regulation laying down the principles on which the casual labourers under this Management to be absorbed into regular establishment have been made. In the absence of any such rules or regulation or orders issued by the Government in this behalf, this Management is not in a position to absorb the casual labourers to the regular establishment as claimed by the workmen. However, the Ministry of Industrial Development under whom this management is functioning has already initiated action for absorption of casual labourers into the regular establishment and the matter is engaging their serious attention.

The O. M., dated 10-2-61 has since been superseded by a subsequent order conveyed in Ministry of Finance O.M. No. F. 7(5) F. III (A)/69, dated 9-4-69. The O.M., dated

15-12-62 is only an amendment to the earlier memo, dated 10-2-61. This also indicates that the employments of the casual labourers be regulated under para. (2) (c) of the Ministry's memo, dated 16-6-49. Another important point conveyed is the question of review of all cases of casual labourers employed before 28-2-63. The Directorate and the Centres working under it started functioning from 1959 and onwards. The Extension Centre, Muvattupuzha was commissioned in August, 1963. These centres were nascent in their origin and too formative in their activities. Naturally, the question of review before 28-2-63; could not have been completed for the reason that it was premature to assess the quantum of casual labour that could be employed on regular basis. Even the full compliment of the regular staff was not working at these Centres at the early stages. Decision regarding target of production and other important policy matters for the proper and effective functioning of the Centres were not fully formulated. At such a stage the question of casual labourers and their regularisation did not arise for consideration.

Regarding the statement in para. 7 and 8 of the claim statement, the question of parity of casual labourers with non-muster roll workers of the State Government with regard to salary and other benefits does not arise. Casual labourers under this management are allowed the following benefits under the Factories Act, 1948.

1. Annual leave with wages at the rate of one day for every 20 days work performed during a year (Sec. 79 of the Factories Act).
2. Extra wages for overtime work at double the normal rate when the daily work exceeds 9 hours a day or the period exceeds 48 hours a week (Sec. 59).
3. Weekly holidays under Sec. 52.
4. Other facilities such as first aid, etc. are also provided under Welfare Chapter V of the Factories Act.

They are also entitled to retrenchment benefits equal to 15 days average pay for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months period. Similarly they are entitled to compensation under Workmen's Compensation Act. They are also entitled to benefits of Employees' Provident Fund and Employees' Family Pension. Casual labourers employed at Ettumanur Centre derive the benefits under the E.S.I. Scheme which included (1) Sickness benefit, (2) Disablement benefit, (3) Dependent benefit and (4) Provision for medical treatment of worker and his family members.

Incidentally of the 25 workmen listed in Ext. A, 16 are employed at Ettumanur Centre where they derive the benefits under the E.S.I. Scheme".

The Management concluded with an affirmation that in the circumstances the claim of the workmen for temporary status in the regular establishment does not arise at this stage since the Government of India, Ministry of Industrial Development has already taken up the matter and till rules or regulations laying down the principles of absorption of the casual labourers to the regular establishment are made, the claim of the workmen for absorption into regular establishment does not arise and the said claim is premature and prayed that the dispute may be dismissed.

6. The only witness who was examined by the Union is Shri Thirivikkraman, the General Secretary of the Union. He has deposed as follows :—

Chief :—I am the General Secretary of the Central Government Small-scale Industrial Organisation Employees' Union. I am working in the Production Centre, Government of India at Ettumanur, since the last 14 years. Among the union members 16 persons are working in the Ettumanur Production Centre, 6 are working in the Muvattupuzha Extension Centre and 3 are working at Thiruvalla Production Centre. Among them there are persons who have entered the service in the year 1959. It is the Director of the Production Centre who has appointed them and who is controlling their work. The names of the employees who are members of our Union and their place of work etc., is shown in a list produced by the Union. The said list is marked as Ext. W1. All the 25 people shown in Ext. W1 are members of our Union. Over and above these 25 people there are 6 more employees who are working at Thiruvalla, Ettumanur and Muvattupuzha who are not members of our Union. In Ext. W1 the names

of the workers, the date of their entry into service and their place of work are shown truly and correctly. All the three establishments are registered under the Factories Act. They are using power for the work done there. The work done by the concerned employees is to assist the workers who work on the machine, foundry section and casting section. The concerned employees are known as casual workers. All of them are working there permanently for more than 12 years. The Union has tried on several occasions to get these employees regularised. A notification concerning these employees is produced and marked as Ext. W2. Along with the said Government notification an Office Memorandum No. F8 of the Ministry of Finance also is produced, which is marked as Ext. W3. The Management has never allowed to absorb these employees in the regular establishment. Another office memorandum from the Finance Department concerning these employees issued on 10-2-61 is produced and marked as Ext. W4. Yet another office memorandum dated 15-12-62 is also produced and marked as Ext. W5. We have demanded that at least we must be considered on a par with N.M.R. workers of the Kerala Government. The copy of the notification dated 25-11-69 is produced. That is a notification issued by the Kerala Government regarding the N.M.R. workers and granting their demands, which is marked as Ext. W6. The copy of the office memorandum dated 17-11-61 of the Ministry of Finance is produced and marked as Ext. W7. The copy of the office memorandum dated 29-8-64 is produced and marked as Ext. W8. The copy of the office memorandum of the Ministry of Finance dated 27-3-71 is marked as Ext. W9. The copy of the office memorandum of the Ministry of Labour dated 24-12-73 is marked as Ext. W10. These employees are getting daily wages. Now they are getting wages at the rate of Rs. 5 to 7.25 per day. Are they getting any other amenities? (A) As per the Factories Act leave with wages alone is given. We have demanded for all the other amenities. We have demanded a day's rest in a week with wages. But they are giving us a day's rest without wages in a week. We are getting one day's leave with wages after 20 days work. We are not given D.A. Neither fixed D.A. nor V.D.A. is given. We are getting only daily wages and nothing else. We have demanded on several occasions for giving us D.A. and V.D.A. We have also demanded retirement benefits, uniform allowance, compensatory allowance, washing allowance etc. But nothing was given. We have demanded the scale of pay of a regular employee, but not yet given. We have demanded all the holidays that are enjoyed by the N.M.R. workers of the State Government. Even the amenities granted as per Exts. W8, W9 and W10 are not given to us. We have demanded for the same. We have demanded that all the workers must be made permanent. The Wage Board constituted for the engineering workmen has fixed the rates of wages which are much higher than what we are getting now. We request that we must be given rates of wages according to the recommendations of the said Wage Board. (Question from court). Are you getting work at least 240 days in an year? (A) Yes. We are getting work for more than 240 days. Is the work done by you in the establishment, the permanent and regular work that is being done? (A) Yes. These workers have never worked at any other place during these concerned years.

Cross : In the Production Centre I have altogether 14 years service. I have been working during these years at Thiruvalla, Muvattupuzha, Ettumanur and Attingal. Now I am working at Ettumanur since one year. I am a clerk and I am on one month's leave now. Is not Ext. W2 a paragraph of the memorandum dated 16-6-49 of the Government of India Extract? (A) No. It is an amendment dated 16-10-49. It is an amendment concerning the memorandum dated 16-6-49. The memorandum dated 16-6-49 is now shown to me and it is marked as Ext. M1. It is not correct to say that Ext. W2 is an extract of a paragraph. In the list of documents for showing that it is an amendment dated 16-10-49 it is shown as extract dated 16-6-49. Before the Labour Court, Quilon, who is the Payment of Wages Authority, we have filed applications under Payment of Wages Act for D.A., rest day with wages for the 12 months in the year 1969 on the basis of delayed wages. That is pending. We are getting overtime wages for overtime work. It is given at certain times on single rate and at other times at double rate. I do not know the reason for this discrimination. We are getting weekly holidays, but we are not getting wages on holidays. For the casual workers there is contributory provident funds scheme. That was given to us because of our petition to the P.F. Commissioner who has come and made an enquiry in the establishment. F.S.I. benefits are given to the employees at Ettumanur. At Muvattupuzha and Thiruvalla

the employees are not getting the same since they are not in a covered area. We are not getting any other benefits which could be specifically mentioned. Are you not getting the enhancement of wages which are given to the casual workers yearly? (A) Upto 1-1-73 it was not done so. After 1-1-73 since the Union has made representations and since the Regional Labour Commissioner has interfered, the enhancement is given. After 1-1-1973 it was given three or four times. During the period mentioned in Ext. W2 the concerned employees were working side by side with the regular employees. Even the sweepers in these establishment are regular employees. All the casual labourers are working there continuously.

RE : Our demand is that we should get all these amenities with effect from 24-1-61.

Cross with permission : In our claim statement we have demanded that we should get these amenities from the period during which the Government has issued the same. We have raised the demand in the year 1965. Those demands are not produced.

7. MW 1 is Shri S. Meera Sahib, Deputy Director, Production Centre, Ettumanur. He has deposed as follows :—

Chief : I am the Deputy Director of Production Centre, Ettumanur, since four years. Previously I was the Asst. Director, Extension Centre, Muvattupuzha. I am conversant with the facts of this case. The statement showing the number of employees in various SISIS and Production Centre, Ettumanur is produced and marked as Ext. M2. Ext. M3 series 1 to 3 are the statements showing the rates of wages paid to the casual workmen in the Production Centre, Ettumanur, Thiruvalla and Muvattupuzha. Ext. M4 is the true copy of the letter sent by the Government of India, Ministry of Industry and Development regarding the absorption of the casual workers under the regular establishment. As per Ext. M3 series 1 to 3 the rates of wages to the casual workers upto 1-8-1974 are shown. Thereafter the rates are enhanced with effect from 1-2-1975 to the extent of 75 paise per head per day. Regarding the casual workmen their period of service ranges from 15 years to 1 year. The work done by them is helping the regular workers in the establishment, wherein we are manufacturing castings, forgings and doing fabrication work and machining work. For these works the said casual workers are necessary for helping the regular workers. These casual workers are also regularly employed. The rates of wages given to the casual workmen are on a par with the market rates available in and around the area and also the P.W.D. rates. At Ettumanur Production Centre the number of workers including the staff and the casual workers would come upto 150. The total number of workers at Ettumanur, Thiruvalla and Muvattupuzha inclusive of the staff and the casual workmen are 230. We are not making profits in Ettumanur Centre and the total loss for all the Centres together from the very inception upto date is about Rs. 75 lakhs. There is another Centre at Attingal under this Directorate wherein there are only two casual workers who are recently employed. This Centre at Attingal was making profits for one year in its history.

Cross : Among the casual workers there are skilled workers also who are helping skilled regular workers. In Muvattupuzha Centre the casual workers are the Machine Operators. These establishments were started by the Government for giving employment to the unemployed and also for training the artisans of Small-scale Industries. At the outset the motive was not for making profits. But now it is considered to be a commercial enterprise. Arrangements are there, for getting raw materials at controlled rates. The Centres are free to dispose of the articles manufactured in the open market. The regular workers were and are getting better wages than the casual workers. From 1965 the casual workers were also demanding the same rate of wages given to the regular workers. We will be able to file a statement showing the difference in wages paid to the regular and casual workers in the various Centres with effect from 1965. We are given D.A. to the regular workers, but not to the casual workers, so also the regular workers are getting holiday wages and Sunday wages, but the casual workers are not getting the same. In Ext. M3 the wages shown are only from 1-1-1973. Previous to Ext. M3 the wages were lower. We can submit statements showing the rate of wages paid to casual as well as regular workers with effect from 1-1-65 onwards.

Re: The permanent workers in these establishments are designated as Mistrys Class III Government servants. They are full-fledged Government servants. There are recruitment rules framed by the President of India for recruiting these Mistrys. The scale of pay of these Mistrys are provided in the said rules and revised by the Pay Commission. To absorb these casual workers into the regular category, Government has powers and not the Directorate. The Directorate has got only the power of appointment of the casual workers. Certain qualifications are prescribed for recruiting the Mistrys as per the rules. For selecting the casual workers such qualifications are not looked into.

Cross with permission : I put it to you that the said recruitment rules were framed only in 1969, is it not ? (A) I do not remember.

8. On a meticulous scrutiny of all the contentions of both the parties as per their statements and an anxious consideration of the oral and documentary evidence adduced by the parties and also on a perusal of the argument notes submitted by the learned counsel for the Management, I am constrained to hold as follows :—

The number of employees referred to in the reference order is 35. Ext. W1 showing the names of 25 workers, point out that the said 25 workers only are the members of the Union. The only witness who was examined for and on behalf of the Union, viz., WW1 Shri Thirvikraman Nair, has admitted that over and above these 25 there are six more employees who are working at Thiruvalla, Ettumanur and Muvattupuzha who are not members of the Union. It has also come in evidence through MW1 Shri Meera Subib, Deputy Director, Production Centre Ettumanur, that there are two more casual workers at Attingal Centre under this Directorate who are recently employed. Regarding the 25 members shown in Ext. W1 statement, which is not challenged by the Management, the date of joining and the place of working are shown. On a perusal of the dates of joining it is seen that one T. V. Kuttappan Nair has joined the service on 4-5-1970 whereas K. V. Thomas has joined the service on 6-10-1958. At any rate the majority of the workers shown in Ext. W1 have completed more than 12 years service as such in their respective places of work, viz., at Production Centre, Ettumanur and Thiruvalla and Extension Centre at Muvattupuzha.

9. Admittedly the casual employees who are concerned in this dispute are allowed by the Management, the benefits of annual leave with wages, at the rate of one day for every 20 days of work performed during the year, extra wages for overtime work at double the normal rate when the daily work exceeds 9 hours a day or the period exceeds 48 hours a week, weekly holidays and other facilities such as first aid etc. It is also admitted by the Management as per their statement, that they are entitled to retrenchment benefits equal to 15 days average pay for every completed year of service or part thereof in excess of six months period, compensation under the Workmen's Compensation Act and also benefits of E. P. F. and Employees' Family Pension. Over and above this, the casual workers employed at Ettumanur Centre derive the benefits under the E. S. I. Scheme including sickness benefit, disablement benefit, dependent benefit and provision for medical treatment of workers and their family members. It has also come in evidence that the E. S. I. benefits are not enjoyed by the casual employees who are working at Thiruvalla and Muvattupuzha area because of the fact that the said areas are not covered by the provisions of the E. S. I. Act.

10. Indisputably the concerned workers are continuously working in the respective Centre for a considerable number of years, but they are given wages only as per the market rates, which are evidenced by Ext. M3 series 1 to 3. MW1, the Deputy Director has unambiguously admitted in his sworn statement that the concerned employees were given increased rates only from the year 1973 and before that they were getting lower wages. He has also admitted in the cross-examination that the regular workers were and are getting better wages than the casual workers and from 1965 the casual workers were demanding the same rates of wages given to the regular workers. The Deputy Director has deposed that among the casual workers there are skilled workers who are helping the skilled regular workers and that in Muvattupuzha Centre the casual workers the Machine

Operators. From the afore-mentioned facts it has to be noted that the casual workers are not employed for any odd casual work for the time being, but are employed for regular work continuously even from the very inception of the establishment and all of them are doing the same kind of work that is being done by the regular workers in the establishments. As admitted by the Management there are skilled workers among them and also Machine Operators. As can be seen from the evidence adduced by both the parties the casual workers, who are unfortunately dubbed as such, have practically no difference between the regular workers in the matter of work and attendance although they are getting only lower wages and fewer amenities than the regular workers, inspite of the fact that the large majority of them have put in service for more than ten or twelve years. Of course, the casual employees were, admittedly, making innumerable number of representations to the Management to redress their grievances, but were of no avail. The arguments of the learned counsel for the Management are to the effect that "the granting of temporary status requires sanction of regular establishment to absorb these workmen, fixation of scales of pay etc., that these are within the exclusive powers of the Government of India, Ministry of Industries and that the Director has no power to create these additional posts." He has also added that since the matter is already under consideration by the Government, there is no question of denial of temporary status by the Director. On a perusal of the afore-mentioned submission by the learned counsel for the Management, any reasonable person can come to the only conclusion that the Director is willing to grant temporary status, regular scales of pay and other benefit to the casual workmen, but the Government of India is lagging behind in the matter of granting him the necessary authority for the same. Even if the above mentioned submission is correct, the net result is that the representations made by the concerned employees since the year 1965, have become futile and can be considered as only a 'cry in the wilderness'. MW1, the Deputy Director himself has admitted that the concerned employees were demanding the same rate of wages etc., given to the regular workers, from the year 1965. But he is washing his hands off as to the responsibility of complying with the request of the concerned workmen, and his learned counsel was arguing as mentioned above, shirking the responsibility and diverting the same to the Government of India and the Ministry of Industries. Now, it cannot be denied that he employer is the Director of the establishment since he is the appointing authority and since he is giving them wages and supervising and controlling their work etc. Of course the demands made by the concerned casual employees are not considered to be exorbitant or unreasonable by the Management. Therefore, even if the implementation of the same can be done only by the Government of India, it should have been done by the Management through the Government of India by incessant intervention and requisition made to the Government. Any how, admittedly the representation made by the workers in the year 1965, is even now pending consideration by the Government of India as alleged by the Management.

11. At this juncture certain documents produced and marked by the Union to substantiate their case deserve consideration. Ext. W3 is the copy of an office memorandum No. F. 8 (2) Est (Spl) 60 dated the 24th January 1961 from the Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi. This Memorandum was in connection with the recommendation of the pay Commission regarding the casual employees and the regulation of the terms and conditions of their employment. Some of the recommendations are as follows :—

"Casual employment should be restricted to work of a truly casual nature and in order to ensure that this is done, there should be general review of the existing position.

All casual labour under the Central Government including those to whom the minimum wages law is not applicable, should have the benefits and safeguards provided by rules, 23-25 of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, relating to weekly holidays, working hours, night shifts and payment for overtime.

Long experience as casual labour should be taken into consideration while making selections for appointment to regular establishments.

The President has been pleased to decide that except where there are statutory rules or provisions in support of the existing practice, the recommendations of the Pay Commission regarding casual labour should be accepted."

It is worthy to note that even in the year 1961 the President has been pleased to decide that the recommendations of the Pay Commission regarding casual labourers should be accepted. At any rate it cannot be denied that these recommendations were not accepted by the concerned Management regarding the concerned employees.

12. Ext. W4 is the copy of the Office Memorandum No. 11(5)E. III dated 10-2-1961 from the Ministry of Finance (Department of Expenditure). This is also in connection with the casual labour. It reads as follows :—

"In supersession of the orders contained in para (2) 2 (c) of this Ministry's Office Memorandum No. F. 1 (10) Est. (Spl)/49 dated 16th June, 1949, the undersigned is directed to say that the Government of India have decided that employees paid from contingencies who are not brought on to regular establishment (i.e. who are classed as 'casual' employees) shall, with effect from the 1st July, 1959, be entitled to a fixed pay of Rs. 70/- p.m. or such other pay as may be fixed in individual cases by special orders. In addition to this, they will be entitled to dearness, compensatory and other allowances at the same rates and in the same manner as are prescribed for Class IV staff belonging to regular establishments with effect from the same date. They shall not be eligible to leave, pension, medical attendance or travelling allowance benefits."

As per this memorandum the casual employees are entitled to a fixed pay of Rs. 70/- per mensem or such other pay as may be fixed in addition to dearness, compensatory and other allowances at the same rate and in the same manner as are prescribed for Class IV regular establishment.

13. Ext. W5 is a copy of the Office Memorandum No. F.II(5)E.III/61 dated 15th December, 1962 from the Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi. In this memorandum it is stated as follows :—

"In accordance with the orders issued in this Ministry's O. M. No. F. 8(2)Est (Spl)60 dated 24th January, 1961, on the recommendations of the Pay Commission, the position of casual labour including those governed by para 2(2)(c) of the Office Memorandum of the 16th June, 1949 should be reviewed.

As a result of the decision taken after review, the remuneration of casual employees brought to regular establishments would be regulated as for regular employees.

If, however, as a result of the review, it is decided to continue such employees on casual basis, the remuneration in all cases should be regulated in accordance with para 3 of the Office Memorandum No. F.8(2)Est(Spl)60 dated the 24th January, 1961.

It is requested that the review in all cases should be completed before 28th February, 1963 and result reported to this Ministry."

14. On a perusal of Exts. W3, W4 and W5 it can be seen that the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) was encouraging the regularisation of casual employees and their treatment on a par with the regular employees. But the learned counsel for the Management has contended in his argument notes as follows :—

"As a matter of fact in terms of Exts. W3, W4 and W5, the question of bringing the casual workers to the regular establishment depending on the nature of the works and on the basis of the guide lines laid down in the said office memoranda has to be reviewed and re-examined by the Government and the same is under consideration."

15. As can be seen, Ext. W3 is dated 24-1-1961, Ext. W4 is dated 10-2-1961 and Ext. W5 is dated 15-12-1962. Therefore these office memoranda are more than a decade old. Even then the learned counsel for the Management would say that they are under consideration. This inordinate delay and unreasonable lethargy regarding the redressing of the genuine grievances of the workmen concerned can only be considered as unjustifiable, unreasonable and also as violation of natural justice.

16. The learned counsel for the Management has at the flag end of his argument notes contended as follows :—

"Regarding the second part of the issue, it is submitted that assuming that the casual workmen are entitled to be brought on to the regular establishment as per the terms of the above said office memoranda, it is submitted, that it cannot have a retrospective effect in as much as the workmen are being paid wages at market rate prevailing in similar institutions. Further it is borne out by evidence adduced on behalf of the Management that the institution is being run under loss and no profit has been derived during any of the years after its existence. This is an important aspect, it is submitted, that should be taken into consideration in giving effect to any award that may ultimately be passed in the case"

In the light of the afore-mentioned contention of the learned counsel for the Management, it has to be understood that the Management is opposed to any retrospective effect even if the award is passed regularising the concerned casual employees with the regular establishment, since he would say that the concerned workers were paid wages at the market rates prevailing in similar institutions. But it is at this juncture that I have to point out that even the Deputy Director MW1 has admitted that although the concerned casual employees were getting wages at the market rates, the rate of wages paid to them are definitely less than the rates of wages obtained by the regular workers at present as well as in the past. Therefore, even if an award is passed regularising the casual employees with retrospective effect, it cannot be considered as unjustifiable and unreasonable.

17. Regarding the loss sustained by the Institution, no cogent evidence has been adduced by the Management except the bald statement of MW1 to that effect. But MW1 himself has admitted in the cross-examination as follows :—

"These establishments were started by the Government for giving employment to the unemployed and also for training the artisans of Small Scale Industries. At the outset the motive was not for making profits. But now it is considered to be a commercial enterprise. Arrangements are there, for getting raw materials at controlled rates. The Centres are free to dispose off the articles manufactured, in the open market."

In the light of the sworn statement of MW1 any reasonable person can come to the only conclusion, that even if the declaration that the Institution has sustained continuous loss etc., is considered to be true, it is only the expected loss since the Institution has been established not with a profit making motive, but with a view to solve the unemployment problem as well as training artisans of Small Scale Industries. It is also interesting to note that the Deputy Director himself has admitted at the flag end of his chief examination that the Centre at Attingal was making profits for one year in its history. Now that the concern has become a commercial enterprise and they are free to dispose off the articles manufactured in the open market, after getting raw materials at controlled rates, the concern has to make profits in the ordinary course of business. Anyhow, whether the establishment has sustained loss or not, it would be a travesty of justice on the part of the Management to discriminate between the concerned employees and the regular employees, despite the fact that the concerned employees are working for the last decade or more and also that they are doing the same and similar work as the regular workers are doing. Therefore the plea of loss on the part of the Management especially when they are confronted with the question of redressing the long standing and genuine grievance of a set of workers, cannot be countenanced on the basis of law, equity or good conscience. The learned counsel for the

Management has then argued that there is no specific claim nor any pleadings in the claim statement that they should be given the award commencing from a date anterior to the date of reference of the dispute. This statement of the learned counsel for the Management cannot be considered to be correct as such. In the claim statement the Union has pointed out that "these employees are to be classified as regular employees vide Government of India, Ministry of Finance O.M.No.F.1(10)Est. SPI/49 dated 16-6-49 and 16-10-49". Thereafter they have pointed out all the concomitant office memoranda of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) thereby contending that the workers are entitled to be regularised with effect from the date of Office Memoranda of the Finance Department. WW1 Shri Thrivikraman, the Secretary of the Union, at the fag end of his sworn statement has deposed that they have raised the demand in the year 1965. The Deputy Director, who was examined as MW1 has admitted in the cross-examination that from 1965 the casual workers were demanding the same rates of wages given to the regular workers. Therefore, the contention of the learned counsel as per his argument notes, that there is no specific claim nor any pleadings in the claim statement etc., regarding payment to be made commencing from a date anterior to the date of reference of the dispute, cannot be considered as gospel truth. In fact, although the spirit of the claim statement of the Union is that the workmen are entitled to get regularisation with effect from the very beginning of the Institution, they have made their demand only in the year 1965. Yet the retrospective payment can be decided, only taking into consideration the financial burden which may be imposed upon the Institution by such an award.

18. The Deputy Director of the Management establishment has deposed at the fag end of the cross-examination as follows :—

"We will be able to file a statement showing the difference in wages paid to the regular and casual workers in the various Centres with effect from 1965. We are giving D. A. to the regular workers, but not to the casual workers so also the regular workers are getting holiday wages and Sunday wages, but the casual workers are not getting the same. In Ext. M3 the wages shown are only from 1-1-73. Previous to Ext. M3 the wages were lower. We can submit statements showing the rate of wages paid to casual as well as regular workers with effect from 1-1-65 onwards."

In spite of the afore-mentioned admission on the part of the Management, no statements were produced by the Management to show the difference in wages between the casual employees and the regular workmen with effect from 1-1-65. Therefore, there is no data for calculation of the financial burden, if at all imposed upon the Management, regarding the retrospective payment.

19. Now under paragraphs 8 to 17 of this award, I have discussed about the unjustifiability of the attitude of the Management towards the concerned casual employees in the matter of absorbing them as regular employees. Therefore I find that the concerned casual employees are entitled to be absorbed in the regular establishment of the Institution with the regular scales of pay and other benefits as enjoyed by the regular employees therein and so I declare that the Management is not justified "in denying temporary status, regular scales of pay and other benefits to the concerned casual workmen employed at the various Production Centres in the State of Kerala".

20. Regarding retrospective payment, I hold that it will not be justifiable on my part to direct the Management to give the scales of pay and other amenities to the concerned employees as per the award with effect from the date of their demand, viz., 1-1-65, since the financial burden involved in the same may be exorbitant, although no data has been given by the Management to show the financial burden specifically. Yet in order to atone for the inordinate delay caused by the Management in redressing the genuine grievances of the concerned workmen, I hold that it will be only just and reasonable on my part to direct the Management to make the payment with effect from 1-1-1972 and I do so.

51 GI/75-16

21. Thus I pass this award in terms specified above and this award shall come into force on the expiry of thirty days from the date of its publication in the Government Gazette.

K. P. M. SHERIFF, Industrial Tribunal.

Alleppey, 28-6-1975

APPENDIX

Witness examined on the side of the Management.—

MW1 Shri S. Meera Sahib.

Witness examined on the side of the Union.—WW1 Shri A. N. Thrivikraman.

Exhibits marked on the side of the Management.—Ext. M1. Copy of Office Memorandum No. F1 (10)-Est (Spl)/49., dated 16-6-1969 from Government of India, Ministry of Finance to all the Ministries of the Government of India.

Ext. M2. Statement showing the No. of employees in the various SISIS and Production Centres, Ettum-anur.

Ext. M3 (Series 1 to 3).—Statements showing the rates of wages paid to the casual workmen in production centres, Ettumanur, Thiruvalla and Muvattupuzha.

Ext. M4 True copy of the letter dated 20-8-1974 sent by the Government of India, Ministry of Industry and Development, regarding the absorption of casual workers under the regular establishment.

Exhibits marked on the side of the Union.— Ext. W1. List showing the names of employees who are members of Union and their place of work etc ..

Ext. W2 Copy of the extract of para. 2 (1) Govt of India, Ministry of Finance O. M. No. F. 1(10) Est-Spl./49 Dated 16-6-1949.

Ext. W3. Copy of Office Memorandum No.F8(2) Est (Spl) 60 dated the 24th January, 1961 from Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi.

Ext. W4. Copy of Office Memorandum No. ii (5)E. II, dated the 10th February, 1961 from Ministry of Finance, Department of Expenditure.

Ext. W5. Copy of Office Memorandum No. F. II(5)E. III/61 dated the 15th December, 1962 from the Ministry of Finance, (Department of Expenditure) New Delhi.

Ext. W6. Copy of Government Notification dated 25-11-69 regarding the N.M.R. workers and granting their demands.

Ext. W7 Copy of O.M. No. F. 7 (84) Est. IV(A)60 dated 17-11-61 from the Ministry of Finance, Dept. of Expenditure.

Ext. W8. Copy of Ministry of Finance O.M. No. F. 8 (41) E. IV(A)/64 dated 29-8-64 from the Ministry of Finance.

Ext. W9. Copy of Ministry of Finance (Dept. of Expenditure) O.M. No. 8(i) E. IV(A)70 dated 27-3-1971.

Ext. W10. Copy of Ministry of Labour Directorate General of Employment & Training O.M. No. EE. I-16(8)/73-VI. dated, 24-12-1973.

[No. L-42012(12)/73-LR. III/D. IIB]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

New Delhi, the 15th July, 1975

S.O. 2399.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Gov-

ernment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Hind Traders, Calcutta-23 and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th July 1975.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
CALCUTTA**

PRESENT :

Shri E. K. Moidu—Presiding Officer.

Reference No. 9 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Hind Traders, Calcutta-23.

AND

Their Workmen

Appearance :

On behalf of Employers—Absent.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port & Dock

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L-32011/14/74-PD/CMT/D. IVA dated 21st January, 1975 referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs Hind Traders, Calcutta-23 and their workmen, to this tribunal, for adjudication. The reference reads as follows :

“Whether the termination of services of seven Lassing Gangs, namely, Sarva Shri (i) Md. Ayub, Tindal (ii) Ali Hussain, (iii) B. K. Saha, (iv) S. K. Aktar (v) S. K. Kaloo (vi) Noor Islam and (vii) S. K. Amin with effect from 3rd May, 1974 by Messrs Hindu Traders, 13/1 Sastitala Road, Calcutta-23 is justified ? If not, to what relief are they entitled.”.

2. The management filed their written statement on 19-2-75 justifying the dismissal of the workmen from service on various grounds. But the workmen did not file any written statement. Neither the Union of the workmen nor the workmen themselves appeared before the Tribunal in response to the summons issued to them. The Union received summons on 6-2-1975 and again registered notice was

issued to them fixing 4-7-1975 as the final hearing of the case. The employer and the Union did not appear on that date also. So, the case was adjourned to 5-7-1975. Neither party appeared on that day as well as to-day to which the case stood posted for final hearing.

3. In the absence of both parties and neither party making out a case against the other, the only alternative is to reject the reference.

4. Accordingly, the Reference is rejected without coming to any decision.

Sd/-

E. K. MOIDU, Presiding Officer

Dated, Calcutta,
The 7th July, 1975.

[No. L-32011/14/74-P&D/CMT/D-IV(A)]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1975

आदेश

का. आ. 2400.—संख्या 377(ई).—केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश करती है कि भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 48 के उपनियम (2) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन निम्नलिखित प्राधिकारियों और अधिकारी द्वारा भी किया जाएगा :—

1. सभी राज्य सरकारें ।

2. भारत सरकार का मुख्य सेंसर ।

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में

[सं. 2/14011/2/75-एस. एंड पी. (डी-4)]

सी. वी. नरीसिंहन, संयुक्त सचिव ।